एम.ए. पूर्वार्द्ध

भूगोल, चतुर्थ प्रश्नपत्र

जनसंख्या और अधिवास भूगोल

(POPULATION AND SETTLEMENT GEOGRAPHY)

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY – BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. Renu Vinod Sharma
   Associate Professor
   Govt. S.N.P.G. Girls (Autonomous) College, Bhopal (M.P.)

2. Dr. Rajeshwari Dubey
   Professor
   Govt. M.L.B. (Autonomous) College, Bhopal (M.P.)

3. Dr. Neerja Bharadwaj
   Professor
   Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

2. Dr. L.S. Solanki
   Registrar
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

3. Dr. Anjali Singh
   Director, Student Support
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

4. Dr. Renu Vinod Sharma
   Associate Professor
   Govt. S.N.P.G. Girls (Autonomous) College, Bhopal (M.P.)

5. Dr. Rajeshwari Dubey
   Professor
   Govt. M.L.B. (Autonomous) College, Bhopal (M.P.)

6. Dr. Neerja Bharadwaj
   Professor
   Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)

COURSE WRITER

Dr. Sharmila Badhwar, Assistant Professor, Govt. College for Women, Sonipat
Units (1-5)

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

जनसंख्या और अधिवास भूगोल

Syllabi	Mapping in Book
इकाई–1 जनसंख्या भूगोल : अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उद्देश्य – अर्थ एवं परिभाषाएं – विषयवस्तु, क्षेत्र एवं उद्देश्य – अन्य विषयों से संबंध; विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास; भूगोल और जनसांख्यिकी : आंकड़ों के स्रोत – आंकड़ों के स्रोत एवं स्वरूप – जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रण की समस्याएं – आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर।	**इकाई 1** : जनसंख्या भूगोल **(पृष्ठ 3–25)**
इकाई–2 वितरण तथा घनत्व की अवधारणा – प्रयोग सिद्ध बनाम सैद्धांतिक वितरण संबंधी संकल्पना – ऊंचाइयों पर आधारित संकल्पना; जनसंख्या घनत्व और वृद्धि : सैद्धांतिक मुद्दे – जनसंख्या घनत्व के प्रकार – जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक; जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि के पारंपरिक, आधुनिक सिद्धांत एवं जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत – पारंपरिक सिद्धांत – आधुनिक सिद्धांत – जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत; विश्व जनसंख्या वृद्धि : स्वरूप एवं निर्धारक; भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि; अधोजनसंख्या और अति जनसख्या की संकल्पना।	**इकाई 2** : जनसंख्या वितरण **(पृष्ठ 27–77)**
इकाई–3 जनसंख्या की सरंचना एवं विशिष्टता – आयु और लिंग – ग्रामीण और शहरी संरचना – नगरीकरण – व्यावसायिक संरचना – लैंगिक मुद्दे; भारतीय जनसंख्या की संरचना – जनसंख्या प्रवास – जन्मदर एवं मृत्युदर का मापन – प्रवासन : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप – भारत की जनसंख्या गतिकी; जनसंख्या और विकास – भारत के जनसंख्या–संसाधन प्रदेश – सामाजिक–आर्थिक विकास तथा जनसंख्या स्तर।	**इकाई 3** : जनसंख्या संरचना **(पृष्ठ 79–186)**
इकाई–4 अधिवास बस्तियों के उद्भव–विकास की सैद्धांतिकता – मानव अधिवास बस्तियों के आकार – अधिवास निरूपक निर्धारक; आकार और वृद्धि में स्थानिक और सामाजिक प्रवृत्तियां – अधिवासों के विविध स्वरूप – सैद्धांतिक मॉडल और अनुभवजन्य निष्कर्ष – विश्व जनसंख्या वृद्धि : रुझान एवं प्रवृत्तियां।	**इकाई 4** : मानवीय अधिवास : उद्भव, आकार तथा अभिवृद्धि **(पृष्ठ 187–215)**
इकाई–5 अधिवास पदानुक्रम का आधार (क्रिस्टॉलर तथा लॉस की संकल्पना) – पदानुक्रम में सहायक कारक – केंद्रीय स्थान सिद्धांत : केंद्रीयता और पदानुक्रम का मापन; भारत में अधिवासीय पदानुक्रम की प्रायोगिक अवस्थिति – भारत में अधिवासों का पदानुक्रमिक प्रतिरूप – भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना।	**इकाई 5** : अधिवास पदानुक्रम **(पृष्ठ 217–244)**

विषय–सूची

परिचय **1–2**

इकाई 1 जनसंख्या भूगोल **3–25**

1.0 परिचय

1.1 उद्देश्य

1.2 जनसंख्या भूगोल : अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उद्देश्य

1.2.1 अर्थ एवं परिभाषाएं

1.2.2 विषयवस्तु, क्षेत्र एवं उद्देश्य

1.2.3 अन्य विषयों से संबंध

1.3 विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास

1.4 भूगोल और जनसांख्यिकी : आंकड़ों के स्रोत

1.4.1 आंकड़ों के स्रोत एवं स्वरूप

1.4.2 जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रण की समस्याएं

1.4.3 आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर

1.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1.6 सारांश

1.7 मुख्य शब्दावली

1.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

1.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 2 जनसंख्या वितरण **27–77**

2.0 परिचय

2.1 उद्देश्य

2.2 वितरण तथा घनत्व की अवधारणा

2.2.1 प्रयोग सिद्ध बनाम सैद्धांतिक वितरण संबंधी संकल्पना

2.2.2 ऊंचाइयों पर आधारित संकल्पना

2.3 जनसंख्या घनत्व और वृद्धि : सैद्धांतिक मुद्दे

2.3.1 जनसंख्या घनत्व के प्रकार

2.3.2 जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक

2.4 जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि के पारंपरिक, आधुनिक सिद्धांत एवं जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत

2.4.1 पारंपरिक सिद्धांत

2.4.2 आधुनिक सिद्धांत

2.4.3 जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत

2.5 विश्व जनसंख्या वृद्धि : स्वरूप एवं निर्धारक

2.6 भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि

2.7 अधोजनसंख्या और अति जनसख्या की संकल्पना

2.8 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

2.9 सारांश
2.10 मुख्य शब्दावली
2.11 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.12 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 3 जनसंख्या सरंचना **79–186**

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 जनसंख्या की सरंचना एवं विशिष्टता
3.2.1 आयु और लिंग
3.2.2 ग्रामीण और शहरी संरचना
3.2.3 नगरीकरण
3.2.4 व्यावसायिक संरचना
3.2.5 लैंगिक मुद्दे
3.3 भारतीय जनसंख्या की संरचना
3.3.1 जनसंख्या प्रवास
3.3.2 जन्मदर एवं मृत्युदर का मापन
3.3.3 प्रवासन : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप
3.3.4 भारत की जनसंख्या गतिकी
3.4 जनसंख्या और विकास
3.4.1 भारत के जनसंख्या–संसाधन प्रदेश
3.4.2 सामाजिक–आर्थिक विकास तथा जनसंख्या स्तर
3.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
3.6 सारांश
3.7 मुख्य शब्दावली
3.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 4 मानवीय अधिवास : उद्‌भव, आकार तथा अभिवृद्धि **187–215**

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 अधिवास बस्तियों के उद्‌भव–विकास की सैद्धांतिकता
4.2.1 मानव अधिवास बस्तियों के आकार
4.2.2 अधिवास निरूपक निर्धारक
4.3 आकार और वृद्धि में स्थानिक और सामाजिक प्रवृत्तियां
4.3.1 अधिवासों के विविध स्वरूप
4.3.2 सैद्धांतिक मॉडल और अनुभवजन्य निष्कर्ष
4.3.3 विश्व जनसंख्या वृद्धि : रुझान एवं प्रवृत्तियां
4.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

4.5 सारांश
4.6 मुख्य शब्दावली
4.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.8 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 5 अधिवास पदानुक्रम **217–244**

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 अधिवास पदानुक्रम का आधार (क्रिस्टॉलर तथा लॉस की संकल्पना)
5.2.1 पदानुक्रम में सहायक कारक
5.2.2 केंद्रीय स्थान सिद्धांत : केंद्रीयता और पदानुक्रम का मापन
5.3 भारत में अधिवासीय पदानुक्रम की प्रायोगिक अवस्थिति
5.3.1 भारत में अधिवासों का पदानुक्रमिक प्रतिरूप
5.3.2 भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना
5.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
5.5 सारांश
5.6 मुख्य शब्दावली
5.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.8 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक 'जनसंख्या और अधिवास भूगोल' का लेखन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एम.ए. भूगोल (पूर्वार्द्ध) के पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है। जनसंख्या और अधिवास भूगोल, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा में जनसंख्या एवं अधिवास से सम्बन्धित तत्वों का अध्ययन, भौगोलिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेशनल जियोग्रेफिक की एक मान्यता के अनुसार विभिन्न बस्तियों की जनसंख्या की संस्कृति, सुरुचि, परंपरा, जलवायु, पर्यावरण और विकास के स्वरूप का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने और उसके विकास में सहयोग करने वाले अध्ययन एवं ज्ञान को 'जनसंख्या और अधिवास भूगोल' कहा जाता है।

जनसंख्या भूगोल उन तरीकों का अध्ययन है जिनमें वितरण, रचना, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि में स्थानीय विभिन्नता का विवेचन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जनसांख्यिकी को सम्मिलित करता है। इस विषय के अंतर्गत किसी दिए गए समय में मर्त्यता, जन्म दर तथा वृद्धि दर जैसे तत्त्वों का अध्ययन किया जाता है। यह जनसंख्या में वृद्धि एवं घटाव तथा जनसंख्या की गति एवं चलनशीलता का विश्लेषण करता है। यह स्थान और समय के संदर्भ में जनसंख्या की गति एवं व्यावसायिक संरचना का भी अध्ययन करता है।

अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों यानी बस्तियों की स्थिति, उत्पत्ति, प्रतिरूप, व्यावसायिक संरचना जैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अधिवास का अर्थ होता है घर, जो मानव जीवन का आधार है। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण–आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी।

प्रस्तुत पुस्तक में जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल से संबद्ध विषयों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक इकाई के आरंभ में विषय विश्लेषण से पूर्व, उसके निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है। इकाई के बीच–बीच में 'अपनी प्रगति जांचिए' स्तंभ के माध्यम से विद्यार्थियों की योग्यता परखने के प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत पुस्तक में जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल से संदर्भित अहम विषयों का सांगोपांग समायोजन किया गया है।

पहली इकाई में जनसंख्या भूगोल की आधारभूत परिभाषाओं, क्षेत्रों एवं उद्देश्यों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है तथा जनसंख्या भूगोल के विकास का विवेचन किया गया है।

दूसरी इकाई में जनसंख्या वितरण तथा घनत्व की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है तथा अधोजनसंख्या व अतिजनसंख्या के संबंध में विस्तार से बताया गया है।

तीसरी इकाई में जनसंख्या की संरचना एवं विशिष्टता पर प्रकाश डाला गया है तथा जनसंख्या और विकास से जुड़े मुद्दों का विवेचन किया गया है।

टिप्पणी

चौथी इकाई में मानवीय अधिवास के उद्‌भव, आकार तथा अभिवृद्धि का विवेचन किया गया है तथा अधिवासों के विविध स्वरूपों का अध्ययन किया गया है।

पांचवीं इकाई अधिवास पदानुक्रम पर आधारित है। इसमें अधिवास पदानुक्रम के आधार तथा उसके व्यावहारिक प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई है।

इन इकाइयों के अध्ययन से विद्यार्थी इन विषयों से भली–भांति अवगत हो सकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा को शांत कर उनका ज्ञानवर्धन करने में सफल होगी।

इकाई 1 जनसंख्या भूगोल

टिप्पणी

संरचना

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 जनसंख्या भूगोल : अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उद्देश्य
  1.2.1 अर्थ एवं परिभाषाएं
  1.2.2 विषयवस्तु, क्षेत्र एवं उद्देश्य
  1.2.3 अन्य विषयों से संबंध
1.3 विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास
1.4 भूगोल और जनसांख्यिकी : आंकड़ों के स्रोत
  1.4.1 आंकड़ों के स्रोत एवं स्वरूप
  1.4.2 जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रण की समस्याएं
  1.4.3 आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर
1.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.6 सारांश
1.7 मुख्य शब्दावली
1.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.9 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय

जनसंख्या भूगोल, मानव भूगोल की एक बड़ी शाखा है जिसमें विश्व की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न विषय निहित हैं। जनसंख्या वितरण इनमें से प्रथम है, जिसे लोगों के रहने के स्थानों के आधार पर वर्णित किया जाता है। विश्व जनसंख्या घनत्व असमान है क्योंकि कुछ स्थान ग्रामीण एवं विरल बसे हुए (जनसंख्या वाले) क्षेत्रों के रूप में माने जाते हैं, जबकि अन्य अधिक घने बसे हुए शहरी क्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोलवेत्ता यह समझने के लिए प्रायः लोगों के पूर्व वितरणों का अध्ययन करते हैं कि वर्तमान में कैसे और क्यों कुछ विशिष्ट क्षेत्र बड़े नगरीय केन्द्रों के रूप में बदल गए। सामान्य रूप से, विरल बसे हुए क्षेत्र रहने के लिए कठोर दशाओं वाले क्षेत्र हैं जैसे कि कनाडा के उत्तरी क्षेत्र, जबकि घने बसे हुए क्षेत्र जैसे कि यूरोप या तटीय अमेरिका, रहन-सहन के लिए अधिक अनुकूल क्षेत्र हैं।

जनसंख्या वितरण से जनसंख्या घनत्व का बहुत करीबी संबंध है, जो कि जनसंख्या भूगोल का एक अन्य विषय है। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को कुल क्षेत्र से विभाजित करके किसी क्षेत्र में लोगों की औसत संख्या का अध्ययन करता है। सामान्य रूप से ये आंकड़े, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या मील के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस इकाई में हम जनसंख्या भूगोल का अर्थ, क्षेत्र एवं उद्देश्य स्पष्ट करते हुए विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में इसके विकास का अवलोकन करेंगे। भूगोल और जनसांख्यिकी पर भी इस इकाई में विचार किया जा रहा है।

1.1 उद्देश्य

टिप्पणी

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- जनसंख्या भूगोल का अर्थ समझते हुए इसके क्षेत्र एवं उद्देश्य से अवगत हो पाएंगे;
- विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास देख पाएंगे;
- जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रण की समस्याओं से अवगत हो पाएंगे;
- आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर को समझ पाएंगे।

1.2 जनसंख्या भूगोल : अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उद्देश्य

जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो लोगों, उनके स्थानीय वितरण एवं घनत्व पर केन्द्रित है। इन तथ्यों का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या भूगोलवेत्ता जनसंख्या में बढ़ोतरी एवं घटोत्तरी, समय के साथ लोगों के आवागमन, सामान्य आवास के प्रतिरूपों आदि का परीक्षण करते हैं। जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी (जनसंख्या सांख्यिकी एवं रूझानों का अध्ययन) से निकट रूप में संबंधित है।

जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं और प्रायः ये भी जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के लिए अध्ययन के विषय हैं। ऐसे कारक, किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण, जैसे कि जलवायु और स्थलाकृति से या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरणों से संबंधित हो सकते हैं।

1.2.1 अर्थ एवं परिभाषाएं

ट्रिवार्था और जनसंख्या भूगोल– जनसंख्या भूगोल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय ट्रिवार्था को है जिन्होंने सन् 1953 ई. में अमेरिकी भूगोलविद परिषद के अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया कि क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में जनसंख्या भूगोल का एक स्वतंत्र उपविषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिये। ट्रिवार्था के विचारों के बाद ही 1954 में अमेरिका में जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन नामक विषय शुरू किया गया। इसके अनुसार, "जनसंख्या भूगोल केन्द्रीय महत्व का विषय है, जिसका उद्देश्य मनुष्य की संख्या व उसकी विशेषताओं का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त भिन्नता का अध्ययन करना है।"

ट्रिवार्था के अनुसार, "पृथ्वी तल पर बसे लोगों की प्रादेशिक पृथक् अंतर सम्बन्धी ज्ञान में ही जनसंख्या भूगोल के तत्त्व निहित हैं।"

ट्रिवार्था का मानना है कि जनसंख्या भूगोल की परिभाषा प्रकृति के आधार पर करनी चाहिए। यह बात आज भी उतनी सत्य है जितनी कि पहले थी। सामान्यतः भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय विभेदीकरण जनसंख्या भूगोल का भी विषय–क्षेत्र है। ट्रिवार्था ने सन् 1969 में लिखा कि जनसंख्या भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में प्रादेशिक अन्तरों को समझना है। उनके कथनानुसार मनुष्य भौतिक भू–दृश्य का

उपयोगकर्ता तथा सांस्कृतिक भू–दृश्य का निर्माता है, इसलिए यदि भूगोलवेत्ता पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण को भली–भांति समझ सकें तो वे पृथ्वी की सम्पूर्ण की संकल्पना करने में समर्थ होंगे।

टिप्पणी

ट्रिवार्था की परिभाषा की आलोचना भी हुई मगर जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा का स्तर प्रदान कराने में ट्रिवार्था की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह भी सम्भव है कि जब प्रादेशिक भूगोल के स्थान पर क्रमबद्ध भूगोल को महत्व दिया जाने लगा तो जनसंख्या भूगोल को भी एक स्वतंत्र शाखा का रूप मिलने में सहायता मिली। ट्रिवार्था ने जनसंख्या भूगोल की परिभाषा में निम्नवत् तथ्यों को समावेशित किया है–

- जनसंख्या का अध्ययन एकपक्षीय नहीं बल्कि सम्पूर्ण भूगोल के अध्ययन का केन्द्र है।
- सभी क्षेत्रों में जनसंख्या अन्य सब घटकों को अर्थ व महत्त्व प्रदान करती है।
- भूगोलवेत्ताओं ने अब तक जनसंख्या भूगोल के अध्ययन को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी।
- जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक स्वतन्त्र क्रमबद्ध शाखा का स्थान मिलना चाहिए।
- जनसंख्या भूगोल का प्रमुख उद्देश्य भू–क्षेत्र में जनसंख्या के सभी तत्त्वों के वितरण में प्रादेशिक अन्तरों को समझना है।

ट्रिवार्था ने जनसंख्या के लक्षणों को जैविक लक्षणों, जैसे जाति–लिंगानुपात, आयु–संरचना, जन्मदर, मृत्युदर आदि एवं सांस्कृतिक लक्षणों, जैसे साक्षरता, भाषा, धर्म, आर्थिक संरचना, स्तर, राष्ट्रीय सजातीय संरचना में विभाजित किया।

विल्बर जैलिंस्की और जनसंख्या भूगोल जैलिंस्की के अनुसार, "जनसंख्या भूगोलविद जनसंख्या के भूविन्यासगत पक्ष का स्थल की सामुच्चयिक प्रकृति के सन्दर्भ में वर्णन करता है।"

जैलिंस्की द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार, "जनसंख्या भूगोल वह है जो उन विधियों का वर्णन करता है जिनसे किसी स्थल के भौगोलिक गुण निर्मित होते हैं तथा जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप जनसंख्या तत्त्व की उत्पत्ति होती है। अलग–अलग तत्त्वगत क्रिया तथा अपने पृथक् व्यवहारगत नियम के परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थान तथा काल के अंतर में बदलाव होता रहता है।"

इस तरह जैलिंस्की ने कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया है, वे हैं–

मनुष्यों की संख्या एवं विशेषताओं की स्थिति के सामान्य वर्णन, संख्याओं तथा विशेषताओं की क्षेत्रगत अंतर की व्याख्या और जनसंख्या तत्त्व का भौगोलिक विश्लेषण अर्थात् किसी भौगोलिक अध्ययन–क्षेत्र के भीतर जनसंख्या में क्षेत्रीय अंतर के कुछ अथवा सभी कारकों से अन्तर्सम्बन्ध की विवेचना।

भौतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिघटना के आलोक में क्लार्क लेज, जनसंख्या के स्थानीय वितरण पर जोर देते हैं और जनसांख्यिकी से जनसंख्या भूगोल को विभेदीकृत करते हैं। सन् 1965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'पॉपुलेशन ज्योग्रॉफी' में क्लार्क ने स्पष्ट

टिप्पणी

किया कि जनसंख्या भूगोल विविध स्थानों में जनसंख्या के वितरण, संघटन, प्रवास और वृद्धि की स्थानीय विशेषताओं से संबंधित है।

मेलेजिन के अनुसार, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या वितरण और विभिन्न जनसंख्या समूहों में उपस्थित उत्पादक संबंधों, आवास-प्रवास के नेटवर्क और समाज के उत्पादक लक्ष्यों के लिए इसकी उपयुक्तता, उपयोगिता और कार्यक्षमता का अध्ययन करता है। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन को बसे हुए स्थलों के क्षेत्रीय समूह के विश्लेषण द्वारा इनकी आर्थिक क्रियाशीलता पर जोर देते हुए चिन्हित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या वितरण के प्रतिमान, मौलिक रूप से आवास-प्रवास के नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और आवासीय प्रतिमानों में परिवर्तन प्रमुख रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं।

मैडम बीजू-गार्नियर ने अपनी पुस्तक 'ज्योग्रॉफी ऑफ पॉपुलेशन' में इंगित किया है कि जनसंख्या भूगोल, जनसांख्यिकीय कारकों को उनके वर्तमान वातावरण के संदर्भ में वर्णित किए जाने से संबंधित है, जो कारकों, उनकी मूल विशेषताओं और संभावित परिणामों का भी अध्ययन करता है।

विलियम जेलिंस्की ने अपनी पुस्तक 'ए प्रोलॉग टु पॉपुलेशन ज्योग्रॉफी' में जनसंख्या भूगोल को ऐसे विज्ञान के रूप में स्पष्ट किया है जो स्थलों की भौगोलिक विशेषता गठित करने वाले तरीकों और उन पर प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। जनसंख्या परिघटनाओं का एक सेट, अंतराल और समय के अनुसार स्वयं में भिन्न होता है, क्योंकि यह अपने स्वयं के व्यवहारिक नियमों का अनुसरण करते हुए एक-दूसरे से और असंख्य गैर-जनसांख्यिकीय परिघटनाओं से अंतर्क्रिया करता है।

इस तरह जनसंख्या भूगोल, मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव जनसंख्याओं के जनसांख्यिकी एवं गैर-जनसांख्यिकीय गुणों की स्थानीय विभिन्नताओं और किसी दी गई क्षेत्रीय इकाई में उपस्थित दशाओं के एक विशेष सेट से जुड़ी अंत:क्रियाओं से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का अध्ययन करती है।

1.2.2 विषयवस्तु, क्षेत्र एवं उद्देश्य

एडवर्ड ऐकरमैन दर्शाते हैं कि जनसंख्या भूगोल की समस्याओं का पहला समूह उन जातीय संबंधों की पहचान करता है जिनमें श्रेणीकरण, वर्गीकरण एवं विभेदीकरण की प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। जाँच के अगले चरण में जातीय संबंधों की स्थापना अथवा स्थानीय वितरण के वे गतिशील पहलू शामिल हैं, जिनमें से अस्थायी विभिन्नता का चर बेहद महत्वपूर्ण होता है। समस्याओं का अन्तिम चरण सह-चर संबंधों की स्थापना से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यह उस स्थानीय प्रक्रिया के संबंधों की खोज है जो विभिन्न तथ्यों के परस्पर क्षेत्रीय संबंधों को दर्शाते हैं।

क्षेत्रीय विभेदीकरण जनसंख्या भूगोल का वह मुख्य क्षेत्र है जो चरों के बीच स्थैतिक संबंधों की समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। भूगोलवेत्ताओं द्वारा जनसंख्या अध्ययन, इसमें अंतर्निहित अवधारणाओं के अनुसार और स्थानिक अंत:क्रियाओं के अध्ययन द्वारा, क्षेत्रीय वितरण सृजित करने वाले प्रक्रमों की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए किया जाता है।

टिप्पणी

जनसंख्या के अध्ययन में स्थानीय प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए, जो जनसंख्या के भौगोलिक स्वरूप (विशेषताओं) से उत्पन्न होती है या इन्हें उत्पन्न करती है। इस तरह, भूगोल की विषयवस्तु जनसंख्या का स्थानिक वितरण एवं स्थानिक अंत:क्रिया है। यह केवल तभी सार्थक होगा यदि एक कदम आगे बढ़कर उन प्रक्रियाओं (प्रक्रमों) की खोज को इसमें शामिल किया जाए जो विशिष्ट स्थानिक वितरणों और अंत:क्रियाओं को प्रभावित और सृजित करती हैं।

जनसंख्या भूगोल, भूगोल के विषयगत अनुभागों की एक औपचारिक और व्यवस्थित उप-शाखा (विषयक्षेत्र) के रूप में मनुष्य पर महत्त्वपूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित करता हैं। मनुष्य ही जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का मुख्य केन्द्र है। मनुष्य की संस्कृति के समावेश के अतिरिक्त, उसके आर्थिक और पृथ्वी से उसके पारस्परिक संबंधों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।

जनसंख्या भूगोल की विषयवस्तु को संक्षेप में निम्नानुसार उल्लेखित किया जा सकता है:

(i) जनसंख्या वितरण का इसके सभी आयामों में अध्ययन, अर्थात इकाइयों के आवासन का आकार और अंतराल, महाद्वीपीय एवं उप-महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण प्रतिमान, वितरण के सार्वभौम और गैर-सार्वभौम आयामों के सकल प्रतिमान, अंतर्स्थायी और अंतर्क्षेत्रीय वितरण।

(ii) जनसंख्या का घनत्व, इसके विभिन्न प्रकार, निर्धारक और क्षेत्रों में घनत्व तथा विश्व प्रतिमान

(iii) जनसंख्या का स्थानिक आवागमन (प्रवासन), आंतरिक प्रवासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, प्रवासन के निर्धारक, प्रकार, कारक, परिणाम एवं कानून एवं एलडीसी (अल्प विकसित देशों) से डीसी (विकसित देशों) की ओर उच्च गुणवत्ता वाली मानवशक्ति का प्रवासन

(iv) जनसंख्या की संवृद्धि- जनसंख्या वृद्धि का मापन, जन्म एवं मृत्यु दरें, जनसंख्या वृद्धि के घटक, निर्धारक, रूझान, कारक, सिद्धान्त एवं जनसंख्या प्रक्षेपण

(v) जनसंख्या संघटन- प्रजातीय संघटन, धार्मिक संघटन, भाषाई संघटन, आयु और लिंग संघटन, व्यवसाय संरचना, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक संघटन, आर्थिक संघटन, निर्भरता अनुपात, कार्मिकशक्ति, नियोजन (रोजगार) स्थिति, औद्योगिक वर्गीकरण, आय एवं व्यय, आय वितरण एवं निर्धनता।

(vi) साक्षरता एवं जनसंख्या की गुणवत्ता- साक्षरता विभेदक, निर्धारक, विश्व प्रतिमान, जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार हेतु सार्वभौम कार्यक्रम एवं प्रविधियां व पद्धतियां।

(vii) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या- ग्रामीण-नगरीय विभेदक, नगरीकरण प्रक्रियाएं, अंश निर्धारक, नगरीकरण के वैश्विक रूझान

(viii) जनसंख्या-संसाधन अनुपात, जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधन विकास, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या के संसाधन आधारित सिद्धान्त, आदर्श जनसंख्या, न्यून जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या, विश्व संसाधन-जनसांख्यिक आयाम, संसाधन-जनसांख्यिकी अनुपात, जनसंख्या नीति।

टिप्पणी

(ix) विश्व जनसंख्या का भौगोलिक सिंहावलोकन- विश्व जनसंख्या वृद्धि (प्रवृत्ति), जनसंख्या रुझान, विश्व प्रवास, विश्व जनसंख्या का वितरण, आयु एवं लिंग अनुपात, जनसंख्या की औसत आयु, आयु-संभाव्यता, तथा विश्व जनसंख्या के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं जलवायु विषयक तथा राजनीतिक सूचक।

जनसंख्या भूगोल में आपको न केवल एक समय पर, बल्कि एक समयावधि के दौरान भी बहुत से जनसांख्यिकी भावों का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार अंतर्कालिक एवं अंतर्क्षेत्रीय विश्लेषण, जनसंख्या भूगोल के ही अंग हैं। जनसंख्या भूगोल के विषय में आपको आबादी के विभिन्न भावों को अलग-अलग नहीं बल्कि, एक साथ स्थानीय तौर पर घटित हो रहे विभिन्न परिघटनाओं की प्रक्रियाओं का रीतिबद्ध अध्ययन करना होगा।

क्लार्क ने मुख्य रूप से जनसंख्या के तीन आयामों पर ध्यान केन्द्रित किया है:

- भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएं
- परम (अनन्य) आँकड़े, तथा
- जनसंख्या गतिकी

जेलिस्की, उन जनसंख्या विशेषताओं के अध्ययन का समर्थन करते हैं जिनका अध्ययन जनगणना में किया जाता है। ट्रैवार्था का सुझाव जनसंख्या के भूतपूर्व रूझानों के अध्ययन और जनसंख्या की वर्तमान जैवशास्त्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं के अध्ययन का है। उन्होंने जनसंख्या भूगोल में अध्ययन किए जाने के लिए विशेषताओं की एक सुविस्तृत (परिपूर्ण) सूची का भी सुझाव दिया है।

जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र को सरल रूप में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- जनसंख्या की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं। इन विशेषताओं में साक्षरता, प्रवासन, प्रजातीय संघटन, जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति व अन्य सम्मिलित हैं।

  आर्थिक विशेषताएं, जैसे कि श्रमशक्ति, व्यवसाय, आय, आय वितरण, जीवनस्तर, निर्धनता, श्रम आधिक्य, नियोजन स्थिति, श्रम अवशोषण, श्रम उपयोग, कार्यकुशलता व अन्य, तथा जनसंख्या के जैवशास्त्रीय अभिलक्षण, जैसे कि प्रजननक्षमता, मृत्यता, आयु, लिंग, प्रजाति, परम आंकड़े व इसी प्रकार के अन्य।

- जनसंख्या परिघटनाओं का स्थानिक एवं पर्यावर्णीय दृष्टिकोण। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की प्रणालियाँ पिछले तीन दशकों में मानव भूगोल को प्रभावित करने वाले अवधारणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों के प्रवाह की प्रतिक्रिया में पर्याप्त तौर पर परिवर्तित हुई हैं। जनसंख्या भूगोलवेत्ता, स्वयं को पद्धतिशास्त्रीय रूपांतरणों में अग्रणी वाहकों के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं तथापि यथार्थवाद, व्यवहारिकतावाद और संरचनावाद पर आधारित नए दृष्टिकोणों और पद्धतियों का उनके द्वारा अंगीकरण त्वरित और पर्याप्त रहा है।

  आधुनिक जनसंख्या भूगोल में रूपांतरण की अनेक धाराओं को चुनिंदा बदलती प्रक्रियाओं और उद्देश्यों, दूसरे शब्दों में बदलते माध्यमों एवं परिणामों के संदर्भ द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है।

टिप्पणी

- जनसंख्या भूगोल में भौगोलिक सूचना प्रणालियों (जीआईएस) का उद्‌भव, एक सबसे सामर्थ्यकारी विकास रहा है। जनसांख्यिकीय खोज के समस्त क्षेत्रों में आंकड़ों की सीमा, गुणवत्ता और अभिगम्यता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, समकालीन ब्रिटेन में जनसंख्या की विस्तृत स्थानीय संरचना का अध्ययन, मानव भूगोल में विशालतम बहु-विचर स्थानिक श्रृंखलाओं को शामिल करते हुए, छोटे क्षेत्रों की जनगणनाओं (पल्ली/पैरिश, वार्ड, गणना जनपदों, ग्रिड वर्गों और पोस्टकोड) से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के परिपूर्ण मानक सेटों द्वारा, अत्यन्त संवर्धित हुआ है। अन्य स्थानिक संदर्भित आंकड़ों की फाइलों (आवास, नियोजन, विद्युत पंजीयन, स्वास्थ्य इत्यादि) के संग्रहण के साथ, उपयोक्ताओं की क्षेत्रीय विशिष्टताओं द्वारा इन आंकड़ों के नियमित कम्प्यूटरीकृत मिलान में सक्षम बनाने के लिए जीआईएस एक शुरूआत है ताकि महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकी संबंधों को प्रथमतया विश्लेषण के पारिस्थितिकीय या विविध अनुभागीय (वर्गों) स्तरों पर स्पष्ट किया जा सके।
- छोटे क्षेत्रों के जनसांख्यिकी आंकड़ों की समानान्तर व्यापक उपलब्धता, वृहत्तर विश्लेषणात्मक सुदृढ़ता के रूप में अब जनसंख्या भूगोल में अंगीकृत की जा रही है। पहले, मानव भूगोल के प्रमुखतया 1960 के दशक के सकारात्मकतावादी प्रतिमानों से उत्पन्न विशेषज्ञता ने स्थानिक विज्ञान के रूप में जनसंख्या विश्लेषण के एक क्षेत्र से निर्मित अनुप्रस्थवर्गीय बहुचर अध्ययनों को सुनिश्चित किया जिसके लिए आधुनिक भूगोलवेत्ता विशेषरूप से भली-भांति तैयार थे। यह अनिवार्य था क्योंकि स्थानिक श्रृंखला के प्रचलित बहुचर विश्लेषणों की जटिल खामियां अब भूगोल के प्रत्यक्षवादी दौर में अपने प्रायः आलोचनारहित और कई बार अनुपयुक्त अंगीकरण के पश्चात व्यापक रूप से समझी जा रही थीं।

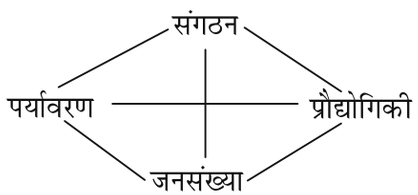

- जनसंख्या भूगोल में आलोचनात्मक पद्धतियों और औपचारिक जनसांख्यिकी के सिद्धान्तों की व्यापक श्रृंखलाओं का समावेशन करने के लिए वुड्स (1979, 1982) द्वारा दृढ़ प्रयास किए गए। इसके सम्बद्ध रूप में मर्त्यता, प्रजननक्षमता और आप्रवासन के क्षेत्र तथा आयु और लिंग के अनुसार विशिष्ट अनुमानों के आधार पर भावी क्षेत्रीय जनसंख्या संरचनाओं का आकलन करने के लिए स्थानिक जनसांख्यिकी लेखापरीक्षणों में विकास होते रहे। इस तरह जनसंख्या प्रक्षेपण एक सुस्पष्ट स्थानिक तरीके से अनुप्रयुक्त किए गए (रीस तथा विल्सन, 1977, वुड्स तथा रीस, 1986, कांग्डन तथा बैटे, 1989)।

  इसी प्रकार, आदर्शीकरण या 'सर्वश्रेष्ठ अवस्थिति' के लिए भूगोलवेत्ताओं की अभिरूचि के जनसंख्या क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग हुए। रॉबर्टसन द्वारा किया गया कार्य (1972, 1974), इकाइयों के लिए जनसंख्या की अधिकतम अभिगम्यता अपेक्षित होने पर इकाई अवस्थितियों की समस्याओं के सटीक लेकिन लचीले

उत्तर पाने के लिए एक नियमित ग्रिड पर जनसंख्या आंकड़ों की सारिणी पर सांख्यिकीय और कार्टोग्रॉफिक पद्धतियों के अनुप्रयोग का एक उदाहरण है।

उद्देश्य

टिप्पणी

जनसंख्या भूगोल का उद्देश्य, पृथ्वी को आच्छादित करने वाले लोगों में क्षेत्रगत विभिन्नताओं (विभेदों) को समझना है। किसी क्षेत्र के समग्र भौगोलिक विश्लेषण में जनसंख्या की विभेदीकृत संवृद्धि को ध्यान में रखना आवश्यक है। ट्रेवार्था के अनुसार, जनसंख्या के आँकड़े, घनत्व, वितरण और गुणवत्ताएं (विशेषताएं), सभी भूगोल के लिए अनिवार्य पृष्ठभूमि उपलब्ध कराते हैं। एकरमैन इंगित करते हैं कि भूगोल, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन करता है और सभी प्रमुख क्षेत्रीय विभिन्नताओं में समय का आयाम जुड़ा होता है। जनसांख्यिकी गतिविधियां (आवागमन) उन बलों में से प्रमुख हैं जो समय एवं अंतराल घटकों में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।

जनसंख्या भूगोल में आलोचनात्मक कार्य, विशिष्ट जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अस्थायी आनुभविक पड़ताल से दूर होकर ऐसे कार्य के रूप में परिवर्तित हुआ जिसका केन्द्रीयकरण दो मुख्य लक्ष्यों को प्रवर्तित करने पर होता गया। इस प्रकार इसके उद्देश्य में शामिल हुआ- जनसांख्यिकीय प्रतिमानों, नियमितताओं और क्रम की खोज, और अंतराल में भिन्न प्रकार से कार्य करने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से इन प्रतिमानों की व्याख्या करना, जो ऐसे प्रतिमानों को सृजित, संशोधित, विनष्ट और प्रतिस्थापित करती हों। यहां विशेष रूप से स्थानिक प्रक्रियाओं के कारगर होने का निहितार्थ नहीं है, यह तर्क दिया जा सकता है कि 'विशुद्ध स्थानिक प्रक्रियाओं जैसी कोई चीज नहीं है, केवल विशेष सामाजिक प्रक्रियाएं विभिन्न अंतरालों में परिचालित होती हैं।'

व्याख्यात्मक प्रक्रियाओं की ओर आते हुए, मानव भूगोल में एक संचेतना विकसित होती गई है जो कि स्थानिक प्रक्रियाओं के अवलोकनों और पहचान (चिन्हीकरण) के शिक्षण और अनुसंधान पर अत्यधिक केन्द्रित है। उन प्रक्रियाओं के लिए यह बेहद कम सरोकार रखती है जो ऐसे प्रतिमानों को सृजित और बाद में संशोधित करती हैं। यह अधिकाधिक स्वीकार्य होता गया है कि गठन और संरचना - स्थैतिकी - प्रक्रियाओं और स्थानिक अंतर्क्रिया-गतिकी पर निर्भर हैं।

समुचित दृष्टिकोण से, हमारे द्वारा स्थानिक प्रक्रियाओं और स्थानिक संरचना के मध्य किए गए विभेद अस्पष्ट हैं क्योंकि वे एक सीमित समय परिप्रेक्ष्य पर आधरित हैं। प्रक्रिया और संरचना, सार रूप में एक ही चीज हैं। जब हम स्थानिक प्रक्रिया को स्थानिक संरचना से अलग करते हैं तो हम मात्र परिवर्तन की आपेक्षिक तीव्रता में एक अंतर की पहचान करते हैं। समुचित रूप में विचार किए जाने पर, उद्देश्यपरकता के तहत एक वितरण की स्थानिक संरचना को एक जारी प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति की निर्देशिका के रूप में देखा जाता है।

(एब्लर, एडम्स तथा गाउल्ड, 1971)

अभिनव प्रक्रियाएं: भूगोलवेत्ता, संरचना से प्रक्रियाओं के परिणाम निकालने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं, लेकिन गठन करने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति के अनुसंधान को लेकर सर्वाधिक चिंतित रहे हैं, न केवल पूर्व और वर्तमान के प्रतिमानों की सहज व्याख्या के

टिप्पणी

लिए, बल्कि सुदृढ़ पूर्वानुमान हेतु आधार निर्मित करने के लिए भी। इससे भी अधिक, बदलाव (स्थानान्तरण) का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि विभेदीकरण के अध्ययन से, हमारा मूलभूत स्थानान्तरण ऐसी प्रक्रियाओं की ओर हो गया है जो किसी भौगोलिक समस्या को स्पष्ट करने में पैमाने के सिलवटनुमा संकुचन से मुक्त हैं। विनिश्चय का समुचित स्तर वह हो गया है जिस पर संबंधित प्रक्रियाएं सर्वश्रेष्ठ ढंग से समझी और विश्लेषित की जाएं।

(ब्रुकफील्ड 1973)

हीनैन (1967) का तर्क है कि 'यहां से जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं में अपनी अभिरुचियों को, अपरिपक्व परिवर्तन वाली गतिशील प्रक्रियाओं के अध्ययन की वरीयता में, अत्यन्त प्रबल रूप से परिवर्तन के अंतिम उत्पादों (निष्कर्षों) या संकलन पर केन्द्रित करने की प्रवृत्ति रही है। उस आरंभिक बोधात्मक दृष्टिकोण के समर्थन में, इस पुस्तक की संरचना को गतिशील घटकों-प्रजननक्षमता, मर्त्यता एवं प्रवासन-और इन्हें प्रवृत्त करने वाली प्रक्रियाओं के समकालीन जनसंख्या भूगोल में प्रमुख व्याख्यात्मक महत्त्व को मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किया गया है - यह जनसंख्या आँकड़ों, वितरण और संघटन में परिवर्तन उत्पन्न करने वाली उनकी स्थानिक एवं अस्थायी अंतर्क्रिया है। अंतर्क्रिया सर्वथा महत्त्वपूर्ण है, और किसी भी गतिशील घटक और उनकी संलग्न प्रक्रियाओं का प्रभावशाली अध्ययन पृथक रूप से नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए विचार करें कि किस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में अकालपीड़ित घने बसे आयरलैंड से अधिक उत्प्रवासन (युवा पुरूष वयस्कों के संदर्भ में चयनात्मक) ने आयरलैंड में आयु, लिंग और वैवाहिक संरचना में परिवर्तनों को प्रेरित किया, जिसके कारण जन्म, मृत्यु और विवाह दरों के स्तरों पर और व्यापक रूप में सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं पर प्रभाव देखने को मिला।

यह प्रक्रिया अध्ययन की प्रेरणा रही है जिसने विचारों, व्यवहार एवं प्रौद्योगिकी के स्थानिक प्रसार पर सैद्धान्तिक, मॉडल आधारित और प्रतिरूपण-उन्मुक्त कार्य को प्रेरित किया है जो अन्य विज्ञानों से व्युत्पन्न सिद्धान्तों के विपरीत तर्कपूर्ण ढंग से भूगोल में अत्यन्त कम संख्या में विकसित सार्थक स्वदेशी सिद्धान्तों में से एक रही है। विसरण अध्ययन के प्रकार, जिनकी अगुवाई हेगरस्ट्रैंड (1967) ने की, का स्पष्ट संबंध अनेक प्रमुख जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं की समझ से है। यह संभव है, उदाहरण के लिए, विचार करने के लिए, यद्यपि अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के लिए नहीं, कि प्रजनन क्षमता और मर्त्यता में कमी के स्थानिक प्रतिमान, गर्भनिरोधकों के ज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी जैसे नवोत्पादों के स्थानीय प्रसार को, स्थानिक और नगरीय अनुक्रमानुसार अनंतरता द्वारा नियंत्रित महानगरीय नवोन्मेष केन्द्रों से विसरण के साथ प्रतिबिम्बित करते हैं।

भविष्य का रास्ता

जनसंख्या के भूगोल या किसी भी चीज के भूगोल जैसी कोई चीज नहीं है, जब तक कि सरल स्थानिक वितरण से भूगोल की एक अत्यधिक प्रतिबंधित और बौद्धिक रूप से असंतोषजनक समकक्षता में विश्वास करने वाले लोग न हों। तद्नुसार, जनसंख्या भूगोल उसी दशा में सम्पूर्ण सैद्धान्तिक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है। यदि प्रतिमानों के वर्णन

टिप्पणी

और हस्तक्षेपी व्याख्याकरण के इसके पारंपरिक अमहत्त्वाकांक्षी सरोकारों को छोड़ दिया जाए और असंदिग्ध रूप से ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं का समावेशन किया जाए जो उन जनसांख्यिकीय समस्याओं के प्रति ताजगीपूर्ण अंतर्दृष्टि का योगदान कर सकें, जिनका अध्ययन अनेक अन्य विषयों जैसे कि जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास और समाजशास्त्र में किया जाता है। जैसा कि वुड्स (1982 बी) का तर्क है, कि जनसंख्या भूगोल का प्रमुख उद्देश्य 'व्यापक क्षेत्र के लिए स्थानिक दृष्टिकोण प्रदान करना है जिसका एक भाग, जनसंख्या अध्ययन के नाम से है।'

1.2.3 अन्य विषयों से संबंध

जनसंख्या भूगोल, भूगोल के उन परिधीय (सीमाओं के) क्षेत्रों से संबंधित है जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी से लगते हैं। जहां जनसांख्यिकी, आंकड़ों पर केन्द्रित है और सांख्यिकीय पद्धतियों पर अत्यधिक निर्भर है, वहीं जनसंख्या भूगोल, किसी क्षेत्र के आंकड़ों से संबंधित और मापन (मानचित्रीकरण) पर निर्भर है। क्लार्क इंगित करते हैं कि जनसंख्या भूगोल को जनसंख्या में क्षेत्रीय विचलनों (विभिन्नताओं) और भौतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिघटनाओं से उनके संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण और राजनीतिक इकाइयों के लिए जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं, जनसांख्यिकी के क्षेत्र से संबंधित हैं।

जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के स्थानिक विश्लेषण से संबंधित है। यह जनसंख्या के आर्थिक अभिलक्षणों को भी समाविष्ट करता है जैसे आमदनी, व्यय, व्यवसाय, आय वितरण, निर्धनता व अन्य। अर्थशास्त्र का विज्ञान मूलभूत रूप से आवंटन एवं मूल्यांकन समस्याओं से संबंधित है। यह विरल संसाधनों को सक्षम (स्पर्धी) सिरों में आवंटित करता है। यह जनसंख्या के घटकों के आर्थिक व्यवहार का भी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विषयवस्तु, मनुष्यों के धनार्जन और धनव्यय करने संबंधी क्रियाकलाप हैं। जनसंख्या भूगोल का मुख्य रूप से मनुष्य पर केन्द्रीयकरण पृथ्वी तल पर एक महत्त्वपूर्ण तत्व के रूप में उपस्थित है। इस तरह, अर्थशास्त्र एवं जनसंख्या भूगोल दोनों ही परस्पर संबंधित हैं और इनमें विश्लेषण के अनेक उभयनिष्ठ क्षेत्र हैं। कदाचित यही वह कारण है कि जिस वजह से सोवियत संघ में जनसंख्या भूगोल को आर्थिक भूगोल का एक भाग माना जाता है। वास्तव में, जनसंख्या भूगोल को जनसंख्या से संबंधित आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र से पृथक नहीं किया जा सकता।

जनसंख्या भूगोल, समाजशास्त्र से भी घनिष्ठ रूप में संबंधित है। यह जनसंख्या के सामाजिक अभिलक्षणों, जैसे कि विवाह, धर्म, जाति, साक्षरता, परिवार, प्रजातीयता, परिवार प्रणाली व अन्य का अध्ययन करता है। इस तरह, ज्ञान की ये दो शाखाएं एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकतीं। इनमें स्पष्ट रूप से अनेक उभयनिष्ठ अंतर्क्रियाएं हैं जो पूर्व में पूर्णरूपेण नहीं थीं। हार्टशोर्न ने अपनी पुस्तक 'दि नेचर ऑफ ज्योग्रॉफी' में जनसंख्या भूगोल के लिए व्यवस्थित विषयशाखा के रूप में संदर्भ नहीं दिया है। इस खण्ड की निर्देशिका में, यह इंगित किया गया है कि जनसंख्या का विषय, पाठ्य में तीन बार संदर्भित है, लेकिन संदर्भ संयोगवश हैं। डिकिंसन और होवार्थ ने अपनी पुस्तक 'दि मेकिंग ऑफ ज्योग्रॉफी में क्षेत्र में जनसंख्या का उल्लेख किए बिना मानव भूगोल के

टिप्पणी

उद्‌भव पर चर्चा की है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक भूगोल का विश्लेषण किया है किन्तु इसमें जनसंख्या अनुपस्थित है। उनके द्वारा प्रस्तुत निर्देशिका में 'जनसंख्या' शब्द सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार, वूल्डरिज और ईस्ट द्वारा लिखित पुस्तक 'दि स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्रॉफी' में भूगोल के संदर्भ में जनसंख्या के विश्लेषण को नकार दिया गया है। यह दर्शाता है कि पूर्व में जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के तत्व के महत्त्व को समुचित मान्यता नहीं दी जा सकी। हेटनर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए जनसंख्या को एक प्रमुख तत्व के रूप में इंगित नहीं किया, हालांकि उन्होंने कई अन्य संबंधित आयामों को मान्यता दी। हेटनर ने जनसंख्या भूगोल को एक महत्त्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में कार्य किया है क्योंकि, जैसा कि उनका कथन है, कि अन्य सभी भौगोलिक तत्वों पर जनसंख्या का महान प्रभाव पड़ता है। लेकिन, यद्यपि हेटनर ने विशिष्ट रूप से जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र को मान्यता प्रदान की है, उन्होंने इसकी विषयसामग्री या पद्धति को विश्लेषित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोष में सम्मिलित मानव भूगोल पर अपने लेख में कैमिल वेलक्स ने जनसंख्या का उल्लेख नहीं किया है। सॉउर के विश्लेषण में, जनसंख्या भूगोल के किसी विशेष क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार, मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल विषय पर अपने लेख में बारोज ने जनसंख्या का कोई संदर्भ नहीं दिया है।

यद्यपि ब्रुहेन्स ने जनसंख्या के भौगोलिक महत्त्व को स्वीकारा है, उन्होंने आवासन एवं बसावट के आकृतिविज्ञान के माध्यम से परोक्ष रूप से इसका अध्ययन प्रस्तावित किया है और परिणामस्वरूप जनसंख्या भूगोल में कम योगदान किया है। हेटनर ने जनसंख्या भूगोल के बारे में कुछ प्रखर टिप्पणियां की हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त रूप में से परिष्कृत नहीं किया है। हेसिंजर ने जनसंख्या भूगोल को विषय की विशिष्ट शाखा के रूप में हेटनर की तरह मान्यता नहीं दी। हेसिंजर द्वारा मनुष्य का विश्लेषण निराशाजनक रूप से मानवशास्त्रीय है। हटिंगटन और शॉ ने अपनी पुस्तक 'प्रिसिंपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्रॉफी' में जनसंख्या का कोई सीधा संदर्भ नहीं दिया है।

जनसंख्या के संबंध में कुछ मात्रा में चर्चा फ्रांस के पियरे जार्ज द्वारा की गई। लेकिन, समग्र रूप में, वर्तमान शताब्दी के पचास के दशक तक जनसंख्या भूगोल एक महत्त्वहीन विषय बना रहा। प्रश्न यह है कि यदि जनसंख्या भूगोल इतना महत्त्वपूर्ण विषय था तो इसे इस तरह उपेक्षित क्यों किया गया? जनसंख्या भूगोल को उपेक्षित किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं:

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व, जनसंख्या के बारे में विश्वसनीय और पर्याप्त आँकड़े विश्लेषण के लिए उपलब्ध नहीं थे। अनेक देशों ने जनगणना कार्यक्रम शुरू नहीं किए थे। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बाहर केवल कुछ ही देशों ने जनसंख्या से संबंधित कुछ अभिलेख रखे थे।

भूगोल के प्रचलित अध्ययन में, पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर अत्यधिक जोर था। हालांकि पृथ्वी, मानवों द्वारा आवासित है, लेकिन उन्हें उपेक्षित किया गया। इस प्रकार, पूर्व में भूगोल का अध्ययन डेनमार्क के राजकुमार के बिना 'हेमलेट' के मंचन सा रह गया था।

टिप्पणी

अतीत में, क्षेत्रीय भूगोल पर अत्यधिक जोर था। इसे भूगोल की धुरी माना जाता था। भूगोल की उपेक्षा, खोज के अनेक क्षेत्रों से स्पष्ट थी। उदाहरण के लिए, अमेरिकन ज्योग्रॉफर्स के प्रकाशन के एक सर्वेक्षण में जनसंख्या पर 1925 से एक चौथाई सदी की अवधि तक केवल 45 शीर्षक ही प्रकाशित हुए। विभिन्न प्रकाशनों में जनसंख्या भूगोल संबंधी योगदानों की संख्या नगण्य रही। अनेक लेखों में, जनसंख्या भूगोल को सहायक स्थिति दी गई और इसे आवासन भूगोल की एक शाखा बना दिया गया। अमेरिकन ज्योग्रॉफर्स के समर्पित क्षेत्रेय अध्ययनों में जनसंख्या के तत्व को आमतौर से नगण्य स्थान दिया गया। दूसरे, डॉक्टोरल शोध निबंधों के रूप में जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में बहुत कम कार्य किया गया। जून 1946 तक अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पूर्ण किए गए कुल 343 डॉक्टोरल शोध निबंधों में से जनसंख्या पर केवल 11 (तीन प्रतिशत से कुछ अधिक) शीर्षक थे।

तीसरे, अनेक अमेरिकी संस्थानों के अध्ययन पाठ्यक्रमों में जनसंख्या भूगोल को शामिल नहीं किया गया। अमेरिका में 20 से अधिक विशालतम या सबसे विशिष्ट विभागों में कार्यक्रमों की सूची से पता चलता है कि किसी एक भी विभाग में जनसंख्या पर विशिष्ट रूप से केन्द्रित पाठ्यक्रम नहीं था। इस सबसे ट्रैवार्था ने निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या भूगोल को अतीत में व्यवस्थित रूप से उपेक्षित किया जाता रहा। पूर्व शती के पचासवें दशक तक, भूगोल को भूदृश्यों के अध्ययन के रूप में समझा जाता था।

1953 में पहली बार, विसकौंसिन विश्वविद्यालय के जी.टी. ट्रैवार्था ने अमेरिकन ज्योग्रॉफर्स की एसोसिएशन के समक्ष अपने अध्यक्षीय संबोधन में जनसंख्या भूगोल को व्यवस्थित भूगोल की एक उपशाखा के रूप में उल्लेखित किया। स्नातक स्तर पर जनसंख्या भूगोल के एक सम्पूर्ण स्वतंत्र पाठ्यक्रम को संयोजित एवं प्रस्तुत करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालयों ने इसका अनुसरण किया। आज, अनेक देशों में जनसंख्या भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जनसंख्या भूगोल के महत्त्व को लेकर प्रमुख विषय विशेषज्ञों (पेशेवरों) की जागरूकता अब काफी बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या भूगोल को विशेष रूप से, और भूगोल को सामान्य रूप से, अब सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जनसंख्या भूगोल ने अपने मार्ग के अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नवाचक बाधाओं को पार कर लिया है और इसके विषयाभ्यासियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ, जनसंख्या के स्थानीय आयामों और इसके अभिलक्षणों को बेहतर समझने की दिशा में प्रगतिपथ पर हैं। हालांकि जनसंख्या भूगोल, भूगोल की आपेक्षिक रूप से नवीन और व्यापक रूप से अल्पविकसित शाखा है, जिसकी सीमाएं बलपूर्वक निर्धारित नहीं की जा सकतीं। इस विकसित होती विषय शाखा की अध्ययन पद्धतियों और विषयसामग्री में सुधार के लिए प्रयास अभी जारी हैं। यह माना गया है कि जनसंख्या भूगोल को एक व्यवस्थित विशेषज्ञता के रूप में विकसित किया जा सकता है। विषयवस्तु को ट्रैवार्था द्वारा रेखांकित किया गया, और हमें जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र और विषयवस्तु पूर्व में उपलब्ध हो चुके हैं।

1950 के दशक के दौरान जनसंख्या भूगोल के अध्ययन की विधि में एक प्रमुख विकास हुआ। इससे क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बेहतर तरीके से समझना संभव हुआ। ट्रैवार्था

ने दावा किया है कि एक सामयिक विधि, स्थलों और लोगों को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि को पश्चिमी भूगोलवेत्ताओं का भी समर्थन मिला और इसके परिणामस्वरूप इस व्यवस्थित विधि का अनुसरण करते हुए अनेक अध्ययन किए गए।

टिप्पणी

व्यावहारिक विधि कहलाने वाली दूसरी विधि अब प्रचलन में है, इसका अधिकांश देशों में जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में अनुसरण किया गया। इस विधि में, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मानवों के व्यवहार को मान्यता और महत्त्व प्रदान किया गया। इस प्रकार की विधि का अनुसरण प्रवासन, प्रजनन क्षमता नियंत्रण आदि के विश्लेषण में किया गया। इस विधि के कारण भौगोलिक अध्ययन एवं अनुसंधान में अनेक तकनीकों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ तकनीकें ये हैं: खेल सैद्धान्तिक विधि, प्रतिरूपण विधि, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के नमूने (प्रतिमान) व अन्य। हाल ही में, जनसंख्या गतिकी के विश्लेषण में एक मात्रात्मक विधि की शुरूआत की गई है। हालांकि अंतराल संबंधी प्रभावों को वर्णित करने में परिमापन को एक प्रमुख समस्या माना गया है। अवलोकनात्मक तकनीकों को परिमापन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए और अधिक विकसित करना होगा। प्रमुख प्रक्रियाओं के सह-विभेद का अध्ययन अब निकट है।

भौगोलिक अध्ययन इन अनुमानों (मान्यताओं) की दिशा में कि अंतराल संबंधों की समझ के लिए सांस्कृतिक, भौतिक और जैवशास्त्रीय जगत, प्रयासरत हैं। हालांकि विसमूहीकृत अनुसंधान, बलपूर्वक परिमापन, जनसंख्या भूगोल की भावी रूपरेखा निर्धारित करने में सर्वाधिक प्रभावशाली होंगे।

जनसंख्या भूगोलवेत्ता, बहु-चर संबंधों के मामलों में एक व्यवस्थित विधि का सहारा भी ले रहे हैं। इस विधि में प्रमुख रूप से प्रणाली की संरचना एवं प्रकार्यात्मकता को समझने पर केन्द्रीयकरण किया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। व्यवस्थित विधि में, भूगोलवेत्ता, अभिलक्षणों और संबंधित संलग्न मानदण्डों को चिन्हित करता है। तब, संरचना स्पष्ट कर लिए जाने के बाद, संरचनात्मक संबंधों को कुछ समीकरणों के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। इस मामले में प्रणाली का विश्लेषण करना और पूर्वानुमान व्यक्त करना आसान हो जाता है। प्रणाली को अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों रूपों में समझना भी आवश्यक है ताकि सैद्धान्तिक सूत्र प्रतिपादन संभव हो सके। किसी परिघटना का अध्ययन करने के लिए यह एक यांत्रिक अभ्यास है।

जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करने के लिए संरचना विधि और व्यवहारिक विधि में परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि संपूरक हैं। पारंपरिक व्यवस्थित विधि, जनसंख्या के स्थानिक प्रतिमानों को समझने में सहायक हो सकती है। जबकि व्यावहारिक विधि में व्यवस्थिति विधि स्थानीय प्रतिमानों में संलग्न अर्थो की व्याख्या के नए तरीके प्रस्तुत करती है। जनसंख्या भूगोल में अब विश्लेषण की सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, और चरित्र में यह अनिवार्य रूप से अधिक परिमाणात्मक हो गया है। जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं द्वारा यदि जनसंख्या भूगोल के विश्लेषण के लिए एक विशेष परिमाणात्मक पद्धति क्रमिक रूप से विकसित की जा सके तो यह जनसंख्या अनुसंधान एवं अध्ययन में अत्यधिक सहायक होगा। ऐसी परिमाणात्मक तकनीक को जियोग्रामैट्रिक्स का नाम दिया जा सकता है और यह उसी प्रकार कार्य कर सकती है जैसे आर्थिक विश्लेषण में इकोनोमैट्रिक्स, और मनोविश्लेषण में साइकोमेट्रिक्स कार्य करती है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. जनसंख्या भूगोल किसकी शाखा है?
   (क) भारत का भूगोल (ख) विश्व का भूगोल
   (ग) मानव भूगोल (घ) भूगोल
2. क्लार्क ने जनसंख्या के किन आयामों पर ध्यान केन्द्रित किया?
   (क) भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक वैशिष्ट्य
   (ख) परम आंकड़े
   (ग) जनसंख्या गतिकी
   (घ) भौतिक–सामाजिक–आर्थिक विशेषताएं, परम आंकड़े एवं जनसंख्या गतिकी

1.3 विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास

जनसंख्या में समग्र वृद्धि और परिवर्तन, जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली दो शताब्दियों में विश्व की जनसंख्या, नाटकीय रूप से बढ़ी है। इस समग्र विषय के अध्ययन के लिए, जनसंख्या वृद्धि को प्राकृतिक बढ़ोतरी के रूप में देखा जाता है। इसमें किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दरों का अध्ययन किया जाता है। जन्म दर, जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या होती है। मृत्यु दर, प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या होती है।

जनसंख्या की ऐतिहासिक-प्राकृतिक बढ़ोतरी दर लगभग शून्य के आसपास रही, जिसका अर्थ यह था कि मोटे तौर पर जन्म लेने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या के समान थी। हालांकि वर्तमान समय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवनशैली के उच्च मानकों के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो जाने से समग्र मृत्यु दर में कमी आई है। विकसित देशों में, जन्म दर गिरी है, लेकिन यह विकासशील देशों में अभी भी उच्च है। इसके परिणामस्वरूप, विश्व की जनसंख्या प्रमुख रूप से बढ़ती जा रही है।

प्राकृतिक बढ़ोतरी के अतिरिक्त, जनसंख्या परिवर्तन में किसी क्षेत्र के शुद्ध आप्रवास पर भी विचार किया जाता है। यह आप्रवासन और उत्प्रवासन के मध्य अंतर है। किसी क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर या जनसंख्या में परिवर्तन, प्राकृतिक बढ़ोतरी और शुद्ध प्रवासन का योग होता है।

विश्व वृद्धि दरों और जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक अनिवार्य घटक जनसांख्यिकीय पारगमन प्रतिमान है जो कि जनसंख्या भूगोल में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। यह मॉडल, किसी देश के चार चरणों में विकास के रूप में होने वाले जनसंख्या परिवर्तनों की विवेचना करता है। जन्म दरों और मृत्यु दरों दोनों का ही ऊँचा होना, प्रथम चरण है जिससे मामूली प्राकृतिक वृद्धि और अपेक्षाकृत छोटी जनसंख्या की स्थिति रहती है। जन्म दरों का ऊँचा और मृत्यु दरों का नीचा होना, दूसरा चरण है जिससे

जनसंख्या में उच्च वृद्धि होती है (यह वह स्थिति है जिसमें विकसित देशों की न्यूनतम संख्या शामिल है)। तीसरा चरण, घटती हुई जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर का है, जिसमें पुनः जनसंख्या वृद्धि मंद पड़ जाती है। अंतिम चौथा चरण जन्म और मृत्यु दरों के निम्न होने से संबंधित है जिसमें प्राकृतिक वृद्धि कम हो जाती है।

टिप्पणी

जनसंख्या निरूपण

पूरे विश्व में विभिन्न स्थलों पर लोगों की विशिष्ट संख्या का अध्ययन करने के अतिरिक्त, जनसंख्या भूगोल में विशिष्ट स्थलों की जनसंख्या का चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए जनसंख्या पिरामिडों का उपयोग किया जाता है। इसमें जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों के पुरूषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाया जाता है। विकासशील देशों में चौड़े आधार और संकरे शीर्ष वाले पिरामिड पाए जाते हैं, जो उच्च जन्म दरों और मृत्यु दरों को इंगित करते हैं।

आमतौर पर विकसित देशों में विभिन्न आयु समूहों में व्यक्तियों का समान वितरण पाया जाता है जो जनसंख्या की मंद वृद्धि को इंगित करता है। हालांकि कुछ में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है जब बच्चों की संख्या, वृद्धि वयस्कों की संख्या के समान या कुछ कम होती है। उदाहरण के लिए जापान का जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या की मंद वृद्धि को दर्शाता है।

तकनीकियां और आंकड़ों के स्रोत

जनसंख्या भूगोल, आंकड़ों से सर्वाधिक समृद्ध विषयक्षेत्रों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश देश, लगभग प्रत्येक दस वर्षों पर समग्र राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इनमें आवास, आर्थिक स्थिति, लिंग, आयु और शिक्षा आदि सूचनाएं निहित होती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, जनगणना प्रत्येक दस वर्ष पर की जाती है। इसे यहां संविधान द्वारा अनिवार्य बनाया गया है। इन आंकड़ों का रखरखाव संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

जनगणना आंकड़ों के अतिरिक्त, जनसंख्या आँकड़े विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, जैसे कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों के जरिए भी प्राप्त होते हैं। सरकारें, विश्वविद्यालय एवं निजी कंपनियां, जनसंख्या विशिष्टताओं एवं व्यवहार के बारे में आँकड़े एकत्र करने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण और अध्ययन आयोजित कराने की दिशा में कार्य करती हैं जो जनसंख्या भूगोल के विषयों से संबंधित हो सकते हैं।

भूगोल में मानव-तत्व

मानव भूगोल की शाखा, पर्यावरण पर मानवीय बोध, मानवीय क्रियाकलापों के निर्माणक और मानवों द्वारा पर्यावरण का प्रबंधन किए जाने का अध्ययन करती है। मानव प्रणालियां, भौतिक प्रणालियों द्वारा प्रभावित होती हैं। संसाधानों को किस प्रकार अनुमानित (आकलित) और उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन भी मानव भूगोल के रूप में किया जाता है।

मानव किस प्रकार भूगोल को अनुभव करते हैं, यह इतिहास, वर्तमान बोध (दृष्टिकोण) और भावी निर्णयों को प्रभावित करता है। मानव भूगोल, मानव की पर्यावरण पर अंतर्निर्भरता, और किस प्रकार पर्यावरण से अंतःक्रिया, बोध (दृष्टिकोण) एवं उपयोग, मानवीय प्रणालियों और उद्‌भव को प्रभावित करता है, इसका भी अध्ययन करता है।

टिप्पणी

मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल कुछ उपश्रेणियां एवं अंतर-विषयक अध्ययन निम्न हैं:

मानवशास्त्र

सांस्कृतिक भूगोल

मानचित्रकला

जनसांख्यिकी

राजनीतिक भूगोल

मानव भूगोल के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरणों में शहरी नियोजन, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, पर्यटन, विपणन, क्षेत्रीय नियोजन, अचल संपत्ति, राजनीति इत्यादि शामिल हैं।

मानव प्रणालियां

- पृथ्वी पर मानव जनसंख्या की विशेषताएं, वितरण और प्रवासन।
- पृथ्वी की सांस्कृतिक विशेषताएं, वितरण एवं जटिलताएं।
- पृथ्वी तल पर आर्थिक अन्योन्याश्रितता के प्रतिमान और संजाल (नेटवर्क)।
- मानव बसावट की प्रक्रियाएं, प्रतिमान और प्रकार्य।
- व्यक्तियों के बीच सहयोग एवं संघर्ष की शक्तियां और इनका पृथ्वी तल के विभाजन और नियंत्रण पर प्रभाव।

1.4 भूगोल और जनसांख्यिकी : आंकड़ों के स्रोत

जनसांख्यिकी मानव आबादी की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे कभी-कभी जनसंख्या अध्ययन भी कहा जाता है।

जनसांख्यिकी मानव आबादी का सांख्यिकीय अध्ययन है। जनसांख्यिकी एक सामान्य विज्ञान हो सकती है जो कि किसी भी प्रकार की गतिशील मानव आबादी अर्थात वह जो कि समय व स्थान के साथ परिवर्तित होती हो; पर लागू हो सकती है। इसमें इन आबादियों के आकार, संरचना, वितरण तथा जन्म, प्रवास, बढ़ती उम्र तथा मृत्यु के फलस्वरूप स्थान और/या समय में परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है।

जनसांख्यिकी विश्लेषण पूर्ण समाजों या शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म तथा जाति के आधार पर पारिभाषित समूहों पर लागू हो सकते है। संस्थागत रूप से, जनसांख्यिकी सामान्य रूप में समाजशास्त्र का क्षेत्र माना जाता है। यद्यपि यहाँ निम्नांकित जैसे कई स्वतंत्र जनसांख्यिकी विभाग हैं-

1. औपचारिक जनसांख्यिकी अपने अध्ययन को जनसंख्या प्रक्रिया के अध्ययन तक सीमित रखती है, जबकि सामाजिक जनसांख्यिकी जनसंख्या अध्ययन का व्यापक क्षेत्र एक आबादी को प्रभावित कर रहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जैविक प्रक्रियाओं के संबध का भी विश्लेषण करती है।

टिप्पणी

2. डेमोग्राफिक्स शब्द का उपयोग गलती से कई बार डेमोग्राफी के लिये किया जाता है, जबकि इसका अभिप्राय सरकार के उपयोग में लाए जा रहे चयनित जनसंख्या विशेषताओं, मार्केटिंग या रायशुमारी अनुसंधान, या ऐसे अनुसंधानों में उपयोग हुए डेमोग्राफिक प्रोफाईल से होता है।

जनसांख्यिकी को समाजशास्त्र के क्षेत्र के तहत भी एक शाखा माना जाता है। यह सांख्यिकी आँकड़ों, सूचनाओं को एकत्रित करने, व्याख्या करने तथा रूझान निर्धारण हेतु प्रस्तुत करने पर अत्यधिक निर्भर करती है। इनमें से अधिकतर आँकड़े विश्व की जनगणना से मिलते हैं। अन्य सर्वे तथा सांख्यिकी रिकॉर्ड का भी कुछ हद तक उपयोग होता है।

जनसांख्यिकीविद प्राथमिक रूप से मूल जीवन की घटनाओं जैसे जन्म तथा मृत्यु दर, प्रवास, रोजगार, तलाक, गर्भनिरोधक के उपयोग, भूख, अर्थशास्त्र, बहते जल तक पहुँच, शिक्षा, जीवन की आशा आदि से सम्बन्धित सूचनाओं को संभालते हैं। इन सांख्यिकीयों का उपयोग कुछ अलग तरीके से होता है। ये अक्सर यह बताने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, जो कि संभावित समस्याओं से बचने या योजना बनाने में मदद कर सकती है। जनसांख्यिकीविद यह अध्ययन करते है कि वस्तुएं क्यों होती है तथा उनके परिणाम क्या है तथा जनसंख्या रूझान के वातावरण पर प्रभाव आदि का भी अध्ययन करते है। जनसंख्या अध्ययन यह निर्धारण करन में मदद करता है कि सरकार अपना पैसा किस प्रकार वितरित करे तथा मदद के संसाधन कहाँ प्रयोग करे। विज्ञापन तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र भी जनसांख्यिकी का बड़े तौर पर उपयोग करते है।

जनसंख्या प्रक्रियाओं की मॉडलिंग हेतु कई प्रकार की जनसांख्यिकी विधियां हैं। इसमें मोर्टेलिटी के मॉडल (लाइफ टेबल, गोमपट्ज मॉडल, हेजाड्र्स मॉडल, कोक्स प्रपोर्शनल हेजार्ड्स मॉडल, मल्टीपल डिक्रीमेंट लाइफ टेबल्स, ब्रास रीलशनल लोजिट्स), फर्टिलिटी (हरनेस मॉडल, कोएल-ट्रसेल मॉडल, पेरिटी प्रोग्रेशन रेशियो), मेरिज (सिंगुलेट मीन एट मेरिज, पेज मॉडल), डिसएबिलिटी (सुलिवन का मॉडल, मल्टीस्टेट लाइफ टेबल्स), जनसंख्या अनुमान (ली कार्टर, लेसली मेट्रिक्स) तथा जनसंख्या मोमेंटम (कीफिट्ज) शामिल हैं।

जनसंख्या तथा जनसांख्यिकी का विज्ञान जनसंख्या तीन प्रक्रियाओं से परिवर्तित होती है: प्रजनन, मृत्यु तथा प्रवास। प्रजनन में महिला के कुल बच्चों की संख्या शामिल होती है तथा फेकन्डिटी (एक महिलाओं की संतान को जन्म देने की क्षमता) के विपरीत होती है। मोर्टैलिटी किसी आबादी के सदस्यों की मृत्यु को प्रभावित करने वाले कारणों, परिणामों तथा प्रक्रियाओं के मापन का अध्ययन है। जनसांख्यिकीविद सामान्यतया मोर्टैलिटी का अध्ययन लाइफ टेबल्स का उपयोग करते हुए करते हैं, जो कि एक ऐसा सांख्यिकी उपकरण है जो आबादी में मोर्टैलिटी की स्थितियों के बारे में (मुख्यत: लाइफ एक्सपेक्टेंसी) सूचनाएं उपलब्ध कराता है।

प्रवास का अभिप्राय व्यक्तियों का अपने मूल स्थान से किसी अन्य पूर्व निश्चित, राजनीतिक सीमा में स्थित स्थान तक पहुँचना है। प्रवास के अनुसंधानकर्ता उन गतियों को प्रवास नहीं कहते जब तक वे कुछ हद तक स्थायी न हों। इस प्रकार जनसांख्यिकीविद पर्यटकों तथा यात्रियों को प्रवासी नहीं मानते। जबकि जनसांख्यिकीविद जो प्रवास का

अध्ययन करते हैं सामान्यतया निवास स्थान के जनगणना के आँकड़ों के आधार पर ऐसा करते हैं। आंकड़ों के अप्रत्यक्ष स्रोत टैक्स फॉर्म तथा लेबर फोर्स के सर्वे भी महत्वपूर्ण हैं।

टिप्पणी

जनसांख्यिकी पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है जिसमें सामान्य विज्ञान, सांख्यिकी या स्वास्थ्य विज्ञान की प्रारम्भिक प्रशिक्षण वाले विद्यार्थी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अनेक क्षेत्रों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान तथा इतिहास का विषय होने के कारण जनसांख्यिकी सामाजिक तथा अन्य विज्ञानों से लिये गये तकनीकी मात्रात्मक तरीकों जो किसी भी क्षेत्र का मुख्य भाग है, के द्वारा बड़ी आबादी से जुड़े मुद्दों तक पहुँचने के लिये साधन प्रदान करती है। जनसांख्यिकी अनुसंधान विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा सांख्यिकी विभागों के साथ-साथ कई अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों में भी किये जाते हैं। जनसंख्या अध्ययन से सम्बन्धित संस्थान सिसरेड नेटवर्क (इंटरनेशनल कमिटी फॉर कोआर्डिनेशन आफॅ डेमोग्राफिक रिसर्च) का भाग है जबकि सभी व्यक्तिगत रूप से जनसांख्यिकी अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक इन्टरनेशनल यूनियन फॉर दी साइन्टिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के सदस्य हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं।

1.4.1 आँकड़ों के स्रोत एवं स्वरूप

जनसंख्या भूगोल के अध्ययन तथा प्रक्षेपण हेतु अनुभवजन्य आंकड़ों पर निर्भर रहना होता है। एक जनसंख्या भूगोलवेता को आंकड़ों के विभिन्न प्रकारों तथा स्रोतों के बारे में ज्ञान होना चाहिये। उसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आबादी के आंकड़ों से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी भी होनी चाहिये।

जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को दो प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। पहले प्रकार के आंकड़े, क्रॉस सेक्शन आँकड़े हैं। ये किसी विशेष समय पर एक चर विशेष या चरों के समूह के लिये किसी आबादी के क्रॉस सेक्शन से एकत्रित किये गये आँकड़े होते है। ये आँकड़े ऐतिहासिक भी हो सकते हैं जिन्हें कई वर्षों की समयावधि में एकत्रित किया गया हो। दूसरे प्रकार के आँकड़े टाइम सीरीज आँकड़े कहलाते हैं। टाइम सीरीज आँकड़े किसी विशेष समय पर एक चर विशेष या चरों के समूह के लिये लम्बी समयावधि के लिये एकत्रित किये जाते हैं। टाइम सीरीज आँकड़े लम्बी अवधि के परिवेश को दर्शाते हैं जबकि क्रॉस सेक्शन आँकड़े केवल टेम्पोरल या किसी भी फिनॉमिना की छोटी अवधि की तस्वीर दर्शाते हैं।

आंकड़े किसी परिवार, घर या व्यक्ति से एकत्रित किये जा सकते हैं। आँकड़े माइक्रो स्तर के होते हैं जो माइक्रो स्तर के अध्ययनों के लिये उपयोग में लिये जाते हैं। मैक्रो लेवल अध्ययनों के लिये आँकड़े विभिन्न परिवारों तथा देशों के पूर्ण तंत्रों से भी एकत्रित किये जा सकते हैं। मैक्रो लेवल के अध्ययनों के लिये मैक्रो लेवल के आंकड़ों की आवश्यकता होती है जो कि कुछ उपयोगी नीतियों को प्रभावित करने वाले निष्कर्ष निकालने के लिये पूरे देश से एकत्रित किये जाते हैं।

• प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े

कुछ आँकड़े प्रश्नावलियों, अनुसूचियों या व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के आँकड़े एकत्रित करने की विधियों को

प्राथमिक विधियाँ कहा जाता है। प्रकाशित स्रोतों जैसे किताबें, रिपोर्ट, जर्नल तथा अन्य स्रोतों से सांख्यिकी आँकड़े भी एकत्रित किये जा सकते हैं।

टिप्पणी

विशिष्ट प्रकार के आँकड़े एकत्रित करने की विधियों को द्वितीयक विधियां कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं ही प्राथमिक स्रोतों से एकत्रित किये जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो कि पहले ही किसी और द्वारा एकत्रित किये गये हों तथा प्रकाशित रूप में उपलब्ध हों। जनसंख्या भूगोलवेत्ता द्वारा किये गये अध्ययन एग्रीगेटिव या सेग्रिगेटिव प्रकार के हो सकते हैं तथा इसी अनुसार उन्हें उपयुक्त आँकड़े पता करने होते हैं।

जनसंख्या आंकड़ों के मुख्यत: तीन स्रोत होते हैं: जनगणना रिपोर्ट, महत्वपूर्ण पंजीकरण तथा विविध सर्वेक्षण।

1.4.2 जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रण की समस्याएं

जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को जनसंख्या आकड़ों का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अनुसंधान और अध्ययन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले इन आंकड़ों में नीचे उल्लेखित दोष हो सकते हैं–

(i) अपर्याप्त जानकारी।

(ii) अपर्याप्त उपलब्धता ।

(iii) पक्षपातपूर्ण डेटा।

(iv) महत्वपूर्ण मामलों की परिभाषाओं में परिवर्तन।

(v) आकड़ों की एकरूपता का अभाव।

(vi) जाँच के विषय के बारे में अज्ञानता अथवा पूर्वाग्रह और गलत बयान के कारण भी आंकड़ा गलत हो सकता है।

कई देशों में अधिक गणना या कम–गणना की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं।

- चरों की परिभाषाओं में परिवर्तन के कारण डेटा विषम हो जाता है
- सीमाओं में परिवर्तन, जनगणना इकाइयों में परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है।
- इस्तेमाल किए गए शब्दों के अर्थ में परिवर्तन और इसी तरह की शब्दावली में परिवर्तन से भी समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या भूगोलवेत्ता विशेष रूप से दो कठिनाइयों का सामना करते हैं:–

(i) जनगणना इकाइयों और क्षेत्रों में बार–बार परिवर्तन।

(ii) बस्तियों के स्थान का सटीक बिंदु दिखाने के लिए किसी निश्चित मानचित्र का अभाव।

बहुधा जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को गणना करने के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का सहारा लेना पड़ता है। इन अप्रत्यक्ष विधियों को जनसंख्या और उसके प्रक्षेप के लिए विश्लेषणात्मक होना चाहिए।

टिप्पणी

लिंग संरचना की सहायता से परोक्ष रूप से कई गणनाएं की जा सकती हैं। जनसांख्यिकीय में इन उपलब्ध आंकड़ों को सबसे विश्वसनीय माना जाता है।

जनसांख्यिकी में उम्र से संबंधित आंकड़ों को कई कारणों से सबसे अविश्वसनीय माना जाता है।

लोग अपनी वास्तविक उम्र छुपा लेते हैं। जनसंख्या भूगोलवेत्ता आयु संरचना और आयु समूह का ठीक से विश्लेषण करके गलत बयान के प्रभाव और अनुमान को बेअसर कर सकते हैं। जनसंख्या भूगोलवेत्ता साक्षरता, शहरीकरण और व्यवसाय आदि जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के लिए कोई मानक परिभाषा नहीं पाते हैं। इससे इन तत्वों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना लगभग असंभव हो जाती है। इसलिये जो सबसे आवश्यक है वह है सभी महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं का एक समान सेट। मानक जनगणना में इसका उपयोग किया जाना बेहतर रहता है।

जनसंख्या समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर्याप्त रूप से सामने नहीं आ पाते हैं। अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों और परिभाषा का एक मानक सेट होना चाहिए और यह कार्य संयुक्त राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। जनसंख्या गणना में इस्तेमाल होनी वाली परिभाषा और प्रक्रियाओं का मानक रूप विकसित करके वह सदस्य देशों की मदद कर सकता है। जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन से जनसंख्या भूगोल दायरा व्यापक हो जायेगा।

1.4.3 आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर

अनुपयुक्त सूचना, अपर्याप्त कवरेज, पक्षपात वाले आँकड़ों, महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा में परिवर्तन, एकरूपता की कमी, तथा आंकड़ों की अशुद्धता (संभावित) के कारण जनसंख्या आंकड़ों की विश्वासनीयता का स्तर प्रभावित होता है। ये आँकड़े उपेक्षा, पक्षपात या शोध विषय के बारे में गलत कथनों के कारण अशुद्ध हो सकते हैं। शोधकर्ता जिन्होंने आँकड़े एकत्रित किये हैं वे प्रशिक्षित तथा योग्य नहीं होते। इसीलिये जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को इन महत्वपूर्ण आंकड़ों का उपयोग करते हुए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है।

अनेक देशों में अधिक गणना या कम गणना की समस्या भी हो सकती है। ये आँकड़े चरों की परिभाषा में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सेन्सस इकाइयों में परिवर्तन उपयोग मे लिये गये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन तथा अन्य समान परिवर्तनों के कारण विषम हो जाता है। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय तुलना जनसंख्या आंकड़ों के मामलों में संभव नहीं है।

प्राय: जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं को महत्वपूर्ण दरों की गणना के लिए अप्रत्यक्ष विधि यां अपनानी पड़ती हैं। ये अप्रत्यक्ष विधियों को पॉपुलेशन आँकड़ों के एक्स्ट्रा पोलेशन व इन्ट्रापोलेशन के लिये विश्लेषणात्मक होना चाहिये। कई गणनाएं लिंग रचना आंकड़ों की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से हो जाती हैं। ये आँकड़े जनसांख्यिकी में उपलब्ध सबसे विश्वसनीय आँकड़े माने जाते हैं।

आयु संरचना से सम्बन्धित आँकड़े कई कारणों से सर्वाधिक अविश्वसनीय होते हैं। लोगों की विशेषकर महिलाओं की अपनी उम्र छिपाने की आदत होती है। जनसंख्या

भूगोलवेत्ता आयु संरचना तथा आयु समूहों का विश्लेषण करते हैं जिससे गलत कथनों तथा अनुमानों का प्रभाव उदासीन हो जाता है।

टिप्पणी

जनसंख्या भूगोलवेत्ता यह पता लगाते हैं कि महत्वपूर्ण तत्वों जैसे साक्षरता, शहरीकरण, व्यवसाय आदि की मानक परिभाषा नहीं है तो क्या विकल्प हो सकते हैं। इसके कारण इन तत्वों की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना लगभग असंभव हो जाती है। इसीलिये इन सभी सेन्सस में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं के एकरूप समुच्चय की आवश्यकता होती है।

जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही उपरोक्त उल्लेखित समस्याएं भारत जैसे विकासशील देशों में बहुत अधिक प्रखर हैं। यहाँ भी उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं के कारण आंकड़ों की विश्वसनीयता सही परिभाषित नहीं है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. जनसंख्या की ऐतिहासिक–प्राकृतिक वृद्धि दर लगभग कितनी रही?

   (क) शून्य के आसपास (ख) दस के आसपास

   (ग) बीस के आसपास (घ) चालीस के आसपास

4. मानव आबादी का सांख्यिकीय अध्ययन क्या कहलाता है?

   (क) प्रौद्योगिकी (ख) जनसांख्यिकी

   (ग) ज्यामिति (घ) क्रेमोग्राफिक्स

5. किससे संबंधित आंकड़े कई कारणों से सर्वाधिक अविश्वसनीय होते हैं?

   (क) क्रिकेट से (ख) फिल्मों से

   (ग) कारोबार से (घ) आयु संरचना से

1.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ग)
2. (घ)
3. (क)
4. (ख)
5. (घ)

1.6 सारांश

जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या वितरण और विभिन्न जनसंख्या समूहों में उपस्थित उत्पादक संबंधों, आवास-प्रवास के नेटवर्क और समाज के उत्पादक लक्ष्यों के लिए इसकी उपयुक्तता, उपयोगिता और कार्यक्षमता का अध्ययन करता है। जनसंख्या भूगोल के

टिप्पणी

अध्ययन को बसे हुए स्थलों के क्षेत्रीय समूह के विश्लेषण द्वारा इनकी आर्थिक क्रियाशीलता पर जोर देते हुए चिन्हित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या वितरण के प्रतिमान, मौलिक रूप से आवास-प्रवास के नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और आवासीय प्रतिमानों में परिवर्तन प्रमुख रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं।

भूगोल की विषयवस्तु जनसंख्या का स्थानिक वितरण एवं स्थानिक अंत:क्रिया है। यह केवल तभी सार्थक होगा यदि एक कदम आगे बढ़कर उन प्रक्रियाओं (प्रक्रमों) की खोज को इसमें शामिल किया जाए जो विशिष्ट स्थानिक वितरणों और अंत:क्रियाओं को प्रभावित और सृजित करती हैं।

जनसंख्या के भूगोल या किसी भी चीज के भूगोल जैसी कोई चीज नहीं है, जब तक कि सरल स्थानिक वितरण से भूगोल की एक अत्यधिक प्रतिबंधित और बौद्धिक रूप से असंतोषजनक समकक्षता में विश्वास करने वाले लोग न हों। तद्नुसार, जनसंख्या भूगोल उसी दशा में सम्पूर्ण सैद्धान्तिक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है। यदि प्रतिमानों के वर्णन और हस्तक्षेपी व्याख्याकरण के इसके पारंपरिक अमहत्त्वाकांक्षी सरोकारों को छोड़ दिया जाए और असंदिग्ध रूप से ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोणों और प्रक्रियाओं का समावेशन किया जाए जो उन जनसांख्यिकीय समस्याओं के प्रति ताजगीपूर्ण अंतर्दृष्टि का योगदान कर सकें, जिनका अध्ययन अनेक अन्य विषयों जैसे कि जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास और समाजशास्त्र में किया जाता है।

जनसंख्या भूगोल, भूगोल की आपेक्षिक रूप से नवीन और व्यापक रूप से अल्पविकसित शाखा है, जिसकी सीमाएं बलपूर्वक निर्धारित नहीं की जा सकतीं। इस विकसित होती विषय शाखा की अध्ययन पद्धतियों और विषयसामग्री में सुधार के लिए प्रयास अभी जारी हैं। यह माना गया है कि जनसंख्या भूगोल को एक व्यवस्थित विशेषज्ञता के रूप में विकसित किया जा सकता है।

जनसंख्या प्रक्रियाओं की मॉडलिंग हेतु कई प्रकार की जनसांख्यिकी विधियां हैं। इसमें मोर्टेलिटी के मॉडल (लाइफ टेबल, गोमपर्ट्ज मॉडल, हेजार्ड्स मॉडल, कोक्स प्रपोर्शनल हेजार्ड्स मॉडल, मल्टीपल डिक्रीमेंट लाइफ टेबल्स, ब्रास रीलशनल लोजिट्स), फर्टिलिटी (हरनेस मॉडल, कोएल-ट्रसेल मॉडल, पेरिटी प्रोग्रेशन रेशियो), मेरिज (सिंगुलेट मीन एट मेरिज, पेज मॉडल), डिसएबिलिटी (सुलिवन का मॉडल, मल्टीस्टेट लाइफ टेबल्स), जनसंख्या अनुमान (ली कार्टर, लेसली मेट्रिक्स) तथा जनसंख्या मोमेंटम (कीफिट्ज) शामिल हैं।

1.7 मुख्य शब्दावली

- **स्थलाकृति** : भूमि का आकार
- **विभेदीकृत** : विभाजित, वर्गीकृत
- **आवासन** : अधिवास, निवास
- **कार्मिक** : कर्मचारी

- **अंगीकरण** : स्वीकारना, अपनाना
- **चिह्नीकरण** : रेखांकन, सीमांकन
- **परिप्रेक्ष्य** : संदर्भ

टिप्पणी

1.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. जनसंख्या भूगोल का उद्देश्य बताइए।
3. जनसंख्या भूगोल समाजशास्त्र से कैसे संबंधित है?
4. जनसंख्या निरूपण से क्या आशय है?
5. प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े किन्हें कहते हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए।
2. विशेषज्ञता के एक क्षेत्र के रूप में जनसंख्या भूगोल का विकास स्पष्ट कीजिए।
3. जनसंख्या भूगोल में आंकड़ों के स्रोत की स्थिति स्पष्ट कीजिए।
4. जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रण संबंधी समस्याओं की विवेचना कीजिए।
5. आंकड़ों की विश्वसनीयता के स्तर पर टिप्पणी लिखिए।

1.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Census of India. 1991 : A state Profile.

Clarke, John L 1973 : Population Geography, Pergamon Press, Oxford.

Mamona, C.B. 1981 : India's populations Problem, Kitab mahal N-Delhi.

United nations 1974 : Methods for projections and Urban and Rural Populations No. VIII, New York.

King, Leslie. 1986 : Central place Theory, Saga Punlications New Delhi.

Nangia, Sudesh. 1976: Delhi Metropolitan Region. K.B. Publications New Delhi.

Ramchandran. R. 1992 : Urbanisation and Urban Systems in India, Oxford University Press, N. Delhi.

Singh. R.L. and Kashi nath singh (editor) 1975 : Readings in Rural settlement Geography, National Geographic society of India.

इकाई 2 जनसंख्या वितरण

टिप्पणी

संरचना

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 वितरण तथा घनत्व की अवधारणा
  2.2.1 प्रयोग सिद्ध बनाम सैद्धांतिक वितरण संबंधी संकल्पना
  2.2.2 ऊंचाइयों पर आधारित संकल्पना
2.3 जनसंख्या घनत्व और वृद्धि : सैद्धांतिक मुद्दे
  2.3.1 जनसंख्या घनत्व के प्रकार
  2.3.2 जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक
2.4 जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि के पारंपरिक, आधुनिक सिद्धांत एवं जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत
  2.4.1 पारंपरिक सिद्धांत
  2.4.2 आधुनिक सिद्धांत
  2.4.3 जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत
2.5 विश्व जनसंख्या वृद्धि : स्वरूप एवं निर्धारक
2.6 भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि
2.7 अधोजनसंख्या और अति जनसंख्या की संकल्पना
2.8 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.9 सारांश
2.10 मुख्य शब्दावली
2.11 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.12 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय

जनसंख्या वृद्धि शब्द एक जनसंख्या में समय के साथ व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। वृद्धि को जनसंख्या में जुड़ रहे नये व्यक्तियों की जन्म-दर से दर्शाया जाता है तथा जन्संख्या में होने वाली कमी को लोगों की मृत्यु-दर, के द्वारा इंगित किया जाता है। दुनिया की जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। वे जगहें जो विरल जनसंख्या वाली हैं, कम लोगों द्वारा आबाद हैं तथा वे जगहें जो सघन जनसंख्या वाली हैं, अधिक लोगों से आबाद हैं।

इस इकाई में हम वितरण तथा घनत्व की अवधारणा, जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण व वृद्धि के सिद्धांत, स्वरूप एवं निर्धारक अधोजनसंख्या और अति जनसंख्या की संकल्पना रेखांकित करेंगे।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- वितरण तथा घनत्व की अवधारणा समझ पाएंगे;
- जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि के सैद्धांतिक मुद्दों से अवगत हो पाएंगे;

टिप्पणी

- जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित हो पाएंगे;
- विश्व की जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक स्पष्ट कर पाएंगे;
- भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि का अवलोकन कर पाएंगे;
- अधोजनसंख्या एवं अति जनसंख्या की संकल्पना का विवेचन कर पाएंगे।

2.2 वितरण तथा घनत्व की अवधारणा

जनसंख्या वितरण तथा घनत्व संबंधी अवधारणा को हम मूलत: निम्नांकित दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं-

2.2.1 प्रयोग सिद्ध बनाम सैद्धांतिक वितरण संबंधी संकल्पना

प्रयोग सिद्ध बनाम सैद्धांतिक वितरण के बीच के अंतर को हम अपने आंकड़ों तथा एक अंतर को बढ़ाने वाली प्रक्रिया के संभावित मॉडल के बीच की भिन्नताओं के माधयम से समझ सकते हैं। हमारे चर/चरों की आवृत्ति या देखे गये वितरण में भिन्नताएं होती हैं जिन्हें हम हमारे आंकड़ों में सीधे-सीधे देख सकते हैं। इसमे कोई निर्णयात्मक भाव नहीं है, केवल आंकड़ों में उपस्थित तथ्यों का विवरण है।

जब हम आगे बढ़ते हुए वर्तमान आंकड़ों के समूहों में निहित तथ्यों को विस्तृत रूप से सीखने का प्रयास करते हैं, तो किन्हीं अपरिचित वितरणों के द्वारा पैदा हुए तथा न समझाये जा सकने योग्य अंतरों को धारण करते हैं। कई बार हम इन्हें सत्य तथा अंतर्निहित वितरण के रूप में देखते हैं जबकि लगभग हमेशा ये एक संकल्पित तत्व हैं।

जब हम अपने विश्लेषण में एक पूर्ण परिमाप वाले मॉडल का प्रयोग करते हैं, तब एक नामित परिमापित वितरण, जैसे सामान्य वितरण को चुनते हैं, और हम ये मानते हैं कि वह आंकड़े पैदा करता है। ये सैद्धांन्तिक वितरण है, जो एक प्रायिकता मॉडल को समझाता व परिभाषित करता है।

इस प्रयोजन के लिये मानव विकसित सैकड़ों वितरण हमारे पास उपलब्ध हैं। किन्हीं आरोपित क्षेत्रों में, अनुभव ये बताते हैं कि कुछ वितरण उपयोगी हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो यह बताए कि हमारा आंकड़ा किसी विशेष वितरण द्वारा उत्पन्न हुआ है। अत: हमने कभी भी अपने परिकल्पित सैद्धान्तिक वितरण पर विश्वास नहीं किया। हम अधिक से अधिक यह उम्मीद लगा सकते हैं कि परिकल्पित सैद्धांन्तिक वितरण से नमूने की क्रिया, हमारे आंकड़ों को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण गुणों को दर्शाए।

सैद्धांन्तिक वितरण हमारे विश्वास की कमी, पुष्टि तथा उपयुक्त होने की अच्छाई की ओर ध्यानाकर्षित करता है। अर्थात हम ऐसी परिणामी प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहेंगे जो वितरण संबंधी परिकल्पनाओं (पुष्ट) से भिन्नताओं के प्रति कम असंवेदनशील हों। हम निर्णय के लिये ऐसे सैद्धांन्तिक वितरण का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे जो हमारे आंकड़ों के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि किन्ही जगहों पर वितरण संभवत: हमारे पास उपस्थित आंकड़ों के समूह को न दर्शाए।

2.2.2 ऊंचाइयों पर आधारित संकल्पना

टिप्पणी

हमारी ऊंचाइयां सामान्यत: वितरित हैं; जैसे कथन को किस प्रकार समझ सकते है? हमें इसे पूर्ण शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यह कथन उससे कहीं अधिक सटीक है जितना हम समझ रहें हैं। सामान्यत: हम 'ऊंचाईयां सामान्यत: वितरित हैं,' को ढीले-ढाले अर्थ में लेते हैं। ऊंचाई का प्रयोगसिद्ध वितरण जो हमने देखा है (किसी भी संदर्भ मे)ं ऐसा लगता है जैसे किसी विशेष सामान्य वितरण के प्रायिकता वक्र के काफी निकट का है। हम इस बात के लिये विश्वास की छलांग लगा सकते हैं कि ये सन्निकटता बहुत अच्छी होगी, अगर हम मूल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचाई का प्रयोगसिद्ध वितरण देख सकते, जहां से हमारे द्वारा देखी गयी ऊंचाईयां ली गयी हैं। हम और भी बेहतर छलांग लगा सकते हैं, यदि हम ये सोचें कि 'अभी तक नहीं जांची गयी किसी दूसरी जनसंख्या से लोगो की ऊंचाई' भी संभवत: समानरूपी निकलेगी।

अगर हम सामान्य वितरण से नजदीकी रूप से समान ऊंचाई के वितरण वाली जनसंख्या के यादृच्छय नमूने के विचार या वास्तविकता को जोड़ें तो नतीजा ये निकलेगा कि लोगों के नमूनों को लेकर उनकी ऊंचाई नापने पर मिले आंकड़े, सामान्य वितरण के लिये गये यादृच्छया नमूने के आंकड़ों के प्रकार से लगभग अविभेद्य होंगें। बाद के व्यवहार की विवेचना सीधे गणितीय तौर पर या अनुकरण के द्वारा की जा सकती है।

अगर हम इस बात का अनुमान लगाये कि हमारे ऊंचाई के आंकड़ो के नमूने राष्ट्रीय प्रायिकता मॉडल से लिये गये हैं तो अनुमानिक कथन उदा. जनसंख्या ऊंचाई वितरण के औसत के लिये एक विश्वसनीय अंतराल उस अनुमान के परिणाम की तरह सांख्यिकीय सिद्धांत का पालन करेंगें। ये गणित के समान है जहां यदि शर्तों के एक समूह को कोई सत्य मानकर (स्वयं सिद्ध) लेता है तो इन मूल ऐक्सियम के तार्किक परिणामी कई दूसरे कथन भी सत्य माने जाते हैं।

हमारे ऊंचाई संबंधी आंकडों के लिये, पहले पैरा में ली गयी विश्वास की वितरण संबंधी छलांग को सामान्यता की गैर महत्वपूर्ण जांच से जाना जा सकता है। लेकिन ये हमें कितनी जानकारी देता है? ये केवल यह बताता है कि हम इस बात की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं कि केवल नमूनों में परिवर्तन से सामान्यता से विस्थापन हो सकता है, जिसे हम आंकड़ों में देख सकते हैं। अनुभव ये बतातें हैं कि, पर्याप्त आंकड़ों के साथ, लगभग सभी परिस्थितियों में हमारे द्वारा की गयी कोई सैद्धान्तिक वितरणात्मक परिकल्पना, अकल्पनीय रूप से दिखेगी। हम जो कर रहे हैं वो कभी भी परिकल्पिक सैद्धांतिक वितरण के लिये सही नहीं होगा। ये केवल परिकल्पिक सैद्धांतिक वितरण के निकटतम समान होगा ताकि निष्कर्ष निकालने के तरीके जो हमारे अनुमान पर आधारित हैं किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से भ्रामक न हो।

ये काफी समझने योग्य इच्छा है कि वास्तविक आंकड़ों से से प्रायिकता मॉडल तथा वितरण को पढ़ाया जायें क्योंकि पासा सिक्के तथा अन्य उबाऊ तथा असंगत हैं। ये ऊपर चर्चित समस्या पर लागू होता है। ये हम कभी नहीं जान सकते कि किसी वास्तविक आंकड़े का विशिष्ट समूह को किसी विशिष्ट प्रायिकता मॉडल से उत्पन्न किया गया है। बस हम ये विश्वास कर सकते हैं कि मॉडल एक अच्छी समानता वाला

टिप्पणी

है। प्रायिकता मॉडल, वास्तविक दुनिया के व्यवहार के मॉडल के प्रयोग के लिये सार निर्मित हैं। इनका सफल कार्यान्वयन दो आधारों पर खड़ा है। पहले आधार में, सार निर्माण को समझना शामिल है, अर्थात मॉडल तथा वे आंकड़े जो मॉडल उत्पन्न करता है, तथा यह कि, आदर्श वातावरण में हम किस प्रकार से निष्कर्षता की दलील पेश करते हैं। द्वितीय आधार में वे समानताएं शामिल हैं जो मॉडल आधारित तर्क को लागू करने का सुझाव दे सकती हैं। ऐसे में वितरण वास्तविक परिस्थिति से उचित सदृश्यता को दिखा सकता है और फिर मूल संदर्भ के रूप परिणाम की व्याख्या कर सकता है।

मॉडल तथा इसके बेतरतीब व्यवहार की प्रकृति को समझने के लिये मानसिक सम्पर्क बनाये जाते हैं। वास्तविक दुनिया का संदर्भ एक ध्यान भंग करने वाली अप्रासंगिकता है। वह एक वास्तविक दुनिया का संदर्भ नहीं है। संदर्भ के साथ सहभागिता, मॉडल को लागू करने की क्षमता की मान्यता, मॉडल के मानकों की व्याख्या तथा किसी निष्कर्षजन्य कथनों की व्याख्या के साथ आती है, मॉडल आधारित तर्क को लागू करने से आती है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. हमारे चर/चरों की आवृत्ति या देखे गए वितरण में क्या होती हैं?
   (क) समानताएं (ख) भिन्नताएं
   (ग) भ्रांतियां (घ) त्रुटियां
2. वास्तविक दुनिया का संदर्भ क्या भंग करने वाली अप्रासंगिकता है?
   (क) ध्यान (ख) विज्ञान
   (ग) रुझान (घ) निद्रा

2.3 जनसंख्या घनत्व और वृद्धि : सैद्धांतिक मुद्दे

भूतल पर जनसंख्या के वितरण में आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक परिवर्तन होता रहा है। यद्यपि परिवर्तन की गति व दिशा देश– काल के अनुसार भिन्न भिन्न रही है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण अत्यधिक विषम है। जहां पर मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थल है वहां अत्यधिक मानव बसाव पाया जाता है।

पृथ्वी के विभिन्न भागों पर मानव के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना भौगोलिक अध्ययन का मूल बिंदु है। फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या ही वह सन्दर्भ बिंदु है जिसके कारण भूगोलवेता अन्य पर्यावरणीय तंत्रों का अध्ययन करता है।

जनसंख्या घनत्व की अवधारणा, लोगों की संख्या को उनके द्वारा कब्जा लिए गए क्षेत्र से सम्बंधित करना भूगोलवेत्ताओं द्वारा नियोजित सबसे पेचीदा और सबसे खतरनाक सहसंबंधों में से एक है। इस संदर्भ में पहली बार 1837 में हेरी ड्यूरी हार्नेस द्वारा आयरलैंड के रेलवे के मानचित्र की एक श्रृंखला का उपयोग किया गया था।

यह तब से यह आंशिक रूप से मौजूदा और संभावित घनत्व के सन्दर्भ में अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या के आकलन के साधन के रूप में विकसित हुआ।

घनत्व सूचकांकों के उपयोग संबंधी मुख्य कठिनाइयाँ

टिप्पणी

जनसंख्या डेटा प्रशासनिक या जनगणना क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, बजाय इसके

(अ) कि जनसंख्या वितरण की सजातीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की तुलना के लिए।

(ब) कि ऐसी एकरूपता किसी भी मामले में दुर्लभ है।

(स) कि घनत्व केवल औसत है। सभी सीमाओं के साथ यह शब्द उपयोग किया जाता है।

(द) कि घनत्व मानचित्रों का निर्माण वर्ग अंतराल के चयन में प्रयुक्त मानदंडों पर निर्भर करता है।

(य) कि ऐसे मानचित्रों की व्याख्या छायांकन विधियों पर निर्भर करती है।

(र) कि वह जनसंख्या संख्या क्षेत्र के कई अलग–अलग विधियों से संबंधित हो सकती है।

विश्व जनसंख्या घनत्व

देश	जनसंख्या घनत्व व्यक्ति/किलोमीटर
चीन	143
भारत	394
इंडोनेशिया	132
पाकिस्तान	244
बांग्लादेश	1101
जापान	336
फिलिपिन्स	334
वियतनाम	273
ईरान	47
तर्की	99
थाईलैंड	129
दक्षिणी कोरिया	507
उत्तरी कोरिया	206
श्रीलंका	315
प्रमुख यूरोपीय देश	
रूसी गणराज्य	08
जर्मनी	226
फ्रांस	116
यूनाइटेड किंगडम	266
इटली	204
स्पेन	92
यूक्रेन	75

टिप्पणी

पोलैंड	123
यूनान	83
पुर्तगाल	113
हैंगरी	106
बेलारूस	46
स्विडेन	22
स्विट्जरलैंड	198
डेनमार्क	131
प्रमुख अफ्रीकी देश	
नाइजीरिया	192
इथोपिया	87
मिश्र	88
तंजानिया	54
कीनिया	74
अल्जिरिया	16
सूडान	21
युगांडा	161
मोरोक्को	75
घाना	113
मोजाम्बिक	31
कैमरुन	48
मेडागास्कर	38
अंगोला	18
उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश	
सयुंक्त राज्य अमेरिका	33
मैक्सीको	61
कनाडा	4
ग्वाटेमाला	146
क्यूबा	101
हँडूरस	73
एल सल्वाडोर	303
निकारागुआ	48
कोस्टारिका	93
पनामा	48

टिप्पणी

प्रमुख दक्षिणी अमेरिका देश	
ब्राजील	24
कोलम्बिया	42
अर्जेंटीना	15
पेरू	24
वेनजुएला	33
चिली	23
बोलिविया	9
परागुए	17
यूरूग्वे	20

Source: World Population Data Sheet, 2014.

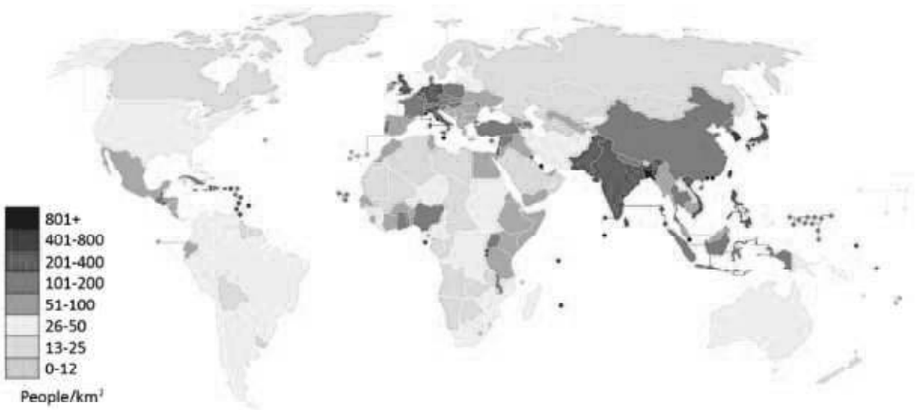

विश्व जनसंख्या घनत्व

जैसा कि डंकन ने कहा है ''घनत्व के आंकड़ों को 'नेट' पर आधारित करने की अपेक्षा सकल क्षेत्र परिष्कृत करने से कई समस्याएं सामने आती है; लेकिन दूसरे शब्दों में, जनसंख्या का घनत्व मनुष्य और भूमि के अनुपात को दर्शाता है।

इसकी गणना किसी काउंटी या क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या को कुल भूमि क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। यदि किसी दी गई जनसंख्या के लिए भूमि का क्षेत्रफल छोटा है, तो घनत्व होगा उच्च, लेकिन यदि भूमि क्षेत्र बड़ा है, तो घनत्व कम होगा।

यह बहुत तत्वों पर निर्भर करता है जैसे कि प्राकृतिक और मानवीय कारक। मिट्टी, वर्षा, जलवायु, आर्थिक संसाधन, जैसे कारक कई जगहों पर भिन्न होते हैं, घनत्व भी भिन्न होगा। घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या–एकाग्रता के अंश को मापता है।

2.3.1 जनसंख्या घनत्व के प्रकार

विभिन्न उपयोगों और उद्देश्यों के लिए जनसंख्या की गणना कई प्रकार से की जाती है। जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:–

1. अंकगणितीय घनत्व

टिप्पणी

2. कायिक घनत्व

3. पोषण या पौष्टिक घनत्व

4. आर्थिक घनत्व

5. कृषि घनत्व

1. अंकगणितीय घनत्व (Arithmetic Density) : किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या के अनुपात को अंकगणितीय घनत्व कहा जाता है। इसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या का ज्ञान होता है। वास्तव में अंकगणितीय घनत्व से मनुष्य और भूमि के साधारण अनुपात का आभास होता है। अंकगणितीय घनत्व के गणना का सूत्र निम्नलिखित है :–

$$\text{अंकगणितीय घनत्व} = \frac{\text{प्रदेश की कुल जनसंख्या}}{\text{प्रदेश का कुल क्षेत्रफल}}$$

इस घनत्व के आकलन की विधि सरल है। कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त भागफल जनसंख्या का अंकगणित घनत्व होता है। वर्तमान में विश्व का (2012) घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

अंकगणितीय घनत्व सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है लेकिन इसके कुछ दोष हैं जिससे यह जनसंख्या की सघनता का सही स्वरूप प्रकट नहीं कर पाता है।

इसकी गणना के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। कुल क्षेत्रफल में पहाड़, जंगल, दलदल, रेगिस्तान, जिला से आदि जन विहीन क्षेत्र भी शामिल कर लिए जाते हैं। वास्तव में इन क्षेत्रों में जनमानस का अभाव पाया जाता है। बसे हुए क्षेत्र का घनत्व काफी कम आता है, जबकि यह अधिक होना चाहिए था।

2. कायिक घनत्व (Physiological Density) : यह अंकगणितीय घनत्व का परिमार्जित रूप है जो वास्तविक रूप से अधिक सार्थक व उपयोगी है। इसकी गणना के लिए कुल क्षेत्रफल के स्थान पर केवल कृषि योग्य भूमि को भी शामिल किया जाता है। यह घनत्व प्रकट करता है कि किसी क्षेत्र की प्रति ईकाई कृषि भूमि पर औसतन कितने लोगों का भार है।मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भूमियों को कुल क्षेत्रफल से निकाल देने के फलस्वरुप कायिक घनत्व अधिक सही और सार्थक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

$$\text{कायिक घनत्व} = \frac{\text{प्रदेश की कुल जनसंख्या}}{\text{प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि}}$$

कायिक घनत्व के भी अपने कुछ दोष हैं। कायिक घनत्व में यह मान लिया जाता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जीविका कृषि पर आधारित है। यह कल्पना कृषि पर आधारित देशों के लिए तो सही हो सकती है, परंतु विकसित देशों के लिए ऐसा तथ्य सही नहीं है।

3. पोषण घनत्व (Nutrition Density) : पोषण घनत्व प्रदर्शित करता है कि किसी प्रदेश में खाद्यनों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्यों की औसत संख्या कितनी है। यह साधारणत : खाद्यान्न भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात है।

$$\text{पोषण घनत्व} = \frac{\text{प्रदेश की कुल जनसंख्या}}{\text{प्रदेश की कुल खाद्यान्न भूमि}}$$

टिप्पणी

जहाँ जनसंख्या के भोजन का आधार स्थानीय रूप से उत्पादित कोई एक खाद्यान्न या कई खाद्यान्न हैं उनके लिए पोषण घनत्व का महत्व बढ़ जाता है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, आदि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में 70% से अधिक क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, इसमें 90% जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है। ऐसे देशों के लिए पौष्टिक घनत्व ज्यादा उपयुक्त है।

4. आर्थिक घनत्व (Economic Density) : जिन देशों में कृषि भूमि कम है अथवा कृषि पर बहुत कम जनसंख्या आश्रित है और अधिकांश जनसंख्या उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवा व अन्य विविध कार्यों से जीविका अर्जित करती है वहां भूमि पर वास्तविक जनसंख्या के दबाव को कृषि या कायिक घनत्व द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। ऐसे देशों के लिए आर्थिक घनत्व का सबसे अधिक महत्व रखता है। आर्थिक घनत्व संपूर्ण जनसंख्या और सभी संसाधनों के मूल्यों का अनुपात होता है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है :–

$$\text{आर्थिक घनत्व} = \frac{\text{देश की कुल जनसंख्या}}{\text{देश के सम्पूर्ण संसाधनों का मूल्य (एकल इकाई के रूप में)}}$$

साइमन ने जनसंख्या और आर्थिक उत्पादों के अलग–अलग सूचकांक तैयार करने की सिफारिश दी। उनके अनुसार जनसंख्या सूचकांक को उत्पादन सूचकांक से भाग देकर आर्थिक घनत्व को प्रतिशत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

इसके लिए निम्नलिखित सूत्र हैः–

आर्थिक घनत्व = जसंख्या सूचकांक / उत्पाद का सूचकांक × 100

इस सूत्र के अनुसार यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या 5% और उस देश का कुल उत्पादन 7% है तो उसका आर्थिक घनत्व 5 / 7 × 100 = 71.43 आएगा।

5. कृषि घनत्व (Agricultural Density) : कृषि घनत्व कुल कृषि योग्य भूमि और कृषि पर आधारित जनसंख्या के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करता है। इस घनत्व में प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि या कुल कृषित भूमि से कृषि में सलंग्न कुल जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। इस प्रकार कृषि घनत्व प्रति इकाई कृषि भूमि पर आश्रित व्यक्तियों की औसत संख्या को प्रदर्शित करता है। कृषि घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है :–

$$\text{कृषि घनत्व} = \frac{\text{कृषि में संलग्न या कृषि पर आधारित जनसंख्या}}{\text{कुल कृषि योग्य भूमि}}$$

जिस प्रदेश में कृषि योग्य भूमि अधिक है वहां पर कृषि घनत्व कम हो जाता है और जहां पर कृषि भूमि कम और जनसंख्या कृषि भूमि पर अधिक आश्रित होती है वहां पर यह अधिक पाया जाता है। भारत, चीन, बांग्लादेश आदि कृषि प्रधान देशों में 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। यहां पर कृषि घनत्व अधिक पाया जाता है। जापान,ब्रिटेन,संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जैसे औद्योगिक देशों में; जहां कम लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, वहां पर कृषि घनत्व कम पाया जाता है।

टिप्पणी

2.3.2 जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक

विश्व में जनसंख्या सभी जगह एक जैसी नहीं पाई जाती है। कहीं पर जनसंख्या का सघन निवास है तो कहीं पर जनसंख्या बिखरी हुई पाई जाती है। जनसंख्या के वितरण के लिए बहुत सारे कारक प्रभावशाली होते हैं। इनका वर्णन करना एक भूगोलवेत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उत्तरदायी कारकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :– 1. प्राकृतिक कारक और 2. मानवीय कारक।

1. प्राकृतिक कारक

जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में जलवायु, खनिज व मिट्टी जलापूर्ति, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु,भूविन्यास आदि का महत्वपूर्ण स्थान है।

जलवायु :– जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु के प्रमुख घटक जैसे की वर्षा,तापमान, आद्रता प्रचलित पवने, वायुदाब आदि मनुष्य के वितरण को प्रभावित करते हैं। विषम जलवायु मनुष्य के वितरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुत अधिक उष्ण और बहुत अधिक शीत जलवायु मनुष्य के बसाव को हतोत्साहित करती है। सीत–उष्णकटिबंधीय जलवायु को मनुष्य के बचाव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार से मानसूनी जलवायु भी मानव बसाव को आकर्षित करती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या का सकेंद्रण मानसूनी एशिया के देशों जैसे कि चीन, जापान वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत आदि में पाया जाता है। अति न्यूनतम और सदैव हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्टिका और ग्रीनलैंड मनुष्य के बसाव के लिए अनुपयुक्त है।

आद्रता और तापमान के संयुक्त प्रभाव से किसी देश की वनस्पति और जीव मंडल का निर्धारण होता है। अत्यधिक आर्द्रता और अत्यधिक शुष्कता देशों में कृषि उत्पादों को सीमित कर देता है जिसे मानव बसाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक आंध्र प्रदेश जैसे कि कांगो बेसिन अमेजॉन बेसिन में घने जंगल मिलते हैं और वर्षभर आर्द्रता की अधिकता रहने के कारण मानव के निवास के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार से अधिक शुष्कता भी मनुष्य बसाव को प्रभावित करती है। इसी प्रकार अधिक शुष्क प्रदेश जैसे कि अफ्रीका में सहारा, कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब थार और गोबी मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल,दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल लगभग निर्जन है वहां जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। वर्षा और जनसंख्या में सीधा संबंध पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर सामान्यत : घटता जाता है।

मिट्टी :– मिट्टी आरंभ से ही मनुष्य के बसाव को आकर्षित करती रही है। जितनी भी आरंभिक सभ्यताएं थी, वो वह उन्हीं जगह पर फली फूली जहां पर उपजाऊ मिट्टी थी। मिट्टी कृषि और अन्य वनस्पति को उपजाने में सहायक होती है। सभी प्राणी जगत इन्हीं वनस्पतियों पर आधारित होता है। अत्याधिक उपजाऊ मिट्टी जैसे काली

मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी आदि के स्थान पर मनुष्य बस्तियों का जमाव केवल कृषि के कारण हुआ।

आज भी किसी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी, तटीय जलौढ़ मिट्टी और काली मिट्टी पर मनुष्य का बसाव सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी अधिक मानव बसाव को प्रोत्साहित करती है। भारत के उत्तरी मैदान, तटीय भागों और काली मिट्टी में मानव सांदरण अधिक और लैटेराइट,पीली मिट्टी और लाल मिट्टी वाले दक्षिण पठार और हिमालय की कम विकसित मिट्टी पर जनसंख्या का केन्द्रण कम पाया जाता है।

टिप्पणी

स्थलाकृति :– किसी भी प्रदेश की जनसंख्या वहां की स्थलाकृति पर निर्भर करती है। पहाड़ी,पथरीली और पठारी भागों में जनसंख्या कम निवास करती है मैदानों और तटीय प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। मैदानों की आकृति समतल होने के कारण कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के साधनों, उद्योग धंधों, परिवहन के साधनों का जाल, व्यापार से सम्बंधित सुविधाएं जैसे बीमा और बैंक आदि पाया जाता है। इसी वजह से विश्व के प्रमुख देशों में उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या का सबसे अधिक केंद्रण पाया जाता है।

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान में, चीन के ह्वांगहो नदी, यंगटिसीक्यांग और टिसीक्यांग के मैदान में, यूरोप में राइन,डेन्यूब, सीन,वोल्गा और अमेरिका में मिसिसिपी नदी के मैदान में सघन पाई जाती है।

इसके विपरीत उबड़ खाबड़ पार्वती भागों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। केवल कुछ घाटियों में और जहां पर बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाया जाता है वहीं पर मनुष्य का निवास स्थान पाया जाता है। जैसे रॉकी और यूराल पर्वत में उपयोगी खनिज पदार्थ के स्रोत्र के निकट अधिवासों का का विकास हुआ है।

खनिज पदार्थ:– औद्योगिक क्रांति के बाद खनिज पदार्थों की उपलब्धि ने जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित किया है। सोना,चांदी,हीरा प्लेटिनम,तांबा,लोहा बॉक्साइट जस्ता अति महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है और यह विश्व में कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं। कोयला पेट्रोलियम थोरियम यूरेनियम आदि शक्ति के साधन है जिनके द्वारा उद्योग और परिवहन को संचालित किया जाता है। यूरोप के जिन भागों में लोहा या कोयला या अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या सगन पाई जाती है इसी कारण से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के शुष्क भागों में पेट्रोलियम पदार्थ के मिलने से जनसंख्या के बसाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि ऐसी वायुमंडलीय दशाएं मनुष्य की बसाव को हतोत्साहित करती हैं। ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात आदि इस प्रकार की उदाहरण है जहां पर शुष्क होने के बावजूद जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में कालगुर्ली और कुलकर्दी के विश्व प्रसिद्ध खाने मिलने से नगरों का विकास हुआ है।

जलाशय :– मनुष्य को अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जल उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में पर्याप्त जनसंख्या पाई जाती है। यही कारण था कि प्राचीन समय में प्रमुख नदि घाटियों में मनुष्य का जमावड़ा पाया गया। नदिया पीने के पानी के अलावा यातायात के साधन के रूप में भी इस्तेमाल

टिप्पणी

की जाती थी। इसलिए प्राचीन सभ्यता के बहुत सारे नगर की नदियों के किनारे पर बसे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल कालीबंगा आदि भारत में नदी के किनारे बसने वाले शहर थे। आधुनिक काल में भी सठिया किनारों पर बड़े–बड़े नगर पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख पतनों पर बड़े–बड़े नगर जैसे कि न्यूयॉर्क सन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, लंदन टोक्यो, शंघाई, कोलकाता, सिंगापुर, चेन्नई, मुंबई आदि इसके उदाहरण हैं।

रेगिस्तान में भी केवल कुछ दलालों के निकट की जनसंख्या का सांद्रण पाया जाता है। पर्वतों पर भी प्राकृतिक स्रोतों के पास जनसंख्या का बसाव पाया जाता है।

स्थिति व अभिगम्यता :– किसी स्थल या समुंदर के संदर्भ में सीधी पर कई प्रकार की हो सकती है जैसे मध्यप्रदेशीय,महाद्वीपीय, सागर तटिय, द्वीपीय, गिरिपदीय, अंतरपर्वतीय आदि। सापेक्षिक स्थिति का मतलब किसी प्रदेश के सम्बन्ध में स्थिति से है। किसी प्रदेश की अभिगम्यता से मतलब है उस प्रदेश का अनेक स्थानों से सुगम में होना। जो प्रदेश जितने अधिक स्थानों से जुड़ता है, वह उतना ही जनसंख्या को आकर्षित करता है। किसी प्रदेश में आवागमन की सुविधा जितनी अधिक होगी और प्रदेश उतनी ही जनसंख्या को आकर्षित करेगा। समतल मैदान रेल मार्ग,सड़क मार्ग और नहर आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। अधिक दुर्गम पर्वतीय स्थानों पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाना मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए वे अधिक अगम्य होते हैं। विश्व में तटीय भागों में बड़े–बड़े नगर पाए जाते हैं, क्योंकि वे अधिक स्थानों से जुड़े होते हैं और व्यापार का केन्द्र बन जाते है।

2. मानवीय कारक

किसी प्रदेश की जनसंख्या को प्रभावित करने में मानवीय कारक जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक और आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं।

आर्थिक कारक :– मनुष्य अपनी जीविका को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। पशुपालन कृषि उद्योग खनन व्यापार परिवहन आखेट और अनेक प्रकार की विविध सेवाएं मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल होती हैं। विश्व के जिस भाग में इन क्रिया कलापों में कोई भी क्रिया अधिक विकसित होती है वहीं पर मनुष्य का केन्द्रण पाया जाता है । भारत के उत्तरी मैदान और चीन के डेल्टाई भागों में कृषि के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है।

औद्योगिक विकास ने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनसंख्या शहरों में प्रवास करती है और शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है यहां पर रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। आर्थिक रूप से विकसित यूरोपीय देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीटजरलैंड, जर्मनी,निदरलैंड आदि में औद्योगिक विकास अधिक होने से यहां से तैयार पदार्थ विश्व के हर भाग में पहुंचता है और विश्व के पिछड़े देशों से भोजन के रूप में सामग्री इन देशों में आती है। यहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और इसी कारण से दूसरे देशों से जनसंख्या यहां पर प्रवास करती है।

राजनितिक कारक :– सरकारी नीतियां जनसंख्या के घनत्व वितरण को प्रभावित करने में कारगर होती हैं। प्रत्येक देश की अपनी अपनी नीति होती है। कई बार

टिप्पणी

कुछ देश प्रवास पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो वहां की जनसंख्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यूरोप के कुछ भागों में जनसंख्या के प्रवास पर नियंत्रण नहीं था, जिससे उन देशों में जनसंख्या बढ़ने लगी। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात सभी राष्ट्रीय सरकारों ने आप्रवास पर नियंत्रण लगा दिया है। कई बार कुछ राजनैतिक कारणों से भी जनसंख्या के प्रवास में उल्लेखनीय वृद्धि पाई जाती है। सन 1947 में भारत–पाकिस्तान विभाजन इसका एक अनूठा उदाहरण था जहां पर करोड़ों की संख्या में जनसंख्या का प्रवास हुआ।

सामाजिक और सांस्कृतिक कारक :– जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक विश्वास, जीवन मूल्य, सामाजिक संगठन, वर्ग, भेद आदि का प्रभाव पड़ता है। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक मान्यता और धार्मिक विश्वास के कारण परिवार नियोजन पर प्रतिबंध होने के कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। विभिन्न मुस्लिम देश और विकासशील देशों में सामाजिक अवरोधों के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। धार्मिक विश्वास और सामाजिक परंपराओं की वजह से कई बार जनसंख्या के स्थानांतरण पर भी प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों या अल्पविकसित देशों के लोग रोजगार और अच्छे जीवन यापन के लिए यूरोपीय और अमेरिकी देशों में प्रवास करते हैं।

जनांकिकीय कारक :– जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नगरीकरण प्रवास आदि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत और चीन जैसे विशाल देशों में प्रकृति की वृद्धि से जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले 50 वर्षों से जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर प्रतिबंध होने से भी जनसंख्या बढ़ रही है। विकासशील देशों में मृत्यु दर में चिकित्सा सुविधाओं से कमी आई है परन्तु जन्म दर ऊंच बनी रहने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

विश्व के विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश (जर्मनी, फ्रांस, स्विड़न, इटली, नींदरलैंड आदि) जापान, ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण होने की वजह से वहां जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक गई है। कम विकसित एशियाई और अफ्रीकी देशों में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम होने की वजह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई है।

नगरों में औद्योगिक विकास से जनसंख्या गांव से नगरों की ओर प्रवास करती है जिससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है और घनत्व बढ़ जाता है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. इनमें से क्या जनसंख्या घनत्व का प्रकार नहीं है?

   (क) कायिक घनत्व (ख) आर्थिक घनत्व

   (ग) कृषि घनत्व (घ) मार्मिक घनत्व

4. मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए कैसी क्रियाएं करता है?

   (क) सामाजिक (ख) पारिवारिक

   (ग) आर्थिक (घ) मनोरंजक

2.4 जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि के पारंपरिक, आधुनिक सिद्धांत एवं जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत

टिप्पणी

जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण के सिद्धांतों को क्रमशः इस प्रकार विवेचित किये जा सकते हैं–

2.4.1 पारंपरिक सिद्धांत

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से प्रथम विश्वयुद्ध 1918 के अंत तक शास्त्रीय और नव–शास्त्रीय विचारधारा के स्कूलों ने जनसंख्या सिद्धांत के विकास में बहुत योगदान दिया।

शास्त्रीय विचारधारा की स्थापना एडम स्मिथ ने की थी इसमें डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस (1798), जॉन स्टुअर्ट मिल और जे.डी. सई इससे जुड़े थे। शास्त्रीय सिद्धांत इस धारणा पर आधारित था कि धन का उत्पादन, उपभोग और वितरण आर्थिक नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्राचीन मतानुसार, बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक संपत्ति थी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर में सुधार होता है और दूसरे मत अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पादन में कमी आई लेकिन शुद्ध उत्पादन पर जनसंख्या का प्रभाव का मूल्यांकन करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को उत्पादन के दोनों पहलुओं उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए मुद्दा यह है कि क्या जनसंख्या वृद्धि, जबकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या एक साथ आनुपातिक आपूर्ति और मांग में वृद्धि हो रही है। हालांकि शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने ह्रासमान प्रतिफल के सिद्धांत को स्वीकार किया जैसा कि बुनियादी आर्थिक नियम है और इसे एक प्राकृतिक नियम का दर्जा दिया है।

जनसंख्या और उत्पादन के बीच संबंधों पर दो स्तरों अनुभवजन्य और सैद्धांतिक पर विवाद जारी रहा। हालांकि बहुमत ने घटते प्रतिफल के सिद्धांत को स्वीकार किया। कुछ अर्थशास्त्रियों–बर्न एंड विर्थ ने जोर देकर कहा कि लोगों की बढ़ती संख्या उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। जैसे–जैसे उन्नीसवीं सदी आगे बढ़ी, उत्पादन सिद्धांत में कई परिवर्तन हुए। स्क्रैप और रिचर्डो जैसे अर्थशास्त्री वर्तमान उत्पादन के सिद्धांत पर अडिग रह कर घटते उत्पादन प्रतिफल के सिद्धांत को झुठलाने पर अड़े रहे।

प्राचीन विद्वानों का यह मत था कि अच्छा जीवन बिताने के लिए किसी देश की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और अपनी रक्षा करने में समर्थ हो। तत्कालिक विचारक जनसंख्या को राज्य के लिए शक्ति का साधन मानते थे इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर नहीं थे। मध्यकालीन ईसाई विचारों की जनसंख्या को नीति का विषय मानते तो जनसंख्या नियमन के लिए अपनाए गए कृत्रिम साधनों जैसे बाल हत्या, गर्भपात आदि को अनैतिक व्यापार मानते थे। इन्होंने इसका जोरदार खंडन भी किया। संभवतः वे तत्काल एक महामारी और होने वाले युद्ध से बड़ी मात्रा में जनसंख्या ह्रास को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। यहां तक की जनसंख्या को कम करने का प्रश्न है इसके लिए वे इंद्रिय निग्रह, अविवाहित रहने को उचित मानते थे। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे, निर्देश दिए गए हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति के

टिप्पणी

अनुसार पुत्र के द्वारा ही पिता को नरक से मुक्ति मिलती है और उस माता–पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पुत्री के विवाह नहीं करता वह नर्क का भागीदार होता है। इसी तरह अन्यत्र वर्णन है कि पुत्र के जन्म से मनुष्य सभी लोगों में विजय प्राप्त करता है। पौत्र के जन्म से उसे अमरता और प्रपौत्र के जन्म से उसे सूर्य की प्राप्ति होती। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति, पुत्र और पुत्रियों के विवाह की अनिवार्यता प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं। प्राचीन यूनानी और रोमन दार्शनिकों ने जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्र के लिए हितकर बताया और अधिक जनसंख्या बढ़ने पर इसको रोकने के उपाय भी बतलाये। जनसंख्या कम करने के लिए अरस्तू और प्लेटो आदि दर्शनिकों ने जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए आत्म संयम को प्रोत्साहित किया और जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुत्र प्राप्ति होने पर दम्पति को पूरस्कृत करने का उपाय भी सुझाया था।

ईसाई अनुयायियों ने जनसंख्या के प्राकृतिक ह्रास, महामारियों, अकाल, युद्ध आदि के कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते थे। प्राचीन काल के विद्वान राज्य का विस्तार करने के लिए पुरुषों की संख्या को जरूरी मानते थे। सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जनसंख्या वृद्धि को आवश्यंक मानते थे और जनसंख्या वृद्धि करने के लिए कई उपाय सुझाते थे।

जनसंख्या विज्ञान का मूल जीवविज्ञान एवं अर्थशास्त्र में है। लेकिन हम जनसंख्या की अवधारणा का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में भी करते हैं। यहां, जगह और समय के संदर्भ में जनसंख्या के अध्ययन पर हमारा केन्द्रीयकरण है। जनसंख्या वृद्धि का परीक्षण करने के लिए अनेक अध्येताओं ने मानव सभ्यता के आरंभ से जनसंख्या पर अपने सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है। कुछ का तर्क है कि जनसंख्या विस्तार, पृथ्वी तल से अनेक सभ्यताओं के समाप्त हो जाने का कारक रहा है। जबकि अन्य लोगों का मानना है कि जनसंख्या की सतत् वृद्धि, मानव जाति, प्रजातियों एवं राष्ट्रों की उत्तरजीविता हेतु अनिवार्य है।

चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने जनसंख्या पर अपने सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि मानव और पर्यावरण के मध्य एक संख्यात्मक संतुलन अवश्य बनाए रखना चाहिए। वास्तव में, वही पहला व्यक्ति था जिसने जनसंख्या के अनुकूलतम स्तर की अवधारणा प्रदान की।

अनेक यूनानी दार्शनिकों ने भी जनसंख्या पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ ने जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया लेकिन कुछ अवरोधवादी विचारक थे, जनसंख्या की निरपेक्ष सीमा पर जिनका विश्वास था।

आरंभिक रोमन विचार, धार्मिक मिथकों पर आधारित थे। उनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि, सैन्य एवं राजनैतिक विस्तार के लिए आवश्यक है। उनका मत था कि विवाह का प्रमुख प्रकार्य राज्य को नागरिक और सैनिक प्रदान करना है।

मध्यकालीन युग, युद्धों, संघर्षों और घुसपैठों का युग था, जिसने इस धारणा को बल दिया कि जीवित रहने और प्रतिरक्षा के लिए जनसंख्या वृद्धि अनिवार्य है। अतः समाज में इसका विस्तार अनिवार्य था। 18वीं शताब्दी के दौरान अनेक प्रख्यात अध्येता उभरे। कुछ जाने-माने अर्थशास्त्रियों में थॉमस मॉल्थस, कोल्बर्टिज्म, डेविड रिकार्डो,

टिप्पणी

डार्विन और मार्क्स तथा एंजेल्स थे। थॉमस मॉल्थस पहला और सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था जिसने जनसंख्या सिद्धान्त को प्रस्तुत किया और अन्य सिद्धान्तों में से अधिकांश, डार्विन, वॉलेस और अन्य प्राकृतिक वैज्ञानिकों के उद्विकासीय सिद्धान्त मॉल्थस के कार्य से प्रेरित थे।

2.4.2 आधुनिक सिद्धांत

आधुनिक विद्वानों ने जनसंख्या से सम्बंधित सिद्धांत दिये हैं। उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना यहां की जा रही है।

• मालथस का जनसंख्या सिद्धांत :

थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध' में जनसंख्या के बारे में अपने विचारों को प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने पिता और गॉडविन द्वारा साझा किए गए प्रचलित आशावाद के खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि एक आदर्श राज्य हो सकता है, अगर मानवीय बाधाओं को दूर किया जा जाये तो।

माल्थस की आपत्ति थी कि खाद्य आपूर्ति पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव पूर्णता को नष्ट कर देगा और दुनिया में परेशानी आएगी । अपने निराशावादी विचारों के लिए माल्थस की कड़ी आलोचना की गई, जिसके कारण उन्हें अपनी थीसिस के समर्थन में डेटा इकट्ठा करने के लिए यूरोप महाद्वीप की यात्रा करनी पड़ी।

उन्होंने 1803 में प्रकाशित अपने निबंध के दूसरे संस्करण में अपने शोधों को शामिल किया। माल्थुसियन सिद्धांत खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध की व्याख्या करता है। इसमें कहा गया है कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह दुख की ओर ले जाता है।

माल्थुसियन सिद्धांत इस प्रकार कहा गया है:

(1) मनुष्य में तीव्र गति से बढ़ने की स्वाभाविक यौन प्रवृत्ति होती है। नतीजतन, जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ जाती है और अगर अनियंत्रित हो तो हर 25 साल में दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार 1 से शुरू होकर 25 वर्षों की क्रमिक अवधियों में जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 होगी।

(2) दूसरी ओर, भूमि की आपूर्ति स्थिर होने के अनुमान के आधार पर ह्रासमान प्रतिफल के संचालन के कारण धीमी अंकगणितीय प्रगति में खाद्य आपूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार क्रमिक समान अवधियों में खाद्य आपूर्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगी।

(3) चूंकि जनसंख्या ज्यामितीय गति से बढ़ती है और खाद्य अंकगणितीय गति से, जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से आगे निकल जाती है। इस प्रकार एक असंतुलन पैदा होता है जो अधिक जनसंख्या की ओर ले जाता है।

खाद्य आपूर्ति को क्षैतिज अक्ष पर और जनसंख्या को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखा गया है। वक्र एम माल्थुसियन जनसंख्या वक्र है जो जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता है। यह तेजी से ऊपर की ओर उठता है।

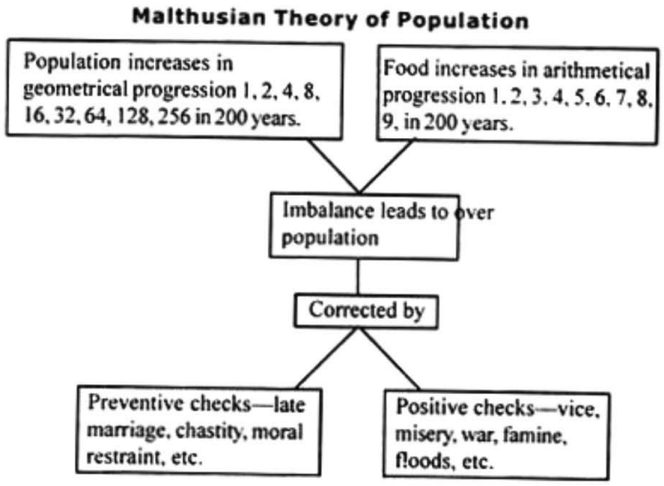

टिप्पणी

(4) जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, माल्थस ने प्रतिबंधात्मक और सकारात्मक नियंत्रक बताए। जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए एक आदमी द्वारा प्रतिबंधात्मक सुझाव हैं :–दूरदर्शिता, देर से विवाह, ब्रह्मचर्य, नैतिक संयम आदि।

यदि लोग निवारक सुझावों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने में विफल रहते हैं, तो सकारात्मक नियंत्रक जैसे बुराई, दुख, अकाल, युद्ध, बीमारी, महामारी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में कार्य करती है जो जनसंख्या को कम करते हैं। इस प्रकार खाद्य आपूर्ति के साथ ये संतुलन लाते हैं।

माल्थस के अनुसार, एक सभ्य समाज में निवारक नियंत्रक हमेशा प्रयोग में रहते हैं। माल्थस ने अपने देशवासियों से अपील की कि वे सकारात्मक नियंत्रकों के परिणामस्वरूप होने वाले दुखों से बचने के लिए निवारक नियंत्रक अपनाएँ।

19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत की व्यापक रूप से चर्चा और आलोचना हुई है।

कुछ आलोचनाएँ

(1) गणितीय रूप सही नहीं : माल्थस के सिद्धांत का गणितीय सूत्रीकरण है कि 25 वर्षों में अंकगणितीय प्रगति में खाद्य आपूर्ति बढ़ती है और ज्यामितीय प्रगति में जनसंख्या वृद्धि होती है। अनुभवजन्य रूप से यह बात सिद्ध नहीं हुई है बल्कि, खाद्य आपूर्ति में अंकगणितीय प्रगति की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है, जबकि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय प्रगति में नहीं रही है।

आलोचना तर्क से परे है क्योंकि माल्थस ने अपने निबंध के पहले संस्करण में अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपने गणितीय सूत्रीकरण का इस्तेमाल किया और अपने दूसरे संस्करण में इसे हटा दिया।

(2) संकीर्ण दृष्टि : माल्थस की दृष्टि संकीर्ण थी और वह विशेष रूप से इंग्लैंड में स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित था। वह ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और

टिप्पणी

अर्जेंटीना के नए क्षेत्रों के खुलने की भविष्यवाणी करने में विफल रहा, जहां अनुप्रयुक्त भूमि पर व्यापक खेती के कारण भोजन का उत्पादन बढ़ा।

नतीजतन, यूरोप महाद्वीप पर इंग्लैंड जैसे देशों को सस्ते भोजन की प्रचुर आपूर्ति प्रदान की गई है। यह परिवहन के साधनों में तेजी से सुधार के साथ संभव हुआ है, एक ऐसा कारक जिसे माल्थस ने लगभग अनदेखा कर दिया था। किसी भी देश को भूख और दुख के डर की जरूरत नहीं है अगर वह अपनी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त उत्पादन करता है।

(3) गलत अनुमान : समय की अवधि के लिए एक स्थिर आर्थिक कानून लागू किया। माल्थस समय के साथ वैज्ञानिक ज्ञान और कृषि आविष्कारों में अभूतपूर्व वृद्धि का सही अनुमान नहीं लगा सके। नतीजतन, खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है। माल्थस का सिद्धांत न केवल उन्नत देशों में बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों में भी 'हरित क्रांति' से गलत साबित हुआ है।

(4) जनसंख्या में जनशक्ति पहलू की उपेक्षा : माल्थस के विचार की प्रमुख कमजोरियों में से एक यह है कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि में जनशक्ति पहलू की उपेक्षा की। वह एक निराशावादी था और जनसंख्या में वृद्धि से डरता था। कन्नन के अनुसार, वह भूल गया कि ''एक बच्चा न केवल मुंह और पेट के साथ, बल्कि दो हाथों से भी दुनिया में आता है।''

इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ जनशक्ति में वृद्धि है जो न केवल कृषि बल्कि औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ा सकती है और इस प्रकार देश को धन और आय के समान वितरण से समृद्ध बनाती है।इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि आवश्यक हो सकती है।

(5) जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से नहीं बल्कि कुल संपत्ति से संबंधित है : माल्थुसियन सिद्धांत जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच कमजोर संबंध पर आधारित है। वास्तव में, सही संबंध देश की जनसंख्या और कुल संपत्ति के बीच है। यह जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का आधार है। तर्क यह है कि यदि कोई देश भौतिक रूप से समृद्ध है और यदि वह अपनी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन नहीं करता है, तो वह अपने उत्पादों या धन के बदले खाद्य सामग्री आयात करके लोगों को अच्छी तरह से खिला सकता है।

उत्कृष्ट उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का है जो अपनी लगभग सभी खाद्य आवश्यकताओं के लिए हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और अर्जेंटीना से आयात करता है क्योंकि यह खाद्य उत्पादों के बजाय धन के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार माल्थुसियन सिद्धांत का आधार ही गलत साबित हुआ है।

(6) जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु दर में गिरावट का परिणाम : माल्थुसियन सिद्धांत एकतरफा है। यह बढ़ती जन्म दर के परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि लेता है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट के कारण दुनिया भर में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। माल्थस चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उस अद्भुत प्रगति की कल्पना नहीं कर सकता था जिसने घातक बीमारियों को नियंत्रित किया है और मानव जीवन को लंबा बना दिया

है। भारत जैसे अविकसित देशों में विशेष रूप से ऐसा रहा है जहां माल्थुसियन सिद्धांत को संचालित बताया जाता है।

टिप्पणी

(7) अनुभवजन्य साक्ष्य इस सिद्धांत को गलत साबित करते हैं : अनुभवजन्य रूप से, जनसांख्यिकीविदों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय के स्तर का एक कार्य है। जब प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ती है, तो यह प्रजनन दर को कम करती है और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आती है। ड्यूमॉन्ट की ''सामाजिक केशिका थीसिस'' ने साबित कर दिया है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ, माता–पिता की आय के पूरकता के लिए अधिक बच्चे पैदा करने की इच्छा कम हो जाती है।

जब लोग उच्च जीवन स्तर के आदी हो जाते हैं, तो एक बड़े परिवार का पालन–पोषण करना एक महंगा मामला बन जाता है। जनसंख्या स्थिर हो जाती है क्योंकि लोग अपने जीवन स्तर को कम करने से इनकार करते हैं। यह वास्तव में जापान, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों के मामले में हुआ है।

(8) नियंत्रक प्रतिबन्ध नैतिक संयम से संबंधित नहीं है : माल्थस अनिवार्य रूप से एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नैतिक संयम, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह आदि पर जोर दिया। लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि मनुष्य जन्म नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधकों और अन्य परिवार नियोजन उपकरणों का आविष्कार करेगा।

लोगों में यौन इच्छा तो होती है लेकिन वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। परिवार नियोजन एक निवारक प्रतिबन्ध के रूप में आवश्यक है।

(9) अधिक जनसंख्या के कारण सकारात्मक नियंत्रक नहीं : माल्थस के निराशावाद और धार्मिक शिक्षा ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अधिक जनसंख्या पृथ्वी पर एक भारी बोझ है जिसे भगवान ने दुख, युद्ध, अकाल, बाढ़, रोग, महामारी आदि के रूप में स्वतः ही कम कर दिया था। लेकिन ये सभी प्राकृतिक हैं। आपदाएं जो अधिक आबादी वाले देशों के लिए विशिष्ट नहीं हैं। वे उन देशों में भी आती हैं जहां जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, जैसे फ्रांस और जापान।

(10) माल्थस एक झूठा पैगंबर : माल्थुसियन सिद्धांत उन देशों पर लागू नहीं होता जिनके लिए यह प्रतिपादित किया गया था। पश्चिमी यूरोप के देशों में माल्थस के हौसले और निराशावाद पर काबू पा लिया गया है। उनकी यह भविष्यवाणी कि यदि वे निवारक साधनों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को रोकने में विफल रहते हैं, तो दुख इन देशों का पीछा करेगा। जन्म दर में गिरावट, खाद्य आपूर्ति की पर्याप्तता और कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से गलत साबित हुआ है। इस प्रकार माल्थस एक झूठा पैगंबर साबित हुआ।

माल्थस सिद्धांत की प्रयोज्यता :

कमजोरियों के बावजूद, माल्थुसियन सिद्धांत में बहुत सच्चाई है। माल्थुसियन सिद्धांत पश्चिमी यूरोप और इंग्लैंड पर लागू नहीं हो सकता है लेकिन इसके प्रमुख उपकरण इन देशों के लोगों का हिस्सा बन गए हैं।

टिप्पणी

वास्तव में, यूरोप के लोगों को माल्थस द्वारा समझदार बनाया गया था, जिन्होंने उन्हें अधिक जनसंख्या की बुराइयों से आगाह किया था और उन्होंने इसके लिए मापक अपनाने शुरू कर दिये थे । तथ्य यह है कि लोग व्यापक पैमाने पर देर से विवाह और विभिन्न गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण उपायों जैसे निवारक साधनों का उपयोग करने लगे।

मार्शल और पिगौ जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और डार्विन जैसे समाजशास्त्री भी इस सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्होंने इसे अपने सिद्धांतों में शामिल किया। कीन्स, शुरू में अति–जनसंख्या के माल्थसियन भय से भयभीत थे, बाद में उन्होंने ''गिरावट जनसंख्या के कुछ आर्थिक परिणाम'' के बारे में लिखाः क्या यह माल्थुसियनवाद का डर नहीं है जिसने फ्रांस में घटती जनसंख्या की समस्या पैदा की है?

माल्थुसियन सिद्धांत अब अपने मूल स्थान पर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इस ब्रह्मांड के दो–तिहाई हिस्से में फैला हुआ है। जापान को छोड़कर पूरा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इसके दायरे में आता है। भारत जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाने वाले पहले देशों में से एक है। बाढ़, युद्ध, सूखा, रोग आदि जैसे सकारात्मक नियंत्रक काम करते हैं। जन्म और मृत्यु दर अधिक है। जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

हालाँकि, जनसंख्या नीति का वास्तविक उद्देश्य भुखमरी से बचना नहीं है, बल्कि गरीबी को खत्म करना है ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादन को त्वरित तरीके से बढ़ाया जा सके। इस प्रकार माल्थुसियन सिद्धांत भारत जैसे अविकसित देशों पर पूरी तरह से लागू होता है। वॉकर सही थे जब उन्होंने लिखाः ''माल्थुसियन सिद्धांत सभी समुदायों पर रंग और स्थान पर विचार किए बिना लागू होता है। अपने चारों ओर फैले सभी विवादों के बीच माल्थुसियनवाद अटूट व अभेद्य है।"

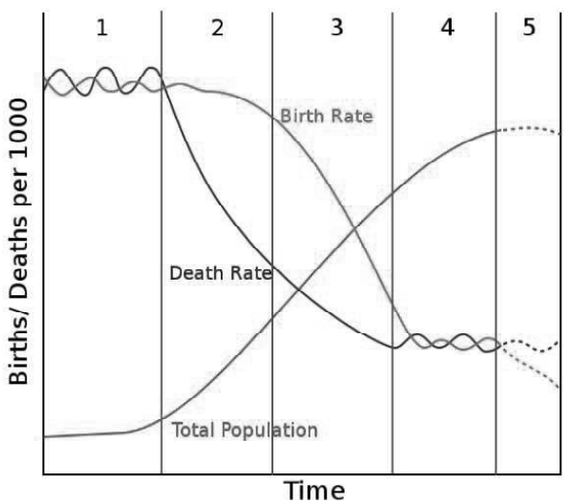

- **जैविक सिद्धांत :**

जैविक सिद्धांत मुख्य रूप से मानव प्रजनन क्षमता से संबंधित हैं।

टिप्पणी

सामान्य तौर पर जनसांख्यिकीविदों ने किसी भी जैविक सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है।

जनसंख्या वृद्धि के रूप में अधिकांश जैविक सिद्धांतवादी प्रकृति की नैसार्गिक इच्छा प्रजातियों के अस्तित्व को कायम रखने की मानते हैं। यह जनसांख्यिकीय विद्वान् स्वीकार नहीं कर सकते।

- **घनत्व सिद्धांत :**

माइकल थॉमस सैडलर (1730–1835), एक अंग्रेज राजनीतिक, अर्थशास्त्री थे। ''जनसंख्या के सिद्धांत'' नामक अपने विशाल उदारवादी कार्य में वे खुद को माल्थुसियन सिद्धांत के समकक्ष मानते थे। उन्होंने जनसंख्या सिद्धांत में स्वतंत्र रूप से योगदान दिया।उन्होंने जनसंख्या का घनत्व के अध्ययन के दौरान नीदरलैंड्स में उर्वरता और घनत्व दोनों को उच्च पाया।

सैडलर ने स्पष्ट अंतर्विरोध की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के बीच प्रत्यक्ष संबंध मौजूद होता है । वहीं पर विपुलता अधिक होती है,जहां मृत्यु दर अधिक है। प्रजनन क्षमता में वृद्धि,बढ़ती मृत्यु दर के कारण है। सैडलर के सिद्धांत के अनुसार हालांकि घनत्व बढ़ रहा है जिससे प्रजनन क्षमता कम होती है लेकिन मृत्यु दर बढ़ जाती है, जो बदले में प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है।

इस तरह के तर्क से सामंजस्य बैठाना मुश्किल है।

- **आहार सिद्धांत :**

1841 में एक और अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस डबलडे (1790–1870) ने जनसंख्या के वास्तविक नियम को प्रतिपादित किया, जिसने जनसंख्या वृद्धि और लोगों के आहार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया।

डबलडे के अनुसार गरीबी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि गरीबों का आहार अपर्याप्त है। उन्होंने अपने सिद्धांत को जानवरों की दुनिया के बारे में प्रसिद्ध तथ्य पर आधारित किया।

खरगोश और सूअर ''अगर मोटापे की एक निश्चित सीमा तक खिलाए जाते हैं तो गर्भ धारण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांस में जन्म दर कम थी क्योंकि फ्रांसीसियों को अच्छी तरह से खिलाया गया था।

1952 में, जोसु डी कास्त्रो ने अपनी पुस्तक ''भूख का भूगोल'' में केंद्रित किया कि प्रोटीन की कमी कुपोषित लोगों को उन लोगों की तुलना में अधिक उपजाऊ बनाती है जो अच्छी तरह से पोषित हैं। उन्होंने अपने निष्कर्षों को आहार में प्रोटीन सामग्री और विभिन्न देशों की जन्म दर के बीच नकारात्मक संबंधों पर आधारित किया।

समाजवादी लेखकों ने सामान्य रूप से सभी मानवीय दुखों को पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में देखा और दावा किया है कि यदि उनके द्वारा सुझाए गए सुधार लागू करने से लोगों की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और बेरोजगारी और अधिक जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी।

टिप्पणी

मार्क्स और एंगेल्स का विचार

प्रारंभिक समाजवादी लेखक जनसंख्या के प्रश्नों से चिंतित थे लेकिन उनके विचार स्पष्ट नहीं थे। जनसंख्या समस्या के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण तैयार करने का श्रेय मार्क्स और एंगेल्स को दिया जा सकता है।

माल्थुसियन सिद्धांत को मार्क्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि समाजवादी समाज में उनके विचार फिट नहीं थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मार्क्स और एंगेल्स ने कोई जनसंख्या सिद्धांत तैयार नहीं किया, उन्होंने केवल बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिसके अनुसार विश्व जनसंख्या के आकार और उसके सामाजिक–आर्थिक सहसंबंधों का निर्धारण होता है। मार्क्स ने माना कि जनसंख्या वृद्धि का कोई प्राकृतिक सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है और जोर देकर कहा : ''उत्पादन के हर ऐतिहासिक तरीके के अपने विशेष कानून होते हैं जिसके अंदर जनसंख्या और इसकी सीमा तय होती है।

उनके अनुसार ''पौधों और जानवरों के लिए जनसंख्या का अमूर्त नियम मौजूद है।'' केवल और केवल इसलिए क्योंकि मनुष्य ने उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया है''। एंगेल्स ने मार्क्स के विचारों का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी एक बात और जोड़ दी।

उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, अधिशेष आबादी अधिशेष पूंजी के साथ जुड़ी हुई है और पूंजीवाद में निहित इस अंतर्विरोध पर केवल समाजवादी ''पुनर्गठन'' द्वारा काबू पाया जा सकता है।

जन्म नियंत्रण पर समाजवादी विचार

अच्छे समाज के मार्क्सवादी विचार साम्यवाद में प्रतिपादित विवाह के घोषणापत्र में निहित हैं। एंगल्स ने कौत्स्की को लिखे एक पत्र में ''अमूर्त संभावना'' के बारे में लिखा था कि एक साम्यवादी समाज में व्यक्तियों को सचेत नियंत्रण द्वारा जनसंख्या को सीमित करना पड़ सकता है।

मार्क्सवादियों का विचार है कि समाजवादी समाज में प्रजनन व्यवहार व्यक्ति और समाज के बीच पूर्ण सामंजस्य विकसित कर लेता है । हालांकि वे आम तौर पर जन्म नियंत्रण के साधनों को गरीबी से बचने के लिए प्रयोग करने को अनुचित मानते थे। आधुनिक समाजवादियों का मत है कि जन्म नियंत्रण ''खुश मातृत्व और रचनात्मकता के सामंजस्य द्वारा महिलाओं की मुक्ति में योगदान देता है। यहाँ तक कि गर्भपात की भी यूरोप के आधुनिक समाजवादी देशों में अनुमति है।

• गणितीय सिद्धांत

तथ्य परक कानून और संबंधित सिद्धांत के द्वारा गणित में विकसित तकनीकों ने जनसंख्या वृद्धि के गणितीय नियम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनसंख्या पर डेटा की उपलब्धता ने इन सिद्धांतों के सत्यापन की सुविधा प्रदान की।

बेल्जियम के खगोलशास्त्री क्वेटलेट ने सबसे पहले गणितीय दृष्टिकोण जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। गणितीय सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सयुंक्त राज्य अमेरिका के वेरहुल्स्ट, पर्ल और रिड द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित

टिप्पणी

जनसंख्या के लॉजिस्टिक विकास का सिद्धांत था। पर्ल और रीड के लॉजिस्टिक कानून के अनुसार सीमित क्षेत्र या ब्रह्मांड में जनसंख्या की वृद्धि चक्रिय रूप में होती है और आधे चक्र तक धीरे–धीरे जनसंख्या बढ़नी शुरू होती है, लेकिन समय की प्रति इकाई पूर्ण गति चक्र के मध्य बिंदु तक पहुंचने तक बढ़ जाती है। कुल जनसंख्या लॉजिस्टिक के सिद्धांत के अनुसार, एस–शेप्ड प्राप्त करती है।

इस सिद्धांत की मुख्य रूप से सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर आलोचना की गई है। यह सिद्धांत जनसंख्या को अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग दोहन करने की अनुमति देता है। प्रजनन व्यवहार से सम्बंधित आकांक्षाओं और प्रेरणाओं में परिवर्तन पर विचार नहीं करता है।

2.4.3 जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत

जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म–दर और उच्च मृत्यु–दर से निम्न जन्म–दर व निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। प्रारंभ में ये तीन अवस्थाएं थीं–

1. **प्रथम अवस्था** : उच्च प्रजननशीलता में उच्च मर्त्यता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से पीड़ित थे। जीवन–प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं।
2. **द्वितीय अवस्था** : द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है।
3. **तीसरी अवस्था** : तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है व उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है।

जनसंख्या संक्रमण मॉडल को थॉमसन एवं नौटेस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह जनसंख्या संबंधी प्रमुख अवधारणा है। इसे यूरोपीय जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर दिया गया था।

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार प्रत्येक समाज और राष्ट्र में जनसंख्या की विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जो मुख्यतः जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर से निर्धारित होती है।

इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या संरचना की प्रत्येक अवस्था जनसंख्या संक्रमण (Population transition) की अवस्था होती है। यह किसी समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक–आर्थिक स्थिति या दशा पर निर्भर करती है।

संक्रमण की प्रारंभिक तीन अवस्थाओं में संशोधन कर वर्तमान में चार अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है, परंतु विकसित देशों की प्रवृत्तियों के आधार पर पांचवीं अवस्था भी निर्धारित की गई है।

टिप्पणी

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की अवस्थाएं (Stages of the Demographic Transition Model (DMT))

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार जनसंख्या संक्रमण की चार अवस्थाएं होती हैं–

- उच्चस्थायी अवस्था
- प्रारंभिक जनसंख्या विस्फोट की अवस्था
- उत्तरार्द्ध में वृद्धि की अवस्था
- आदर्श निम्न स्थायी अवस्था
- पांचवीं अवस्था–प्रजाति विनाश की अवस्था

1. उच्च स्थायी अवस्था

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की प्रथम अवस्था उच्च स्थायी अवस्था होती है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 30–40 प्रति हजार के मध्य होती है। ऐसे में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती और इसमें स्थायित्व बना रहता है।

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की प्रथम अवस्था वाली दशा किसी भी समाज या राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन को बताती है। अल्पविकसित औद्योगिक पूर्व कृषि प्रधान परंपरावादी समाज और पारंपरिक अर्थव्यवस्था की स्थिति में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का स्तर उच्च होता है।

सामाजिक पिछड़ेपन के कारण समाज परंपरावादी, रूढ़िवादी, प्राचीन मान्यताओं पर आधारित और मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है। यहां बच्चे को ईश्वर की देन और पुरुष बच्चे को वंश का आधार जैसी मान्यताएं स्थापित होती हैं। साक्षरता का निम्न स्तर, वैज्ञानिकता का अभाव सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होता है। इससे जन्म दर उच्च बनी रहती है।

दूसरी ओर आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खाद्य पोषाहार की समस्याएं, भुखमरी, गरीबी, महामारी जैसे कारणों से मृत्यु दर उच्च होती है। ऐसे समाज में जीवन प्रत्याशा अत्यंत कम होती है। ये परिस्थितियां उच्च जन्म दर के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि नहीं होने देतीं और जनसंख्या में स्थिरता बनी रहती है।

वर्तमान में प्रथम अवस्था में विश्व के किसी भी देश को नहीं माना जा सकता। विषुवतीय अफ्रीकी देश तथा अल्पविकसित एशियाई देश प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश इस अवस्था में लंबे समय से बने हुए थे। लेकिन वर्तमान में इन देशों में भी आर्थिक–सामाजिक विकास की प्रक्रिया के क्रमशः तीव्र होने के कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित हो चुका है।

भूमंडलीकरण के कारण इन पिछड़े देशों में वैश्विक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साक्षरता शिक्षण–प्रशिक्षण और जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिससे इस अवस्था से बाहर निकला जा सकता है।

टिप्पणी

2. प्रारंभिक जनसंख्या विस्फोट की अवस्था

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की प्रथम अवस्था के बाद दूसरी 'प्रारंभिक जनसंख्या विस्फोट की अवस्था' उत्पन्न होती है। इसमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास प्रारंभ होता है और खाद्य पोषाहार की समस्या का समाधान होने लगता है।

ऐसे में जीवन स्तर में अपेक्षाकृत सुधार होता है। परिणामस्वरूप मृत्यु दर में कमी आने लगती है और यह घटकर लगभग 20 प्रति हजार तक हो जाती है। लेकिन सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने के कारण सामाजिक पिछड़ापन बना रहता है। ऐसे में समाज की परंपरावादी रूढ़िवादी मान्यताएं जन्म दर को पूर्ववत बनाए रखती हैं अतः जन्म दर लगभग 30–40 प्रति हजार बनी रह जाती है। ऐसे में प्राकृतिक वृद्धि दर तीव्र हो जाती है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है।

भारत 1951 के बाद इस अवस्था में 2001 तक बना रहा। चीन भी इस अवस्था में लंबे समय तक बना रहा। वास्तविक अर्थ में दूसरी अवस्था विकासशील समाज और राष्ट्र की अवस्था होती है। वर्तमान में भारत इस अवस्था से बाहर निकल चुका है और जनगणना 2011 के अनुसार इसे तीसरी अवस्था का प्रारंभ माना जा रहा है।

भारत में जनांकिकीय अभिलक्षणों में सुधार का कारण क्रमशः आर्थिक–सामाजिक विकास की प्रक्रिया का तीव्र होना है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत आर्थिक–सामाजिक विकास शिक्षा जागरूकता विशेषकर महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी की नीति, विशेष आरक्षण और महिलाओं के पक्ष में सूचनाओं का प्रसारण जैसे उपायों पर बल देने के साथ ही लिंग परीक्षण पर कानूनी रोक और कठोर कार्रवाई का प्रावधान जैसे उपायों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है।

इससे लिंगभेद को समाप्त कर जहां एक ओर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। भारत में जनसंख्या नियंत्रण की इस नीति को ही, 'केरल मॉडल' के नाम से जाना जाता है।

3. उत्तरार्द्ध में वृद्धि की अवस्था

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की द्वितीय अवस्था के बाद क्रमशः सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी तीव्र होती है जिससे जनसंख्या में जागरूकता उत्पन्न होती है। साक्षरता में वृद्धि और लिंग समानता के कारण जननांकीय लक्षणों में सुधार होता है और मृत्यु दर के अनुरूप क्रमशः जन्म दर में भी कमी आने लगती है और तीसरी अवस्था के अंत तक यह घटकर लगभग 20 प्रति हजार तक हो जाती है।

इस समय मृत्यु दर में और नियंत्रण स्थापित हो जाता है जो लगभग 10 प्रति हजार तक आ जाती है। नवीन विकसित समाज और देश इसी अवस्था में होते हैं। यूरोपीय देश भी जनसंख्या विस्फोट के बाद इस अवस्था से गुजरे हैं। वर्तमान में चीन, भारत तथा कई विकासशील देश इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं।

जिस देश की आधार जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में अधिक बड़ी हो जाती है वहां जन्म दर में नियंत्रण के बावजूद दीर्घकाल तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। चीन और भारत में ऐसा देखा जा सकता है।

टिप्पणी

4. आदर्श निम्न स्थायी अवस्था

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की तीसरी अवस्था के बाद चौथी अवस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया आर्थिक विकास के समान ही तीव्र और प्रभावशाली हो जाती है। आर्थिक–सामाजिक दोनों स्तरों पर राष्ट्र और समाज पूर्ण विकसित हो जाता है।

साक्षरता का उच्च स्तर, उच्च नगरीकरण, उच्च औद्योगिकीकरण, तकनीकी क्रांति, प्रति व्यक्ति आय का अति उच्च स्तर जैसी दशाएं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर देती हैं और जनसंख्या में स्थायित्व आ जाता है।

इस अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों लगभग 10 प्रति हजार से कम हो जाती हैं। जन्म दर का स्तर मृत्यु दर से थोड़ा अधिक होता है और जनसंख्या में वृद्धि स्थिरता के साथ होती है। सभी विकसित देश और विकसित समाज इसी अवस्था में होते हैं। विश्व के सभी विकसित देश इस अवस्था में प्रवेश कर लंबे समय तक बने रहते हैं।

5. प्रजाति विनाश की अवस्था

जनांकिकीय संक्रमण के मॉडल के अनुरूप ही अधिकांश देशों और समाजों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखी गईं लेकिन विकसित देशों में एक नवीन प्रवृत्ति सामने आई है जो ऋण जनसंख्या वृद्धि के रूप में मिलती है। इसमें जनसंख्या में लगातार कमी की स्थिति बनी हुई है अर्थात जनसंख्या में वृद्धि की जगह कमी आ रही है। इस अवस्था को ही क्लार्क महोदय ने प्रजातीय विनाश की अवस्था कहा और इसी आधार पर इस जनांकिकीय संक्रमण मॉडल की आलोचना भी की।

क्लार्क ने माना कि इस अवस्था की कल्पना थॉमसन एवं नोटेस्टीन ने जनांकिकीय संक्रमण मॉडल में नहीं की। यह अवस्था विकसित समाज की उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी और अधिक स्वतंत्रता अर्थात स्वच्छंद प्रवृत्तियों से निर्धारित होती है। उच्च जीवन स्तर और उच्च प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में समाज भौतिकतावादी हो जाता है, जिससे परिवार जैसी संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं।

विवाह के प्रति नकारात्मक सोच, बच्चे के जन्म के प्रति निराशा, जिम्मेदारियों को उठाने से बचना और निजी जीवन को विशेष महत्व देना जैसे कारक जन्म दर को हतोत्साहित करते हैं। स्त्री–पुरुष के संबंधों में सहज जीवन की अवधारणा से भी बच्चों के जन्म के प्रति नकारात्मक नजरिए का विकास होता है।

ऐसे में जन्म दर में तीव्रता से कमी आने लगती है। यह स्थिति ही प्रजातीय विनाश का कारण है। ऐसे समाज में तलाक जैसी घटनाएं सामान्य होती हैं। इससे भी वैवाहिक संबंधों में बच्चे के जन्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती। ये विकसित समाज में उत्पन्न ऐसी स्थितियां हैं, जिनकी कल्पना जनांकिकीय संक्रमण मॉडल में नहीं की गई थी और यह आलोचना का कारण भी बना।

जनांकिकीय संक्रमण मॉडल बताता है कि जिन देशों या समाजों की जनांकिकीय संरचना चौथी अवस्था से पूर्व की है वह यहां तक आने का प्रयास करती है और इसी अनुरूप वर्तमान में भी ऐसे देशों की नीतियां जनसंख्या नियंत्रण पर आधारित हैं।

दूसरी ओर ऐसे देश जो इस अवस्था से आगे निकल चुके हैं उन्हें पुनः इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और यदि विकसित देशों की जनसंख्या

नीति का अध्ययन किया जाए तो प्रायः सभी देशों में जनसंख्या वृद्धि की नीति पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को विकसित देशों के लिए भी प्रासंगिक कहा जा सकता है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

5. प्राचीन काल के विद्वान राज्य का विस्तार करने के लिए किसकी संख्या को जरूरी मानते थे?

   (क) नारियों की (ख) पुरुषों की

   (ग) पशुओं की (घ) शिशुओं की

6. किसके अनुसार एक सभ्य समाज में निवारक नियंत्रण हमेशा प्रयोग में रहते हैं?

   (क) माल्थस के (ख) डार्विन के

   (ग) पिगौ के (घ) मार्शल के

2.5 विश्व जनसंख्या वृद्धि : स्वरूप एवं निर्धारक

विश्व में बहुत अधिक लंबी अवधि के लिए उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में संतुलन बना रहा। 8000 ईसा पूर्व कृषि की शुरुआत से विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। खाद्यान्न का उत्पादन होने के परिणामस्वरूप जनसंख्या थोड़ी–सी बढ़ गई। ऐसा अनुमान है कि 4000 ईसा पूर्व तक है जनसंख्या 8. 6 करोड़ हो गईं। 18 वीं शताब्दी तक जनसंख्या बढ़ कर 80 करोड़ हो गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ी। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतराल बढ़ने के कारण विश्व की जनसंख्या 20वीं शताब्दी में 250 करोड़ हो गई।1988 तक जनसंख्या 500 करोड़ हो गई। शुरुआत में विश्व की जनसंख्या को 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए 10 लाख वर्ष लगे और उसके बाद विश्व की जनसंख्या को 100 करोड़ होने में केवल 120 वर्ष लगे(1808 से 1928). और उसके बाद अगले 100 करोड़ होने में केवल 32 वर्ष लगे और उससे अगले सौ करोड़ होने में 15 साल और उसे अगले 100 करोड़ होने में केवल 13 वर्ष लगे।

1810 अरब (1)

1930 अरब (2) 120 साल

1960 अरब (3) 30 वर्ष

1975 अरब (4) 15 वर्ष

1988 अरब (5) 13 वर्ष

1999 अरब (6) 11 वर्ष

2011 अरब (7) 12 वर्ष

2025 अनुमानित अरब (8) 14 वर्ष

विश्व जनसंख्या वृद्धि का इतिहास 1810 –2025

तालिका से हमें विश्व की जनसंख्या वृद्धि का अनुमान मिलता है। सन 1970 में विश्व की वार्षिक सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर 2.07 : थी,इस वृद्धि दर के साथ विश्व

टिप्पणी

की जनसंख्या को दोगुना होने में केवल 32 वर्ष का समय लगा। विश्व की जनसंख्या को 2 गुना होने समय अलग अलग था। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई वैसे ही जनसंख्या वृद्धि का दुगना होने में समय घटता चला गया। 1970 में विश्व के बड़े बड़े विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना शुरू किया जिसे जनसंख्या का दोगुना होने का समय बढ़ने लगा। 1970 में यह 33 वर्ष था जो 1980 में बढ़कर 41 वर्ष हो गया। 1990 में यह अवधि बढ़कर 44 वर्ष हो गया और 2000 यह बढ़कर 55 वर्ष हो गया। 2010 में जनसंख्या दोगुना होने का समय 67 वर्ष हो गया। ऐसा अनुमान है कि 2050 में जनसंख्या दोगुना होने का समय 160 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विकासशील देश जैसे भारत,पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अपनी जन्म दर को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विश्व के प्रत्येक देश में जन्म दर और मृत्यु दर अलग–अलग है। विकसित देशों की जन्म दर कम और विकासशील देशों की जन्म दर अधिक रही।

विश्व जनसंख्या का दोगुना समय (अनुमानित आंकड़े) :

1. 10,000 ई.पू. 5 मिलियन
2. 1659 ईस्वी 500 मिलियन 1500 वर्ष
3. 1850 ई. 1000 मिलियन 200 वर्ष
4. 1930 ई. 2000 मिलियन 80 वर्ष
5. 1975 ई. 4000 मिलियन 45 वर्ष
6. 2012 ई. 8000 मिलियन 37 वर्ष

जनसंख्या और आर्थिक विकास

आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है तथा इसे एक समय अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान में वृद्धि के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। जीडीपी और जीएनपी में परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है।

आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की सामान्य जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षणिक स्तर में सुधार होता है। आर्थिक विकास को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) द्वारा मापा जाता है।

आर्थिक वृद्धि के कारक

अनेक ऐसे कारक है, जिनकी मात्रा में सुधार या वृद्धि से अर्थव्यवस्था उच्च विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। प्रमुख कारक निम्नांकित हैं–

प्राकृतिक संसाधन : एक अर्थव्यवस्था के लिए प्राकृतिक संसाधन बेहद आवश्यक होते हैं। अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों की खोज, एक अर्थव्यवस्था के साथ उपलब्ध दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का सुधार और विवेकपूर्ण उपयोग इसकी वृद्धि को सुगम बनाता है।

टिप्पणी

भौतिक पूंजी अथवा आधारिक अवसंरचना : भौतिक पूंजी जैसे सड़कों, स्वचालित मशीनरी, कारखानों, वाहनों में निवेश, मानवीय गतिविधियों के लिए मानव पूंजी की तुलना में अधिक कुशल है। यह समय, ऊर्जा की बचत करता है एवं अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में सुधार करता है।

जनसंख्या अथवा श्रम : श्रम, उत्पादन का एकमात्र सक्रिय कारक है। एक अर्थव्यवस्था के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के अन्य समस्त कारक जनसंख्या की मात्रा, संरचना, वितरण एवं गति आर्थिक विकास की दर में सहायता या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जितना कुशल और सस्ता श्रम होगा, उत्पादन सस्ता और उच्च गुणवत्ता का होगा।

मानव पूंजी : शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से जन कौशल और क्षमताओं में सुधार के लिए मानव पूंजी में निवेश में वृद्धि से उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार होगा जिससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।जिन देशों में अधिक पूँजी निवेश की जाती है वे प्रगति की ओर अग्रसर हैं।

प्रौद्योगिकी : उन्नत तकनीक श्रम के समान स्तरों के साथ उत्पादकता में सुधार करती है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए लागत कम हो जाती है और समय भी कम लगता है। उच्च तकनीक होने से आप कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन कर सकते हैं।

विधान : स्पष्ट रूप से निर्मित किए गए विधान अर्थव्यवस्था के निर्बाध कार्य संचालन में सहायता करते हैं।

जनसंख्या किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को निर्धारित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जनसंख्या का अत्यधिक होना या अत्यंत कम होना इस पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

ऐसा कहा जाता है कि एक वृद्धिशील जनसंख्या वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार, बड़ा कार्यबल, जनांकिकीय लाभांश के लाभ, अधिक नवाचार, कुल उत्पादन में वृद्धि और बहुत कुछ प्रदान करके आर्थिक विकास में सहायता करती है। यद्यपि, यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। तीव्र गति से वृद्धि करती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक भी बनती है।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव

1. **प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव**– अति जनसंख्या देश के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, दोहन तथा अवक्रमण करती है। विशेष रूप से भारत जैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां कृषि बहुसंख्यक आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। भूमि उत्पादन का एक सीमित कारक है। भूमि का विखंडन इसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के अयोग्य बना देता है जिससे उत्पादकता कम हो जाती है।
2. **प्रति व्यक्ति आय में कमी**– जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है

टिप्पणी

3. **अपर्याप्त पूंजी निर्माण**– व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में कमी के कारण, अधिकांश आय का उपभोग के वस्तुओं परव्यय किया जाता है। बचत नगण्य होती है, इसलिए पूंजीगत वस्तुओं या पूंजी निर्माण में निवेश के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है।

4. **बेरोजगारी और अल्प–रोजगार**– जनसंख्या में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य हो जाती है।

5. **पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव**– अति जनसंख्या का सर्वाधिक गंभीर एक प्रभाव यह है कि वृद्धिशील जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, शहरीकरण, अपशिष्ट उत्पादन, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान, वनोन्मूलन, रेत खनन, घटते जल स्तर ने पर्यावरण को अवक्रमित किया है,

6. जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक बुरा प्रभाव है।

7. **संघर्ष एवं अपराध**– सीमित संसाधनों के लिए अत्यधिक व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा से विवेक प्रभावित होता है। अपराध, शराब, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग दिनचर्या में शामिल हो जाता है।

8. **अपर्याप्त जीवन स्तर**– जनसंख्या में वृद्धि के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने से व्यक्तियों का का जीवन स्तर निम्न कोटि का हो जाता है।

9. **वैश्विक महामारी और जानपदिक रोग**– अल्प आय एवं बचत के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश नगण्य होता है। दूसरी तरफ निर्धनता, अपर्याप्त स्वच्छता और भीड़ भाड़ के कारण महामारी और जानपदिक रोगों का प्रकोप निरंतर होता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन के वुहान में एक महामारी कोविड –19 का प्रकोप। इसकी विशाल जनसंख्या और मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण यह प्रकोप कुछ ही समय में एक वैश्विक महामारी बन गया।

अपनी प्रगति जांचिए

7. किस क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ी?

(क) आर्थिक (ख) राजनीतिक

(ग) सामाजिक (घ) औद्योगिक

8. क्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है?

(क) जनसंख्या (ख) रोजगार

(ग) नौकरियां (घ) उत्पादन

2.6 भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि

भारत में विश्व की 17. 5 प्रतिशत जनसंख्या विश्व के 2. 4 प्रतिशत भू –भाग पर निवास करती है। भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका की

संयुक्त जनसंख्या से भी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है।

टिप्पणी

जनसंख्या का वितरण (Distribution of population)

भारत की जनसंख्या वितरण में अनेक विषमताएँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि जनसंख्या का केन्द्रण भूमि की प्रकृति, आकार, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे सघन और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या के जमाव वाला राज्य है। मध्य में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के दो बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं जिनका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10. 4 प्रतिशत और 9.37 प्रतिशत है परंतु इन राज्यों में भारत की केवल 5.6 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार उनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले छोटा है।

जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भौतिक कारक,सामाजिक कारक और जनांकिकीय कारक आते हैं।

भौतिक कारक :– जलवायु,मृदा, प्राकृतिक संसाधन, उच्चावच और खनिज संसाधन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर भारत के मैदान, डेल्टा तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी भारत के आंतरिक भागों की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है क्योंकि यहां पर उर्वरा मिट्टी, उपजाऊ समतल भूमि, पर्याप्त वर्षा, सुविकसित सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। जहां पर भी प्राकृतिक संसाधन या खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं वहां पर भी जनसंख्या का सकेंद्रण पाया जाता है जैसे झारखण्ड।

सामाजिक– आर्थिक कारक

मनुष्य के क्रियाकलाप, औद्योगिक ज्ञान जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। औद्योगिक विकास के कारण नगरों की पोषण क्षमता बेहतर होती है, जिससे नगरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत के जितने भी औद्योगिक नगर हैं जैसे मुंबई, कोलकाता दिल्ली आदि नगरों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जहां पर कृषि उन्नत अवस्था में है वहां पर भी जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश,पंजाब,हरियाणा आदि में जनसंख्या अधिक होने का कारण कृषि का उन्नत अवस्था में होना भी है।

जनांकिकीय कारक

जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रजनन दर,मृत्यु दर और प्रवास सबसे महत्वपूर्ण है कारक हैं। जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। आप्रवासन से भी औद्योगिक नगरों की जनसंख्या बढ़ जाती है।

टिप्पणी

जनसंख्या का राज्यवार वितरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या 2011	भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग	कोटि (सकेंद्रण सूचकांक)
उत्तर प्रदेश	19,95,81,477	16.49	1
महाराष्ट्र	11,23,72, 972	9.29	2
बिहार	10,3 8,04,637	8.58	3
पश्चिम बंगाल	9,13,47,736	7.55	4
आंध्र प्रदेश	8,46,65,533	7.00	5
मध्य प्रदेश	7,25,97,565	6.00	6
तमिलनाडु	7,21,38,958	5.96	7
राजस्थान	6,86,21,012	5.67	8
कर्नाटक	6,11,30,704	5.05	9
गुजरात	6,03,83,628	4.99	10
उड़ीसा	4,19,47,358	3.47	11
केरल	3,33,87,677	2.76	12
झारखंड	3,29,66,238	2.72	13
असाम	3,11,69,272	2.58	14
पंजाब	2,77,04,236	2.29	15
छत्तीसगढ़	2,55,40,196	2.11	16
हरियाणा	2,53,53,081	2.09	17
दिल्ली	1,67,53,235	1.38	18
जम्मू और कश्मीर	1,25,48,926	1.04	19
उत्तराखंड	1,01,16,752	0.84	20
हिमाचल प्रदेश	68,56,509	0.57	21
त्रिपुरा	36,71,032	0.30	22
मेघालय	29,64,007	0.24	23
मणिपुर	27,21,756	0.22	24
नागालैंड	19,80,0602	0.16	25
गोवा	14,57,723	0.12	26
अरुणाचल प्रदेश	13,8 2,6 11	0.11	27
पुदुचेरी	12,44,464	0.10	28
मिजोरम	10,91,014	0.09	29
चंडीगढ़	10,54,686	0.09	30
सिक्किम	6,07,688	0.05	31
अंडमान और निकोबार द्विप समूह	3,79,944	0.03	32
दादरा और नगर हवेली	3,42,853	0.03	33
दमन और दीव	2,42,911	0.02	34
लक्षद्वीप	64,429	0.01	35
भारत	1,21,01,93,422	100.0	

Source: Census of India, 2011, Series- 1, India:Primary Census Abstract.

जनसंख्या का घनत्व

टिप्पणी

जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपातिक सम्बन्ध द्वारा व्यक्त किया जाता है।

घनत्व कई प्रकार से व्यक्त किये जाते हैं :–

गणितीय घनत्व

कायिक घनत्व

कृषिय घनत्व

आर्थिक घनत्व

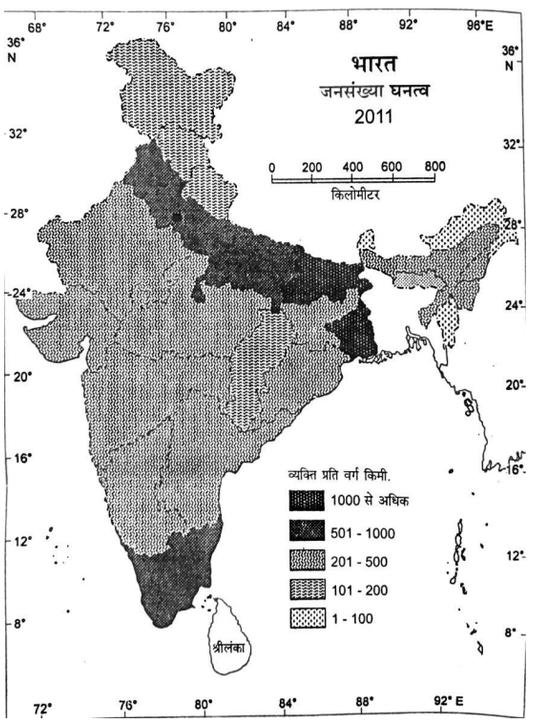

2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अंकगणितीय घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

भारत में जनसंख्या घनत्व की वृद्धि एवं वितरण

वर्ष	घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
1901	77
1911	82
1921	81
1931	90
1941	103
1951	117
1961	142
1971	177

टिप्पणी

1981	216
1991	267
2001	325
2011	382

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लगातार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो रही है।

जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय प्रतिरूप

किसी भी देश की जनसंख्या घनत्व से उस देश के अंदर मौजूद जनसंख्या की विषमताओं का पता नहीं चलता। भारत में जनसंख्या घनत्व में राज्य स्तर पर अनेक विषमताएँ देखने को मिलती हैं। किसी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम तो किसी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो दिल्ली में अधिकतम घनत्व 11297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर
दिल्ली	11297
चंडीगढ़	9252
हरियाणा	478
पुडुचेरी	2598
दमन और दीव	2169
लक्षद्वीप	2013
बिहार	1102
पश्चिम बंगाल	1029
केरल	859
उत्तर प्रदेश	828
दादरा और नगर हवेली	698
पंजाब	550
असम	397
झारखंड	414
गोवा	394
महाराष्ट्र	365
त्रिपुरा	350
कर्नाटक	319

टिप्पणी

आंध्र प्रदेश	308
गुजरात	308
उड़ीसा	269
मध्य प्रदेश	336
राजस्थान	201
उत्तराखंड	189
छत्तीसगढ़	189
मेघालय	132
जम्मू कश्मीर	124
हिमाचल प्रदेश	123
मणिपुर	122
नागालैंड	119
सिक्किम	86
मिजोरम	52
अरुणाचल प्रदेश	17
अंडमान निकोबार दीप समूह	46
तमिलनाडु	480

Source: Census of India, 2011, Series-1, India: Provisional Population Totals.

1. अधिक घनत्व

इस वर्ग में देश के 5 राज्य केरल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश आते हैं। इन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति से लेकर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश भी इस वर्ग में आते हैं।

अधिक घनत्व का कारण है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उपजाऊ मैदान का विस्तार, समतल भूमि, सिंचाई के उन्नत साधन पर्याप्त वर्षा आदि। यहाँ पर कृषि उन्नत अवस्था में है और सड़कों और रेलमार्गों का जाल बिछा होने, रोजगार के साधन उपलब्ध होने से जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। केरल के तटीय मैदानों में भी कृषि उन्नत अवस्था में है और यहाँ पर बागानी और वाणिज्य फसलों की कृषि की जाती है। केरल और तमिलनाडु के तटीय मैदान उन्नति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर पर्यटन, औद्योगिकरण और नगरीकरण से अच्छी आय प्राप्त होने के कारण जनसंख्या का सांद्रण पाया जाता है।

2. सामान्य घनत्व

इस वर्ग के अंतर्गत उड़ीसा, कर्नाटक,आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, असम और झारखंड आते हैं। इन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।

टिप्पणी

उड़ीसा के तटीय भागों में यद्यपि जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है परंतु इस प्रदेश के आंतरिक भाग उबड़–खाबड़ होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। बिहार के छोटा नागपुर पठार में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है परन्तु बाकी के भागों में रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु और गुजरात के भागों में उद्योग, खनन कार्यों और सिंचित कृषि की वजह से सामान्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।

3. न्यून घनत्व

इस वर्ग में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड,छत्तीसगढ़,जम्मू कश्मीर, मेघालय,मणिपुर हिमाचल,नागालैंड आदि राज्य जाते हैं। यहाँ पर घनत्व 101व्यक्ति से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।

मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आदि पर्वतीय प्रदेश होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जम्मू–कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय के कुछ भाग बर्फ से ढके रहते हैं और जनसंख्या निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां की भूमि उद्योग धंधों के लिए,कृषि के लिए बहुत अधिक उपयुक्त नहीं है।

राजस्थान में बारिश की कमी के कारण कृषि उन्नत अवस्था में नहीं है। रेत के टीलों और की कंटीली झाड़ियों की वजह से यहां पर कृषि करना बहुत मुश्किल है और यहां के पशु पालन से जुड़े व्यक्ति अपने पशुओं के साथ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र भी उबड़–खाबड़ और चट्टानी हैं और कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं हैं।

4. अति न्यून घनत्व

इस वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनका घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसके अंतर्गत मिजोरम, अंडमान निकोबार दीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं।

अरुणाचल प्रदेश,सिक्किम और मिजोरम उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित होने के कारण उबड़–खाबड़, दुर्गम,वनाच्छादित हैं। यहां पर मानव निवास के लिए प्रतिकूल दिशाएं, विषम जलवायु अनुपजाऊ मिट्टी और यातायात के साधन की कमी के कारण जनसंख्या का आभाव पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप की जलवायु मनुष्य के आवास लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती और यह भारत की मुख्य भूमि से भी कटा हुआ है। यही कारण है कि यहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है

5. अत्यधिक घनत्व

इस वर्ग के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिनका जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस वर्ग में बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी लक्षदीप, दमन व दीव आदि आते हैं।

टिप्पणी

इन सभी प्रदेशों में कृषि व्यापार यातायात उद्योग व खनन इत्यादि विकसित अवस्था में हैं। पश्चिम बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित होने के कारण बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। बिहार भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है। यहां पर भी कृषि उन्नत अवस्था में है। इसी कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है।

दिल्ली व चंडीगढ़ राजधानी नगर होने के कारण जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है।

जनसंख्या वृद्धि

दो समय–बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं।

धनात्मक वृद्धि :– धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय–बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य प्रदेशों से लोग आकर बस जाएं।

ऋणात्मक वृद्धि :– जब दो समय–बिंदुओं के बीच लोगों की जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। यह तब होता है जब जन्म दर, मृत्यु दर से कम हो या लोग उस प्रदेश से बाहर चले जाएं।

प्राकृतिक वृद्धि :– इस प्रकार की वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ती है।

अभिप्रेरित वृद्धि :– जनसंख्या वृद्धि को अभिप्रेरित घटकों जैसे प्रवास के अंतवर्ती और बहिवर्ती संचलन के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं (phases of Population Growth) भारत की दशकीय वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दोनों ही बहुत उच्च हैं। भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2. 4 प्रतिशत और दशकीय वृद्धि दर 21. 54: है। 110 वर्षों में भारतीय जनसंख्या में 5 गुना से अधिक वृद्धि हुई। विगत 110 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 93.11 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारत के जनांकिकीय इतिहास की अवस्थाएं

भारत के जनांकिकीय इतिहास को चार सुस्पष्ट अवस्थाओं में बांटा जा सकता है –

- प्रावस्था 'क'– 1901 से लेकर 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रूद्ध या स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय वृद्धि दर अत्यंत कम थी। वर्ष 1911से 1921 के बीच जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर कम हो गई थी।

  जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण महामारियां और बीमारियां थी। सन 1918 में अकेले इन्फ्लूएंजा से एक करोड़ से अधिक लोग मारे गए और प्रथम विश्व युद्ध में हजारों भारतीय युद्ध में काम आए। उस समय फसलों के बचाव के लिए किटनाशक उपलब्ध नहीं होने के कारण फसलें खराब हो जाती थी और लोग भुखमरी का शिकार होकर मर जाते थे। निरक्षरता, आधारभूत सुविधाओं अदक्ष प्रणाली भी उच्च मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार थी।

टिप्पणी

- प्रावस्था 'ख'– 1921– 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद भारतीय जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होने लगी।

  अब अवधि में चिकित्सा ज्ञान में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप हैजा, निमोनिया, इनफ्लुएंजा, चेचक जैसी महामारियों पर काबू पा लिया गया था जिससे मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई। इन दशकों में कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप जन्मदर उच्च बनी रही। परिवहन के विकसित साधनों की वजह से अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री जल्दी पहुंचने लगी और मृत्यु दर कम हो गई। देश के विभाजन के कारण 1941 की वृद्धि दर 1.42 से घट कर 1951 में 1.33 प्रतिशत रह गई। इसका कारण देश के लाखों लोगों का प्रवास और और हजारों लोगों का मारा जाना था।

- प्रावस्था 'ग'– 1951 –1981 के दर्शकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान मृत्यु दर में तेजी से कमी आई और जन्म दर ऊंची बनी रही। इस अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 2. 2 प्रतिशत तक उच्च बनी रही और जनसंख्या में दुगुनी वृद्धि हो गई।

  इस अवधि में केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार ने अनेक विकासात्मक कार्य देश में प्रारम्भ कर दिये। जिसके फल स्वरुप कृषि और उद्योग खंडों में विकास होने से रोजगार में वृद्धि हुई, भुखमरी कम हुई, चिकित्सा में वृद्धि होने से मृत्यु दर में कमी आई और जनसंख्या तेजी से बढ़ी।

  हरित क्रांति के कारण खदानों का उत्पादन बढ़ा, जिससे सुनिश्चित भोजन की व्यवस्था होने से जनसंख्या में अत्यधिक से वृद्धि हुई।

  इस अवधि के दौरान तिब्बत नेपाल बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने अंतर–राष्ट्रीय प्रवास किया जिससे भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई। तत्पश्चात 70 के दशक के बाद भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और शिक्षा के बढ़ते स्तर के कारण जनसंख्या वृद्धि में कुछ कमी आने लगी। सन 1981 में जनसंख्या हल्की सी घटकर 24.66 प्रतिशत हो गई। इसे प्रजनन प्रेरित वृद्धि कहा जाता है।

- प्रावस्था 'घ'– 1981 के बाद से वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही परंतु धीरे–धीरे मंद गति से घटने लगी। वर्ष 1991 में दशकीय वृद्धि दर थोड़ा–सी घटकर 23.87 प्रतिशत और 2001 में घटकर 21.54 प्रतिशत रह गई।

  अशोधित जन्म दर में गिरावट की प्रवृति को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में कमी के लाने हेतु उतरदायी माना जाता है। इस समय देश में विवाह की औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, स्त्री शिक्षा में सुधार से भी जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है।

टिप्पणी

भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर
1901	23,83,96,327	–
1911	25,20,93,320	5.75
1921	25,13,21,213	0.31
1931	27,89,77,238	11.00
1941	31,86,60,580	14.22
1951	36,10,88,090	13.31
1961	43,92,34,771	21.51
1971	54,81,59,652	24.80
1981	68,33,29,097	24.66
1991	84,63,02,688	23.85
2001	102,70,15,247	21.34
2011	121,05,69,573	17.7

Source: Census of India, 2011, India, Provisional Population Totals.

जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं

भारत में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 21.54 प्रतिशत थी। 2001 से 2011 के दशक में यह औसत वृद्धि दर घटकर 17.64 प्रतिशत रह गई। पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में वृद्धि दर में भिन्नताएं थी। उदाहरणतया नागालैंड में –– 0.47 प्रतिशत और दादरा व नगर हवेली में 55.5 प्रतिशत।

तालिका : भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रारूप

राज्य / केंद्र	वृद्धि दर	वृद्धि दर	दशकीय वृद्धि	
दादरा और नगर हवेली	2001–2011	1991–2001	– 3.72	अति उच्च वृद्धि दर
दमन और दीव	53.54	55.73	–2.19	
मेघालय	27.82	30.65	–2.83	उच्च वृद्धि दर
पुदुचेरी	27.72	20.62	7.1	
अरुणाचल प्रदेश	25.92	27.00	–1.08	
बिहार	25.07	28.62	–3.55	
जम्मू व कश्मीर	23.71	29.43	–5.72	
मिजोरम	22.78	29.82	–6.04	मध्यम वृद्धि दर
छत्तीसगढ़	22.59	18.27	4.32	
झारखंड	22.34	23.36	–1.02	

टिप्पणी

राजस्थान	21.44	28.40	−6.97	
दिल्ली	20.96	47.02	−26.06	
मध्य प्रदेश	20.30	24.26	−3.96	
उत्तर प्रदेश	20.09	25.85	−5.76	
हरियाणा	19.90	28.43	−8.53	
उत्तराखंड	19.17	20.41	−1.24	
गुजरात	19.17	22.66	−3.49	
मणिपुर	18.65	24.86	−6.21	
चंडीगढ़	17.1	40.28	−23.18	
असम	16.93	18.92	−1.99	
महाराष्ट्र	15.99	22.73	−6.74	
कर्नाटक	15.67	17.51	−1.84	
तमिलनाडु	15.6	11.72	3.88	
त्रिपुरा	14.75	16.03	−1.28	
ओडिशा	13.97	16.25	−2.28	
पश्चिम बंगाल	13.93	17.77	−3.84	
पंजाब	13.73	20.1	−6.37	निम्न वृद्धि दर
सिक्किम	12.81	17.54	−4.73	
आंध्र प्रदेश	12.36	33.06	−20.7	
गोवा	11.1	14.59	−3.49	
अंडमान निकोबार	8.17	15.21	−7.04	
दीप समूह	6.68	26.9	−20.22	
लक्षद्वीप	6.23	17.3	−11.07	
केरल	4.85	9.43	−4.57	
नागालैंड	−0.47	64.53	−65	

Source: Census of India, 2011, India: Provisional Population Totals.

निम्न वृद्धि दर वाले राज्य :– जैसा कि तालिका में स्पष्ट है; इस वर्ग में 10 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि की दशकीय वृद्धि दर 15% से कम थी।

मध्यम वृद्धि दर वाले राज्य :– मध्यम वृद्धि वाले 15 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 15 से 25% है।

उच्च वृद्धि दर वाले राज्य :– 3 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 15 से 35% है।

अति उच्च वृद्धि दर वाले राज्य :– इस वर्ग में 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं,जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 50% से अधिक है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

9. भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है?

   (क) 20 प्रतिशत (ख) 17.5 प्रतिशत

   (ग) 15.5 प्रतिशत (घ) 10.7 प्रतिशत

10. जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कैसे संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है?

    (क) राजनीतिक (ख) प्राकृतिक

    (ग) अनुपातिक (घ) सामाजिक

2.7 अधोजनसंख्या और अति जनसख्या की संकल्पना

किसी भी प्रदेश का विकास वहां पर उपलब्ध संसाधनों और मनुष्य के अंतर–संम्बन्धों पर निर्भर करता है। जनसंख्या और संसाधनों के परस्पर संबंधों की पूर्ण जानकारी हेतु संबंधित प्रदेश की जनसंख्या के आकार, प्रौद्योगिक स्तर और प्रकृति के साथ–साथ वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों की मात्राओं की गुणवत्ता का ज्ञान भी आवश्यक होता है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए मानव संसाधन का भी उपयुक्त रूप से होना आवश्यक है क्योंकि संसाधनों का दोहन और संरक्षण मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। किसी भी देश में उपस्थित प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पर्यवेक्षण तथा सर्वेक्षण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

अनुकूलतम जनसंख्या : किसी प्रदेश की मानवीय जनसंख्या द्वारा वहां पर उपस्थित पर्यावरणीय दशाओं के अंतर्गत उच्चतम जीवन सर को प्राप्त करने के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। संसाधन संतुलन का प्रतीक होता है। यह किसी प्रदेश की ऐसी आदर्श स्थिति है जिसमें प्रदेश सर्वाधिक आर्थिक और सामाजिक उन्नति प्राप्त करता है। किसी भी प्रदेश में मनुष्य और संसाधनों का संबंध स्थाई नहीं होता है क्योंकि मनुष्य नई प्रौद्योगिकी ज्ञान तथा उन्नत विज्ञान की सहायता से नए–नए संसाधनों की खोज करता है और कुछ संसाधनों का ह्रास होता है। जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के स्थिर रहने से जनातिरेक होता है और जनसंख्या के कम होने या स्थिर होने और नए संसाधनों के विकास से अधोजनसंख्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

संसाधनों और जनसंख्या के पारस्परिक अंतर–संबंधों से तीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है, जो इस प्रकार हैं :–

– अनुकूलतम जनसंख्या

– जनाधिक्य या अति जनसंख्या

– अधोजनसंख्या या अल्पजनसंख्या

अधोजनसंख्या और अति जनसंख्या को समझने से पहले हमें अनुकूलतम जनसंख्या के संकल्प को समझना होगा।

टिप्पणी

किसी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए वहां पर उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान प्रौद्योगिकी और ज्ञान के अनुसार पूर्ण विकास करने और उपभोग करने के लिए आवश्यक निश्चित जनसंख्या जिससे जीवन का उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो, उसे उस प्रदेश की अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है

जनसंख्या और संसाधनों के मध्य पूर्ण संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना कठिन है परंतु साम्य की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अनुकूलतम शब्द एक सापेक्षिक शब्द है जिसका अर्थ देश और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिससे उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है; अनुकूलतम या अभीष्ट जनसंख्या कही जा सकती है। आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से किसी प्रदेश में मनुष्य की उस संख्या को अनुकूलतम माना जाता है जिसे वहां पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्तम जीवन स्तर प्राप्त होता है।

उत्तम जीवन स्तर के अंतर्गत केवल प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति पर्याप्त भोज्य पदार्थ, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, उच्च स्तरीय आवास, विकसित परिवहन के साधन, उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन की पूर्ण सुविधा, अति उत्तम व्यापारिक दशा, पूर्ण विकसित सांस्कृतिक दशाएं आदि भी शामिल हैं क्योंकि इनकी सहायता से ही मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।

सबसे पहले 18वीं शताब्दी में कंटीलोन ने अनुकूलतम जनसंख्या शब्दावली का प्रयोग किया और बताया कि किसी निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जा सकता है जो उत्तम जीवन स्तर को कायम रखने में समर्थ होती है।

किसी भी प्रदेश में उपलब्ध आदर्श जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से वह प्रदेश अतिजनसंख्या या अल्पजनसंख्या की समस्या से ग्रसित हो सकता है।

अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा

कुछ भूगोलवेत्ताओं और समाज शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम जनसंख्या को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :–

डाल्टन के अनुसार :–''अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है।''

मानव भूगोल के शब्दकोष के अनुसार '' मनुष्य की वह संख्या जो किसी दी गई आर्थिक, सैन्य व सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल उत्पन्न करती है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है।''

साउंडर्स के अनुसार ''अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम सामाजिक कल्याण उत्पन्न करती है।''

पीटरसन के अनुसार ''अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्तियों की वह संख्या है जो किसी दी हुई प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल उत्पन्न करती है।''

सावी के अनुसार ''अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो और पूर्ण रोजगार,दीर्घ जीवन प्रत्याशा,उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान और संस्कृति, सामाजिक सामंजस्य, परिवारिक तत्व की प्राप्ति होती है।''

टिप्पणी

अनुकूलतम जनसंख्या संकल्पना का महत्व– अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का विकास सबसे पहले यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। विभिन्न जनसंख्याविदों ने अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का अपनी–अपनी दृष्टि से वर्णन किया। साम्यवादी लेखकों के विचार में माल्थस के सिद्धांत का ही परिष्कृत रूप है। बहुत से अर्थशास्त्रियों और भूगोलवेताओं का मत है कि वर्तमान संसार में समाज की गतिशीलता और निरंतर विकसित हो रही प्रौद्योगिकी से संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन का आकलन बेहद कठिन हो गया है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार संसाधनों के वास्तविक आकलन के अभाव में कुल जनसंख्या के आधार पर कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आज तटस्थ हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के कारण उनको संसाधनों में बदला जा सकता है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का कोई महत्व नहीं है। अति जनसंख्या और अल्प जनसंख्या की गणना अनुकूलतम जनसंख्या के संदर्भ में की जा सकती है। इसलिए इसका सैद्धांतिक महत्व अधिक है।

अनुकूलतम जनसंख्या के मापन में अनेक कठिनाइयां व अवरोध आते हैं जिसके कारण इसके मापन का व्यावहारिक महत्व कम है।

किसी देश या प्रदेश की अनुकूलतम जनसंख्या क्या होनी चाहिए इसका निर्धारण करना कठिन कार्य है। अधिकततम आर्थिक उत्पादन,उच्चतम जीवन स्तर या समाज कल्याण को परिभाषित करना ही बहुत कठिन है।अधिकतम सामाजिक कल्याण,आर्थिक उत्पादन, सैन्य शक्ति आदि के संदर्भ में जनसंख्या का अनुकूलतम आकार अलग–अलग हो सकता है। अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पूर्ण रोजगार, उच्चतम जीवन स्तर,प्रति व्यक्ति आय,संसाधनों का संपूर्ण उपयोग, संतुलित जनांकिकीय संरचना, प्रदूषण रहित विकास आदि मापदंड के रूप में लिए जाते हैं।

1. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** : प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय सकल उत्पादन पर ही निर्धारित करती है और औसत आय को प्रकट करती है। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर निर्भर करता है। देश के निवासियो द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किये गये अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) कहा जाता है। GNP = GDP – विदेशियो द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य. विदेश में देश के नागरिको द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।
2. **प्रति व्यक्ति आय** : यह मापदंड अधिक सार्थक नहीं है क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों तथा व्यक्तियों में इसका इसका वितरण असमान है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च नहीं हो सकता।

टिप्पणी

3. **उच्चतम जीवर स्तर** : उत्तम जीवन स्तर जीवन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति से संबंधित है इसमें उच्चतम आय,पूर्ण रोजगार, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं आदि सभी शामिल है। जिस भी क्षेत्र में जीवन स्तर उच्च होगा वहां की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कही जायेगी।

4. **संसाधनों का पूर्ण उपयोग** : इसका अर्थ यह है कि ज्ञात प्रौद्योगिकी और तकनीक के फलस्वरूप संसाधनों का पूर्ण उपयोग। प्रत्येक क्षेत्र में नवीन तकनीकों के प्रयोग होने से नए–नए संसाधनों की खोज की जाती है और संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि होती रहती है।यह देश और कालानुसार परिवर्तनशील है।

5. **प्रदूषण रहित विकास** : अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को निरंतर क्षति पहुंचाई जा रही है। निरंतर विकास हेतु जंगलों को साफ किया जाना, मृदा अपरदन,जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि से गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है। अनुकूलतम जनसंख्या को केवल आर्थिक उत्पादन या आय के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे हम पर्यावरण संबंध में भी देखते हैं। अगर किसी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण अधिक है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद हम इसे अनुकूलतम जनसंख्या प्रदेश नहीं मान सकते।

6. **पूर्ण रोजगार** : योग्यता के अनुसार से सभी व्यक्तियों को रोजगार की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है।इसे आय के वितरण में असंतुलन घटता है।

7. **जनांकिकीय सरंचना** : किसी प्रदेश की जनसंख्या में आयु,लिंग आदि जनांकिकीय घटक संतुलित होने पर निर्भरता में कमी होती है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर कम होने से जनसंख्या स्थाई हो जाती है।

(अ) अधोजनसंख्या (Under Population)

जब किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है यदि जनसंख्या उससे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इस स्थिति को अधोजनसंख्या,अल्प जनसंख्या, जनाभाव, जनाल्पता आदि कहा जाता है। इस प्रकार के देश या प्रदेश में उपस्थित जनसंख्या के जीवन स्तर में गिरावट लाए बिना ही जनसंख्या के भरण–पोषण के यत्न करने होते हैं। ऐसे प्रदेशों में उत्पादन स्तर और जीवन स्तर में उत्थान की प्रवृत्ति पाए जाती है। जिस प्रदेश की जनसंख्या अनुकूल जनसंख्या से कम होती है तो उस प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक जनसंख्या की जरूरत होती है।

ऐसे प्रदेशों को अधोजनसंख्या वाले प्रदेश माना जाता है जहाँ की जनसंख्या उस प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाती।

क्लार्क के अनुसार ''अधोजनसंख्या वहां पाई जा सकती है जा जनसंख्या इतनी अल्प होती है कि इसके संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती अथवा जहां संसाधन

जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि किये बिना ही वृहत्तर जनसंख्या का पोषण करने में हम समर्थ होते हैं।''

टिप्पणी

अधोजनसंख्या की प्रकृति पूर्ण और सापेक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है। पूर्ण जन अभाव की स्थिति बहुत ही कम पाई जाती है। यह केवल कुछ एकाकी लघु क्षेत्रीय इकाई में ही उत्पन्न हो सकती है जिसका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संबंध अन्य क्षेत्रों से ना हो। लेकिन ऐसा कोई भी लघु एकाकी प्रदेश वास्तव में विश्व में उपलब्ध नहीं हो पाता है।

मुख्यतः सापेक्ष जनाभाव ही अधिक पाया जाता है। यह स्तिथि विश्व के सभी विकसित और विकासशील क्षेत्रों में पाई जा सकती है। यह स्तिथि जब उत्पन्न होती है जब प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध,महामारी आदि से किसी क्षेत्र की मृत्यु दर में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाये।

भारत में 20वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में प्लेग, हैजा जैसी महामारी के परिणाम स्वरुप जनसंख्या की तीव्र मृत्यु दर से जनसंख्या और संसाधनों में असंतुलन जैसी अवस्थाओं से सामना हो चुका है। इस प्रकार की परिस्थिति अधिकांश पिछड़े समाजों में उत्पन्न होती है।

विश्व के कई विकासशील देशों जैसे मध्य अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के घने जंगलों में जनसंख्या बहुत कम होने से जनाभाव की स्थिति पाई जाती है।

जनाभाव वाले प्रदेशों में औद्योगिक विज्ञान व तकनीकी विकास भी बहुत कम है और वहां पर विद्यमान संसाधनों का मनुष्य दोहन भी नहीं हो पाया है। क्योंकि जनसंख्या अकुशल है और तकनीकी ज्ञान ज्ञान का अभाव है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त जनसंख्या अनिवार्य है।

विकसित देशों में जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जनाभाव केवल ग्रामीण भूभागों में पाया जाता है। वहां विस्तृत कृषि भूमि पाई जाती हो और जनसंख्या उस अनुपात में कम होती है। इस भूमि की सामर्थ्य वहां पर विद्यमान जनसंख्या के भरण पोषण से ज्यादा है और और भूमि का भी पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता है। विश्व के शीतोष्ण घास के मैदान जैसे कि दक्षिण अमेरिका के पंपास,सयुंक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी, अफ्रीका के वेल्स,ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और यूरेशिया के स्टेपीस घास के मैदानों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यहां पर कृषि की अपार संभावनाएं विद्यमान है। लेकिन जनसंख्या का अभाव होने से विशेष प्रगति नहीं हो पाई है और संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

(ब) अति जनसंख्या या जनाधिक्य (Over Population)

जनाधिक्य उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर जनसंख्या उस क्षेत्र के सामान्य पोषण क्षमता से अधिक हो और वहां पर जनसंख्या वृद्धि अनुपात में संसाधनों का विकास ना हो पाए। फलस्वरुप जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। ऐसी अवस्था को अधिक जनसंख्या,जनातिरेक या जनाधिक्य आदि कहा जाता है।

टिप्पणी

इस प्रकार की स्थिति अनुकूलतम जनसंख्या के विचलन का परिणाम है। इस स्थिति में अनेक कारणों के परिणामस्वरूप संसाधनों का विकास जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है और वहां पर विद्यमान संसाधनों पर भार बढ़ जाता है। बेरोजगारी और निर्धनता में वृद्धि होने लगती है। प्रति व्यक्ति औसत आय में कमी आने से जीवन स्तर में भी गिरावट होने लगती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, संसाधनों का अभाव या श्रम की मांग कम होने से जनसंख्या जनाधिक्य होता है। जनाधिक्य होने में एक या एक से अधिक कारक उत्तरदायी होते हैं।

जनसंख्या जनाधिक्य दो प्रकार का होता है :–

1 पूर्ण जनाधिक्य 2 सापेक्ष जनाधिक्य

1. **पूर्ण जनाधिक्य** : इस प्रकार के जनाधिक्य में उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या और ज्ञात संसाधनों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। वहां की जनसंख्या उस क्षेत्र में विद्यमान संसाधनों के मुकाबले अधिक बढ़ जाती है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है। इस प्रकार की स्थिति को पूर्ण जनाधिक्य कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है परंतु ग्रेट ब्रिटेन और जापान में यह स्थिति देखने को मिलती है।
2. **सापेक्ष जनाधिक्य** : इस प्रकार की स्थिति वहां पाई जाती है जहां संपूर्ण उत्पादन की मात्रा वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त हो जाती है। नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उस क्षेत्र में उत्पादन की संभावनाएं तो विद्यमान होती है परंतु उस समय विशेष में तकनीकी ज्ञान की कमी से संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। भविष्य में उत्पादन स्तर में सुधार होने से सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति समाप्त हो सकती है। विश्व में पूर्ण जनाधिक्य की स्थिति की तुलना में सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति अधिक सामान्य होती है। यह प्राय : छोटे–छोटे विकासशील देशों या बड़े विकासशील देशों के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ऐसी क्षेत्रों जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में होते है और वहां के संसाधनों में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक करकों के कारण आर्थिक विकास की गति मंद होती है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय कम पाई जाती है।

जनाधिक्य की स्थिती राष्ट्रीय ही नहीं अपितु प्रादेशिक स्तर पर भी पायी जा सकती है। छोटे देशों में यह राष्ट्रीय स्तर पर पायी जाती है क्योंकि वहां पर संसाध ान सिमित होने के कारण जनाधिक्य पाया जाता है।परन्तु बड़े देशों में यह प्रादेशिक भी हो सकती है क्योंकि कुछ प्रदेशों में जनसंख्या केंद्रित होने से जनाधिक्य पाया जाता है। भारत का उत्तरी मैदान, चीन के पूर्वी तटीय मैदान, इंडोनेशिया का जावा द्वीप जनाधिक्य की स्थिति में है। यही स्थिति कई बार विकसित देशों में स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हो सकती है। यह जनाधिक्य ग्रामीण, नगरीय स्तर पर भी पाया जाता है।

(i) ग्रामीण जनाधिक्य : ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के विकास की तुलना में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ने के कारण जनातिरेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस

टिप्पणी

स्थिति को ग्रामीण जनातिरेक कहा जाता है। ग्रामीण जनाधिक्य विकासशील कृषि प्रधान देशों में मिलता है जहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होने के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। तकनीकी ज्ञान का सिमित प्रयोग, पिछडी प्रौद्योगिकी, पूँजी की कमी के कारण संसाधनों का उचित दोहन नहीं होता। औद्योगिक विकास कम होने से प्रति व्यक्ति उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। इससे बेरोजगारी, निर्धनता बढ़ती है। इस प्रकार के जनातिरेक के लिए निम्नांकित कुछ कारण उत्तरदायी हैं :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर का अधिक होना जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र प्राकृतिक वृद्धि हो जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा द्वितीय व तृतीय क्षेत्र अल्प मात्रा में विकसित होते हैं और प्रति व्यक्ति आय कम होने से जीवन स्तर निम्न होता है।
- कृषि के मशीनीकरण से श्रम में कमी हो जाती है और बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।इससे उत्पादन में वृद्धि होती है परंतु इसका लाभ श्रमिक वर्ग को नहीं मिल पाता है और गरीबी बढ़ती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि सीमित होती है और कृषि योग्य भूमि का विकास नहीं हो पाता । ऐसा होने से कृषि उत्पादन कम होता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का वितरण असमान होने के कारण अधिकतर भूमि बड़े किसानों के पास और बहुत ही कम भूमि छोटे किसानों के पास होती है। बड़े किसान अपनी भूमि पर कृषि नहीं कर पाते इसी कारण भूमि को परती छोड़ दिया जाता है जिससे संपूर्ण कृषि भूमि का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। छोटे किसानों की बेरोजगारी की दशा से गुजरने या कुछ समय के लिए ही रोजगार उपलब्ध होने से उनकी आय कम हो जाती है।

किसी देश के समग्र विकास हेतु जनाधिक्य का हल ढूंढना आवश्यक होता है क्योंकि जनाधिक्य की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैल जाती है। ग्रामीण जनातिरेक को कम करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास नीति के तहत कृषि क्षेत्रों पर विकास पर बल दिया और विभिन्न परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई। जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम आरम्भ किये गए और संरचनात्मक ढांचे का विकास करके गैर कृषि क्षेत्र के लिए आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान खोले गए।

औद्योगिक जनाधिक्य : नगरीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग स्थानांतरण करके नगरीय क्षेत्रों में आते है और वहां पर जनातिरेक उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप औद्योगिक और नगरीय केंद्रों में बेरोजगारी बढ़ने लगती है जिससे इन क्षेत्रों में अनेकों सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

औद्योगिक जनाधिक्य मुख्यतः तीन कारणों से उत्पन्न होता है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों या लघु नगरीय केंद्रों में रोजगार के अभाव और मजदूरी कब मिलने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अधिक मजदूरी की तलाश में नगरों और औद्योगिक केंद्रों में के लिए प्रवास करते हैं।इससे नगरों में जनसंख्या का दबाव

टिप्पणी

बढ़ जाता है। अकुशल श्रमिकों के लिए पर्याप्त रोजगार यहाँ भी उपलब्ध नहीं होने से वे बेरोजगार हो जाते हैं। इससे नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

– आर्थिक मंदी या उद्योगों में उत्पादन में ह्रास होने के कारण कुछ उद्योगों को बंद कर दिया जाता है। इन में कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। सन 1930 में विश्वव्यापी मंदी के कारण उद्योगों के उत्पादन में ह्रास होने से ब्रिटेन सहित अनेक पश्चिमी यूरोपीय देशों में औद्योगिक जनातिरेक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

– कुछ उद्योगों के कंप्यूटरीकृत होने से उनमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। आधुनिक मशीनों का प्रयोग होने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है और श्रमिकों की छंटनी करनी पड़ती हैं।

औद्योगिक जनाधिक्य विकसित और विकासशील दोनों देशों में पाया जाता है परंतु इसके कारण और प्रकृति में अंतर देखे जा सकते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

11. "अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है"– यह किसकी परिभाषा है?

    (क) डाल्टन की (ख) साउंडर्स की

    (ग) पीटरसन की (घ) सावी की

12. जनसंख्या जनाधिक्य कितने प्रकार का होता है?

    (क) पांच (ख) चार

    (ग) तीन (घ) दो

2.8 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (घ)
4. (ग)
5. (ख)
6. (क)
7. (घ)
8. (क)
9. (ख)
10. (ग)

11. (क)

12. (घ)

2.9 सारांश

टिप्पणी

प्रयोग सिद्ध बनाम सैद्धांतिक वितरण के बीच के अंतर की चर्चा की हम अपने आंकडों तथा एक अंतर को बढ़ाने वाली प्रक्रिया के संभावित मॉडल के बीच की भिन्नताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे चर/चरों की प्रयोगसिद्ध, आवृत्ति या देखे गये वितरण में भिन्नताएं होती हैं जिन्हें हम हमारे आंकडों में सीधे–सीधे देख सकते हैं।

भूतल पर जनसंख्या के वितरण में आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक परिवर्तन होता रहा है। यद्यपि परिवर्तन की गति व दिशा देश– काल के अनुसार भिन्न भिन्न रही है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण अत्यधिक विषम है।

औद्योगिक क्रांति के बाद खनिज पदार्थों की उपलब्धि ने जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित किया है। सोना,चांदी,हीरा प्लेटिनम,तांबा,लोहा बॉक्साइट जस्ता अति महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है और यह विश्व में कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं। कोयला पेट्रोलियम थोरियम यूरेनियम आदि शक्ति के साधन है जिनके द्वारा उद्योग और परिवहन को संचालित किया जाता है। यूरोप के जिन भागों में लोहा या कोयला या अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या सगन पाई जाती है इसी कारण से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के शुष्क भागों में पेट्रोलियम पदार्थ के मिलने से जनसंख्या के बसाव उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध' में जनसंख्या के बारे में अपने विचारों को प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने पिता और गॉडविन द्वारा साझा किए गए प्रचलित आशावाद के खिलाफ विद्रोह किया कि एक आदर्श राज्य हो सकता है, अगर मानवीय बाधाओं को दूर किया जा जाये तो।

माल्थुसियन सिद्धांत को मार्क्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि समाजवादी समाज में उनके विचार फिट नहीं थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मार्क्स और एंगेल्स ने कोई जनसंख्या सिद्धांत तैयार नहीं किया , उन्होंने केवल बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिसके अनुसार विश्व जनसंख्या के आकार और उसके सामाजिक–आर्थिक सहसंबंधों का निर्धारण होता है। मार्क्स ने माना कि जनसंख्या वृद्धि का कोई प्राकृतिक सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है और जोर देकर कहा : ''उत्पादन के हर ऐतिहासिक तरीके के अपने विशेष कानून होते हैं जिसके अंदर जनसंख्या और इसकी सीमा तय होती है।

एक वृद्धिशील जनसंख्या वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार, बड़ा कार्यबल, जनांकिकीय लाभांश के लाभ, अधिक नवाचार, कुल उत्पादन में वृद्धि और बहुत कुछ प्रदान करके आर्थिक विकास में सहायता करती है। यद्यपि, यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। तीव्र गति से वृद्धि करती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक भी बनती है।

टिप्पणी

जनसंख्या और संसाधनों के परस्पर संबंधों की पूर्ण जानकारी हेतु संबंधित प्रदेश की जनसंख्या के आकार, प्रौद्योगिक स्तर और प्रकृति के साथ–साथ वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों की मात्राओं की गुणवत्ता का ज्ञान भी आवश्यक होता है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए मानव संसाधन का भी उपयुक्त रूप से होना आवश्यक है क्योंकि संसाधनों का दोहन और संरक्षण मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। किसी भी देश में उपस्थित प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पर्यवेक्षण तथा सर्वेक्षण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

2.10 मुख्य शब्दावली

- **पर्यटन** : एक स्थान से दूसरे लोकप्रिय स्थान का भ्रमण।
- **जनाधिक्य** : जनसंख्या का अधिक होना।
- **अधोजनसंख्या** : जनसंख्या का कम होना।
- **स्थलाकृति** : धरातल की आकृति।
- **नियंत्रक प्रतिबंध** : नियंत्रण संबंधी अवरोध।

2.11 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या की ऊंचाइयों आधारित संकल्पना से क्या आशय है?
2. घनत्व सूचनात्क क्या है?
3. जनांकिकीय कारक क्या होते हैं?
4. जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत क्या है?
5. जनसंख्या वितरण के भौतिक कारक बताइए?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या वितरण तथा घनत्व की अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए?
2. जनसंख्या घनत्व वृद्धि के सैद्धांतिक मुद्दे स्पष्ट कीजिए।
3. जनसंख्या वितरण–वृद्धि के पारंपरिक व आधुनिक सिद्धांतों का परिचय दीजिए।
4. विश्व जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप व निर्धारक विवेचित कीजिए।
5. अधोजनसंख्या एवं अतिजनसंख्या की संकल्पना रेखांकित कीजिए।

2.12 सहायक पाठ्य सामग्री

Census of India. 1991 : A state Profile.

Clarke, John L 1973 : Population Geography, Pergamon Press, Oxford.

Mamona, C.B. 1981 : India's populations Problem, Kitab mahal N-Delhi.

United nations 1974 : Methods for projections and Urban and Rural Populations No. VIII, New York.

King, Leslie. 1986 : Central place Theory, Saga Punlications New Delhi.

Nangia, Sudesh. 1976: Delhi Metropolitan Region. K.B. Publications New Delhi.

Ramchandran. R. 1992 : Urbanisation and Urban Systems in India, Oxford University Press, N. Delhi.

Singh. R.L. and Kashi nath singh (editor) 1975 : Readings in Rural settlement Geography, National Geographic society of India.

टिप्पणी

इकाई 3 जनसंख्या संरचना

टिप्पणी

संरचना

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 जनसंख्या की संरचना एवं विशिष्टता
  3.2.1 आयु और लिंग
  3.2.2 ग्रामीण और शहरी संरचना
  3.2.3 नगरीकरण
  3.2.4 व्यावसायिक संरचना
  3.2.5 लैंगिक मुद्दे
3.3 भारतीय जनसंख्या की संरचना
  3.3.1 जनसंख्या प्रवास
  3.3.2 जन्मदर एवं मृत्युदर का मापन
  3.3.3 प्रवासन : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप
  3.3.4 भारत की जनसंख्या गतिकी
3.4 जनसंख्या और विकास
  3.4.1 भारत के जनसंख्या–संसाधन प्रदेश
  3.4.2 सामाजिक–आर्थिक विकास तथा जनसंख्या स्तर
3.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
3.6 सारांश
3.7 मुख्य शब्दावली
3.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

3.0 परिचय

जनसंख्या के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द 'संरचना' आम तौर पर सकल और साधरण से परिष्कृत और विशिष्ट जनसंख्या के लिए एक मील का पत्थर है। यह संरचना एक जनसंख्या की एक या एक से अधिक व्यक्तिगत विशेषताओं और गुणों के वितरण को दर्शाती है। ऐसे सामूहिक लक्षण जिनसे एक विशेष समय पर किसी जनसंख्या की अनूठी संरचना का निर्माण होता है, या जिनसे एक विशेष समयावधि के दौरान एक परिवर्तशील ढाँचे का निर्माण होता है उन्हें संघटक कहा जाता है। ऐसे परिवर्तनशील जनसांख्यिकीय लक्षण जिनसे जनसंख्या को उम्र, लिंग और वैवाहिक स्थिति के अनुसार या सामाजिक संगठन के मौलिक चरों जैसे, राष्ट्रीयता, जाति, रंग, भाषा, धर्म, शिक्षा के अनुसार अथवा आर्थिक आधर पर श्रम शक्ति दर्जा, पेशा और उद्योग के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके उनको संघटक कहा जाता है। जे. आई. क्लार्क के अनुसार, जनसंख्या का ढाँचा, जनसंख्या के उन पहलुओं को दर्शाता है जिन्हें मापा जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं होते।

जनसंख्या संरचना एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय बनावट को दर्शाती है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना रोग और मृत्यु की

टिप्पणी

घटनाओं को प्रदर्शित करने में उपयोगी है। उदाहरण के लिए, दो समान आकार के समुदायों को एक समान स्वास्थ्य देखभाल की जरुरत नहीं है, भले ही दूसरे की तुलना में एक की जनसंख्या कम हो, अधिक समृद्ध हो या नस्ली तौर पर एक समान ही क्यों न हो। एक दिए गए क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं, प्रजनन के प्रभावों, मृत्यु दर और प्रवासन प्रक्रियाओं के लिए मांग के अपेक्षाकृत कम स्तरों की सूचना प्रदान कर सकती है।

इस इकाई में, आप जनसंख्या संरचना एवं विशिष्टता तथा भारतीय जनसंख्या की संरचना को समझते हुए जनसंख्या और विकास के पहलू से अवगत होंगे।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- जनसंख्या संरचना और इसकी विशेषताओं को समझ पाएंगे;
- भारतीय जनसंख्या की संरचना से अवगत हो पाएंगे;
- जनसंख्या और विकास के पहलू की विवेचना कर पाएंगे।

3.2 जनसंख्या की संरचना एवं विशिष्टता

जनसंख्या ढाँचा (संरचना) एक ऐसा सक्रिय कारक है जो जनसंख्या वृद्वि के स्वभाव और आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति एवं इसकी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। जनसंख्या ढाँचे के वास्तविक रूपांतरण और वितरण स्पष्ट रूप से भूगोल से संबंधित हैं। भूगोलवेत्ता भी एक क्षेत्र विशेष के भौगोलिक व्यक्तित्व की भिन्नता को समझने के लिए आयु–संरचना, लिंग–संरचना और व्यावसायिक–संरचना के स्थानीय विश्लेषण में रुचि रखते हैं।

भिन्नता और निर्धारक

जनसंख्या संरचना प्रायः विभिन्न राष्ट्रों और एक राष्ट्र के विभिन्न भागों के बीच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बदलाव विभिन्न कारकों के एक परिचालक के संचालन का परिणाम हैं। जनसांख्यिकीय भिन्नता के बीच कुछ प्रमुख कारक हैं जो जनसंख्या के संरचना को आकार देने में अति गंभीर भूमिका निभाते हैं, जैसे प्रजनन, मृत्युदर और प्रवासन। इसके अतिरिक्त, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक कारक भी जनसंख्या संरचना को कभी–कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी–कभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

जनसंख्या में जीवित बच्चे का जन्म प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। यह जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। मृत्यु दर जनसंख्या संरचना में बदलाव के लिए विशेष होती है। मृत्यु दर के स्तर विशिष्ट होते हैं, इसलिए यह जनसांख्यिकीय संरचना के महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में गिनी जाती है। प्रवासन तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जनसंख्या की संरचना को बदल सकती है।

जनसंख्या संरचना की विशेषताएँ

टिप्पणी

जनसंख्या संरचना में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:–

- जनसांख्यिकीय विशेषताएँ जैसे कि उम्र और लिंग
- सामाजिक विशेषताएँ जैसे कि जाति, नागरिकता और वैवाहिक स्थिति
- आर्थिक विशेषताएँ जैसे कि आर्थिक गतिविधियाँ

जब जनसंख्या का आकार, इसका केन्द्रीयकरण और वितरण एक जनसंख्या के बाजार क्षेत्र को दर्शाते हैं तो जनसंख्या की विशेषताओं की समीक्षा के लिए अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्ति या समूह बीमार होने के एक समान जोखिम पर नहीं हैं या समाज की स्वास्थ्य सेवाओं का एकसमान उपभोग नहीं कर रहे हैं। जनसांख्यिकीय कारक जैसे कि उम्र, आयु वर्ग और लिंग, व्यक्तियों और समूहों के औसत जोखिम को निर्धारित करने के लिए बहुमूल्य सूचना प्रदान करते हैं। समग्र तौर पर ये चर परिवर्तनशील चिन्हित संरचनात्मक उपाय हैं।

जनसंख्या संरचना एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय बनावट को दर्शाती है। एक क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना रोग और मृत्यु के घटने को व्यक्त करने में उपयोगी है, और इसीलिए स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता और मांग है। दो समान आकार के समुदायों को एक समान स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत नहीं है। भले ही दूसरे की तुलना में किसी एक की जनसंख्या, अधिक विशाल, समृद्ध या नस्ली तौर पर एक समान ही क्यों न हो। स्वास्थ्य संबधी आचरण, धूम्रपान करने वाले लोग आदि भी ऐसे कारक हो सकते हैं।

समय के साथ जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन संबंधी जानकारी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि एक दिए गए क्षेत्र की वर्तमान जनसांख्यिकीय संरचना एक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन क्षमता का प्रभाव, मृत्यु दर, और प्रवासन प्रक्रियाओं के लिए मांग के अपेक्षाकृत कम स्तर को सूचित कर सकती है। इसकी मौजूदा संरचना का परिणाम भविष्य में मांग के एक बहुत ज्यादा भिन्न स्तर के रूप में हो सकता हैं।

जनसंख्या संरचना संबंधी परिवर्तन आम तौर पर वर्णनात्मक सोच के अनुरूप होते हैं। शुरू में इनकी उपयोगिता इनके लक्षणों के संदर्भ में किसी जनसंख्या की रूपरेखा उनकी योग्यता से व्युत्पन्न होती है। किसी क्षेत्र का उम्र विभाजन, नस्लीय ढाँचा, आय स्तर, और धर्म विशेषताओं के विविध प्रकार हैं जो किसी जनसंख्या को स्वरूप प्रदान करते हैं।

3.2.1 आयु और लिंग

आयु

किसी व्यक्ति की आयु उसका विशिष्ट गुण होती है। यह उसके जन्म से शुरू होती है और लगातार तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि उम्र लगातार परिवर्तनशील है, जो जन्म से ही तब तक तेजी से बढ़ती रहती है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। हालांकि किसी जनसंख्या या समस्त व्यक्तियों की आयु को इतनी आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह या तो

टिप्पणी

इसके सभी सदस्यों की कुल आयु के रूप में या इसके सदस्यों की आयु की आवृत्ति वितरण के रूप में अथवा केन्द्रीय प्रवृत्ति जैसे कि अंकगणितीय औसत आदि कुछ उपायों के रूप में या एक मध्य रेखा, की कल्पना हो सकती है। व्यक्तियों के समूह की आयु भी किसी जनसंख्या के लिए विशिष्ट होती है और समय के साथ–साथ बदलती रहती है।

किसी जनसंख्या की लगातार परिवर्तनशील आयु, वर्ष, माह या समय सबसे छोटी इकाई के संदर्भ में विभिन्नता प्रदान कर सकती है। इस निरंतरता के कारण इसके आयु–संरचना अध्ययन के लिए कुछ सुविधाजनक वर्गों में आयु को व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न अनियंत्रित समूहीकरण हो सकते हैं। एक वर्ष के आयु वर्ग, पाँच वर्ष के आयु वर्ग और दस वर्ष के आयु वर्ग को अपनाया गया है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष वर्गों को भी अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक गतिविधियों और बहुत ज्यादा व्यापक समूह क्षमता में आयु संरचनाओं के निहितार्थ के अध्ययन में जिसका आर्थिक रूप से उत्पादक के साथ सीधा संबंध है; जनसंख्या के आश्रित खंडों को अपनाया जा रहा है।

पूर्व–वयस्क आयु समूह

पूर्व–व्यस्क आयु समूह में या तो 15 या 20 वर्ष की आयु से नीचे के व्यक्तियों को रखा जाता है जिसे आश्रित किशोर का वर्ग भी कहा जाता है। भारतीय जनगणना में 15 वर्ष आयु से नीचे के व्यक्तियों को इस समूह के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

विकासशील देशों में जनसंख्या का 40 प्रतिशत से अधिक भाग 15 वर्ष की आयु के बच्चों से बना है, जबकि औद्योगीकृत राष्ट्रों में इस वर्ग में जनसंख्या की एक चौथाई से केवल कुछ अधिक जनसंख्या ही होती है। भारत में कुल जनसंख्या की लगभग 41 प्रतिशत जनसंख्या 15 वर्ष की उम्र से कम है, और केवल 11 प्रतिशत व्यक्ति ही 50 वर्ष और उससे अध्कि आयु वर्ग में हैं। अधिकांश देशों की तरह ही भारत की शहरी जनसंख्या भी ग्रामीण जनसंख्या से न केवल इसकी व्यवसायिक संरचना, विकास दर और लिंग संरचना बल्कि इसकी आयु संचना से भी अलग है। शहरी आबादी में किशोरों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है।

उत्पादक आयु समूह

20 से 64 या 15 से 59 वर्ष आयु सीमा में आने वाले व्यक्तियों को इस समुह के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस समूह के सदस्य किसी राष्ट्र के श्रमबल की सैद्धांतिकता का प्रतिनिधत्व करते हैं। हालांकि, इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी आमतौर पर बहुत कम होती है।

सेवा–निवृत्त आयु समूह

यह दूसरा आश्रित आयु वर्ग है जिसमें 60 या 65 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति शामिल हैं। भारतीय जनगणना में 60 वर्ष और इससे ऊपर के व्यक्तियों को इस समूह के अंतर्गत माना जाता है। इस समूह के व्यक्तियों को वृ(आयु और कमजोर शरीर के कारण कार्य के योग्य नहीं माना जाता है।

लिंग

टिप्पणी

लिंग जनसंख्या संरचना में एक आसानी से विचार योग्य तत्व संस्थापित है और एक सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता है।

मूल रूप से किसी जनसंख्या की लिंग संरचना तीन कारकों : पुरुष जन्मों के आधिपत्य से संबधित, पुरुषों के बीच मृत्यु की अपेक्षाकृत उच्च घटना और लिंग चयनात्मक प्रवासन से निर्धरित होता है। इन तीन कारकों के अतिरिक्त जिसे साधारण तौर पर मुख्य निर्धारक के रूप में माना जाता है, वह सामाजिक रिवाज और परंपराएं हैं, जिन्हें चौथे कारक के रूप में माना जा सकता है। यह चौथा कारक भारत में पाए गए लिंग अनुपात में क्षेत्रीय बदलावों का सबसे अधिक प्रभावशाली निर्धारक है।

वास्तव में, पुरुष का ज्यादा जन्म और महिला शिशुओं की उच्च अस्तित्व प्रत्याशा एक सार्वभौमिक घटना है। यह कारक वास्तव में लिंग संरचना में बदलाव और क्षेत्रीय असमानता लाता है। निश्चित रूप से ऐसे साक्ष्य दर्शाते हैं कि औद्यौगीकृत और विकसित देशों में या किसी असामान्य रूप से प्रचुर मात्रा में संसाधन प्रवासन के देशों में यह प्रमुख निर्धारक है।

आयु – लिंग संरचना

किसी जनसंख्या की सामुदायिक आवश्यकताएँ और मांग उत्पादों, सेवाओं, और अर्थिक अवसरों के साथ साथ उपभोग के तरीकों, जीवन शैली, और समाजिक आचरण आदि आयु–लिंग संरचना से प्रभावित होती है। ऐसा आयु–लिंग संरचना में बदलाव के कारण होता है और इससे जनसंख्या विकास या पतन एवं मांग में परिर्वतन होना स्वाभाविक है। किसी समुदाय की आयु–लिंग संरचना सभी संस्थानों पर अच्छा–बुरा प्रभाव छोड़ती है। यह दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, लेकिन आयु–लिंग संरचना में परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में जटिल होता है जहां ये जनसंख्या के छोटे आकार, भौगोलिक अलगाव, अपर्याप्त समझौतों अथवा कुछ सीमित संयोजित ताकतों के द्वारा प्रभावित होते हैं। सार्वजनिक नीति निर्धारक, बिज़नेस लीडर और कार्यक्रम प्रबन्धक लगातार एहसास करते हैं कि जनसांख्यिकीय संरचना, और विशेषकर लिंग और आयु, इसके अतिरिक्त जनसंख्या आकार और परिवर्तन की जानकारी, भविष्य के कर्तव्यों और योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त, आयु–लिंग संरचना में परिवर्तन – प्रजनन क्षमता, मृत्युदर, और प्रवासन की मौलिक जनसांख्यिकीय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एक साथ ये प्रक्रियाएं किसी जनसंख्या की आयु–लिंग संरचना को निर्धरित करती हैं। आयु–लिंग संरचना की प्रकृति में प्रजनन क्षमता, मृत्युदर और प्रवासन के वर्तमान और भविष्य के स्तरों को प्रभावित करती हैं।

मूल धरणा : किसी जनसंख्या की आयु–लिंग संरचना जन्म, मृत्यु और प्रवासन दर की भविष्यवाणी करने में जनसांख्यिकी विशेषज्ञ की सहायता करती है। किसी जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना एक जनसंख्या पिरामिड, क्षैतिज बार रेखांकन की शृंखला के रूप में सामान्यतः चित्रित हैं।

कोहोर्ट एक ही समय के आसपास जन्मे लोगों का एक समूह होता है। इस मामले में, पाँच वर्ष की समय सीमा में जन्में लोग समय के आधार पर सामान्य अनुभव

टिप्पणी

और दृष्टिकोण साझा करते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड बनाने के लिए, हम प्रत्येक कोहोर्ट के लिए दो बार ग्राफ निर्माण करते हैं– एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। हम इसको शुरू से अंत तक, एक शून्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पंक्ति से अलग रखते हैं। आम तौर पर दर्शाए गए पिरामिड के बाईं तरफ पुरुषों की संख्या का प्रतिशत होता है जो कि प्रत्येक कोहोर्ट का निर्माण करता है और दाईं तरफ महिलाओं की संख्या या प्रतिशत दर्शाए जाते हैं। मान लीजिए पिरामिड के आधार पर आयु 0–4 कोहोर्ट गठित है और शीर्ष बिंदु पर आयु 70–90 + कोहोर्ट गठित है। जनसंख्या पिरामिड हमें कोहोर्टों के आकार की तुलना करने और प्रत्येक कोहोर्ट में पुरुषों और महिलाओं की संख्या या प्रतिशत की तुलना करने की अनुमति देता है।

- जनसंख्या पिरामिड एक विशिष्ठ समय में विभिन्न कोहोर्टों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का छायाचित्रा प्रदान करता है। साधारण तौर पर किसी देश के जनसंख्या पिरामिड तीन आकारों व्यापक, संकोचक या अपरिवर्तित में से एक के अनुरूप होते हैं। व्यापक पिरामिड त्रिकोणीय होता है। यह आधार पर विस्तृत होता है, और प्रत्येक क्रमिक बार नीचे से ऊपर एक के बाद एक अपेक्षाकृत छोटा होता है। व्यापक पिरामिड कोहोर्ट का संबंधित आकार दर्शाता है। यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और अधिकतर लोग युवा हैं। एक संकोचन पिरामिड मध्यस्थिति की तुलना में आधार पर संकरा होता हैं। इसका आकार दर्शाता है कि जनसंख्या में अधिकतर मध्य आयु वर्ग और विस्तृत लोग हैं। अपरिवर्तित पिरामिड संकोचक पिरामिड के बराबर होता है। वृत्त की तुलना में अन्य सभी कोहोर्ट मोटे तौर पर बराबर आकार के होते हैं। चित्र दर्शनीय है–

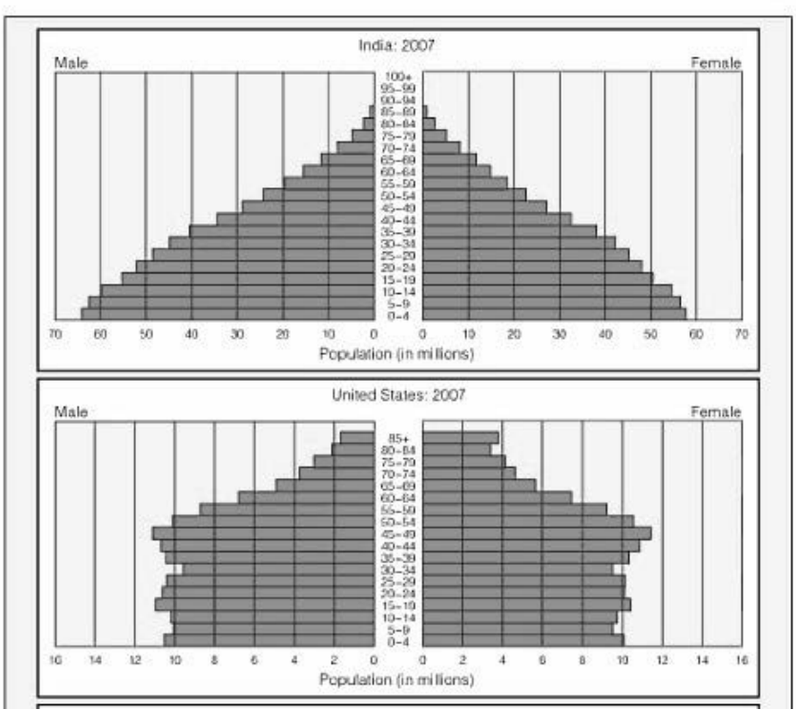

- आयु–लिंग सरंचना का ज्ञान जनसांख्यिकी विशेषज्ञों को जन्म, मृत्यु और प्रवासन दर की भविष्यवाणी करने में मदद देता है। उदाहरण के लिए, भारत की

टिप्पणी

जनसंख्या में 60 प्रतिशत पुरुष हैं और 15–54 वर्ष आयु वर्ग महिलाओं के लिए प्रसव की उम्र है। इससे यह वास्तविकता समझने में मदद मिलेगी क्योंकि भारत में जन्म दर अमेरिका की तुलना में अधिक है और भारत की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष लगभग 15.4 मिलियन व्यक्तियों की दर से बढ रही है। आयु–लिंग संरचना की जानकारी यह समझने में भी मदद देती है कि भारत की मृत्यु दर अमेरिका की मृत्यु दर से कम क्यों है। भारत में मृत्यु दर प्रति 8 व्यक्तियों में से 1 है, जबकि अमेरिका में मृत्यु दर 7 व्यक्तियों में से 1 है। अमेरिका की 12 प्रतिशत जनसंख्या लगभग 65 वर्ष से अधिक है, जबकि भारत में यह जनसंख्या केवल 5 प्रतिशत ही है।

- हम आयु–लिंग संरचना के विषय में जानते हैं तो लिंग अनुपात की गणना प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या अन्य अपरिवर्तनशील अधिमान्य, जैसे कि 10, 100 या 10,000 की संख्या में कर सकते हैं। भारत का जनसंख्या पिरामिड 0–4 उम्र के आयु वर्ग में लगभग 6 करोड़ और 50 लाख पुरूषों तथा 5 करोड़ 60 लाख महिलाओं को दर्शाता है। जो 1,000 पुरुषों पर 900 महिलाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। लिंग अनुपात पुरुषों को बहुत समर्थन देता हैं क्योंकि यह कन्या शिशु–हत्या की प्रथा, महिलाओं की सामान्य उपेक्षा, मातृक मृत्यु–दर, और प्रवासन दर से प्रभावित है। पुरुषों के अनुरूप महिलाओं के महत्व को लेकर सांस्कृतिक विश्वास और मूल्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में चीन के अनुरूप बेटों का मूल्य बेटियों की तुलना में अधिक है। क्यों? परंपरा द्वारा किसी पुरुष की दुल्हन उसके माता–पिता के साथ रहती है और उनकी वृद्धावस्था में देखभाल करती है। जब एक बेटा विवाह करता है तब दुल्हन का परिवार उसके परिवार को दहेज का भुगतान करता है।

साक्षरता और शिक्षा

आसान शब्दों में साक्षरता समझने के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है।

कुछ समय तक 'तीसरी दुनिया' शब्द के प्रयोग के बारे में अस्पष्टता थी। लेकिन इसके साथ ही यह भी सोच लेना चाहिए कि स्पष्टता तो यहां पर पहली और दूसरी दुनिया भी जरूर होनी चाहिए। अग्रांकित सारिणियों में इसी संदर्भ में आँकड़ों को एक हद तक एक सीमांक के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह पारंपरिक परिभाषा नहीं है लेकिन फिर भी इससे दुनिया की विभिन्न व्यवस्थाओं की स्थापनाओं को एक मापदंड के अनुसार दर्शाने में मदद मिलती है।

साक्षरता और जनसंख्या विकास दर के रूप में पारिभाषित मूल्यों के साथ सीमाओं एवं परिणामों के रूप में अनिर्णित है। पहली दुनिया की सारी जनसंख्या की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक है, जबकि विकास दर 0.60% से नीचे स्थित है। दूसरी दुनिया के संदर्भ में साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक जबकि विकास दर 0.60 और 0.88 के बीच है। अंत में, तीसरी दुनिया की साक्षरता दर 12 प्रतिशत से अधिक, जबकि विकास दर 0.99 और 3.83 के बीच है।

टिप्पणी

विकास दर एवं साक्षरता के एक प्रकार्य के रूप में विश्व की प्रथम जनसंख्या महिलाओं की साक्षरता को छोड़कर 2008 का डेटा							
देश	जनसंख्या	पुरूष	महिला	विकास दर	साक्षरता दर	महिला की साक्षरता दर	औसत आयु
रूस	140,702,094	64,928,065	72,774,029	−0.47	99.40%	99.50%	45
जापान	127,288,419	92,083,345	65,205,074	−0.14	99.00%	99.00%	45
पोलैंड	38,500,696	18,659,067	19,841,629	−0.05	99.80%	99.70%	45
जर्मनी	82,369,548	40,482,726	41,886,822	−0.04	99.00%	99.00%	45
इटली	58,145,321	28,485,387	29,659,934	−0.02	99.40%	99.30%	45
स्पेन	40,491,051	19,784,905	20,706,146	−0.10	99.00%	97.20%	45
यूनाईटेड किंगडम	60,943,912	30,172,796	30,771,116	−0.28	99.00%	99.00%	45
फ्रांस	64,057,790	31,312,486	32,745,304	−0.57	99.00%	99.00%	45

पहले साक्षरता दर में कुछ परस्पर व्यापता होने के कारण कुछ भ्रम रहा होगा। निर्धारक कारकों को ध्यान में रखते हुए आम देखेंगे कि क्यों एक देश को तीसरे विश्व के क्रम में मुख्यतः इसकी जनसंख्या विकास दर के आधर पर स्थित किया गया है। प्रत्येक देश कई समानताएं साझा करते हैं, इसलिए इस तालिका का वर्णन अधिक प्रभावशाली ढंग से हुआ है। कुछ क्रम में कुछ देश इस श्रेणी से बाहर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका, चीन, इरान और भारत। इसलिए इनकी विकास दर के भाग के लिए इनके प्रवृत्ति क्रम का स्थान सही ठहरता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, अन्य तालिकाएं दी गई हैं, जिनमें सामाजिक संरचना मामलों जैसे दुनिया के उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को आसानी से संदर्भित किया जा सकता था। इस तरह के वर्गीकरण से विवाद समाप्त नहीं होता। सभवतः और अधिक बेहतर अभिव्यक्ति का एक समूह पुरानी दुनिया, नई दुनिया और भविष्य की दुनिया के लिए प्रयोग किया गया होता। अगर कोई चाहता है तो इन संदर्भों को शब्दिक रूप से लिया जा सकता है। एक दूसरे अर्थ में ये वास्तविक रूप से लाक्षणिक हैं। हालांकि, भारत भविष्य के विश्व व्यवस्था में मध्य भाग में होने के साथ नई विश्व व्यवस्था में एक हिस्से के रूप में अमेरिका, चीन और ईरान में पफार्मिंग से शायद कम विवादास्पद है। जब आँकड़ों की समीक्षा की जाती है तब यह समझा जाता है कि क्यों एक देश एक निश्चित तालिका में प्रकट होने के लिए विकास दर के साथ नहीं है। इसके लिए दृढ़ निर्धारक कारक हैं। यह प्रत्येक की संवेदनशीलता के लिए किसी भी संकट को कम कर देगा। तालिका में दिखाया जा रहा है कि रूस और जापान शीर्ष पर हैं। पहली दुनिया या पुरानी दुनिया या उच्च वर्ग, इसका चुनाव करना पाठक पर छोड़ दिया गया है। सूची उन देशों के लाभों को दर्शाती है जिनकी उच्च साक्षरता से मिलकर सबसे कम जनसंख्या विकास दर है।

चीन और थाईलैंड हमें दूसरी दुनिया में लाते हैं जो जनसंख्या दर और अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता के साथ उन्नति का नेतृत्व करते हैं। अमेरिका उच्च साक्षरता दर के साथ लेकिन अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या विकास दर के कारण अंतिम स्थान को बनाए हुए है।

टिप्पणी

यहां पर ऐसे विवाद का कुछ स्पष्ट अर्थ है। अगर यह उच्च जनसंख्या विकास दर के लिए नहीं थी तो अमेरिका निश्चित रूप से पहली दुनिया में होता। चुँकि विशेषकर अमेरिका एक प्रौढ़ जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, पहली दुनिया का एक और सूचक है। इस मामले में अभी तक प्रौढ़ जनसंख्या में एक अच्छी चिकित्सा प्रणाली और उच्च जीवन आशा या घटना भी हो सकती है। पहली दुनिया के देशों के मामलों को रखने के रूप में उपरोक्त सभी कुछ लागू होता है और जनसंख्या वृद्धि में कमी महत्वपूर्ण स्वीकार्य कारक है।

इसे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक समृद्ध विरासत के साथ एक देश जैसा दिखता है। चीन में कोई भी सोच सकता है कि वे पहली दुनिया के जैसे बन सकेंगे। यह अमेरिका, चीन और भारत जो तीसरी दुनिया है; जैसे देशों में प्रकट होगा, जिनके पास इन सभी तीनों दुनियाओं के आगे जीने की योग्यता होगी।

विकास दर एवं साक्षरता के एक प्रकार्य के रूप में विश्व की द्वितीय जनसंख्या							
2008 का डेटा							
देश	जनसंख्या	पुरूष	महिला	विकास दर	साक्षरता दर	महिला की साक्षरता दर	औसत आयु
चीन	1,330,044,544	684,251,523	645,793,082	0.63	90.90%	78.80%	35
थाइलैंड	65,493,298	32,384,771	33,108,527	0.64	92.60%	94.60%	30
इरान	65,875,223	33,352,625	32,522,598	0.79	82.50%	73.00%	30
कनाडा	33,212,696	16,522,000	16,789,000	0.83	99.00%	99.00%	45
दक्षिण अफ्रीका	48,782,755	24,254,778	24,527,977	0.83	82.40%	85.70%	25
अमेरिका	304,059,724	149,000,000	153,400,000	0.88	99.00%	99.00%	45

यह दिलचस्प है कि चीन, ईरान अमेरिका दूसरी दुनिया के समान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, जब इन तीनों देशों पर दृष्टि डाली जाती है तब यह नई दुनिया क्रम के सदस्यों के रूप में इस श्रेणी में एक बेहतर संदर्भ बना सकते हैं। कुछ देश जो विश्व के मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव को रखते हैं विशेषकर इस क्रम में अनुकुल संस्थाओं के संदिग्ध विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं। या दूसरे तरीके से वर्णन किया जाए तो वे भविष्य के दुनिया या तीसरी दुनिया पर डालने वाले बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव को सामाजिक दृष्टि से स्थापित कर सकते हैं।

विकास दर एवं साक्षरता के एक प्रकार्य के रूप में विश्व की तृतीय जनसंख्या							
2008 का डेटा							
देश	जनसंख्या	पुरूष	महिला	विकास दर	साक्षरता दर	महिला की साक्षरता दर	औसत आयु
वियतनाम	86,116,559	42,685,467	43,432,092	0.99	90.30%	92.30%	25
ट्यूनिशिया	10,383,577	5,229,457	5,153,820	0.99	74.30%	65.30%	30
टर्की	75,793,836	37,226,582	37,567,254	1.01	87.40%	79.60%	30
कतर	824,789	550,568	274,221	1.09	89.00%	88.60%	30
मेक्सिको	109,955,400	53,822,620	56,132,780	1.14	91.60%	89.60%	25
लेबनान	3,971,941	1,930,017	2,041,924	1.15	88.30%	82.20%	25
इंडोनेशिया	237,512,355	118,825,333	118,687,022	1.18	90.40%	86.80%	30
अलजीरिया	33,769,669	17,008,087	16,761,582	1.21	69.90%	61.00%	25
ब्राजील	196,342,587	97,109,121	99,233,466	1.23	88.60%	88.80%	30

टिप्पणी

बहरीन	718,306	388,890	319,416	1.34	86.50%	85.00%	20
मोरक्को	34,343,219	17,118,613	17,224,606	1.51	52.30%	39.60%	25
भारत	1,147,995,904	591,681,864	556,341,034	1.58	61.00%	48.30%	25
मिश्र	81,713,517	41,186,961	40,526,558	1.68	71.40%	59.00%	25
इजराइल	7,112,359	3,465,446	3,547,913	1.71	91.70%	95.90%	30
घाना	23,382,848	11,708,895	11,673,953	1.93	57.90%	67.10%	20
दक्षिण अरब	28,146,657	15,285,286	12,681,371	1.95	82.90%	70.80%	20
फिलीपींस	96,061,683	48,061,497	48,000,186	1.99	92.60%	95.80%	25
पकिस्तान	172,800,051	88,319,237	84,480,814	2.00	49.90%	36.00%	20
नाइजीरिया	146,255,306	74,567,270	71,688,036	2.03	69.10%	60.60%	20
तंजानिया	40,213,162	19,904,505	20,308,657	2.07	69.40%	70.70%	20
सूडान	40,218,455	20,377,631	19,840,824	2.13	60.90%	50.50%	20
सइना	19,747,586	10,109,770	9,637,816	2.19	80.80%	73.60%	20
लीबिया	6,173,579	3,162,824	3,010,755	2.22	84.20%	72.00%	25
पश्चिम बैंक	2,407,681	1,225,627	1,182,054	2.23	92.00%	80.00%	25
जोर्डन	6,198,677	3,250,501	2,948,176	2.34	91.10%	84.70%	25
इराक	28,221,181	14,280,744	13,940,437	2.56	79.00%	24.40%	20
अफगानिस्ता	32,738,376	16,760,104	15,978,272	2.63	28.00%	12.60%	25
केन्या	37,953,838	19,022,143	18,931,695	2.76	73.60%	79.70%	20
ओमान	3,311,640	1,826,126	1,485,514	3.19	81.40%	73.50%	20
इथोपिया	82,544,838	40,618,659	41,926,179	3.21	35.90%	35.10%	20
कांगो	66,514,506	33,058,982	33,455,524	3.24	67.20%	55.10%	20
गाजा	1,500,202	764,038	726,162	3.42	92.00%	88.00%	25
यमन	23,013,376	11,695,782	11,317,594	3.46	54.00%	30.00%	20
कुवैत	2,596,799	1,570,000	1,026,512	3.59	93.00%	91.00%	30
संयुक्त अरब अमीरात	4,621,399	3,174,048	1,447,351	3.83	88.70%	81.70%	30

तीसरी दुनिया वियतनाम और टयूनीशिया के नेतृत्व में है जबकि मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत अत्यंत घनी आबादी वाले देश हैं।

उन देशों के लिए पारंपरिक रूप से विचार पुरुष वर्चस्व के लिए हो जाता है जैसे कि अरब राष्ट्रों में साधरण तौर पर पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। पहली दुनिया जहां पर महिलाएं पुरुषों की संख्या से अधिक हैं, इनके लिए सन्निहित हैं। तीसरी दुनिया में महिलाओं के लिए साक्षरता भी पारंपरिक रूप से कम है। पहली दुनिया जहां पर यह उन पुरुषों के समान है, इसके लिए सन्निहित है। एक और अन्य विशेषता के रूप में उन समुदायों में विभिन्न जनसंख्या विकास दर अधिक है। तीसरी दुनिया में, यह कभी–कभी 2.00 से भी ऊपर है, जबकि पहली दुनिया में 1.00 से भी नीचे है। अधिकांश मामलों में यह एक पतन को दर्शाती है।

अधिकांश अरब, मध्य एशिया और अफ्रीकी समाजों में साक्षर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है और पुरुषों की संख्या को महिलाओं की संख्या से अधिक करने में सहजता होती है; क्योंकि उन देशों में पारंपरिक रूप से विचार पुरुष वर्चस्व के होते हैं। क्या इनमें कभी भी महिलाओं की आबादी पुरुषों की संख्या से अधिक तेज़ी से बढ़ेगी या क्या यह एक गलत सूचक है? यह हो सकता है कि कुछ विशिष्ट देशों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था हो जाए, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। ऐसी प्रथा भूमिका के अंतर्गत आने के लिए महिलाओं की संख्याओं को बढ़ाने की अनुमति हो सकती है।

टिप्पणी

अधिकांश मामलों में जहां साक्षरता दर असाधारण रूप से कम है और उल्लेख के रूप में जनसंख्या विकास दर 2.00 से ऊपर है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम का प्रभाव भी एक कारक हो सकता है। तीसरी दुनिया में अधिकांश देश बहुत ज्यादा इस्लाम से प्रभावित हैं। यह प्रभाव केवल अरब में ही नहीं देखा जाता बल्कि इंडोनेशिया जैसे देशों में भी देखा जा सकता है। इन सभी देशों में एक अन्य आम परिस्थिति है कि उनकी जनसंख्या की एक औसत आयु है। वे सभी अपेक्षाकृत युवा हैं। कई मामलों में औसत आयु 20 वर्ष के आसपास है। यह उस तीसरी दुनिया के रूप में प्रकट होगा जो औपचारिक रूप से इस संदर्भ में अगली पीढ़ी के रूप में हो।

आयु के अनुरूप साक्षरता और शिक्षा

युवा वयस्कों को हाल ही में स्कूली शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है– आज एक समूह के रूप में एक बड़े तबके को पुराने वयस्क समूहों की तुलना में औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा प्राप्त हो रही है। दूसरी तरपफ, बड़े व्यक्तियों को और ज्यादा अनुभव का लाभ प्राप्त हो रहा है। जब आयु पर विचार किया गया तो पता चला कि 25–35 आयुवर्ग के युवा वयस्क को सेवा–निवृत्ति की आयु 56–65 वर्ष के वयस्कों की तुलना में उच्च साक्षरता प्राप्त हैं। लेकिन विभिन्न देशों बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड, पोलैंड में बहुत से महत्वपूर्ण अंतर है। जहाँ दो आयु समूहों के लिए औसत साक्षरता स्कोर के बीच का अंतर 50 अंकों से अधिक है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और अमेरिका में यह अंतर 20 अंकों से कम है।

किसी भी देश में साक्षरता स्कोर की श्रेणी पुराने वयस्कों के लिए अधिक विस्तृत होती है। हालांकि कुछ देशों में ये श्रेणियाँ दोनों आयु समूहों के लिए काफी समान होती हैं। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में युवा और पुराने वयस्कों दोनों आयुवर्गों के लिए औसत साक्षरता स्कोर अपेक्षाकृत अधिक उच्च है। यह निष्कर्ष बताता है कि समग्र साक्षरता प्राप्ति में विभिन्न राष्ट्रों के बीच बहुत असमानता है जिसका एक प्राचीन इतिहास है। प्राप्त अनुपात से इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि नॉर्डिक देशों में सभी आयु वर्गों को एक आपेक्षित साक्षरता लाभ प्राप्त है। कुछ देशों जैसे कि अमेरिका में 26–35 और 56–65 आयु वालों के लिए स्कोर की श्रेणियों में व्यापक विस्तार है।

वैवाहिक स्थिति

एक व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति यह जानकारी देती है कि व्यक्ति विवाहित है या नहीं। वैवाहिक स्थिति को लेकर प्रश्न, जनगणना और क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र सहित कई मतदानों और आवेदन फॉर्मों आदि में पूछे जाते हैं।

सामान्यतः इस प्रश्न का संभावित उत्तर केवल ''अविवाहित'' और ''विवाहित'' होता है। हालांकि कई बार अन्य विकल्प भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि ''तलाकशुदा'', ''विधवा'', विदुर या मृतपत्नी/मृत पति, और ''अविवाहित पार्टनर''। जब कोई व्यक्ति अविवाहित है तो तकनीकी रूप से कानूनी ''एकल'' शब्द लिखना वैधानिक है, फिर भी यह देखा गया है कि अन्य मदों को शामिल करना वांछनीय होता है। कुछ अविवाहित लोग विभिन्न कारणों से ''एकल'' नहीं लिखना चाहते हैं और वे यह वर्णन करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। कुछ मामलों में यह जानना कि व्यक्ति

अविवाहित है, इसकी तुलना में यह जानना कि वे तलाकशुदा, विधवा/विधुर, या एक रिश्ते में है ज्यादा उपयोगी होता है।

टिप्पणी

पारिवारिक स्थिति बच्चों की संख्या के साथ वैवाहिक स्थिति का संयोजन करती है। विवाह की परिवर्तनशील प्रकृति के बावजूद, विवाह, तलाक, और वैवाहिक स्थिति बेहद उपयोगी है और परिवर्तनशील जनसांख्यिकीय के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि लगभग सारी दुनिया की जनसंख्या के लिए विवाह करना एक अपेक्षित घटना है। विवाह की उपेक्षा करना, एक मुख्य जीवन नियम की उपेक्षा करना होगा जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन क्षमता की घटना और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जनसांख्यिकीय के परिचारक, और आर्थिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। वैवाहिक स्थिति का अध्ययन हमें कभी विवाह नहीं किए हुए लोगों की विशेषताओं के साथ–साथ नए विवाहित लोगों की विशेषताओं के अध्ययन द्वारा विवाह के मार्ग की जाँच करने की अनुमति देता है। निःसंदेह, विवाह और तलाक का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से वैवाहिक स्थिति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। हम समान कोहोर्ट के लिए विवाह और तलाक के डेटा की तुलना कर विवाह की अवधि का अध्ययन कर सकते हैं। विवाह के पहले और बाद की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को विवाह विघटन और पुनर्विवाह की प्रक्रियाओं का कार्य पर प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जा सकता है।

विवाह के साथ जुड़े जीवन को बदलावों को जातीय, नस्लीय, और सामाजिक आर्थिक समूहों के अंतर्गत और देशों के बीच तुलना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वैवाहिक स्थितियों के आंकड़ों की सहायता से हम आय, शिक्षा, रोजगार, और दीर्घायु की असमानता की विशेषताओं का बारीक रूप से पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। वैवाहिक स्थितियों में परिवर्तन के अध्ययन द्वारा हम कानूनी प्रणाली, आर्थिक, और सामाजिक वातावरण में बदलाव का परिवार और बच्चों पर प्रभाव जानने में सक्षम हो सकते हैं। वैवाहिक स्थिति के आंकड़ों के उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। वैवाहिक स्थिति पर जनगणना और सर्वेक्षण के अधिकतर जवाब सही नहीं होते।

सर्वेक्षण या जनगणना के समय शायद ही कभी कोई कानूनी दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा जाता है। पूर्व में सहवास, आम सहमति से यूनियनों और विवाहों के आम कानून पर चर्चा को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, जब वैवाहिक स्थिति द्वारा वगीकृत आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। लोग स्वयं को विवाहित के रूप में सूचित करते हैं जो कि कानूनी रूप से विवाहित नहीं हो सकते हैं, हालांकि सहवास की पृष्ठभूमि में कई सांस्कृतिक प्रतिबंध ''आधुनिक'' और ''परंपरागत'' समाजों दोनों में सुगमता के लिए किया गया है। कई उत्तरदाता सहवास करने के रूप में उनकी स्थिति को दर्ज करने में संकोच कर सकते हैं और इसे दर्ज करने के बजाय विवाहित के रूप में दर्ज करते हैं। वैकल्पिक रूप से, कई व्यक्ति जो विवाह के आम कानून में सहवासरत रह रहे हैं वे अपनी वास्तविक कानूनी स्थिति और जनगणना या सर्वेक्षण के दिशा–निर्देशों के बावजूद, स्वयं को एकल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण घटना के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से विवाह और तलाक पर प्राप्त आंकड़े विश्वसनीय हो सकते हैं और विभिन्न प्रकारों की वैवाहिक दरों के लिए न्यूमरेटर के रूप में सेवा दे सकते हैं। जिम्मेदारी को आकड़ों के स्रोत के संदर्भ में अवश्य लेना चाहिए। विवाह पर डेटा केवल सिविल विवाह के लिए संकलित हो सकते

हैं, हालांकि धार्मिक अनुष्ठान कानूनी रूप से स्वीकृत हो सकते हैं। इसके विपरीत, चर्च रजिस्टर कुछ देशों में विवाहों का केवल डेटा स्रोत हो सकता है।

टिप्पणी

एक विशेष देश या क्षेत्र में संचालित जनगणना के प्रकार वैवाहिक स्थिति वर्गों के लिए प्राप्त आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। प्रगणना की विशेषताओं पर आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं जो व्यक्ति से संबंधित साधरण स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जीवनसाथी किसी भी कारण से अस्थायी रूप से अनुपस्थिति हो सकता है। प्रगणना के कानून के संदर्भ के साथ यह ''विवाहित, जीवनसाथी उपस्थिति'' को कम करके बताए जाने के लिए और ''विवाहित, जीवनसाथी अनुपस्थिति'' को बढ़ा–चढ़ाकर बताये जाने के लिए, की श्रेणियों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

3.2.2 ग्रामीण और शहरी संरचना

बस्तियों के आकार और स्थान के आधर पर जनसंख्या को दो भागों में बाँटा जाता है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण जनसंख्या देश के भीतरी भागों में छोटे आकार की बस्तियों के रूप मे रहती है। शहरी जनसंख्या उसे कहते है जो बड़े आकार की बस्तियों में रहती है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण बात है कि यह वर्ग व्यावसायिक ढाँचे पर आधरित होता है।

यह बिना कहे समझा जा सकता है कि जनसंख्या हर स्थान पर फैली हुई है। भूमि क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में जनसंख्या का विशिष्ट मूल्यांकन अर्थहीन है। यह कृषि या अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिए उपयोगी क्षेत्रों की भिन्नता के कारण है। इसके अलावा, एक कृषि प्रधान समाज में उच्च जनसंख्या घनत्व अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। मानव कल्याण के पथ पर एक बाधा है। इसकी अपेक्षा एक इतने ही घनत्व वाला औद्योगीकृत समाज अधिक विकसित एवं कल्याणकारी होता है।

भौगोलिक वितरण के संदर्भ में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच विभाजन एक महत्त्वपूर्ण कारक है। कई दशकों से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का प्रवाह एक आम घटना है। जबकि शहरी क्षेत्रों की परिभाषाएं देश–देश और क्षेत्र–क्षेत्र में अलग–अलग होती हैं। दुनिया में सबसे अधिक सभ्य शहरी समाज पश्चिमी और उत्तरी यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, शीतोष्ण दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इन सब में जनसंख्या का 75 प्रतिशत से अधिक भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है, और यह पश्चिम जर्मनी में 85 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। देश में मौजूद शहरीकरण का एक मध्यवर्ती चरण उष्णकटिबंधीय लैटिन अमेरिका के हिस्सों में बन रहा है, जहाँ पर 50 से 65 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। एशिया और अफ्रीका के कई विकासशील देशों में शहरीकरण प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है और इन देशों में यह देखा जा रहा है कि शहरी जनसंख्या कुल आबादी के लगभग एक तिहाई भाग से भी कम है।

कुछ देशों में शहरीकरण की तेजी काफी आश्चर्यजनक है। 1960 में मेक्सिको शहर की आबादी लगभग 5,00,000 थी जिसका 1985 में लगभग 1,70,00,000 होना अनुमानित था और 2000 तक इसके 2,60,00,000 से 3,10,00,000 तक पहुँचने का अनुमान था। वृद्धि इस अनुमान से कही अधिक हुई। दुनिया के विकासशील देशों के लिए सामान्य

हस्त–नियम यह है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या विकास दर समग्र जनसंख्या की विकास दर की दो गुनी है। इस प्रकार समग्र जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत है। संभावना यह है कि यहां वार्षिक शहरी विकास दर कम से कम 6% है।

टिप्पणी

3.2.3 नगरीकरण

हर समाज की अपनी एक संरचना होती है और यह संरचना वहां की परम्पराओं के आधार पर निर्धारित होती है। व्यक्तियों के विचार, उनका व्यवहार, सोचने का तरीका, कार्य करने की कुशलता आदि ऐसे प्रतिमान हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है। यह हस्तान्तरण उस समाज की विरासत को प्रकट करता है। इसलिए जब कभी भी किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसकी संरचनात्मक विशेषताओं को एवं प्रमुख परम्पराओं को आधार माना जाता है। सभी परम्पराएं समाज की संस्कृति से जुड़ी होती हैं और संस्कृति को किसी भी देश और समाज की आत्मा माना जाता है। संस्कृति के माध्यम से उस देश के इतिहास की जानकारी भी मिल जाती है। कोई भी संस्कृति मानव जीवन के अनुभवों की सूचक होती है जिनके आधार पर वह समूह एक विशिष्ट समूह बन जाता है और अन्य मानव समूहों से अलग देखा तथा समझा जा सकता है। व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां उसके व्यवहार एवं स्वभाव में परिवर्तन ला देती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज की संरचना भी विश्व के अन्य देशों की संरचनाओं एवं संस्कृतियों से, मौलिक रूप से आध्यात्मिक उद्देश्यों के कारण भिन्न है।

नगर तथा गांव मानव व सामाजिक जीवन के दो पहलू माने जाते हैं। शहर समाज से निर्मित एक वातावरण है जिसमें सामुदायिक जीवन के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का सम्पूर्ण संशोधन किया जाता है। परन्तु इसके विपरीत गांवों का प्रकृति से निकट का सम्बन्ध होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि जहां पर मानव एवं प्रकृति के बीच अन्तःक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है वह गांव है और इसके विपरीत जहां पर मानव एवं प्रकृति के बीच सम्बन्ध अप्रत्यक्ष एवं क्षीण है वह नगर होते हैं। गांव एवं नगर दोनों के पर्यावरण में भी बहुत अन्तर पाया जाता है और यही अन्तर दोनों में भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है।

नगर का अर्थ

नगर किन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन नहीं है, बल्कि मानवीय साधनों के विकसित होने के साथ–साथ नगर भी विकसित एवं बसते चले गए। मानव के विकास के साथ–साथ विकसित हुई कृषि ने मानव को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह निश्चित समय तक निश्चित स्थान पर रहे। इसके कारण गांवों का जन्म हुआ। गिस्ट एवं हेलबर्ट कहते हैं कि ''सभ्यता की उत्पति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूतकाल के अंधकार में खो गई है।'' नगरों की उत्पति के विषय में मार्गेट मूरे ने कहा कि 'नगर की उत्पति धातु युग में हुई है, जिन व्यक्तियों के पास धातुओं के अस्त्र थे, वे अन्य उन व्यक्तियों पर जिनके पास पत्थर के अस्त्र होते थे, शासन करते थे। ये व्यक्ति सैनिकों को भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ रखते थे। ये ऐसे स्थानों पर बस गए जहां वे

आक्रमणकारियों से ठीक से अपनी सुरक्षा कर सकें। इस प्रकार नगर स्थायी सैनिक शिविरों के रूप में विकसित हुए।'

टिप्पणी

नगरों की जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता, औपचारिक व द्वितीयक सम्बन्ध की प्रधानता, भोगवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषता बन जाती है।

किंग्स्ले डेविस का कहना है कि "सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा यह एक अनुपम प्रकार के वातावरण अर्थात् नगरीय परिस्थितियों की उपज होती है। नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पाई जाती है। नगर कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है।''

सोमबर्ट, ''नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उनके निवासी परस्पर एक–दूसरे को नहीं पहचानते।''

बर्गल के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है? किन्तु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है।''

क्लीन और थॉमस के विचारानुसार, ''पहले गांव विकसित हुए। कालान्तर में ये ही गांव, नगरों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये नगर धीरे–धीरे साम्राज्यों की राजधानी बन गए। अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये नगर विशाल न होकर बहुत छोटे होते थे।''

समफोर्ड– "नगरों का विकास गांवों से ही हुआ है। आजकल जो नगर दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर गांवों में ही मौजूद हैं।''

चार्ल्स फूले– ''नगरों का जन्म यातायात तथा संदेशवाहन के साधनों के जन्म और विकास के फलस्वरूप हुआ है। जिन स्थानों पर यातायात और संदेश वाहन के साधनों के विकास की स्थिति अनुकूल थी, वहीं पर बड़े नगरों का जन्म हुआ। यही कारण है कि समुद्र के किनारे सबसे बड़े नगर विकसित हुए।''

एण्डरसन के अनुसार, "नवीन आविष्कार नगरों की उत्पति तथा विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये नगर ऐसे स्थान पर विकसित हो जाते थे जहां आर्थिक और भौगोलिक सुविधाएं काफी मात्रा में उपलब्ध रहती थीं। नगरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया एवं प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप नगरों का जन्म हुआ।"

'नगर' के साथ साथ 'महानगर', विराट नगर, विश्व नगर तथा नगर समूह इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इन सब शब्दों में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का घनत्व, आवागमन एवं संचार साधनों की सुविधाओं के आधार पर अन्तर किए जाते हैं।

भारत में जिस नगर की जनसंख्या दस लाख से अधिक है वह 'महानगर' कहलाता है। 50 लाख से ज्यादा वाला 'विराट नगर' कहलाता है। भारत में मुम्बई, कलकता, दिल्ली और चेन्नई 'विराट नगर' की श्रेणी में आते हैं। विश्व नगर में जनसंख्या का आकार निश्चित नहीं किया गया है परन्तु विश्व नगर वह होता है जहां विश्व के अधिकांश भागों के लोग रहते हैं। पाण्डिचेरी 'विश्वनगर' की श्रेणी में आता

है। वैसे भारत के चारों विराट नगर विश्व नगर की श्रेणी में आते हैं जिसकी रचना कई पूर्व पृथक नगरों द्वारा होती है। दिल्ली तथा कोलकाता 'कोनवेंशन' अथवा 'नगर समूह' माने जाते हैं।

टिप्पणी

नगर की परिभाषा जनसंख्या के आधार पर भी दी गई है। अमेरिका के जनगणना वालों ने नगर उसे माना है जहां 95,000 जनसंख्या हो या उससे अधिक। फ्रांस ने 2000 तथा मिस्र ने 11,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर कहा है। विल काक्स ने 1,000 जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग मील) तथा जेफरसन ने 10,000 जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग मील) आबादी वाले क्षेत्रों को नगर माना है।

व्यवहार को आधार मानकर भी नगरों को परिभाषित किया गया है। विलकाक्स के अनुसार– ''जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है, उसे गांव तथा जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे शहर अथवा नगर कहेंगे।'' बर्गल के अनुसार–''नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं।''

अपरिचित होने के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने नगरों की परिभाषा दी है। लुईस बर्थ–''समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े, घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है।''

मगफोर्ड : ''नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं एक संस्थात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौन्दर्यात्मक प्रतीक है।''

थियोडोरसन– ''नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च घनत्व, गैर–कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं द्वितीयक सम्बन्धों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता, आदि है।''

इन उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नगर वह स्थान है जहां पर जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है।

नगरीय समाज की विशेषताएं

विभिन्न विद्वानों ने नगरीय समुदाय की अलग–2 विशेषताएं बताई हैं।

किंग्सले डेविस (Kingsley Davis) ने नगर की अग्रलिखित विशेषताएं बताई हैं–

(1) सामाजिक भिन्नता, (2) द्वितीयक संघ, (3) सामाजिक सहिष्णुता, (4) द्वितीयक नियंत्रण, (5) सामाजिक गतिशीलता, (6) ऐच्छिक संघ, (7) व्यक्तिवादिता और (8) स्थानीय अलगाव।

रोनाल्ड फ्रीडमैन–के अनुसार नगर की निम्न विशेषताएं हैं–

(1) समूहों एवं व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्याश्रितता, (2) अधिक जनसंख्या एवं अधिक जनघनत्व, (3) विभिन्नताएं, (4) परिवारों के कार्यों में कमी, (5) सदस्यों में अनजानापन, (6) संदेश वाहन के साधनों की बहुलता, (7) प्राथमिक सम्बन्धों का अभाव, (8) श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण और (9) नगरीय संस्कृति की परिवर्तनशील प्रकृति।

पार्क, बर्गेस, नेल्स एण्डरसन, जिमरमैन एवं सोरोकिन ने नगरीय समुदायों की विशेषताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया है–

टिप्पणी

(1) **जनसंख्या का घनत्व**– गांवों एवं शहरों में अन्तर उनकी जनसंख्या मानी जाती है। गांवों की अपेक्षा शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या की अधिकता के कारण ही नगरों को महानगर, विराट नगर या विश्व नगर की श्रेणियों में रखा गया है। नगरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती, कानून का उल्लंघन, बेकारी, गरीबी, गन्दी बस्तियां, प्रशासन आदि से सम्बन्धित समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं।

(2) **जनसंख्या की विभिन्नता**– नगरों में अनेकों धर्मों, प्रान्तों, सम्प्रदायों, मतों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं। अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि यहीं से जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि ऐसे नगरों में वेश–भूषा, जीवन स्तर, रहन–सहन प्रथाएं एवं संस्कृति भिन्न–भिन्न पाई जाती हैं।

(3) **व्यवसायों में विभिन्नता**– नगरों में अनेकों प्रकार के व्यवसाय तथा नौकरियां पाई जाती हैं। जैसे सिगरेट, माचिस, लोहा, चमड़ा, कपड़ा, चूड़ी, ऊन, मशीन निर्माण, प्लास्टिक, बारूद, दवाइयां, बर्तन, सीमेंट, लकड़ी, ईंट, कागज आदि से सम्बन्धित हजारों प्रकार के व्यवसाय पाये जाते हैं।

(4) **मकानहीनता**– मकानहीनता नगरों की एक निराशाजनक विशेषता है। बड़े नगरों में मकान की एक बहुत बड़ी समस्या है। अनेक निम्नवर्गीय व्यक्ति अपनी रातें सड़कों की पटरियों पर व्यतीत करते हैं। मध्यवर्गीय व्यक्तियों के पास केवल एक या दो कमरों के मकान होते हैं और वो भी ऊंची–ऊंची मंजिलों पर। नगरों में बच्चों को खेलने के लिए सार्वजनिक स्थान भी बड़ी कठिनाइयों से उपलब्ध होता है।

(5) **श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण**– शहरों में कार्यों का बंटवारा रहता है। यहां पर अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यक्ति काम करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति किसी एक काम में निपुण होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता भी पैदा होती है।

(6) **द्वितीयक सम्बन्धों की प्रधानता**– 'बोगार्डस' के अनुसार, "नगरीय समूहों में द्वितीयक सम्बन्धों की प्रधानता होती है। अपने आकार एवं अधिक जनसंख्या के कारण नगर प्राथमिक समूह नहीं बन पाते। क्योंकि यहां के लोग आपस में प्राथमिक संपर्क में नहीं आते हैं। बिना एक–दूसरे को जाने बात कर लेते हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि नगर विनम्रता एवं पारस्परिक सुविधा के लिए होते हैं। परन्तु ये विनम्रता एवं पारस्परिक सुविधा सब बनावटी होती हैं। नगरवासी परदेशियों को प्राणी न मानकर जीवित यंत्र मानते हैं। एक व्यक्ति नगर में रहते हुए भी अपने ही क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से न तो परिचित हो पाता है और न ही उनके नाम जान पाता है।" 'ली' कहते हैं कि ''नामहीनता लाखों व्यक्तियों के नगर में पहचान को समाप्त कर देती है। अनेक नगरवासी सामाजिक रिक्तता

टिप्पणी

में विश्वास करते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रित करने वाले संस्थात्मक आदर्श नियम प्रभावी नहीं होते। यद्यपि वे अपने चारों ओर अनेक व्यक्तियों एवं अनेक संस्थागत संगठनों से परिचित होते हैं, तथापि वे किसी समूह अथवा समुदाय के प्रति अपनापन अनुभव नहीं करते। सामाजिक रूप में वे प्रचुरता के मध्य निर्धन होते हैं।''

(7) **कृत्रिमता**– नगर के लोगों का जीवन बनावट एवं आडम्बरयुक्त होता है। ये लोग दिखावे में विश्वास करते हैं।

(8) **गतिशीलता**– नगरों में सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। शहरी लोग एक स्थान छोड़कर लाभ के लिए अन्य स्थानों पर जाने के लिए तैयार होते हैं। उनमें स्थान के प्रति कम लगाव पाया जाता है।

(9) **विभिन्नता**– नगर विभिन्नताओं का केन्द्र होता है। धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज, व्यवसाय, पहनावा, रुचि, हित आदि के आधार पर नगर में अनेक भिन्नताएं पायी जाती हैं।

(10) **सुरक्षा**– नगर में पुलिस, गुप्तचर, जेल, न्यायालय आदि होने के कारण लोगों को जीवन के खतरों, चोरी, हत्या, लूटपाट आदि से सुरक्षा प्राप्त होती है। आर्थिक संकट में भी रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध होने के कारण वहां आर्थिक सुरक्षा एवं मानसिक संतोष मिलता है तथा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ रचनात्मक कार्यों को भी कर सकता है।

(11) **फैशन में रुचि**– नगरों में फैशन को विशेष महत्व दिया जाता है। मकान का रख–रखाव, पहनावों, ब्यूटी कल्चर तथा कला के क्षेत्र में शहरों में फैशन देखने को मिलता है।

(12) **सामाजिक दूरी**– सामाजिक दूरी अनामकता एवं विजातीयता की उपज है। नगरवासी एकान्त अनुभव करता है। व्यक्ति की सच्ची भावनाओं का पता ही नहीं चलता है। औपचारिक विनम्रता सच्ची विनम्रता का स्थान ले लेती है। नगरवासी पड़ोसी न होकर रात्रिवासी बन जाते हैं।

(13) **व्यक्तिवादिता**– शहरों में व्यक्ति अपने आप में व्यस्त रहता है। सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। समुदाय की चिन्ता न होकर व्यक्ति अपनी ही चिन्ताओं में लगा रहता है।

(14) **मानव सभ्यता के पोषक**– नगरों में अनेकों प्रकार की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं पायी जाती हैं जिसके कारण वहां पर सभ्यता का विकास होता रहता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की सभी उच्च एवं विकसित संस्थाएं नगरों में ही पूर्ण रूप से विकसित हुई हैं। नगर ही सभ्यता के निर्माता एवं पोषण रहे हैं। अतः वे मानव समाज के विकास के प्रतीक हैं। नगरों के विकास की कहानी सभ्यता के विकास को भी बयान करती है।

(15) **राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र**– नगरों को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नगरों के अन्दर ही सरकार के सभी कार्यालय एवं विभाग होते हैं। इसके साथ ही राज्यों की राजधानियां, सैनिकों की छावनियां

टिप्पणी

एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के मुख्यालय पाये जाते हैं। इसलिए सरकार एवं राजनैतिक दल की अपनी नीति एवं भावी कार्यक्रमों का निर्धारण नगरों के महत्व को ध्यान में रखकर करते हैं। अधिकांश राजनीतिक आन्दोलन नगरों से ही प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार नगर लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रदान करते हैं।

(16) **सामाजिक समस्याएं**– वर्तमान समय में शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त हैं फिर भी नगरों में अपराध, बाल–अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, गन्दी बस्तियां, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, प्रदूषण एवं बीमारी आदि अनेक समस्याओं के केन्द्र बन रहे हैं।

(17) **धर्म एवं परिवार का महत्व**– नगरों में शिक्षा का महत्व बढ़ जाने के कारण व्यक्ति अपने आपको अधिक मॉडर्न समझने लगे हैं जिसके कारण उनकी कर्मकांड, पूजा–पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठानों आदि में कोई रुचि नहीं रही है। इसके बजाए वह क्लबों, होटलों, डांसघरों, सिनेमाघरों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ईश्वर की अपेक्षा वह अपनी शक्ति पर ज्यादा विश्वास करते हैं। परिवार की अपेक्षा व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है।

(18) **प्रतिस्पर्द्धा**– नगरों में जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर व्यक्ति आगे बढ़ने की होड़ में घुड़दौड़ में लगा हुआ है।

(19) **शिक्षा एवं संस्कृति के केन्द्र**– नगरों में गांवों की अपेक्षा हर प्रकार के स्कूल विद्यालय, विश्व विद्यालय, महाविद्यालय आदि मिल जाते हैं और उनमें हर विषय से सम्बन्धित शिक्षा एवं ज्ञान भी उपलब्ध हो जाता है। कुछ ऐसे संस्थान एवं शिक्षण संस्थाएं हैं जो केवल शहरों में ही पाई जाती हैं–जैसे कला, संगीत, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि। नगरों में अनेकों प्रकार की भाषा एक ही व्यक्ति जानता है। ये सभी चीजें मानव सभ्यता का उल्लेख करती हैं। नगरों का माहौल व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।

(20) **स्वास्थ्य एवं मनोरंजन**– नगरों में कुछ ऊंची तकनीक वाले चिकित्सालय उपलब्ध होते हैं। हरेक प्रकार की दवाइयां भी यहां पर आसानी से मिल जाती हैं। जो व्यक्ति की रोगों से रोकथाम करती हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में मनोरंजन के साधन भी अधिक मात्रा में तथा सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं जैसे सिनेमाघर, टेलीविजन, संगीत, नृत्य एवं कला केन्द्र, नाट्यशाला आदि। स्वास्थ्य की दृष्टि से शहरों में पार्क तथा खेल कूद की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अविष्कारों ने मानव को रोगमुक्त बनाने के लिए नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

(21) **आर्थिक विषमता**– नगरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद आर्थिक विषमता बहुत अधिक पाई जाती है। नगरों में हमें ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जिनके पास खाने के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं होता है, रहने के लिए मकान अथवा चिकित्सा या मनोरंजन तो उससे कोसों दूर है तो दूसरी तरफ ऐसी जनसंख्या भी है जिनके पास ये सब चीजें बहुतायत से पाई जाती हैं।

(22) **यातायात एवं संदेश**– हरेक प्रकार के यातायात की सुविधा नगरों में उपलब्ध है। रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, बसें, रिक्शे, कारें, टैक्सियां आदि बहुतायत मात्रा में हैं।

टिप्पणी

नेल्स एण्डरसन ने आधुनिक नगरीय समुदायों की निम्न पांच और विशेषताओं का उल्लेख किया है–

(क) **सुदृढ़ प्रशासन**– नगरों में क्योंकि अनेक प्रकार की समस्याएं (जनसंख्या ज्यादा) जन्म ले लेती हैं जिसके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वहां पर कड़े प्रशासन हों। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबन्ध, पानी एवं बिजली की उचित व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि (आवश्यकतानुसार) पुलिस व्यवस्था, न्याय का उचित प्रबन्ध, व्यापार, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, संचार साधनों की व्यवस्था, सफाई एवं सार्वजनिक कल्याण आदि की उचित व्यवस्था करने के लिए सुदृढ़ प्रशासन अति आवश्यक है।

(ख) **मुद्रा अर्थव्यवस्था**– आधुनिक युग में मुद्रा अर्थव्यवस्था होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार का कार्य सुगमतापूर्वक हो जाता है। विनिमय करने के लिए सामान लेकर जाने की समस्या से मुक्ति मिल गई है। इससे धन और समय दोनों की बचत होती है। यह बचत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है जिससे व्यक्ति शक्ति का परिचायक बन जाता है।

(ग) **सांस्कृतिक आविष्कार**– नगरों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आविष्कारों का जन्मदाता माना जाता है। यहां नए सांस्कृतिक परिवर्तन धीरे–धीरे गांवों में भी पहुंच जाते हैं। नगरों में विभिन्न संस्कृतियों के सम्पर्क एवं पर–संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के कारण संस्कृति में परिवर्द्धन, परिष्कार एवं परिवर्तन होते रहते हैं।

(घ) **लिखित आलेख**– नगरों में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, उसके बाद व्यापार खूब फलने–फूलने लगा जिसका असर व्यक्ति के लेखन कार्य व कागज पर पड़ा यानि इनका प्रयोग भी बढ़ गया। अब मनुष्य मुंह से बातें कर कार्य नहीं करता बल्कि हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर अपने अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगर पुलिस विभाग की ओर देखा जाए तो वहां पर कोई भी कार्य बिना प्रत्यक्ष प्रमाण एवं लिखित अलेखों में नहीं होता है क्योंकि यहां विभाग का मुख्य विश्वास लिखित दस्तावेजों पर ही निर्भर रहता है। इसलिए नगरों के अन्दर अधिकांश कार्य लिखित रूप में ही किए जाते हैं।

(ङ) **आविष्कार एवं तकनीकी शिक्षा**– आजकल नगरों के अन्दर तकनीकी शिक्षा का बहुत अधिक बोलबाला है। इससे सम्बन्धित अनेकों शिक्षण संस्थान भी बच्चों तथा वृद्धों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। परिणामस्वरूप वहां पर रोज कुछ न कुछ नये अविष्कार सुनने में आते रहते हैं।

आवास

रहने के लिए घर, शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक मूल आवश्यकता है, लेकिन इसमें विकास की दर बढ़ाने की कुंजी भी छिपी है। अन्य किसी उद्योग की तरह, आवास में भी निवेश का रोजगार पर गुणक प्रभाव पड़ता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आवास/निर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापक रोजगार

टिप्पणी

उत्पन्नता प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में आठ गुना है (आईआईएम अहमदाबाद खोज 2005)। निर्माण क्षेत्र का रोजगार 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। आवास, गृह–आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करता है। आवास का स्टील और सीमेंट, संगमरमर/सिरेमिक, बिजली के तारों, टाइल्स, पीवीसी पाइप, और विभिन्न प्रकार के फिटिंग उद्योग पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है और इन सबका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

राष्ट्रीय नगरीय आवास और निवास नीति, 'सबके लिए आश्रय' का उद्देश्य उपलब्ध करने का मूल ढांचा प्रदान करता है। इस नीति की शुरुआत 1998 में की गई थी जिसका दीर्घकालीन लक्ष्य था बेघरपन दूर करना, खराब घरों में रहने वाले लोगों के लिए आवास की परिस्तिथियां सुधारना, और सबके लिए सेवाओं तथा सुख साधन के कम से कम मूल स्तर मुहैया करवाना।

10वीं योजना के दौरान, नगरीय क्षेत्रों में आवास डिलीवरी बढ़ाने के नजरिए से, संसाधन आधार को विस्तृत करने और नए संस्थागत तंत्र शुरू करने की पुरजोर कोशिश की गई थी। ऐसी कोशिशें भी की गईं जिनसे समाज के गरीब लोगों को मूल आश्रय से संबंधित सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें। कई नीतियों और शुरुआतों के बावजूद, गरीबों के लिए ये फायदे दिलवाने की कोशिशें पूरी नहीं हो सकी हैं।

	2001	2011
आबादी, आवास और मूल सुविधाएं		
भारत की कुल जनसंख्या	1028.6 मिलियन	1369.56 मिलियन
नगरीय आबादी	286.1 मिलियन	517 मिलियन
प्रतिशत शेयर नगरीय	27.8 प्रतिशत	26.16 प्रतिशत
कुल नगरीय आवास स्टॉक	52.0 मिलियन	110.1 मिलियन
पक्के घर	79.16 प्रतिशत	66 प्रतिशत
अर्ध–पक्के मकान	15.58 प्रतिशत	27.7 मिलियन
कच्चे घर	5.27 प्रतिशत	4.9 प्रतिशत
अवधि स्तर वाले घर, नगरीय		
स्वामित्व के साथ	66.8 प्रतिशत	69 प्रतिशत
किराए पर	28.5 प्रतिशत	21.72 प्रतिशत
अन्य	4.7 प्रतिशत	3.1 प्रतिशत
पहुंच प्राप्त घर, नगरीय		
पीने हेतु सुरक्षित पानी	90.01%	92.1%
बिजली	87.59%	93.1%
शौचालय	73.72%	81%
ड्रेनेज	77.86%	81.1%
घर के अंदर रसोई	75.96%	61.4%
खाना पकाने हेतु एलपीजी	47.96%	65%
खाना पकाने हेतु बिजली	0.31%	0.11%
खाना पकाने हेतु बायोगैस	0.37%	0.41%

टिप्पणी

भारत एवं राज्यों में गंदी बस्तियां (स्लम) जनसंख्या एवं अन्य आंकड़े : 2011 की जनगणना के अनुसार

क्रम	राज्य	गंदी बस्तियों का प्रतिशत	गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों की संख्या	गन्दी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	बच्चे (0–6)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	साक्षरता
	भारत	5.41%	13,920,191	65,494,604	33,968,203	31,526,401	8,082,743	13,354,080	2,216,533	77.72 %
1	महाराष्ट्र	10.54%	2,499,948	11,848,423	6,328,217	5,520,206	1,428,850	1,863,882	364,254	84.55 %
2	आंध्र प्रदेश	12.04%	2,431,474	10,186,934	5,103,377	5,083,557	1,149,779	1,428,212	270,556	75.32 %
3	तमिलनाडु	8.04%	1,463,689	5,798,459	2,886,993	2,911,466	614,969	1,853,315	30,996	82.06 %
4	प. बंगाल	7.03%	1,391,756	6,418,594	3,321,700	3,096,894	656,780	1,060,811	106,373	81.38 %
5	मध्य प्रदेश	7.83%	1,117,764	5,688,993	2,957,524	2,731,469	771,999	1,251,713	356,481	77.25 %
6	उत्तर प्रदेश	3.12%	1,066,363	6,239,965	3,298,339	2,941,626	863,392	1,373,211	19,186	68.98 %
7	कर्नाटक	5.39%	707,662	3,291,434	1,650,724	1,640,710	418,295	922,589	172,129	75.63 %
8	छत्तीसगढ़	7.43%	413,831	1,898,931	966,623	932,308	254,080	338,098	174,050	80.36 %
9	राजस्थान	3.02%	394,391	2,068,000	1,078,991	989,009	307,035	582,562	100,675	69.79 %
10	दिल्ली	10.63%	367,893	1,785,390	974,329	811,061	229,029	482,870	0	75.16 %
11	उड़ीसा	3.72%	350,032	1,560,303	800,963	759,340	188,962	321,167	199,836	78.95 %
12	गुजरात	2.78%	345,998	1,680,095	912,571	767,524	240,589	186,577	125,538	70.49 %
13	हरियाणा	6.56%	332,697	1,662,305	887,947	774,358	225,889	497,042	0	75.87 %
14	पंजाब	5.26%	293,928	1,460,518	776,388	684,130	176,257	581,984	0	74.18 %
15	बिहार	1.19%	216,496	1,237,682	649,475	588,207	208,383	260,442	16,630	68.15 %
16	जम्मू और कश्मीर	5.28%	103,633	662,062	342,422	319,640	94,204	11,136	10,797	68.02 %
17	उत्तराखंड	4.84%	93,911	487,741	257,624	230,117	66,176	91,953	2,321	76.88 %
18	झारखंड	1.13%	72,544	372,999	192,908	180,091	53,465	58,164	66,680	75.51 %
19	केरल	0.60%	45,417	202,048	97,429	104,619	20,327	21,923	411	93.11 %
20	असम	0.63%	42,533	197,266	101,424	95,842	22,229	42,358	3,702	81.57 %
21	पुदुचेरी	11.58%	34,839	144,573	70,491	74,082	16,002	34,521	0	81.39 %
22	त्रिपुरा	3.80%	34,143	139,780	70,143	69,637	14,755	40,291	3,337	90.71 %
23	चंडीगढ़	9.01%	21,704	95,135	53,340	41,795	14,720	29,230	0	66.38 %
24	नागालैंड	4.16%	17,152	82,324	42,651	39,673	11,114	0	64,253	88.85 %
25	मिजोरम	7.16%	15,987	78,561	38,861	39,700	10,430	69	73,552	98.11 %
26	हिमाचल प्रदेश	0.89%	14,385	61,312	32,555	28,757	6,509	16,062	488	87.74 %
27	मेघालय	1.94%	10,518	57,418	28,737	28,681	8,241	1,589	40,752	89.02 %
28	सिक्किम	5.14%	7,203	31,378	16,216	15,162	3,229	1,658	8,745	88.13 %
29	गोआ	1.80%	5,497	26,247	13,826	12,421	3,240	651	112	82.44 %
30	अरुणाचल प्रदेश	1.12%	3,479	15,562	8,029	7,533	2,226	0	4,631	69.39 %
31	अंडमान और निकोबार	3.72%	3,324	14,172	7,386	6,786	1,588	0	48	82.80 %

स्रोत : https://www.census2011.co.in/slums.php

नगरीय सड़कें

टिप्पणी

नगरीय संरचना निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा नगरीय सड़कें बनाने में खर्च होता है, यानि, कुल निवेश का 56 प्रतिशत। पुनर्निवेश लागत 5.4 लाख करोड़, की गणना के लिए मुख्य और कनेक्टिंग सड़कों की सेवा अवधि पांच साल मानी गई है। सड़क स्थान की निवेश आवश्यकता, 20 वर्ष अवधि के लिए 3 लाख करोड़ तक जाती है। 31.3.1951 3.99 लाख कि.मी से लेकर 31.3.2008 को भारत में कुल सड़क लंबाई बढ़ कर 41.10 लाख कि.मी. हो गई थी। समन्वित रूप से, तकरीबन उसी समय में डामर–सड़क 1.57 लाख कि.मी. से बढ़कर तकरीबन 20.36 लाख हो गई। देश में सड़क नेटवर्क 31.3.200 में 33,25,765 कि.मी. से बढ़कर 31.3.2004 (तकरीबन 9,51,511 जेआरवाय तथा पीएमजीएसवाय योजनाओं के तहत) किमी में 36.21.507 हो गया और 31.3..2008 (तकरीबन 10.61.809 जेआरवाय तथा पीएमजीएसवाय योजनाओं के तहत) को यह 41,09,592 कि.मी हो गया। राष्ट्रीय हाइवे की संख्या में, 2000–08, आठ साल की अवधि में, 14,744 किमी की वृद्धि हुई (2000 में 52,010 कि.मी. से मार्च 2008 में 66,754)।

नगरीय सड़कों के भीतर, 91 प्रतिशत सड़कें नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित सड़कें (2,77,264 किमी) हैं। नगरपालिकाओं के तहत तकरीबन 68 प्रतिशत डामर सड़कें हैं। नगरीय सड़कों में अन्य भिन्न श्रेणियों में दूसरे दर्जे पर आती हैं एमईएस सड़कें (14,143 किमी), जिसके बाद नम्बर आता है रेलवे सड़कों का (11,749 किमी), मुख्य बंदरगाह सड़कें (792 किमी) और अल्प बंदरगाह सड़कें (379 किमी)। खैर, देश में हुई सड़कों की वृद्धि, यहां बढ़ने वाले दर्ज किए वाहनों से तो कम ही है। सड़कों पर वाहनों के आवागमन की वृद्धि राजमार्गों के विकास से कहीं अधिक है। 1951 और 2006 के बीच वाहनों की आबादी 11 प्रतिशत सीएजीआर के वृद्धि दर से बढ़ी जबकि कुल सड़क लंबाई 4.2 सीएजीआर बढ़ी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भाग, 1951 और 2008 के दौरान मात्र 2.2 प्रतिशत बढ़ा।

1.25 किमी सड़क की लंबाई प्रति जमीन वर्ग के हिसाब से, भारत का राष्ट्रमार्ग कवरेज यूएसए (0.68 किमी/वर्ग किमी) की तुलना में अधिक सघन है, चीन (0.36 किमी/वर्ग किमी) और ब्राजिल (0.20 किमी/वर्ग किमी) से कहीं अधिक है। भारत में एक्सप्रेस–वे न के बराबर हैं जबकि चीन का राष्ट्रमार्ग नेटवर्क 45,339 किमी लंबा है, जिसमें चार से छः लेन हैं और देश के मुख्य नगरों को जोड़ता है। इसके अलावा, पक्की सड़क की लंबाई का अनुपात 50 प्रतिशत से थोड़ा कम है और जापान, मलेशिया एवं कोरिया की तुलना में तो यह बहुत कम है। नगरीय सड़कों के लिए कुल पूंजी व्यय की आवश्यकता 17.3 लाख करोड़ है। निवेश आवश्यकता की गणना के लिए इन सबकी कुल आवश्यकता का जोड़ निकाला जाता है– 1. मुख्य सड़कें (धमनी और उप–धमनी सड़कें), 2. कनेक्टिंग सड़कें, और 3. सड़क तक पहुंचने के स्थान (स्थानीय तथा उप–स्थानीय सड़कें)।

क्षेत्रीय विकास के लिए परिवहन के नेतृत्व वाली योजना का एक अच्छा उदाहरण है हैदराबाद का नेहरू आउटर रिंग रोड, यह आठ लेन वाला एक्स्प्रेसवे (158 किमी

टिप्पणी

लंबा) ग्रेटर हैदराबाद के आसपास 3000 वर्ग किमी का घेरा बनाता है। रिंग रोड की एक किमी दूरी तक सैटेलाइट टाउनशिप्स की योजना बनाई गई है जिसलिए, सड़क के दोनों तरफ बिसनेस पार्क, टेक्नोलोजी क्लस्टर आदि को आकर्षित करने हेतु आउटर रिंग रोड योजना लागू करने के लिए हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड की स्थापना की गई है। मेट्रो रेल और बसों का 25 किमी लंबा एकीकृत नेटवर्क बनाने का भी प्रावध ाान किया जा रहा है। रिंग रोड खुलने के कारण आस पास की जमीनों की बढ़ती कीमतों को, आउटर और इनर रिंग रोड के बीच के क्षेत्र में, भविष्य में होने वाले संरचना विकास हेतु पैसा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है; यह, भूमि मूल्यों को अनलॉक करने के माध्यम से नगरीय संरचना के वित्तपोषण का अच्छा उदाहरण होगा।

ठोस कचरे (सोलिड वेस्ट) का प्रबंधन

नगरों द्वारा निर्मित ठोस कचरे का प्रबंधन और निपटान एक बड़ी समस्या है। सीपीसीबी द्वारा, 2005 में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, रोज तकरीबन 1,15,000 एमटी नगरीय कचरा निर्मित होता है। जहां आवश्यकता के अनुसार ठोस कचरे को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मौजूद नहीं हैं, संग्रह प्रदर्शन में भी भिन्नता है। आमतौर पर, नगरों में, एकत्रित कचरे को भूमि भराव स्थलों पर फेंक दिया जाता है और उसके वैज्ञानिक निपटान पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। महानगरीय नगरों के मामले में, नगरीय ठोस कचरे के संग्रह की दक्षता 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत है। इसके साथ ही छोटे नगरों में, ये आंकड़े गिर कर 50 प्रतिशत से कम हो जाते हैं। यूएलबी द्वारा प्रति ठोस कचरा टन के संग्रह परिवहन, व्यवस्थान और निपटान हेतु 500–1500 तक का खर्च किया जाता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, नगरों को ठोस कचरा संरचना में निवेश के योग्य बनाने के लिए, 2005 में नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीनीकरण मिशन' नामक योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में नगरीय संरचना तथा शासन (यूआइगी) संघटक अंग के तहत, 65 मिशन नगरों को पानी की आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन और सड़कों के सुधार के लिए अर्ध आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई थी। छोटे और मध्यम आकार के नगरों के लिए अन्य संघटक अंग के तहत लाभ दिया गया था जिसका नाम था 'छोटे और मध्यम नगरों के लिए नगरीय संरचना विकास योजना'।

योजना की मध्यावधि समीक्षा से पता चला कि नगरीकरण से निपटने के लिए लागू किया गया पहले राष्ट्रीय ध्वज प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीनीकरण मिशन' (जेएनएनयूआरएम), पूरे देश में नगरीय क्षेत्र में केंद्रीकरण के नवीनीकरण में सफल रहा है और इसने कई राज्यों में महत्वपूर्ण सुधारों हेतु अनुकूल वातावरण बनाने में भी सहायता की है। खराब लागत वसूली के कारण, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों पर निवेश अभी भी नगरों की कार्यसूची में प्राथमिकता नहीं पा सका है।

गन्दी बस्तियां

भारतीय समाज में औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। यद्यपि औद्योगिक केन्द्रों एवं नगरों का देश के विकास में विशेष योगदान है,

फिर भी इन दोनों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इनमें प्रमुख गन्दी बस्तियों (स्लम) का विस्तार है।

टिप्पणी

कारखानों में कार्य करने तथा नौकरी की तलाश में ग्रामीण लोग भारी संख्या में औद्योगिक केन्द्रों तथा नगरों में प्रवसन कर जाते हैं, तथा नौकरी प्राप्त करने में सफल तो हो जाते हैं, परन्तु उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या निवास स्थान की आती है। उनके लिए उपयुक्त निवास स्थान का प्रबंधन नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप वे कारखानों के निकट स्थानों पर ही बस्तियां स्थापित कर लेते हैं। घनी बस्तियों में किराये इतने अधिक होते हैं कि श्रमिक वर्ग के लोग इसमें रहने के संबंध में सोच भी नहीं सकते। इसलिए औद्योगिक केन्द्रों के आसपास अनेक अनधिकृत, गन्दी बस्तियों का विकास हो जाता है। इन बस्तियों में यद्यपि किराया तो कम होता है, परन्तु अन्य अनेक समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि वहां के वातावरण को दूषित कर देती हैं। अतः गंदी बस्तियों का विकास एवं विस्तार औद्योगीकरण व नगरीकरण का दुष्परिणाम ही हैं।

भारतीय संदर्भ में अधिकांश उद्योग नगरों में ही सीमित हैं तथा पिछले 50– 60 वर्षों में इनका अत्यधिक विकास हुआ है। उद्योग व व्यवसाय हेतु अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बड़े पैमाने पर इन केन्द्रों में मनुष्यों का एकत्रीकरण होता है कि यह प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि नगर आयोजक अधिक मात्रा में सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। और धीरे–धीरे गन्दी बस्तियो का विस्तार होता जाता है। वातावरण आरोग्य समिति के अनुसार हमारे देश के नगरों में गंदी बस्तियों का विस्तार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। मकानों की कमी को पूरा करने के लिए प्रायः सभी बड़े औद्योगिक नगरों में अक्राता (कानपुर) बस्ती (कलकत्ता) चौल व धारावी (मुंबई), चेरी (चेन्नई) अनेक गंदी बस्तियों विकसित हुई हैं। इन बस्तियों में गंदगी का प्रकोप होता है। कमरों के भीतर हवा व रोशनी आने का कोई प्रबंध न होने के कारण दिन में भी अंधेरा रहता है। फर्श में नमी रहती है। मुंबई में 73.3 प्रतिशत, कलकत्ता में 71.9 प्रतिशत, दिल्ली में 63 प्रतिशत श्रमिक एक कमरे वाले अस्वस्थ्यकर मकान में निवास करते हैं। इसी एक कमरे में खाना पकाना, नहाना, खाना, सोना, जन्म तथा मृत्यु सभी होता है।

स्पष्टतः इन परिस्थितियों का विपरीत प्रभाव न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य पर ही होता है बल्कि उनके नैतिक स्तर का भी पतन होता है। वहां का पर्यावरण एक ऐसी निम्न मानसिकता को जन्म देता है, जिसके पनपने से अपराध व व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। यहां पर अनिश्चितताओं का अत्यंत घोर अंधकार होता है, जिससे श्रमिक मानसिक चिन्ता– स्नायु रोग आदि के शिकार हो जाते हैं। यहां पर निवास करने वाले व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन में अत्यंत व्यस्त होने के कारण सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करते हैं। नैतिक आदर्शों एवं नैतिक सामाजिक मूल्यों का निरंतर पतन होता रहता है। यहां के व्यक्ति केवल अपने वर्तमान की उलझनों के कारण स्वयं के तथा अपने बच्चों के भविष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करते हैं।

उचित व्यवसाय तथा उचित जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति अनेक बार अकेले ही नगरों में जीवनयापन करता है। परिणामस्वरूप पुरुष अपराध, जुआ, शराब और वेश्याओं की ओर अग्रसर होते हैं। गांवों में निवास करने वाला व्यक्ति जब नगरों में गंदी बस्तियों

टिप्पणी

में निवास करता है तो उसके सामाजिक मूल्य त्याग, परोपकार, सहानुभूति, प्रेम आदि का स्थान स्वार्थ, स्पर्धा, रागद्वेष आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। नगरों में खर्चे अधिक होने के कारण श्रमिक अपने बच्चों को भी पर्याप्त सुविधाएं (अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, स्वस्थकर वातावरण) प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे देश की आगे आने वाली युवा पीढ़ी (ऊर्जावान मानव– संसाधन) अपनी पूर्ण शक्ति से देश का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम नहीं हो पाती है।

3.2.4 व्यावसायिक संरचना

व्यवसाय को जनसंख्या संरचना के आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे ''गतिविधियों की एक ऐसी अपेक्षाकृत निरन्तर चलायमान प्रवृत्ति के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा कार्मिक अपनी जीविका कमाते हैं और अपनी सामान्य सामाजिक स्थिति को भी पारिभाषित करते हैं।'' विश्व भर में इतने सारे विविध व्यवसाय प्रचलन में हैं कि आज इनकी गिनती कई सैंकड़ों में है। उदाहरण के लिए, भारत में हाल ही में हुई जनगणना में 550 विभिन्न व्यवसायों को मान्यतारूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्पष्ट रूप से इस वजह से व्यवसायिक सांख्यिकी को संचालित करने में बहुत परेशानियाँ पेश आती हैं। व्यवसाय के इन आँकड़ों को अधिक नियंत्रण योग्य बनाने एवं उनके सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए भारतीय जनगणना में भी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की ही तरह व्यवसायों को 9 प्रमुख मदों के तहत वर्गीकृत किया गया है। स्पष्टता एवं सरलता के लिए इन 9 श्रेणियों को संक्षेप में तीन मुख्य समूहों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में परंपरागत ढंग से वर्गीकृत किया गया है।

किसी प्राथमिक समूह में (1) खेती (2) कृषि मजदूरी (3) पशुपालन, वानिकी, मतस्यपालन, शिकार, वृक्षारोपण, बागवानी और अन्य सहयोगी गतिविधियाँ और (4) खनन और उत्खनन आदि कार्य शामिल हैं;

द्वितीयक समूह में (1) घरेलू उद्योग, (2) घरेलू उद्योग समान गतिविधियाँ और (3) निर्माण कार्य शामिल हैं; और

तृतीयक समूह में (1) व्यापार और वाणिज्य, (2) ट्रांसपोर्ट, भंडारण, संचार और (3) सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

3.2.5 लैंगिक मुद्दे

लिंग महिला–पुरुष का सामाजिक वर्गीकरण है। यह पुरुष और महिला के बीच समाज द्वारा स्थापित अंतर है। इसलिए समाज की विभिन्न प्रथाओं को, जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करती हैं, महिला–पुरुष भेदभाव की संज्ञा दी जा सकती है। किसी पितृसत्तात्मक समाज में, जो प्रायः विश्व के सभी भागों में प्रचलित है, महिला–पुरुष भेदभाव एक आम बात है। वह जाति हो या वर्ग, वंश अथवा नृजाति, महिलाएं हर जगह सर्वाधिक उत्पीड़ित प्राणी हैं। महिला–पुरुष भेदभाव मुख्यतः शासक और शासित का संघटन है। प्रचलित विचार है कि कुछ लोग बृहत्तर बुद्धि जैसी कुछ विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं, और उन्हें जन्म से ही श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि महिलाएं अधीनस्थ प्राणी हैं।

टिप्पणी

नारीवादी मानव विज्ञानी सिमोन दे बोउवार की टिप्पणी ठीक ही है कि 'स्त्री जन्म नहीं लेती बल्कि गढ़ी जाती है।' यह पंक्ति पूर्णतः स्पष्ट कर देती है कि यह शिशु पालन की प्रथा है जो एक महिला को निरंतर याद दिलाती रहती है कि उसे कपड़े पहनना, खाना खाना, गाना, हंसना, बात करना और सारे कार्य उसी तरह से करने चाहिए जैसा कि समाज उससे चाहता हो।

यदि महिलाएं कामकाजी हों, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उन्हें घर पर काम नहीं करना है। वे घरेलू काम के प्रति उत्तरदायी हैं। इस दोहरे बोझ के बावजूद, महिलाओं को वह प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वे हकदार हैं। इस तरह, कहा जा सकता है कि इन समस्याओं का मूल कारण पितृसत्तात्मक समाज है।

महिला–पुरुष भेदभाव तब होता है जब एक को दूसरे से बेहतर माना जाए और जाति, वंश लिंग, रंग और मत जैसे उनके जन्मजात गुणों में अंतर किया जाए। यह भेदभाव शिक्षा दिलाने, संपत्ति के अधिकार, आने–जाने, निर्णय निर्माण, अधिकार आदि के आधार पर हो सकता है। महिला–भेदभाव की जड़ लोगों की सोच में है। कई रूढ़िवादी धार्मिक लोग बालिकाओं को उनके घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। जो लोग सामाजिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं के प्रबल समर्थक होते हैं, वे विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देते।

भारतीय समाज में महिला–पुरुष भेदभाव एक आम बात है। लड़कियों की पसंद महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। भारत के कई हिस्सों में लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं और अगर उन्हें स्कूल भेजा भी जाता है, तो लड़कों की शिक्षा और प्रगति को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़कियों से घरेलू कामकाज में हाथ बंटाने, छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने आदि की आशा की जाती है।

महिला–पुरुष भेदभाव में अब बदलाव आने लगा है। स्कूलों और कॉलेजों में अधिक से अधिक लड़कियों का दाखिला हो रहा है। महिला कामगार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं।

लैंगिक भेदभाव के कारण

लैंगिक भेदभाव के कुछ कारण इस प्रकार हैं–

- **शैक्षिक पिछड़ापन** : जाने–माने जनसांख्यिकीविद् सोनल दे देसाई का मानना था कि बेटियों की पढ़ाई–लिखाई के प्रति माता–पिता की उदासीनता की जड़ें महिलाओं की स्थिति में हैं। माता–पिता अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दिलाने के कई कारण बताते हैं। सबसे पहला विचार यह है कि लड़कियों की शिक्षा से माता–पिता को कोई लाभ नहीं मिलता और दूसरा यह कि उनके भविष्य में कार्यों को, मुख्यतः जनन संबंधी और प्रायः खेती मजदूरी समेत होने के कारण, औपचारिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है।
- **जाति व्यवस्था** : जाति व्यवस्था एक अति प्राचीन प्रणाली है जिसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। जाति का अदर्शन एक भ्रांति है। जाति व्यवस्था आधुनिक भारतीय समाज और राजनीति का एक हिस्सा है। लिंग, धर्म और अन्य विषयों के साथ इसकी पारस्परिक क्रियाएं इसे कई सामाजिक और आर्थिक

टिप्पणी

प्रक्रियाओं में, और इन प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव में एक निर्णायक कारक बनाती हैं। जाति व्यवस्था के बने रहने में जाति और लिंग के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। लिंग और जाति दोनों के बीच संबंध है और दोनों एक–दूसरे को आकार देते हैं। क्लॉद लेवी स्त्रास के अनुसार, सच्चा और सगोत्र विवाह (जाति के भीतर विवाह) मानव समुदाय की सीमाओं से परे विवाह की संभावना को मान्यता देने से महज इनकार करना है। यहां तक कि एक तरफ उच्च वर्ग की महिलाओं का पुनर्विवाह वर्जित और वहीं इसके विपरीत कभी–कभी निम्न–जाति की महिलाओं से सहवास मान्य था। श्रम विनियोग की एक प्रणाली के रूप में जाति व्यवस्था के विशाल तर्काधार ने अन्य ऊंची जातियों के प्रयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला–पुरुष संहिताओं को आकार दिया है।

दलित समुदायों, अनुसूचित जाति (जनसंख्या का 15 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (7 प्रतिशत) आज भारत में सबसे बड़े और निम्न जाति के सर्वाधिक जाने–माने समूह हैं। शोधों से पता चलता है कि इन समूहों में गरीबी की दर अभी भी अन्य समूहों के लोगों की तुलना में स्पष्टतः अधिक है। किंतु, इन समूहों में महिलाओं की स्थिति उल्लेखनीय है। दलित समुदायों में राष्ट्रीय जनसंख्या की तुलना में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) नाम मात्र के लिए कम है, और लड़कों और लड़कियों के जीईआर के बीच अंतर नगण्य है, जबकि जनसंख्या के अन्य वर्गों में यह अंतर स्पष्ट है। इन समूहों में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी दर भी उच्चतर है और इस तरह उनके पूरी तरह से घरेलू काम में ही उलझे रहने की संभावना कम है, हालांकि उनका रोजगार नैमित्तिक श्रम में निहित है। इन समुदायों में महिलाओं की स्थिति पर उनकी उच्चतर आर्थिक उत्पादकता के प्रभावों को अच्छी तरह से समझने के लिए, खास कर यह देखने के लिए कि इससे उनकी निर्णय निर्माण की क्षमता में वृद्धि होती है या नहीं, और शोध होना चाहिए। इन समुदायों के अंतः समुदायों और घरेलू प्रक्रियाओं पर शोध का भी अभाव है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का परिमाण निर्धारण और मूल्यांकन कठिन होता है।

- **धार्मिक मान्यताएं** : धर्म भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और हाल में यह भारतीय राजनीति का एक वर्धमान हिस्सा बन गया है। धर्म से महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित हैं। धार्मिक परंपरा के वाहक के रूप में देखी जाने वाली इन महिलाओं की सार्वजनिक और निजी भूमिकाओं पर अक्सर धर्म के नाम पर प्रतिबंध होते हैं। महिलाओं को अक्सर शिक्षा प्राप्त करने या आर्थिक रूप से उत्पादक होने से हतोत्साहित किया जाता है। युवावस्था की पहली सीढ़ी से ही उन पर विवाह के बहुत अधिक दबाव रहते हैं (खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में); और धर्मों के भीतर पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह इस बात के उदाहरण हैं कि धर्म महिलाओं के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। महिलाओं के धार्मिक समुदायों में उनकी भूमिका को समझना उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हेतुक (प्रेरणात्मक) एजेंटों को समझने; और उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रयास कार्यक्रम तैयार करने दोनों के लिए जरूरी है।

टिप्पणी

स्वीडन की सामाजिक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक राजनीतिज्ञ अन्ना मारिया लिंद का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की आबादी अभी भी पारंपरिक जीवन व्यतीत करती है। धार्मिक कानून और परंपराएं आज भी कई लोगों के, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन का निर्धारण करती हैं। इसके बावजूद कि महिलाओं को पहले से ही जमीन और संसाधनों पर अधिकार है, सामाजिक और धार्मिक कारक परिवार के भीतर गांठ उत्पन्न होने से रोकने के लिए कई महिलाओं को इस अधिकार से दूर रहने को विवश करते हैं। भारत में समाज के सभी वर्गों में बेटे के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है, जो लड़कियों के लिए उनके जीवन पर्यंत मानदंड तय कर देता है। पुरुषों की तरह, महिलाएं भी परिवार में और राष्ट्र के विकास में एक महती भूमिका निभाती हैं। किंतु उनके योगदान को पुरुष प्रभावी समाज में मान्यता नहीं दी जाती।

भारतीय परिवार में महिलाओं की स्थिति

विवाह दो पक्षों के बीच एक समझौता है। सामान्यतः, यह समझौता उल्लिखित शर्तों के अधीन होता है और इन शर्तों को दोनों पक्ष राजी–खुशी से स्वीकार करते हैं। विवाह एक समझौता है किंतु एकदिशीय है जहां वर पक्ष अपनी शर्तें रखता है और दूसरे, यानी वधू पक्ष को उन्हें मानना पड़ता है, उनकी पसंद और स्वीकृति के परे। विवाह समझौते की शर्तों को मानने से मना करने की स्थिति में परिवार में महिलाओं को जब–तब प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि महिला पक्ष विवाह समझौते में अपनी शर्तें रखे। यह पक्षपात भारतीय परिवारों में निरंतर बना हुआ है और सभी तबकों में महिलाओं के शोषण का पक्षधर है। महिला की शिक्षा और मार्गदर्शन भी इस स्थिति में योगदान करते हैं। खास कर उनका परिधान उनकी कमजोरी में एक अहम भूमिका निभाता है। युगों से चली आ रही महिलाओं की कमजोरियों के कुछ कारणों का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है :

- पुरुष पक्षपात
- महिलाओं को उत्पादन का एक साधन माना जाना
- उत्तम परिधान एवं पहनावा
- सामाजिक दबाव
- जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक वर्जनाएं
- फलप्रद संसाधनों की अपर्याप्त सुलभता
- गरीबी
- उन्नति की अपर्याप्त सुविधाएं
- आर्थिक दुर्बलता

श्रम विभाजन : लैंगिक भूमिका

घर में काम करने के कारण स्त्रियों को गैर उत्पादक श्रम करने वाली महिला कहकर पुकारा जाता है। घर में काम करने के इस विभाजन को 'लैंगिक श्रम विभाजन' कहते हैं। एक महिला का कार्य घर के अंदर होता है इसलिए इसे व्यक्तिगत कहकर छोड़

टिप्पणी

दिया जाता है जबकि पुरुष का कार्य घर से बाहर होता है, उसे सार्वजनिक कार्य कहा जाता है। अधिकांश समाजों में महिलाओं के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग करके प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय समाज के मध्यम वर्ग में धन कमाकर लाने का उत्तरदायित्व पुरुषों का होता है और स्त्रियां घर का कामकाज करती हैं तथा बच्चों का पालन–पोषण एवं देखभाल करती हैं। स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता एवं श्रम में लैंगिक आधार पर विभाजन जैसे मुद्दे परस्पर एक–दूसरे से संबद्ध हैं। पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में जब महिलाओं ने श्रम कार्य करना आरंभ किया तब से श्रम विभाजन की विचारधारा को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा है।

श्रम विभाजन के अंतर्गत स्त्री–पुरुष की इस प्रक्रिया को जैविक रचना के आधार पर प्राकृतिक एवं अनुपूरक समझा जाता है। पश्चिम में नारीवादी आंदोलन के उदय ने श्रम विभाजन को लेकर बहुत से प्रश्न खड़े कर दिए और इसके साथ–साथ विभिन्न समाजों एवं संस्कृतियों में महिलाओं की लगभग एक जैसी अधीनता पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।

आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्व भर में एक समान काम करने के बावजूद महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम पैसे मिलते हैं। लैंगिक असमानता एवं भेदभाव के कारण व्यवसायों में भी परिवर्तन आ गया है। श्रम बल में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, इसके अवमूल्यन एवं निर्णयन की प्रक्रिया महिलाओं को बाहर कर देने से संबद्ध है।

महिलाएं पुरुष वर्ग द्वारा उत्पीड़ित एवं उपेक्षित हैं। पितृ–सत्तात्मक संरचना भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से लगभग सभी जगह एक जैसी है। वर्तमान समाज में भेदभाव का मुख्य केंद्र वर्ग नहीं बल्कि लैंगिकता है। स्त्री–पुरुष श्रम विभाजन पर परा सांस्कृतिक शोध ने जीवन–निर्वाह के विविध साधनों से समाज में महिलाओं की उत्पादनशील गतिविधियों की विस्तृत रेंज को स्पष्ट करने का प्रयास किया है लेकिन साथ ही उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर इनके निहितार्थों पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

आज भारत में अर्थव्यवस्था दो वर्गों में बंटी हुई है– संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र वे हैं जहां नियमित वेतन मिलता है, श्रम के कानून होते हैं और श्रम से जुड़े लाभ मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र वे हैं जहां न तो ये काम पक्के होते हैं और न इनमें नियमित वेतन मिलता है। अधिकांश स्त्रियां जो अपने घर से बाहर काम करती हैं वे असंगठित क्षेत्र हैं और इनमें कई प्रकार के शोषण होते हैं। यद्यपि यह नियम सभी मानते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए परंतु ज्यादातर महिलाएं पुरुषों से कम वेतन पाती हैं। कृषि या निर्माण कार्य में जिनमें प्रायः स्त्रियां काम करती हैं, पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन मिलता है। स्त्रियां चाहे घर में काम करती हों या बाहर, घर के काम को हमेशा एक स्त्री का ही उत्तरदायित्व समझा जाता है। वे स्त्रियां जो घर और बाहर के काम को करती हैं दोहरे बोझ से पीड़ित होती हैं। इस स्थिति का हम कैसे भी विश्लेषण करें पर निश्चित रूप से स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं और उसकी तुलना में उनके लाभ बहुत कम हैं।

समाज में लैंगिकता को लेकर आज भी कई पूर्वाग्रह और रूढ़ियां प्रचलित हैं। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है।

टिप्पणी

लैंगिक पूर्वाग्रह

लैंगिक पूर्वाग्रह से अभिप्राय अलग–अलग लिंगों के हिसाब से उनके साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं उनके साथ होने वाले पक्षपात से है। लैंगिक रूढ़िबद्धता से अभिप्राय किसी भी लिंग को एक विशेष छवि में बांधने से है। सामान्यतः रूढ़ शब्द का प्रयोग किसी भी वस्तु या घटना के अत्यधिक सामान्यीकरण करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की छाप होती है जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित वर्ग में बांट सकते हैं। यह छाप वास्तव में किसी समूह विशेष की छाप है और यदि इस समूह के किसी व्यक्ति में उस समूह का एक भी गुण न हो तो भी उस व्यक्ति पर कई बार सिर्फ इसलिए थोपी जा सकती है कि वह एक समूह विशेष का हिस्सा था। इस प्रकार लैंगिक रूढ़िबद्धता में भी अलग–अलग लिंगों की कुछ विशेष छवि को गढ़ लिया जाता है। ये छवियां मस्तिष्क में इस प्रकार से बैठ जाती हैं कि हमारा मस्तिष्क विभिन्न लिंगों को इन छवियों के भीतर ही देखता है और इसी कारण जन्म होता है लैंगिक पूर्वाग्रहों का। लैंगिक पूर्वाग्रह एवं लैंगिक रूढ़िबद्धता एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारे मन–मस्तिष्क में लैंगिक रूढ़िबद्धता छवियां इस कदर बस जाती हैं कि हम कब पक्षपातपूर्वक व्यवहार करने लगते हैं हमको पता ही नहीं चलता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार, लैंगिक रूढ़िबद्धता ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चों को उनकी एक्स भूमिकाओं में ढाला जाता है तथा जिसके कारण वयस्क तथा बच्चे अपने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं से वंचित कर दिए जाते हैं।

लैंगिक रूढ़िबद्धता

हमारे समाज में प्रत्येक लिंग के लिए बहुत सारी लैंगिक रूढ़िबद्धता मौजूद हैं। रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाएं बचपन से ही सिखाई जाती हैं। ये न दिखाई देने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और यह समाजीकरण भिन्न–भिन्न माध्यमों के द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण के लिए जब किसी लड़के से कहा जाता है कि 'लड़कियों की तरह मत रो' या लड़कियों को कहा जाता है कि 'ज्यादा उछल–कूद मत करो' तो वास्तव में हमारे मस्तिष्क में फिट रूढ़िबद्धता सक्रिय होती है और साथ ही वे बच्चे जिनको ऐसा बोला जाता है उनके दिमाग में भी रूढ़िबद्धता कार्य कर रही होती है। ऐसे ही व्यवहारों से बच्चे स्त्री (feminine) एवं पुरुष (masculine) वाले गुण सीखते हैं। स्कूल में आज भी गृह–विज्ञान एवं कला को लड़कियों के लिए जबकि इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर जैसे विषय लड़कों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। पुरुष अपने आप को लड़कियों से बेहतर एवं श्रेष्ठ मानते हैं। अधिकांशतः स्त्रियां भी स्वयं ऐसी ही धारणा रखती हैं। ऐसा समाज के बनाए खांचों एवं रूढ़िबद्धता के कारण ही है।

हमारी सामाजिक संरचना में स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की भूमिका का निर्धारण बचपन से ही हो जाता है। सामाजिक रूढ़ियों के अनुसार स्त्री एवं पुरुष में अलग–अलग गुण होने चाहिए। सामाजिक संरचना एवं रूढ़िबद्ध छवियों के अनुसार तय स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के कुछ मानदंडों की सूची निम्नलिखित है–

टिप्पणी

स्त्रीत्व के गुण	पुरुषत्व के गुण
कोमल	कठोर
आश्रित	स्वतंत्र
आज्ञाकारी	प्रभावशाली
सहयोगी	प्रतियोगी
कमजोर	बहादुर
पालन–पोषण करना	स्तरीय भूमिकाएं
भावुक	भावुक नहीं
अतार्किक	तार्किक

यदि हम इन गुणों को देखें तो यह पाएंगे कि समाज द्वारा तय स्त्री एवं पुरुष की भूमिकाएं एकदम विपरीत हैं। यदि पुरुष तार्किक है तो स्त्री को अतार्किक माना जाता है। स्त्री का भावुक होना आवश्यक है परंतु यदि पुरुष भावुक हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा गहराई से सोचें तो हम ये पाएंगे कि महिलाओं के गुणों का अवमूल्यन किया गया है। और पितृसत्ता के प्रभाव से महिलाएं भी अपने गुणों के अवमूल्यन को स्वीकार कर लेती हैं। वास्तव में इनमें से यदि कोई भी अपनी तय भूमिका से अलग सांचे में जाता है तो उसको बुरा समझा जाता है। समाज की नजर में अच्छी स्त्री एवं अच्छा पुरुष वही है जो इन तय भूमिकाओं के भीतर ही रहते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करे।

लैंगिक भूमिकाएं एवं रूढ़िबद्धता

अधिकांशतः बचपन से ही लड़के एवं लड़कियों की लिंगाधारित भूमिका निर्धारित कर दी जाती है और फिर अपने जीवन काल में वे उन रूढ़िबद्धताओं का सामना करते रहते हैं। लड़की के जन्म को ही बुरा माना जाता है। बेटी पैदा होने पर दुख की अभिव्यक्ति की जाती है और भाग्य को कोसा जाता है। दूसरी तरफ लड़के के पैदा होने पर खुशी जाहिर की जाती है और जश्न मनाया जाता है। बेटी के पैदा होने पर मां की भी उपेक्षा की जाती है और उसको अच्छा खान–पान नहीं दिया जाता। ऐसे में उनकी ये निराशा उनकी बेटियों में भी हस्तांतरित होती है। लड़कों को खूब दुलार से पाला–पोसा जाता है और उनका पालन–पोषण भी अच्छे से किया जाता है। दोनों के लिए अलग–अलग तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। यहां तक कि रंगों का चुनाव भी लिंग के हिसाब से किया जाता है। दोनों के खिलौनों में भी बहुत अंतर होता है। लड़कियों को बर्तन, गुड़िया आदि जबकि लड़कों को बंदूकें, गाड़ियां, हवाई जहाज और विडियो गेम जैसे खिलौने दिए जाते हैं।

लड़कियों के तरुणावस्था में प्रवेश करते ही उन पर प्रतिबंध लगने प्रारम्भ हो जाते हैं। उनके चलने–फिरने, हंसने–बोलने, पहनने–ओढ़ने सबके तरीकों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। लड़कों के लिए प्रतिबंध नहीं होते उल्टा उनको स्वतन्त्रता मिलनी प्रारम्भ हो जाती है। लड़कियों के विवाह के लिए मां–बाप अधिक

टिप्पणी

चिंतित होते हैं क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों के तहत उनको अनेक रस्मो–रिवाज अदा करने होते हैं जिसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे में कई लड़कियां स्वयं हीन भावना महसूस करने लगती हैं और अपने आप को अपने माता–पिता पर बोझ समझने लगती हैं। इसलिए देश के कई भागों में लड़कियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। लड़की शिशु मृत्यु दर हमेशा लड़के शिशुओं की मृत्यु दर की तुलना में अधिक होती है। विवाह के पश्चात भी लड़कियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है और यहां तक कि मार भी दिया जाता है।

लड़कियों एवं लड़कों की शिक्षा में गहरा भेद मिलता है जिसका कारण उनके लिंग के हिसाब से उनके साथ पक्षपात करना एवं उनकी रूढ़िवादी छवि को गढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता दर 82.1 प्रतिशत थी। दोनों में साक्षरता के अंतर के बहुत से कारण हो सकते हैं जो लैंगिक भेदभाव को दर्शाते हैं। लड़कियों के लिए शिक्षा से वंचित होने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे–अपने छोटे भाई–बहन की देखभाल करना, जल्दी विवाह हो जाना, अत्यधिक निर्धनता होना आदि। बहुत सारी लड़कियां विवाह के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। परिवार में भी लड़कियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। यदि वे लड़की को पढ़ाते भी हैं तो इसलिए ताकि उनका विवाह हो सकें। उनको सीमित विषयों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। उनसे नौकरी की अपेक्षा नहीं रखी जाती। लड़कों की शिक्षा का संदर्भ इसके बिलकुल विपरीत हैं। उनकी शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है और उनकी शिक्षा पर पैसा भी खर्च किया जाता है क्योंकि पढ़–लिख कर कमाएगा और मां–बाप के पास ही रहेगा जबकि लड़कियों को पढ़ा–लिखा कर क्या करना है, उनको तो पराए घर जाना होता है। इस प्रकार की सोच लड़के एवं लड़कियों की लैंगिक भूमिका के कारण ही है।

लड़के यदि किसी से झगड़ा करके घर लौटे तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है जबकि लड़कियों को शांत एवं भावुक बनने के लिए कहा जाता है। लड़के यदि रोते हैं तो उनको ताने दिए जाते हैं कि 'लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो' 'शर्म आनी चाहिए तुमको, चूड़ियां पहन लो' आदि। इस तरह की बातों से लड़के उग्र, हिंसक एवं लड़ाकू बनते हैं।

बाहर के कार्यों के लिए लड़कों को ही बाहर भेजा जाता है जबकि घर के कार्य करने के लिए लड़कियों को कहा जाता है। घर के काम में लड़कियों को कुशल बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि वह शादी के बाद घरेलू कार्य अच्छे से कर सकें एवं अपनी घर–गृहस्थी संभाल सकें। लड़कों के लिए कुछ बनने एवं पैसा कमाने के लिए जोर दिया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ बनकर अपने घर को चलाने में सहायता करें। कई बार लड़कों पर इस बात का इतना दवाब बनाया जाता है कि गलत रास्ते की ओर चले जाते हैं। वे गलत तरीकों से पैसा कमाने लगते हैं या फिर मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और अपना जीवन संकट में डाल देते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लड़का एवं लड़की दोनों की ही समाज में निश्चित भूमिकाएं हैं। और दोनों से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वाह करें।

टिप्पणी

लैंगिक रूढ़िबद्धता के प्रमुख कारण

हमने देखा कि कैसे स्त्री एवं पुरुष को समाज द्वारा तय उनकी भूमिकाओं में बांध कर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पुरुषों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है परंतु उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। स्त्रियां सर्वाधिक भेदभाव की शिकार हैं। इन लैंगिक रूढ़िबद्धताओं के कारणों की पहचान करना और उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। लैंगिक रूढ़िबद्धता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं–

- **पितृसत्ता का प्रभाव** : भारत में पुरुष–प्रधान समाजों की अधिकता है। यहां पितृसत्ता का प्रभाव है जिसके अंतर्गत पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ होता है और स्त्रियों को किसी प्रकार का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। यह विचारधारा स्त्रियों का शोषण एवं उत्पीड़न करती है। केवल भारत जैसे विकासशील देश में ही नहीं अपितु विकसित देशों में भी स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के बराबर नहीं है। पितृसत्तात्मक विचारधारा स्त्री एवं पुरुष में गहन भेदभाव करती है क्योंकि यह केवल एक लिंग 'पुल्लिग' को ही अन्य से श्रेष्ठ मानती है।

- **सामाजिक रीति–रिवाज** : कई बार सामाजिक रीति–रिवाज कुछ इस प्रकार से बने होते हैं जो स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव पर ही आधारित होते हैं और उनका पालन भी किया जाता है। लड़की के जन्म से जुड़ी मान्यताएं आज भी मानी जाती हैं। दहेज प्रथा आज और भी विकराल रूप में हमारे सामने है। लड़कियां बाहर निकल कर काम तो करने लगी हैं परंतु घर में उनकी भूमिका में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया है। विवाह आज भी सामाजिक दबाव में किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां सामाजिक रीति–रिवाज भी भेदभाव में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं।

- **धार्मिक रूढ़ियां** : लगभग हर धर्म में ऐसी धार्मिक रूढ़ियां एवं मान्यताएं हैं जिनसे लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा मिलता है। हर धर्म के कर्ता–धर्ता अधिकांशतः पुरुष ही होते हैं महिलाएं नहीं। विभिन्न धर्मों में पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ बताया है। स्त्रियां, पुरुष के संरक्षण में ही रहती हैं। इसलिए धर्म भी स्त्रियों की हीन अवस्था और उनके साथ भेदभाव के लिए जिम्मेदार है।

- **शिक्षा का अभाव** : शिक्षा का अभाव लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रमुख कारण है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, समाज में हो रहे अन्याय एवं असमानता के खिलाफ तभी आवाज उठा सकेंगे जब शिक्षा द्वारा उनके भीतर चेतना जाग्रत होगी। शिक्षा के अभाव का दंश भी स्त्रियों को अधिक झेलना पड़ता है। घर–परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में वे स्वयं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं और इसलिए अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को समझ भी नहीं पातीं और न ही इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पाती हैं।

- **स्त्रियों का आर्थिक रूप से अक्षम होना** : हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव सबसे अधिक महिलाओं के साथ ही होता है और महिलाएं इसके विरुद्ध आवाज तक नहीं उठातीं। उनको रूढ़िबद्धता की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका एक कारण तो यह है कि वे अपनी स्थिति को ही अपने जीवन की नियति मानकर जीती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक

टिप्पणी

रूप से आत्मनिर्भर न होना है। वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी पिता पर, कभी भाई पर, कभी पति पर तो कभी बेटों पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में उनको पुरुषों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि जो स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं वे उन स्त्रियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र होती हैं जो आत्मनिर्भर नहीं होतीं।

- **राजनीति में महिलाओं की सीमित भूमिका** : यदि हम राजनीति में महिलाओं की भूमिका को देखें तो हमें केवल चंद ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने रूढ़िबद्धता को तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत में इन्दिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज आदि, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टों, बांग्लादेश में शेख हसीना जैसी महिलाओं ने अपने देश की बागडोर संभाली है। परंतु इनकी संख्या इतनी कम रही है कि इससे महिलाओं की राजनीति में वांछित भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती। भारत में संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित है। संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कितने वर्षों से रुकी हुई है। जब तक राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की उचित संख्या में भागीदारी एवं उनको स्वयं निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी तब तक वे समाज के हर क्षेत्र में भेदभाव एवं रूढ़िबद्धता का सामना करती रहेंगी। इन सबको समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वे राजनीति में आएं और नीति एवं निर्णयों में समानता के मूल्यों को फलीभूत करें।

महिला सशक्तीकरण

जब हम किसी व्यक्ति के सशक्तीकरण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार एवं कार्य करने की सत्ता प्रदान करने से होता है। साथ ही अपने जीवन की परिस्थितियों पर उसका अधिक नियंत्रण हो जाता है। सामान्यतः सशक्तीकरण को हम महिलाओं के संदर्भ में प्रयोग करते हैं क्योंकि ये वो कमजोर तबका है जिसको सशक्त बनाने की अधिक आवश्यकता है।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया था। वर्ष 1980 को 'महिला विकास वर्ष' के रूप में मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च भी 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में विश्वभर में मनाया जाता है। भारत में भी वर्ष 1975 को 'महिला वर्ष' एवं 1976–1985 के दशक को 'महिला दशक' के रूप में मनाया गया था। वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तीकरण वर्ष' के रूप में मनाया गया था। इसके बाद से ही महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को लोकप्रियता मिली और आज भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि उनको सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व एवं दक्षता हासिल हो और वे सुरक्षित रहें। लैंगिक असमानता, हिंसा, स्वास्थ्य आदि जैसे पहलुओं की दिशा में कार्य करके महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं का सशक्तीकरण आधुनिक जीवन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है।

टिप्पणी

इसके माध्यम से समाज के रवैये में बुनियादी परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें व्यवहार में तब्दील कर सकें, जिससे समाज का उत्थान हो। महिलाओं का सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, जिसका मूल उद्देश्य ही हाशिये के लोगों को मुख्य धारा में लाना है ताकि उनको सत्ता संरचना एवं विकास में भागीदार बनाया जा सके।

महिला सशक्तीकरण की अवधारणा मुख्यतः महिलाओं के लिए अधिकारों को मानवाधिकारों की श्रेणी में रखने की मांग करती है और महिला एवं पुरुष के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। साथ ही यह अवधारणा महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने और उनको उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य करती है। वास्तव में महिला सशक्तीकरण एक व्यापक अवधारणा है जो महिलाओं के स्वयं के जीवन पर नियंत्रण, उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने, उचित आर्थिक अवसर प्रदान करने, संसाधनों के उचित उपभोग एवं समाज में उनकी उपयुक्त भागीदारी से संबंधित है। सशक्तीकरण के प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकते हैं और सामूहिक स्तर पर भी। कई बार समूह में सम्मिलित होकर ही मनुष्य की चेतना जाग्रत होती है और वह अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। महिला सशक्तीकरण को हम तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं–

- सामाजिक सशक्तीकरण
- आर्थिक सशक्तीकरण
- राजनीतिक सशक्तीकरण

1. सामाजिक सशक्तीकरण

सामाजिक सशक्तीकरण महिला सशक्तीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के प्रति समाज की अवधारणा को बदलने के लिए सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में कदम उठाने होंगे। इसके लिए सर्वप्रथम अभावग्रस्त वर्गों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकें, मिड–डे मील, विभिन्न छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नवोदय विद्यालयों की स्थापना भी वंचित वर्गों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई।

विद्यालय की समाप्ति के बाद आगे की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियों में इजाफा किया गया है। हॉस्टल सुविधाओं को बढ़ाया गया है ताकि अपने घर से दूर पढ़ने वाले छात्र पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर लगा सकें।

इसके अलावा हमारे भारत के संविधान में भी वंचित तबकों के सशक्तीकरण के लिए शोषण और सामाजिक अन्याय से सुरक्षा के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में सशक्तीकरण के लिए रोजगार, तकनीकी कौशलों के विकास के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा का सार्वभौमिकरण, निरक्षरता उन्मूलन एवं लैंगिक

संवेदनाओं की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बनाया जा सके।

टिप्पणी

महिला सशक्तीकरण के लिए दलित महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि दलित महिलाएं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। यह वर्ग सर्वाधिक प्रताड़ित है। इनको वर्ग, जाति, लिंग तथा संस्कृति के स्तर पर घर, गांव एवं अपने समाज में भी प्रताड़ित होती है। ऐसे में इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर इनका सशक्तीकरण किया जा सकता है। एक शिक्षित महिला ही अपना व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कर सकती है।

महिलाओं के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं एवं लड़कियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके साथ ही महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा एवं शारीरिक शोषण से बचना होगा। संवैधानिक प्रावधानों एवं कानून के साथ–साथ बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रयास कर रही है परंतु महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण तब तक असंभव है जब तक समाज की मानसिकता में उनके प्रति परिवर्तन नहीं आता। इसमें शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

2. आर्थिक सशक्तीकरण

सशक्तीकरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए रोजगार और आय के साधन पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके लिए विभिन्न वित्तीय संगठनों की स्थापना की गई है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की संख्या को कम करने के लिए कई ऐसी योजनाओं का प्रारम्भ किया गया है जो विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कृषि एवं उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं के प्रयास को पहचान कर उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। विभिन्न व्यवसायों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।

महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए और उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल का वातावरण उनके लिए सहायक होना चाहिए। इसके लिए वहां पर उनके बच्चों की देख–रेख की सुविधा, क्रेच तथा वृद्ध और विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

3. राजनीतिक सशक्तीकरण

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण उनके सम्पूर्ण सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है। हालांकि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं को वोट डालने का एवं चुनाव लड़ने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त है। इस प्रकार वे सरकार के हर स्तर पर

टिप्पणी

निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। परंतु यह एक विडम्बना है कि उनके पास निर्णय लेने का अधिकार होते हुए भी निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी होना महिलाओं की समाज में समानता एवं उनको अधिकार दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में भी सीटों के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक कब से विचारधीन है परंतु इसको प्राथमिकता नहीं दी गई।

यदि हम सशक्तीकरण की अवधारणा को व्यापक दृष्टि से देखें तो इसका समन्वय तब मुश्किल हो जाता है जब प्रत्येक राष्ट्र अपनी एक अलग स्त्री प्रथा, स्त्री कानून, स्त्री रूढ़िवादिता, हर स्त्री के लिए अलग आचरण, संस्कार एवं बंधन रखता है। भारत जैसे बहु–सांस्कृतिक देश में अलग–अलग स्थानों पर स्त्रियों के लिए अलग–अलग प्रथाएं प्रचलित हैं। ऐसे में सशक्तीकरण को कानूनी प्रक्रिया में बांधना मुश्किल ही नहीं असंभव प्रतीत होने लगता है।

महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं ने स्वयं कई आंदोलन किए एवं सरकार ने समय–समय पर नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से सशक्तीकरण के नारे को साकार करने का प्रयास किया। सही मायने में महिलाएं यदि अपना सशक्तीकरण चाहती हैं तो उनको शैक्षिक योग्यता प्राप्त करके अपनी सोच, निर्णय लेने की क्षमता एवं अपनी विभिन्न भूमिकाओं में तालमेल रखकर सशक्तीकरण की दिशा में स्वयं पहला कदम उठाना होगा और सरकारों को भी रास्ता दिखाना होगा। महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में शामिल किया जाए। आत्मनिर्भरता को महिलाएं अपने सम्पूर्ण बौद्धिक एवं सामाजिक विकास के रूप में देखती है।

प्रसिद्ध नारीवादी कमला भसीन महिला सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव देती हैं–

- महिलाओं के योगदान को समाज में जाहिर करना, यानी यह दर्शाना कि महिलाएं बच्चों को जन्म देने और घर–गृहस्थी संभालने के साथ–साथ किसान, श्रमिक, कारीगर, व्यवसायी आदि भी हैं, वे सदैव उत्पादन में लगी रहती हैं और जीडीपी में उनका योगदान हमेशा ज्यादा रहा है। वे जीवन की उत्पादक, प्राकृतिक संसाधनों की प्रबन्धक आदि हैं।
- महिलाओं और समाज को, महिलाओं में पहले मौजूद रही और अब तक मौजूद विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी, क्षमता और कौशलों की पहचान कराना।
- महिलाओं को आत्म–सम्मान और आत्म–विश्वास प्रदान करने वाला सामाजिक वातावरण तैयार करना।
- महिलाओं और लड़कियों को उनके पूरे सामर्थ्य का एहसास कराने के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कुछ गिनी–चुनी परंपरागत भूमिकाओं और व्यवसायों में धकेलने की जगह और विकल्प प्रदान करना। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करना,जो उन्हें घरेलू बनाने की जगह सशक्त बनाए।

टिप्पणी

- महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाना,वे कब और किससे शादी करेंगी, क्या वे बच्चों को जन्म देंगी और कब देंगी, वे क्या पढ़ेंगी और कब पढ़ेंगी। परिवार, समुदाय और राष्ट्रीय मामलों पर भी निर्णय लेना। सभी स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं और लड़कियों की वास्तविक आवश्यकताओं, परिवार के भीतर और बाहर उनके दर्जे, उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में महिलाओं और पुरुषों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं की भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतें और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विशेष जरूरतें पूरी करने के लिए उनको सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना।
- महिलाओं को उत्पादन के साधनों तक पहुंच और नियंत्रण, संपत्ति और अन्य संसाधनों तथा आमदनी पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करना।

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका

महिलाओं के सशक्तीकरण में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जा सकता है। परंतु शिक्षा की विषय–वस्तु और प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं के पक्ष में हो। महिलाओं को शिक्षित बनाने, जानकारी एवं ज्ञान देने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये शिक्षा उनको पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियम, मूल्यों, व्यवहार एवं पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करेगी। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो केवल शब्दों को ही पढ़ने और समझने में मदद न करे अपितु दुनिया को भी पढ़ने, समझने एवं नियंत्रित करने में सहायता करे। शिक्षा महिलाओं को तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल करने में मदद करती है जो उन्हें अपमानजनक और अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास एवं ताकत प्रदान करती है। महिलाओं की साक्षरता उनकी जागृति का केंद्र बनकर उनको सशक्त करने में मदद करेगी। इससे वह अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रख सकेंगी। शिक्षा महिलाओं को चुप्पी तोड़ने में भी सहायक होगी। इसके लिए स्कूल एवं कक्षाओं में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जो महिलाओं को अधिक से अधिक आजादी दे सके।

महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ–साथ मानवीय मूल्यों का भी सशक्तीकरण आवश्यक है। तभी हमारे आस–पास समानता, न्याय एवं शांति होगी। महिलाओं का सशक्तीकरण केवल तभी त्वरित गति से संभव हो सकेगा, जब पुरुष इस बात को समझेंगे कि महिलाओं का सशक्त होना उनके लिए भी अच्छा और परिवारों एवं राष्ट्रों के लिए भी अच्छा होगा। पुरुषों को भी इस दिशा में प्रयत्न करने होंगे।

लैंगिक अनुपात

लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए और लैंगिकता तथा विकास के बारे में सामाजिक विभाजकों के बदलते पहलुओं

टिप्पणी

का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। घटते लिंग अनुपात की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बल्कि कुछ राज्यों में तो इसने भयावह रूप ले लिया है। इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चिंता प्रकट की जाती रही है। शोध अध्ययनों ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। इन अध्ययनों से यह पता चला है कि स्थायी पितृसत्तात्मक मानदंडों एवं मानसिकता के माहौल में सहायता प्राप्त प्रजनन संबंधी तकनीकों एवं कार्यप्रणाली में उन्नति की वजह से इस तरह के जन्म–पूर्व लिंग चयन की संभावना ज्यादा हो गई है और बढ़ती ही जा रही है।

पिछले दशकों में लिंग अनुपात तेजी से घटा है। जहां 1901 में यह 972 था 1991 में यह घटकर 927 रह गया। इसके बाद लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए यह अनुपात 2011 में 948 हो गया। 1991–2011 के दौरान शिशु लिंग अनुपात (0–6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या) के आंकड़े यह बताते हैं कि पूरे उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में यह खाई 2011 में और अधिक गहरी और चौड़ी हुई है जबकि 2011 में केवल हरियणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ही शिशु लिंग अनुपात बहुत कम था।

जेंडर पूर्वाग्रह पर आधारित लिंग चयन की प्रथा की वजह से जन्म के समय गायब लड़कियों की संख्या 2007–2012 के दौरान 3.3 लाख प्रतिवर्ष थी। इसके पहले के 6 वर्षों के 5.8 लाख प्रतिवर्ष के औसत की तुलना में जन्म के समय लड़कियों की संख्या में कमी दिखती है।

भारत में बाल लिंगानुपात 914 प्रति 1000 है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 1000 लड़कों की तुलना में 914 लड़कियां हैं अर्थात 86 लड़कियां कम हैं। ग्रामीण इलाकों में तो यह स्थिति और भी खराब है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध आज भी कम नहीं हैं। जो लड़कियां इस प्रकोप से बच जाती हैं उनमें 5 से 9 वर्ष तक के आयु वर्ग की 50 प्रतिशत लड़कियां कुपोषण का शिकार होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चिंता यह है कि लगभग आधी लड़कियां रक्ताल्पता (एनीमिया) और अंडरवेट की शिकार हैं। लड़कियों के जीवन में आउटडोर गतिविधियों और स्वस्थ्य जीवनशैली को बहुत कम महत्व दिया जाता है और उनमें से अधिकतर घरों तक ही सीमित रहती हैं और सबसे खराब बात यह है कि 4 वर्ष की होने से पहले ही 4 में से 1 लड़की यौन शोषण का शिकार होती है। लाखों लड़कियां कुपोषण, निरक्षरता, कमजोरी एवं प्रताड़ना का शिकार हैं।

विद्यालयों में कई बार टायलेट की सुविधा भी नहीं होती। स्वच्छता एवं रजो स्वास्थ्य की स्थिति तो और भी खराब है। मासिक धर्म हमारे समाज में शर्म का विषय है। इसकी चर्चा को समाज में वर्जित माना जाता है। लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में कर दिया जाता है। ऐसी कमजोर, अशिक्षित एवं अशक्त लड़की, कमजोर एवं खराब सेहत वाले बच्चे को जन्म देती है और इस प्रकार गरीबी, खराब सेहत एवं भेदभाव का चक्र चलता रहता है।

अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की लैंगिक भेदभाव वाली मानसिकता कैसे पनपती है? दरअसल यह समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है जिससे हम गुजरते हैं। इसके लिए समाज में जागरूकता लाना बड़ा जरूरी है। सरकार की तरफ

टिप्पणी

से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत जोर–शोर से की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना है। इसके अतिरिक्त उन जिलों की पहचान की जाएगी जहां लिंग अनुपात काफी निम्न है और वहां के लिए लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थानीय महिला संगठनों/युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी योजनाएं भी महिला स्वास्थ्य क्षेत्र के सशक्तीकरण में अपनी भूमिका निभाती हैं। इनमें कुछ हैं– सुकन्या समृद्धि योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, सबला किशोरावस्था बालिकाओं के लिए योजनाएं आदि। वास्तव में महिलाओं का स्वास्थ्य उनके सम्पूर्ण सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ महिला समाज के एक उत्पादक के रूप में बढ़ती है। वह अपनी आय से न केवल अपने परिवार की बल्कि अपनी स्वयं की भी मदद कर सकती है।

लैंगिक असमानताएं और उनके अन्य रूप

भारतीय समाज की भिन्नताओं के कारण समाज द्वारा आरोपित सामाजिक लिंगभेद एवं संबंध न तो स्थायी हैं और न ही ये सार्वभौमिक हैं। ये समय, स्थान एवं संस्कृति में बदलाव के साथ–साथ बदलते रहते हैं। साथ ही इन पर सांस्कृतिक पर्यावरणीय, आर्थिक एवं राजनीतिक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे जन्म से ही अपने लिंग के बारे में सीखने लगते हैं। वे ये भी सीखते हैं कि दूसरों की दृष्टि में स्त्री या पुरुष दिखने के लिए उनको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। सारी जिंदगी वे माता–पिता, शिक्षकों एवं बुजुर्गों से यही सीखते रहते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस अवधारणा को लैंगिक अदायगी (Gender Performitivity) कहा जाता है। लैंगिक अदायगी एक महत्वपूर्ण विचार है। इस अवधारणा में व्यक्ति को ऐसे पात्रों के रूप में देखा जाता है जो कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं जिससे उनकी पहचान निर्धारित की जाती है। इन क्रियाओं में सामाजिक कायदे–कानून एवं आदतों पर आधारित उनके रोज के किए जाने वाले व्यवहार शामिल हैं। लैंगिक अदायगी के इस सिद्धांत को प्रसिद्ध नारीवादी 'जूडिथ बटलर' ने दिया था। उनके अनुसार लैंगिकता इस बात की अभिव्यक्ति नहीं है कि हम क्या हैं? बल्कि इस बात की अभिव्यक्ति है कि हम क्या करते हैं? और ये क्या करना ही बचपन से हमें मर्द एवं औरत के सांचों में डाल देता है।

रुथ हार्टले के अनुसार लिंग पर आधारित समाजीकरण चार प्रक्रियाओं द्वारा होता है–

सामान्यतः इन चार प्रक्रियाओं के आधार पर लिंग भेद किया जाता है जो लैंगिक समाजीकरण का कारण होता है।

टिप्पणी

1. अक्सर यह देखा जाता है कि लड़कों का प्रारम्भ से ही सशक्त एवं स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पालन–पोषण किया जाता है। इसके विपरीत कुछ संस्कृतियों में छोटी लड़की के कपड़ों, बालों एवं साज–सज्जा के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। उसे यह बार–बार बताया जाता है कि वह कितनी सुंदर है। बचपन के इन शारीरिक अनुभवों का बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। वे अपने आप को एक खास ढांचे में रखकर देखने लगते हैं जैसे सशक्त, कोमल, सुंदर आदि।
2. लड़के एवं लड़कियों का ध्यान किसी विशेष चीज की तरफ आकर्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया, किचन सेट, टेडी बीयर आदि दिए जाते हैं जबकि लड़कों को खेलने के लिए बंदूक, कार, हवाई जहाज आदि जैसे खिलौने दिए जाते हैं। बहुत से निर्धन घरों में लड़कियां इन खिलौनों से नहीं खेलतीं बल्कि बचपन से ही वे असली बर्तन साफ करती हैं, घर की सफाई करती हैं एवं छोटे भाई–बहनों का ध्यान रखती हैं जबकि वे खुद बच्ची होती हैं। इन घरों में ही लड़के या तो स्कूल जाते हैं या फिर काम पर जाते हैं। इस तरह लड़के एवं लड़कियों के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार होता है इसलिए इनकी रुचियां एक खास दिशा में धाराबद्ध होने लगती हैं। जब वे बड़े होते हैं तो उनकी योग्यताएं एवं सपने भी अलग–अलग दिशा में बढ़ते हैं। कुछ विशेष चीजों से बचपन में बनी उनकी पहचान, भविष्य में उनके चुनाव पर भी असर डालती है।
3. कई बार परिवार के सदस्यों, अध्यापकों, मित्रों द्वारा लड़के एवं लड़कियों के लिए भिन्न–भिन्न सम्बोधन होते हैं जो उनके लिए उस प्रकार की छवि गढ़ देते हैं और फिर इसका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए लड़कियों को कहा जाता है कि बिटिया कितनी प्यारी लग रही है एवं लड़कों से कहा जाता है तुम हट्टे–कट्टे जवान हो।
4. लड़के एवं लड़कियां पैदा होते ही अपने चारों ओर पारंपरिक पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की भूमिकाओं को एवं स्त्रियोचित तथा पुरुषोचित गतिविधियां होते हुए देखते हैं। लड़कियां अपनी मां के साथ घर के कार्यों में उनकी मदद करती हैं जबकि लड़के अपने पिता के साथ बाहर के कार्यों में मदद करते हैं। अधिकतर समुदायों में लड़के एवं लड़कियों की परवरिश अलग तरह से की जाती है। वहां लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही वातावरण में बहुत अंतर होता है। वे सारी गतिविधियां देखते हैं और इस प्रकार उनके समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्री एवं पुरुष में गंभीर भेदभाव एवं असमानता है। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही पीड़ित हैं। परिवार ही सबसे पहली धुरी है जहां लैंगिक असमानता जन्म लेती है। लड़का एवं लड़की के लिंग अनुपात हमें बताते हैं कि भारत में लड़के के जन्म को वरीयता दी जाती है और पितृवंशात्मकता पर जोर दिया जाता है। दोनों की शिक्षा में भी अंतर पाया जाता है। लड़कों को अधिक बेहतर अवसर प्रदान करवाए जाते हैं जबकि लड़कियों की शिक्षा को

लेकर कोई प्राथमिकता नहीं दिखाई देती है। यदि स्कूल दूर हो तो छुड़वा लिया जाता है। यदि परिवार निर्धन है तो लड़की की शिक्षा सबसे पहले बलि चढ़ाई जाती है।

रोजगार की बात करें तो स्त्री एवं पुरुष रोजगार में काफी अंतर नजर आता है। यह अंतर दो तरीकों से देखा जा सकता है– पहला तो कार्य की प्रकृति में अंतर। महिलाओं को कुछ विशेष कार्य करने की अनुमति नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल महिलाओं के लिए ही उचित समझे जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है– वेतन का। अक्सर समान कार्य के लिए भी महिला एवं पुरुष के वेतन में भेदभाव किया जाता है।

टिप्पणी

भारत में लैंगिक असमानता के कारण और प्रकार

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया बाल्वे के अनुसार "पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है, और उसका शोषण करता है।" महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम, या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है।

उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिन्दू ग्रंथ 'मनु स्मृति' के निर्माता मनु के अनुसार "ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने पर पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है।"

मुसलमानों में भी समान स्थिति है और वहां भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी, धार्मिक ग्रन्थों और इस्लामी परम्पराओं द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसी प्रकार अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार के या अलग तरीके से भेदभाव हो रहे हैं।

महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से एक कारण अत्याधिक गरीबी एवं उनका शिक्षाविहीन होना है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वेश्यावृति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होती हैं। महिलाओं को न केवल असमान वेतन या अधिक कार्य करवाया जाता है बल्कि उनके लिए ऐसी नौकरियां पेश की जाती हैं जिनमें कम कौशल की जरूरत पड़ती है और जिनका वेतनमान कम होता है। यह लिंग निर्धारण के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।

लड़की को शिक्षित करना अभी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसको अपने पिता का घर छोड़ कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरी–कौशल की शर्तों को वे पूरा नहीं कर पातीं। वहीं प्रत्येक वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम, लड़कों से अच्छा रहता है। ये प्रदर्शित करता है कि 12वीं कक्षा के बाद माता–पिता

लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं करते जिससे कि वे नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, परिवार, खाने की आदतों के मामले में भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है।

टिप्पणी

समाज में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए हमें समानता पर जोर देना होगा। विभिन्न नीतियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी ताकि वे महिलाओं की बात को रख सकें। क़ानूनों में सुधार करना होगा। निर्णयों में महिलाओं को शामिल करना होगा। उनके लिए शिक्षा, रोजगार आदि के अवसर बढ़ाए जाएंगे। सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाएगा।

अपनी प्रगति जांचिए

1. इनमें से क्या जनसंख्या संरचना की सामाजिक विशेषताओं में शामिल नहीं है?
   (क) जाति (ख) आर्थिक गतिविधियां
   (ग) नागरिकता (घ) राष्ट्रीयता
2. नगर वह स्थान है जहां के निवासी परस्पर एक–दूसरे को नहीं पहचानते : इस अर्थ में नगर को किसने परिभाषित किया है?
   (क) किंग्स्ले डेविस (ख) बर्गल
   (ग) सोमबर्ट (घ) एण्डरसन

3.3 भारतीय जनसंख्या की संरचना

जनसंख्या संघटन का तात्पर्य जनसंख्या की संरचना से है।इसके अंतर्गत वह घटक शामिल किए जाते हैं जिनके संयोजन से किसी जनसंख्या या मानव समूह की रचना होती है। जनसंख्या की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन या संयोजन कहा जाता है। जनसंख्या का संघटन लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास, धर्म, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता इत्यादि द्वारा होता है।

क्लार्क के अनुसार ''संघटन या जनसंख्या संरचना जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनको मापा जा सकता है।''

जनसंख्या संगठन में वह तत्व आते हैं जिनके आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं और जिनका मापन किया जा सकता है। इनको जनसंख्या के मात्रात्मक पक्ष के रूप भी कहा जाता है।

इन सभी घटकों में से मुख्य घटक है :–लिंग,आयु,ग्रामीण– नगरीय अनुपात,व्यवसाय, आर्थिक संगठन, साक्षरता,भाषा, जाति और धर्म। इन घटकों का अध्ययन का तात्पर्य होता है क्षेत्रीय विषमताओं को प्रदर्शित करना। इन घटकों की व्याख्या और विश्लेषण द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की विषमताओं और उनसे संबंधित तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है।

लिंग संघटन

टिप्पणी

इसका तात्पर्य है किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का संघटन। स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या द्वारा किसी समाज की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। ये दोनों ही घटक किसी भी समाज के लिए और किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।

जनसंख्या का लिंग संयोजन प्राय : एक अनुपात में व्यक्त किया जाता है जिसे लिंगानुपात कहते हैं।भारत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{स्त्रियों की जनसंख्या}}{\text{पुरुषों की जनसंख्या}} \times 1000$$

अगर लिंगानुपात 1000 आता है तो इसका मतलब है इस स्त्रियों व पुरुषों की संख्या बराबर है। अगर यें आंकलन हजार से कम आता है,, तो इसका मतलब यह है कि हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है।और अगर यह आंकलन 1000 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब यह है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है।

लिंगानुपात के परिकलन की विधियां :– स्त्री और पुरुषों के अनुपात को दर्शाने के लिए कई प्रकार की विधियां इस्तेमाल की जाती हैं :–

1. प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या – इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:–

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{कुल स्त्रियां}}{\text{कुल पुरुष}} \times 100$$

2. प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या – गणना सूत्र निम्नलिखित है :–

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{कुल स्त्रियां}}{\text{कुल पुरुष}} \times 1000$$

3. प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या – गणना सूत्र निम्नलिखित है :–

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{कुल पुरुष}}{\text{कुल स्त्रियां}} \times 100$$

4. प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या –निम्नलिखित सूत्र से गणना की जाती है :–

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{कुल पुरुष}}{\text{कुल स्त्रियां}} \times 1000$$

5. कुल जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत – इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है :–

$$\text{स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{\text{कुल पुरुष}}{\text{कुल स्त्रियां}} \times 100$$

टिप्पणी

6. कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत – इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है :–

$$\text{पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

अलग–अलग देशों में लिंगानुपात अलग–अलग विधियों द्वारा प्रदर्शित जाता है। भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

भारत में लिंगानुपात : भारत में लिंगानुपात सभी आयु वर्गों में पुरुषों के पक्ष में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है जो कि 2001 (933) की तुलना में 10 अंक कम है। विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी जन्म के समय पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है। यहां पर औसतन प्रति हजार पुरुष शिशुओं के जन्म के विपरीत स्त्री शिशुओं जन्म संख्या 937 पाई जाती है।जन्म से लेकर लगभग 50 वर्ष की आयु तक स्त्रियों की मृत्यु दर भी पुरुषों से अधिक रहती है जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों का अनुपात और भी कम हो जाता है।

भारतीय जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 922 देश के सामान्य लिंगानुपात 927 से कुछ कम है। स्त्री मृत्यु दर उच्च होना इसका कारण हो सकता है।

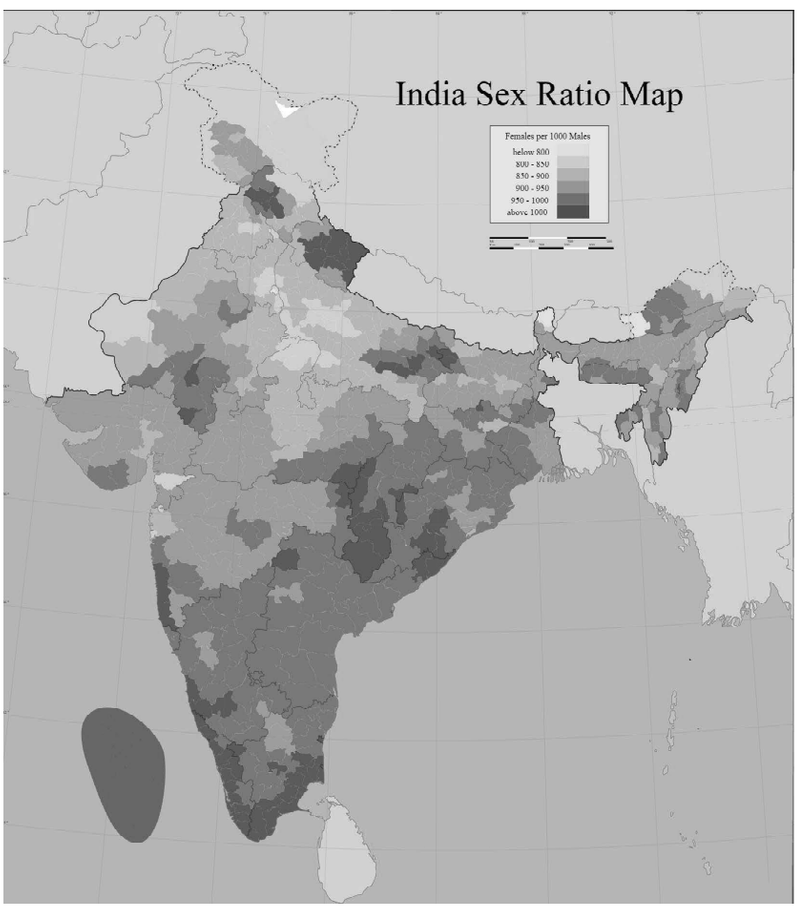

तालिका

भारत में लिंगानुपात प्रवृति (1901–2011)

वर्ष	कुल	ग्रामीण नगरीय	नगरीय
1901	972	979	910
1911	964	975	872
1921	955	970	846
1931	950	966	838
1941	945	965	831
1951	946	965	860
1961	941	963	845
1971	930	949	858
1981	934	951	879
1991	927	938	849
2001	933	944	900
2011	943	949	929

टिप्पणी

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 972 थी। तब से लेकर निरंतर महिलाओं की संख्या में उतार चढाव देखने को मिले।1911 से लेकर 1941तक ये निरंतर कम होता रहा और 1951 में यह थोड़ा से बढ़ कर 946 हो गया।1961में यह घटकर 941 और 1971 में घटकर 930 हो गया। पुन : 1981 में बढ़कर 934 हो गया और 1991 में फिर घटकर 927,2001 में बढ़कर 933 और 2011 में दश अंकों की बढ़ोतरी के साथ 943 हो गया।

1. ग्रामीण –नगरीय भिन्नता

तालिका से सुस्पष्ट है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लिंगानुपात कम है। नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात कम रहने की प्रवृत्ति 19 1 से लेकर 2011 तक बनी हुई है। जनगणना 1901में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में क्रमशः 910 स्त्रियां प्रति हजार पुरुष था जो क्रमशः घटते हुए 1991 में 938 और 894 तक पहुंच गया। देश के आंतरिक भागों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में या विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात में विभिन्नता के लिए मुख्य रूप से प्रवास ही जिम्मेदार है। हमें लिंगानुपात में निरंतर ह्रास होता रहा है। 1901 में ग्रामीण लिंगानुपात 1979 से घटकर 1991 में 938 हो गया। 2011 में ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात क्रमशः 949 और 929 था।

भारत में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भिन्नता का प्रमुख कारण यह है कि, लिंग परक प्रवास से देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बेरोजगारी, निर्धनता, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण बड़ी संख्या में शहरों में शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, मनोरंजन इत्यादि के साधनों को देखते हुए प्रवास करते हैं। इस प्रवास में मुख्यतः संख्या पुरुषों की होती है। स्त्रियां मूलतः अपने मूल स्थान पर ही रहती हैं। वे केवल शादी के कारण ही अपना निवास परिवर्तन करती हैं।

टिप्पणी

2. सामाजिक वर्गानुसार भिन्नता

भारत के विभिन्न धार्मिक व जातीय समुदाय के अनुसार लिंगानुपात का अवलोकन किया जाए तो उनमें भी विशेष अंतर देखने को मिलता है। हिंदू समुदाय का लिंगानुपात देश के अनुपात सामान्य लिंगानुपात अनुसार पाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात हिंदुओं की तुलना में कम पाया जाता है। सिख समुदाय में भी लिंगानुपात सामान्य पाया जाता है। इस समुदाय में पुरुष मृत्यु दर और महिला मृत्यु दर में कोई विशेष अंतर नहीं है। मुस्लिम समुदाय में अशिक्षा, बेरोजगारी और अनेक रीति–रिवाजों की वजह से महिला मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। ईसाई समाज में उच्च शैक्षिक स्तर,स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता,सामाजिक समानता कारण स्त्रियों की मृत्यु दर विकसित देशों की की भांति कम पाई जाती है।

सामाजिक वर्ग	1981	1991	अन्तर
अनुसूचित जाति	932	922	–10
अनुसूचित जनजाति	983	972	–11
अन्य वर्ग	930	923	–7
कुल जनसंख्या	935	927	–8

1981 में भारत का सामान्य लिंगानुपात 935 और अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 932 था जो घटकर 1991 में क्रमशः 927 और 922 हो गया। 1991 में सामान्य लिंगानुपात 8 अंकों की और और अनुसूचित जाती में 11 अंकों की कमी दर्ज की गई।

3. प्रादेशिक भिन्नता

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वोच्च लिंगानुपात 1084 केरल राज्य में पाया गया जबकि निम्नतम लिंगानुपात 618 केंद्र शासित क्षेत्र दमन और दीव में पाया गया। केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी में भी 1037 लिंगानुपात दर्ज किया गया। तमिलनाडु,आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,मणिपुर, मेघालय,मिजोरम,उड़ीसा, कर्नाटक,हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,गोवा, त्रिपुरा, आसाम,झारखंड,पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप में उच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया। पंजाब,सिक्किम,जम्मू कश्मीर,अंडमान निकोबार,दिल्ली,हरियाणा,दादरा एवं नगर हवेली,चंडीगढ़, दमन और दीव में 900 से कम लिंगानुपात दर्ज किया गया।

आयु संघटन

आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को आयु संघटन कहते हैं। इसे किसी प्रदेश की आयु सरंचना भी कहते हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में आयु सरंचना विभिन्न मिलती है। 15 –59 आयु वर्ग को क्रियाशील जनसंख्या माना जाता है। जिस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्ध और बच्चों की संख्या अधिक होगी वहां पर निर्भरता अधिक मिलेगी और विकास की गति मंद पाई जाएगी।किसी क्षेत्र की जनसंख्या 15 –59 आयु वर्ग में अधिक पाई जानी है तो वहां पर प्रगति के आसार पाए जाते हैं। क्रियाशील जनसंख्या होने से संसाधनों का प्रबंधन ठीक होता है।

आयु संघटन को प्रभावित करने वाले कारक

टिप्पणी

जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास आयु संघटन को प्रभावित करने वाली मुख्य कारक हैं जो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। सामाजिक आर्थिक दशा भी आयु संरचना को प्रभावित करती है।

प्रजननता :– प्रजनन दर जनसंख्या की आयु संरचना का प्रमुख निर्धारक तत्व है। जिन देशों में जन्म दर उच्च होता है वहां पर निम्न आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या अनुपात पाया जाता है और जीवन प्रत्याशा कम होने के कारण उच्च आयु वर्ग में जीवन का अल्प अंश मिलता है। विकासशील देशों जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों में उच्च जन्म दर के कारण 35 से 40% जनसंख्या 0–14 आयु वर्ग में पाई जाती है। और 65 वर्ष से या उससे अधिक 4% से भी कम जनसंख्या मिलती है। इसके विपरीत विकसित देशों में जन्म दर निम्न और जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण 0 – 14 आयु वर्ग में 25% से कम जनसंख्या और 65 या इससे अधिक आयु वर्ग में 10% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है।

मृत्यु दर :– विभिन्न आयु वर्गो में मृत्यु दर अलग–अलग पाई जाती हैं। जिस भी आयु वर्ग में मृत्यु दर कम हो जाती है उसी आयु वर्ग की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों चिकित्सा और पोषण में सुधार के कारण 0 से 14 आयु वर्ग में जनसंख्या वृद्धि पाई गई। जीवन प्रत्याशा में सुधार होने से उच्च आयु वर्ग में भी जनसंख्या बढ़ जाती है। विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा कम होने की वजह से पूछ आयु वर्ग की जनसंख्या में कमी पाई जाती है और जीवन प्रत्याशा अधिक होने से विकसित देशों में उच्च आयु वर्ग में संख्या अधिक होती है।

प्रवास :– प्रवास आयु संघटन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या प्रवास विशेष आयु वर्ग में होता है और जिस देश से प्रवास होता हैं वहां पर उस आयु वर्ग में जनसंख्या कम और जहाँ पर प्रवास होता है उस आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या के प्रवास में युवकों और प्रोढों की प्रमुखता पाई जाती है जिसके कारण उत्प्रवास करने वाले देशों में बाल व वृद्ध जनसंख्या का अनुपात ऊंचा हो जाता है और युवा जनसंख्या का अनुपात पहले से कम हो जाता है। इसके विपरीत अप्रवास करने वाले देशों में युवा जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है।

अन्य कारक :– आयु संघटन पर प्राकृतिक संकटों, युद्ध, महामारियों, जनसंख्या नीतियों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। किसी भी महामारी का प्रभाव बाल आयु वर्ग पर सर्वाधिक होता है, वहां की जनसंख्या कम हो जाती है। युद्ध का प्रभाव युवा आयु वर्ग पर सर्वाधिक होता है, तो इस आयु वर्ग में सर्वाधिक मृत्यु दर पाई जाती है। इसी प्रकार देश की जनसंख्या नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। चीन ने 1990 में एक शिशु से अधिक शिशुओं के जन्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे जन्म दर में तीव्र ह्रास हुआ। इसी प्रकार भारत में जनसंख्या नीति के तहत परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया, जिससे जन्म दर में उल्लेखनीय कमी आई।

भूगोलवेत्ता आयु संरचना के विश्लेषण के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उसमें आयु पिरामिड, आयु सूचकांक, आयु वर्ग और माध्यिका आयु प्रमुख हैं। आयु

पिरामिड एक अरेखीय प्रतीक है जबकि आयु वर्ग, आयु सूचकांक और आयु माध्यिका सांख्यिकी विधियां हैं।

टिप्पणी

भूगोलवेत्ता क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शाने के लिए वर्ण मात्री मानचित्र तैयार करते हैं। और ये मानचित्र प्रादेशिक तुलना के लिए उपयुक्त होते हैं। वर्ण मात्री मानचित्र बनाने के लिए संपूर्ण जनसंख्या को आयु वर्गों में रखा जाता है।

सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय दृष्टि से 15 और 65 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण विभाजक मानी जाती है। इसके अनुसार जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है।

1. बाल आयु वर्ग (0–14)
2. वयस्क आयु वर्ग (15 –64)
3. वृद्ध आयु वर्ग (65 वर्ष एवं अधिक)

आयु वर्गों की संख्या और उनके मध्य का समय अंतराल विभिन्न देशों की जनगणना में भिन्न–भिन्न हो सकता है। आयु वर्गों का समय अंतराल समान या उद्देश्य के अनुसार विषम भी हो सकता है।

1. बाल आयु वर्ग (0–14) : इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में बाल जनसंख्या का आकार व अनुपात एक समान नहीं पाया जाता है क्योंकि इस पर जन्म दर,मृत्यु दर,आर्थिक स्तर और जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है।

जनांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था वाले देशों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होने के कारण बाला आयु वर्ग का अनुपात सामान्यत : उच्च पाया जाता है। संक्रमण की द्वितीय अवस्था मृत्यु दर तीव्र ह्रास और जन्म दर के मंद पतन के कारण बाल आयु अनुपात अधिकतम सीमा तक बढ़ जाता है। तृतीय अवस्था में इसके अनुपात में ह्रास हो जाता है। संक्रमण की अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के लिए निम्न होने के बाद बाल संख्या सीमित हो जाती है। संपूर्ण विश्व की 26% जनसंख्या बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। अफ्रीकी देशों में 45% जनसंख्या बाल आयु वर्ग में पाई जाती है। विकसित देशों में केवल 16% जनसंख्या ही बाल आयु वर्ग में पाई जाती है।

2. वयस्क आयु वर्ग (15–64) : इस आयु वर्ग में 15 से लेकर 64 वर्ष आयु के सदस्य शामिल होते हैं। इस आयु वर्ग को क्रियाशील जनसंख्या आयु वर्ग माना जाता है। जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक पाई जाती है वहां पर अधिक आयु तक लोग आर्थिक क्रियाओं में सलंग्न रहते हैं। इसके विपरीत जहां पर जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है वहां पर क्रियाशीलता की ऊपरी सीमा 55 से 60 वर्ष के मध्य पाई जाती है।

वयस्क आयु वर्ग में जैविक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रजननशील,आर्थिक रूप से सर्वाधिक क्रियाशील व उत्पादक और जनांकिकीय रूप से सर्वाधिक गतिशील जनसंख्या मानी जाती है। विश्व के विभिन्न देशों में व्यस्क जनसंख्या का प्रतिशत अलग–अलग पाया जाता है। सयुंक्त राष्ट्र संघ(2014)के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में

वयस्क आयु वर्ग का अनुपात विकसित देशों में 67% और विकासशील देशों में 65% है। संपूर्ण विश्व के लिए वयस्क आयु वर्ग का औसत 66% है।

3. वृद्ध आयु वर्ग (65 वर्ष या उससे अधिक) : इस आयु वर्ग के लोग वरिष्ठ नागरिक भी कहलाते हैं। वृद्ध व्यक्ति को लंबी आयु के कारण जीवन का सर्वाधिक अनुभव होता है लेकिन स्वास्थ्य संबंधी क्षमता कम हो जाने से उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली है। कम विकसित देशों में यह मात्र 4% है।

टिप्पणी

आयु पिरामिड

यह विधि जनसंख्या की आयु संरचना के विश्लेषण की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधि है। आयु पिरामिड मुख्यतः दंड आरेख है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर स्त्री और पुरुषों की निरपेक्ष संख्या अथवा उसके प्रतिशत को और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर समान समय अंतराल पर आयु वर्गों को अंकित किया जाता है। आने के लिए बीच में ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाया जाता है जिस पर आयु को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी एक और पुरुष और दूसरी और महिला संख्या या प्रतिशत अनुपात में क्षैतिज स्तम्भ बनाये जाते हैं।

इसकी आकृति पिरामिड से मिलती है इसलिए इसको पिरामिड आरेख भी कहा जाता है। आयु पिरामिड का आधार विस्तृत और शीर्ष संकुचित होता है।

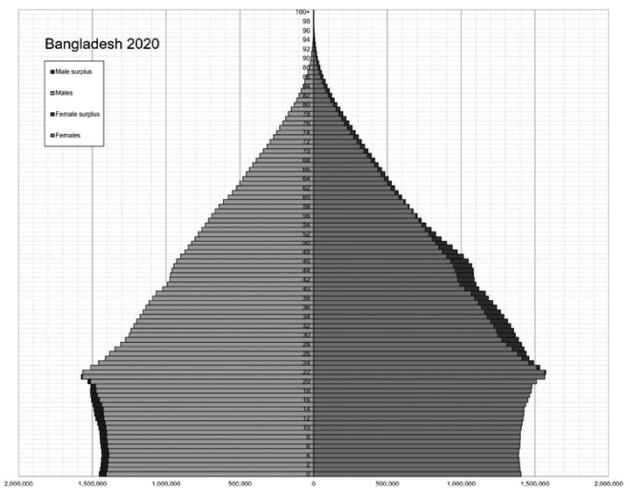

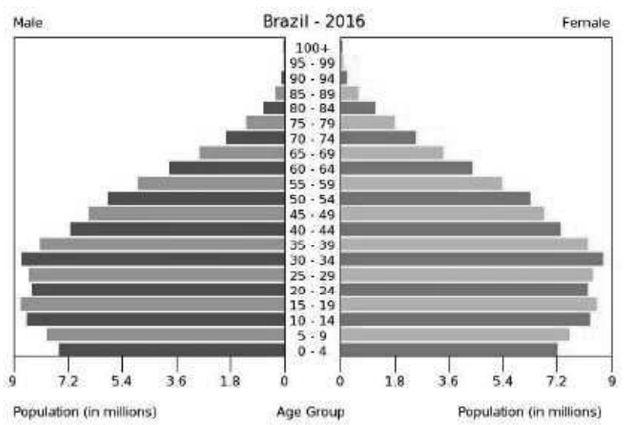

टिप्पणी

जिन देशों के संक्रमण की प्रथम अवस्था है वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च और जीवन प्रत्याशा अल्पतम पाई जाती है।जन्म दर उच्च होने से निम्न आयु वर्गों में जनसंख्या का अनुपात अधिक रहता है,जिससे पिरामिड का आधार विस्तृत होता है। उच्च मृत्यु दर और अल्प जीवन प्रत्याशा के कारण उच्च आयु वर्गों जनसंख्या कम हो जाती है, जिससे शीर्ष नुकीला हो जाता है। मध्य अफ्रीकी देशों में इसी प्रकार का आयु पिरामिड पाया जाता है।

जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में कमी आने लगती है किंतु जन्म दर उच्च रहती है जिसे निम्न आयु वर्गों उच्च बना रहता है। मृत्यु दर पर गिरने से जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है और ऊपरी आयु वर्गों का संकुचन धीरे–धीरे होता है लेकिन शीर्ष अभी भी नुकीला रहता है।

संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म दर में ह्रास होने लगता है और जन्म दर भी कम होने लगती है। इस अवस्था में निम्न आयु वर्गों के स्तंभ पहले से संकुचित जाते हैं और मध्यवर्ती और उच्च वर्ग के स्तम्भ पहले से बड़े हो जाते हैं। भारत इसी श्रेणी में आता है।

जनांकिकीय के संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पर हो जाते हैं और जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। इस अवस्था में पिरामिड के निचले आयु वर्गों में जनसंख्या का आकार संकुचित हो जाता है, मध्य आयु वर्गों की लंबाई धीरे–धीरे घटती है और उच्च आयु वर्ग के स्तंभ अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं। विश्व के सभी विकसित देश इस अवस्था में पाए जाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि के आयु पिरामिड इसी प्रकार के बनते हैं।

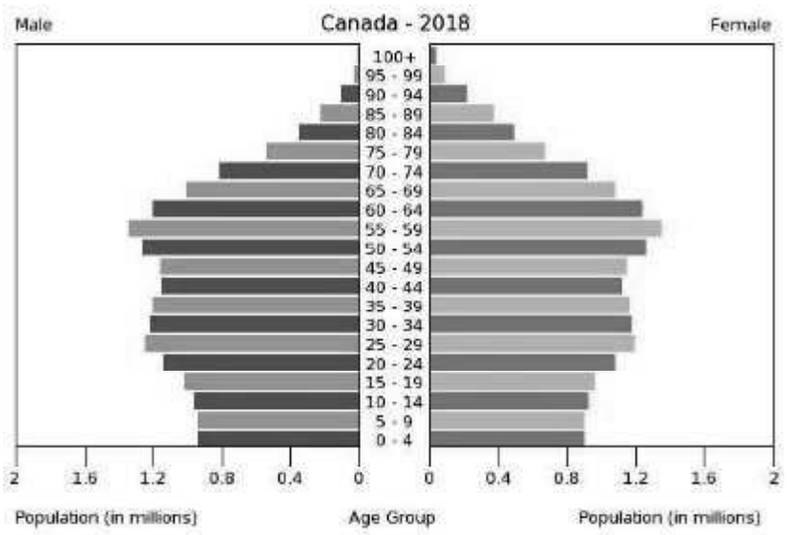

आयु पिरामिड की आकृति जनांकिकीय संक्रमण की विशेष अवस्था के अनुसार होती है। अतः इसको देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि संबंधित देश या क्षेत्र संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है। इस प्रकार किसी क्षेत्र की जनांकिकीय इतिहास को आयु पिरामिड के माध्यम से जाना जा सकता है।

टिप्पणी

किसी देश की आयु पिरामिड की सामान्य अवस्थाओं में अगर विकृति आती है तो उन विकृतियों के जिम्मेदार कारकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में मृत्यु दर अधिक होने से आयु पिरामिड में विशेष बदलाव देखे गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान ने गर्भपात को मान्यता दे दी जिससे निम्न आयु वर्ग के आयु पिरामिड में बदलाव दिखाई दिये।

जनसंख्या पिरामिड से क्रियाशील और आश्रित जनसंख्या का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। क्रियाशील जनसंख्या उत्पादक कार्यों में लगी होती है जबकि आश्रित जनसंख्या आर्थिक बोझ को बढ़ाती है। अगर किसी देश की अधिक जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या है तो उस देश में आर्थिक विकास देखने को मिलता है।

भारत में जनसंख्या की आयु सरंचना

आयु सरंचना किसी भी देश की जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था को प्रकट करती है।भारत जनाँकिकीय संक्रमण की विस्फोटक अवस्था में है, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अन्तर होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अधिकांश विकासशील देश इसी अवस्था में है जहां पर बाल जनसंख्या का आकार प्राय कुल जनसंख्या के एक तिहाई या उससे भी बड़ा पाया जाता है और वृद्ध जनसंख्या का आकार छोटा पाया जाता है। इस प्रकार के देशों का आधार बहुत विस्तृत और शीर्ष संकुचित होता है।

भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 37.85% बाल आयु वर्ग, 58.11% वयस्क आयु वर्ग और 4.04% वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत था।

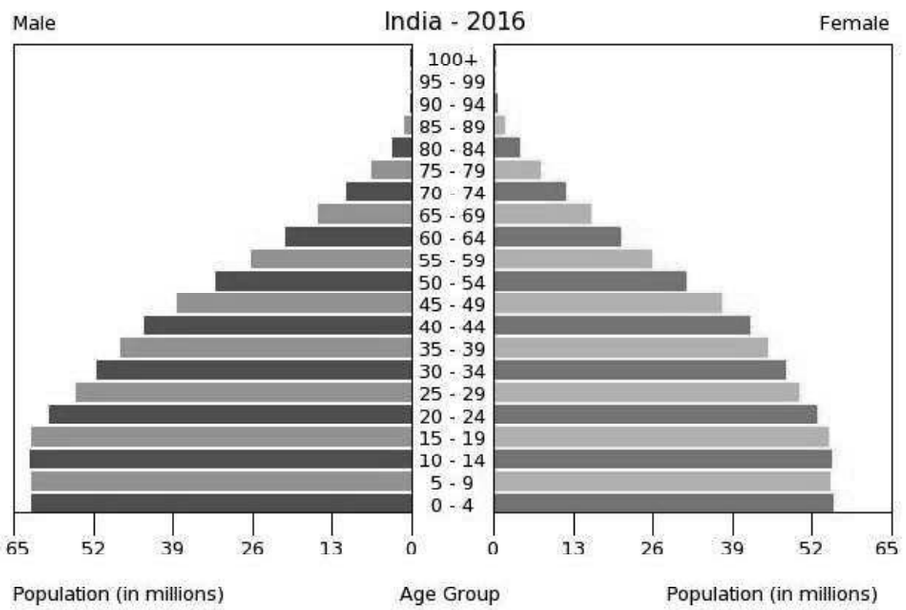

अगर भारत की आयु पिरामिड को हम देखते हैं तो उसे स्पष्ट होता है कि भारत का आयु पिरामिड का आधार अधिक विस्तृत है बाल आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक

केंद्रित है जो उच्च जन्मदर का सूचक है। आयु पिरामिड का शीर्ष नुकीला है जो निम्न जीवन प्रत्याशा का संकेत है। 1991 में भारत में जीवन प्रत्याशा 58 वर्ष थी।

टिप्पणी

तालिका

भारत की जनसंख्या का आयु वर्गों में प्रतिशत वितरण (2010)

आयुवर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
0—4	9.32	9.41	9.22
5—9	10.48	10.64	10.32
10—14	10.96	11.14	10.77
15—19	9.95	10.26	9.62
20—24	9.20	9.24	9.16
25—29	8.38	8.24	8.52
30—34	7.32	7.17	7.48
35—39	7.03	6.89	7.19
40—44	5.98	6.02	5.94
45—49	5.15	5.16	5.14
50—54	4.05	4.15	3.95
55—59	3.23	3.12	3.35
60—64	3.12	3.00	3.23
65—69	2.18	2.08	3.00
70—74	1.59	1.55	1.63
75—79	0.76	0.72	0.81
80—84	0.51	0.47	0.56
85	0.59	0.54	0.5
योग	100	100	100

Source: Sample Registration System Statistical Report 2010,Registrar General India.

भारत का आयु वर्गों में वितरण

भारत में जनसंख्या की आयु संरचना के अध्ययन के लिए उसे चार प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।

तालिका

भारत में जनसंख्या का बृहत् आयु वर्गों में प्रतिशत वितरण 2010

आयुवर्ग	कुल	पुरुष	महिला
0—14	30.76	31.19	30.41
15—39	41.88	41.8	41.97
40—59	18.14	18.45	18.38
60	8.45	8.56	9.34
कुल	100	100	100

टिप्पणी

(1) बाल आयु वर्ग(0–14) :– यह भारत की कुल जनसंख्या 30.76 प्रतिशत है। 5 वर्ष की आयु से कम पुरुष शिशुओं की संख्या 9.41% तथा महिला शिशुओं की संख्या 9.22% थी। 5 –9 और 10 –14 आयु वर्ग में पुरुष शिशुओं की संख्या 10.34 और 11.14% क्रमशः थी। 5 – 9 तथा 10 –14 आयु वर्ग में महिला शिशुओं की संख्या क्रमशः 10.32% तथा 10.70% थी। यह आयु वर्ग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आता है। इसका भरण पोषण सक्रिय जनसंख्या पर आधारित होता है। पिछड़ी आर्थिक व्यवस्था में इस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा होती है। जन्म दर अधिक होने के कारण इस आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। भारत में परिवार नियोजन के प्रचार और प्रसार के कारण कुल जनसंख्या में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत धीरे–धीरे घट रहा है। 1961 में देश की 41.1 प्रतिशत जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग में थी जो बढ़कर 1971 में 42. 0 और 1981 में घटकर 39.3 फिर 1991 में घटकर 34.3 और 2010 में घट कर 30.76 प्रतिशत हो गई।

(2) युवा आयु वर्ग (15–39):– भारत की लगभग 41.88% जनसंख्या युवा वर्ग में आती है। 2010 आंकड़ों के अनुसार इस आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या 41. 97% तथा पुरुषों की संख्या 41. 80% थी। यह वर्ग सक्रिय जनसंख्या में आता है, जिसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 1961 में इस वर्ग में 30.8 प्रतिशत जनसंख्या थी जो घटकर 1971 में 36.6% और 1981 में बढ़कर 38.1% और 1991 में 39.8 और 2010 में यह बढ़कर 41.88 प्रतिशत हो गई।

(3) प्रौढ़ आयु वर्ग (40–59):– भारत में 40 से 59 आयु वर्ग को प्रौढ़ और 60 वर्ष को वृद्ध आयु वर्ग माना जाता है। इस आयु वर्ग में देश की 18.41% जनसंख्या आती है। देश की प्रौढ़ जनसंख्या युवा जनसंख्या से आधी से भी कम पाई जाती है। इसका कारण है निम्न जीवन प्रत्याशा। 1961 में इस आयु वर्ग में 15.4 प्रतिशत जनसंख्या थी तथा 1971 में भी यह 15.4 प्रतिशत ही थी। 1981 में थोड़ा बढ़कर 15.8% और 1971 में फिर 15.7% और 2010 में यह बढकर 18.41% हो गई। चिकित्सा सुविधाओं से भारत में जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है, यही कारण है कि 2010 में यह बढ़कर 18.40% हो गई।

(4) वृद्ध आयु वर्ग (60):– विकसित देशों में इस वर्ग में 65. आयु वर्ग जनसंख्या को लिया जाता है परंतु भारत जैसे विकासशील देश जहां पर जीवन प्रत्याशा कम है 60. आयु वर्ग के लोगों को इस वर्ग में दिया जाता है। 2010 के आंकड़ों के अनुसार इस वायु वर्ग में कुल 8.95% जनसंख्या थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 8.56% जबकि स्त्रियों की संख्या 9.34% थी। 1961 में इस आयु वर्ग में 5.7 प्रतिशत जनसंख्या थी, जो बढ़कर 1971 में 6.0 प्रतिशत, 1981 में 6.5 प्रतिशत, 1996 में 6.8 प्रतिशत तथा 2010 में बढ़कर 8.95 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा तथा संक्रमण की उच्च अवस्था का परिणाम थी।

टिप्पणी

भाषाई संघटन

भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बसाव की लंबी प्रक्रिया चली और अलग–अलग स्थानों से आने वाले विभिन्न नृ –जातीय वर्ग अपने साथ विभिन्न देश की बोलियां और भाषाएं लेकर आए।

1961 की जनगणना के दौरान किए गए विस्तृत भाषाई सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि भारत में 187 भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें से 94 भाषाएँ ऐसी हैं जो 10 हजार से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भारत के 97 प्रतिशत लोगों के द्वारा 23 भाषाएं बोली जाती हैं और केवल 3 प्रतिशत लोगों द्वारा 164 भाषाएं बोली जाती हैं।

तालिका

भारत : 2001 में अनुसूचित भाषाओं को बोलने वालों की तुलनात्मक संख्या

आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
हिंदी	41.03
बांग्ला	8.11
तेलुगू	7.31
मराठी	6.99
तमिल	5.91
मलयालम	5.01
उड़िया	4.48
पंजाबी	3.21
असमिया	1.28
मैथिली	1.18
संथाली	0.63
कश्मीरी	0.54
नेपाली	0.28
सिंधी	0.25
कोंकणी	0.24
डोगरी	0.22
मणिपुरी	0.14
बोडो	0.13
संस्कृत	————

2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत के 42. 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला,मराठी, तेलुगू,तमिल भाषा भी अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है।

प्रमुख भाषाई परिवार

भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंधित चार मुख्य भाषाई परिवार से है :–

टिप्पणी

1. इंडो –यूरोपीयन परिवार
2. द्रविड़ परिवार
3. ऑस्ट्रिक परिवार
4. साइनो –तिब्बती परिवार

1. इंडो यूरोपियन परिवार (आर्य) : यह भाषा उत्तरी भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का सबसे बड़ा समूह है। इस भाषा का प्रमुख क्षेत्र खड़ी बोली का प्रदेश कहलाता है जिसमें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है। क्षेत्र से दूर जाने पर इस भाषा के विभिन्न रूप और उसमें उप भाषाएं देखी जा सकती हैं। दार्दी, कोहिस्तानी, कश्मीरी, लहनदा, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी, असमिया, बघेली, अवधी, उड़िया, कछी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, नेपाली इस भाषा की शाखाएं हैं।

हिंदी इस परिवार की मुख्य भाषा है जो देश की 40% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। यह प्रमुख रूप से बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है।

उर्दू भाषा हिंदी भाषा से नजदीक है, यह बिहार, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नगरीय भारत के ज्यादातर स्थानों में बोली जाती है।

2. द्रविड़ परिवार : द्रविड़ परिवार में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल शामिल है जो देश के 22% लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बोली जाती है।

3. ऑस्ट्रिक परिवार या आग्नेय परिवार : यह भाषा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जनजातीय समूह द्वारा बोली जाती है। यह भाषा दो प्रमुख शाखाओं से संबंध रखती है–

- मुण्डा (संथाली)
- मोन –खमेर (खासी तथा निकोबारी

मुंडा भाषा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। मोन खमेर खांसी और जयंतिया की पहाड़ियों में बोली जाती है निकोबारी निकोबार द्विप समूह में बोली जाती है।

4. साइनो –तिब्बती परिवार : साइनो तिब्बती मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में बोली जाती है। इस भाषा के तीन उपविभाग हैं:–

- **तिब्बतो –हिमालय :** इस वर्ग में हिमाचल प्रदेश की चंबा, लाहौली, किन्नौरी व लेपचा भाषाएं शामिल हैं। बालटी, लद्दाखी,भूटिया, तिब्बती भाषा जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भाग में बोली जाती है।
- **उत्तरी असम व अरुणाचल प्रदेश :** उत्तरी आसाम व अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैंय अबोर,अका,असमिया मिरि,मिशिंग और डफला।

टिप्पणी

- **असमिया – म्यांमारी** : यह भाषा आसाम के बोडो, कोच्चि, कुकीचीन, मिरि,नागा और जाकसा जनजातियों द्वारा बोली जाती है।

भारत के भाषाई प्रदेश

भाषा और बोली द्वारा प्रादेशिक पहचान बनती है। किसी भी प्रदेश की अलग पहचान उसके लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा से होती है। स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। भाषा के आधार पर प्रमुख प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया लेकिन जनजातियों की भाषाएं और बोलियां इस प्रादेशीकरण उनके रूपरेखा के अनुसार नहीं था,क्योंकि जनजातियों का वितरण बहुत जटिल है। जनजाति द्वारा बोली गई भाषाएं राज्यों के अनुसार नहीं है।

मुख्यतः भारत की मुख्य भाषाएं 12 भाषाई प्रदेशों की रचना करती हैं।

तालिका

भारत : भाषाई प्रदेश

भाषाई प्रदेश	राजनीतिक प्रदेश
कश्मीरी	जम्मू और कश्मीर
पंजाबी	पंजाब
हिंदी ध्उर्दू	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्य, प्रदेश, दिल्ली,हरियाणा
बांग्ला	पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान–निकोबार,उत्तरपूर्वी क्षेत्र के अंदर राज्य
असमी	असम व उत्तर पूर्वी
उड़िया	ओडिशा
गुजराती	गुजरात
मराठी	महाराष्ट्र, गोवा
कन्नड़	कर्नाटक
तेलगु	आंध्र प्रदेश
तमिल	तमिलनाडु, पुदुचेरी
मलयालम	केरल,लक्षद्वीप

कोई भी भाषा उसी भाषाई राज्य तक सिमित नहीं है बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में भी वह भाषा बोली जाती है।

धार्मिक संघटन

भारत 80% से भी अधिक जनसंख्या द्वारा हिंदू धर्म का अनुसरण किया जाता है। धर्म किसी भी जाति या राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। हिंदू धर्म के अलावा भारत में बौद्ध, जैन, सिख धर्म का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लाम धर्म भी भारत में पाया जाता है।

टिप्पणी

तालिका

भारत की जनसंख्या का धार्मिक संघटन(1961–2011)

धार्मिक वर्ग	कुल जनसंख्या का प्रतिशत					
	1961	1971	1981	1991	2001	2011
हिन्दू	83.50	82.82	82.63	82.41	80.46	79.8
मुस्लिम	10.70	11.2	11.36	11.67	13.43	14.23
ईसाई	2.40	2.59	2.43	2.32	2.34	2.30
सिख	1.80	1.89	1.96	1.96	1.99	1.87
बौद्ध	0.70	0.71	0.71	0.77	0.77	0.70
जैन	0.50	0.40	0.48	0.41	0.41	0.37
पारसी व अन्य	0.40	0.41	0.43	0.43	0.78	0.88

Source: Census of India 2011, Series &1, India : Report on Religion Data.

भारत में जनसंख्या की धार्मिक अवस्थिति

1. हिंदू : भारत का सबसे बड़ा धर्म है। भारत के हिंदुओं की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत है। हिंदू धर्म के अनुयाई पूरे देश में फैले हुए हैं परंतु कुछ राज्यों या प्रदेशों में हिंदुओं का सकेंद्रण कम है। बिहार, उत्तरांखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि हिंदू बहुल राज्य हैं। इन अधिकांश राज्यों में हिंदू जनसंख्या 85% से अधिक है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। भारत के जम्मू कश्मीर में इस्लाम धर्म और उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाई धर्म के अनुयाई अधिक है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

2. इस्लाम : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 14.23 प्रतिशत है। इसका अनुपात 1991 में 11.64 प्रतिशत था।

भारत में इस्लाम धर्म का प्रारंभ 11वीं शताब्दी में माना जाता है परंतु इसका वास्तविक प्रसार 13वीं शताब्दी में हुआ जब प्रथम मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मुस्लिम शासन के समय मुस्लिम शासकों ने बहुत सारे हिंदुओं को लालच देकर या जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। भारत में मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से हिंदुओं के बाद द्वितीय के स्थान पर है। 1947 से पहले भारत में मुस्लिम जनसंख्या 22.6 प्रतिशत थी। विभाजन के पश्चात मुस्लिम भूलता वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। मुस्लिम समुदाय में जन्म दर अधिक होने के कारण इनका प्रतिशत बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर गुजरात और तमिलनाडु आते हैं।

3. ईसाई : भारत में ईसाई धर्म तीसरे स्थान पर आता है। ईसाई धर्म का जन्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व फिलिस्तीन में हुआ माना जाता है इसके संस्थापक ईसा मसीह

टिप्पणी

थे। ईसाई धर्म की उत्पत्ति यहूदी धर्म से हुई मानी जाती है। भारत की 2.30% जनसंख्या ईसाई धर्म अनुयायी है।

ईसाई धर्म तीन समूह में विभक्त है :– पूर्वी कट्टरपंथी,रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कट्टरपंथी बाइबिल में अधिक विश्वास रखते हैं और रोमन कैथोलिक चर्च में आस्था रखते हैं तथा प्रोटेस्टेंट उदारवादी होते हैं। भारत में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वर्ग के ईसाई रहते हैं। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आरंभ हुआ। यहां पर अनेक ईसाई मिशनरियों ने भारत आकर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इनके प्रभावाधीन अनेक दलित हिंदुओं और निम्न जनजाति के लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। 1961 में भारत में ईसाई जनसंख्या 2.40 प्रतिशत थी जो घटकर 2011 में 2.30 प्रतिशत रह गई। ईसाई समाज के लोगों में उच्च शिक्षा प्रतिशत पाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है।

मेघालय में 70.3%, मिजोरम में 87% और नागालैंड के 90% जनसंख्या ईसाई धर्मावलंबी है। केरल और मणिपुर में इसाई धर्म के अनुयायी अधिक पाए जाते हैं। ईसाइयों की वास्तविक संख्या की दृष्टि से केरल (82.9 लाख) सबसे बड़ा राज्य है उसके पश्चात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आते हैं।

4. सिक्ख धर्म : सिक्ख धर्म भारत में चौथे नंबर पर आता है। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। हिंदू संख्या के धर्म परिवर्तन से इस धर्म का उद्‌भव हुआ। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 1.7 प्रतिशत जनसंख्या सिख जनसंख्या है। भारत की 90% से अधिक सिख जनसंख्या पंजाब में केंद्रित है। पंजाब की कुल जनसंख्या का 60% सिक्ख और 36.9% हिंदू हैं। पंजाब के अतिरिक्त कुछ सिक्ख हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।

5. बौद्ध धर्म : बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे जिन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रवर्तन किया। भरत को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कहा जाता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति दुखः वाद को लेकर हुई। इस धर्म के अनुसार इच्छाओं और तृष्णा को त्याग कर निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने दुख निवारण जो मार्ग बताया उसकी आठ अंग हैः– 1 सम्यक् दृष्टि 2 सम्यक् संकल्प 3 सम्यक् वाणी 4 सम्यक् कर्म 5 सम्यक् आजीव 6 सम्यक् व्यायाम 7 सम्यक् स्मृति 8 सम्यक् समाधि। सइस मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है कि वे दोनों अतियों के मध्य का मार्ग है। बौद्ध धर्म में नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया गया।

भारत की मात्र 0.7% जनसंख्या बौद्ध धर्म के अनुयायी है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा है। बी. आर. अंबेडकर की प्रेरणा से दलित वर्ग के बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कर दिया लिया था। बौद्धों का सकेंद्रण जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में स्पीति क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में कमेंग जनपद में पाया जाता है।

6. जैन धर्म : जैन धर्म का उद्‌भव स्थल भी भारत को ही माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। स्वामी महावीर के अनुसार संसार के दुखों को कम

करने के लिए मनुष्य को परिवार, संपत्ति, आसक्ति तृष्णा, संसार आदि को त्याग कर भी भिक्षु बन कर जीवन निर्वहन करना चाहिए। जैन धर्म अहिंसा और नैतिकता पर अधिक जोर देता है। जैन धर्म में पांच बातों को आवश्यक माना गया हैः–1 अहिंसा 2 असत्य त्याग 3 अस्तेय 4 ब्रह्मचर्य और 5 अपरिग्रह।

टिप्पणी

जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं– दिगंबर(निर्वस्त्र) और श्वेतांबर (श्वेत वस्त्र धारी)। इस समय जैन धर्म धर्म अनुयायियों की संख्या 45. 5 लाख है। जैन धर्मावलंबी मुख्य वाणिज्य क्रियाओं और राजनीति में सक्रिय रहते हैं और नगरों में बसते हैं। इनका सकेंद्रण महाराष्ट्र,गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है।

7. पारसी धर्म : पारसी धर्म की उत्पत्ति पुरानी मानी जाती है। इसके संस्थापक जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म का प्रचार आठवीं शताब्दी में हुआ जब कुछ धर्म प्रचारक दीव नामक द्वीप पर आए। पारसी धर्म में ईश्वर को होरमत्तज कहा जाता है। पारसियों की धार्मिक पुस्तक अवेस्ता है। प्रत्येक पारसी परिवार में दिन–रात अग्नि का प्रज्वलित रहना आवश्यक माना जाता है। भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 13 लाख है। ये मुख्यतः मुंबई और सूरत के आसपास निवास करते हैं।

3.3.1 जनसंख्या प्रवास

किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण होते हैं – जन्म दर में वृद्धि एवं बाहर से आने वाले मनुष्यों के वहां बसने से। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में जनसंख्या ह्रास के दो कारण हो सकते हैं–मृत्यु दर में वृद्धि और जनसंख्या के अन्य स्थानों के लिए स्थानांतरण।

किसी स्थानीय क्षेत्र में व्यक्तियों के आगमन अथवा वहां से मनुष्यों के बहिर्गमन को प्रवास या प्रव्रजन कहते हैं।इसे स्थानांतरण या देशांतरण भी कहा जाता है।

मनुष्य एक गतिशील प्राणी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मनुष्य इतिहास से के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रतिरूप के निर्धारण में प्रवास का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व के हर क्षेत्र में प्रवास होता रहा है और ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में जलवायु परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाले विभिन्न मानव प्रजातियां वहां से स्थानांतरित होकर विश्व विभिन्न भागों में पहुंच गई और इसके फलस्वरूप समस्त संसार में मानव बसाव हो गया। मनुष्य जिस स्थान को को छोड़ता है वहां की संस्कृति, रीति–रिवाज, तकनीकी कौशल, ज्ञान आदि को आपने साथ जाता है नूतन स्थानों पर इसका प्रसार करता है। ठीक उसी प्रकार नये स्थान की संस्कृति से प्रभावित होता है वहां की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रवास विश्व की प्रजातीय संरजना और सांस्कृतिक विकास का अत्यंत प्रबल कारक है, जो मानव इतिहास की प्रत्येक काल में सक्रिय रहा है। आधुनिक काल में राजनीतिक प्रतिबंध और नियंत्रण के कारण यह अधिक नियंत्रित व सीमित हो गया है।

एक भूगोलवेत्ता की दृष्टि में प्रवास केवल मानव संसाधन का पुनर्वितरण ही नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वयं प्रवासित मनुष्य, वह क्षेत्र जिससे मनुष्य

बहिर्गमन करता है और वह क्षेत्र जहां मनुष्य का आगमन होता है – तीनो प्रभावित होते हैं। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या परिवर्तन, संरचना, प्रतिरूप आदि के विश्लेषण में प्रवास का अध्ययन महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी

प्रवास की परिभाषा

बोग (1959) ने केवल उस निवास परिवर्तन को प्रवास माना है जिसमें किसी व्यक्ति या उसके परिवार का पूर्ण आवास परिवर्तन तथा सामाजिक पुनर्समायोजन होता है। उन्होंने स्थानीय संचरण को प्रवास के अंतर्गत शामिल नहीं किया।स्थानीय संचलन या विचरण का अभिप्राय किसी मानव समुदाय का स्थानीय क्षेत्र में आगमन से है इससे किसी अन्य क्षेत्रीय इकाई या जन समुदाय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रवास का अर्थ है एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने निवास को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना।

अतः प्रवास के लिए स्थान परिवर्तन के साथ–साथ दोनों स्थानों में न्यूनतम दूरी का होना भी अति आवश्यक है।

सयुंक्त राष्ट्र संघ के अनुसार '' प्रवास सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भौगोलिक स्थानांतरण हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपना निवास स्थान बदलता है''

प्रवास के रूप

एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए जनसंख्या स्थानांतरण के दो रूप होते हैं:

1. उत्प्रवास या प्रव्रजन (Emigration)
2. अप्रवास या आव्रजन (Immigration)

1. **उत्प्रवास (Emigration)** : जिस स्थान को मनुष्य छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं उस स्थानांतरण को उत्प्रवास या बाह्यप्रवास और स्थानांतरित होने वाले मनुष्य को उत्प्रवासी कहा जाता है।
2. **अप्रवास (Immigration)** : अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उनके संदर्भ में स्थानांतरण को अप्रवास या आव्रजन और इसमें शामिल होने वालों को अप्रवासी कहा जाता है।

प्रवास के कारण

प्रवास के अंतर्गत दो शक्तियां जिन्हे आकर्षण शक्ति व प्रतिकर्षण शक्ति कहते हैं। किसी स्थान या प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक और भौगोलिक दशाएं अन्य प्रदेशों से मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि,खनिज एवं शक्ति संसाधन, उपयुक्त भूविन्यास, प्रचूर जल संसाधन, जलवायु इत्यादि आकर्षण शक्ति का कार्य करते हैं।

आर्थिक संकट, महामारी, सूखा, बाढ़, निर्धनता, बेरोजगारी, उपजाऊ कृषि भूमि की कमी, पानी की अनुपलब्धता, संसाधनों की कमी, धार्मिक उन्माद आदि प्रतिकर्षण शक्ति मनुष्य को बहिर्गमन करने को मजबूर करते हैं।

टिप्पणी

जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले वाले कारक निम्नलिखित हैं :–

1. प्राकृतिक कारक
2. आर्थिक कारक
3. सामाजिक– सांस्कृतिक कारक
4. राजनीतिक कारक

1. प्राकृतिक कारक : प्राकृतिक करकों में जलवायु, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी व भूकंप आदि प्रमुख हैं। आदिकालीन प्रवास के लिए मुख्यतः जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर सहित अनेक विद्वानों का मत है कि सभी प्रमुख मानव प्रजातियों के विकास का मूल स्थान मध्य एशिया था जहाँ गर्म जलवायु में विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ जो हिमयुग के आगमन पर जलवायु के अति ठंडी हो जाने पर बाहरी प्रदेशों के लिए स्थानांतरित होती रही। हिम युग और अंतरहिमयुग के क्रमिक आगमन के कारण मध्य एशिया से बड़े पैमाने पर मानव प्रजातियों का बाहरी प्रदेशों में स्थानांतरण होता रहा।

अंतिम हिम युग के उपरांत जब मध्य एशिया में शुष्कता अधिक बढ़ गई और वहां अधिक जनसंख्या का रहना मुश्किल हो गया था तब वहां के निवासी बड़ी संख्या में बाहर की ओर प्रस्थान कर गए।उनकी एक शाखा तुर्किस्तान व अफगानिस्तान के दर्रो से होकर पश्चिमोत्तर भारत में पहुंच गई, जिसे आर्य के रूप में जाना जाता है। मध्यकाल में शुष्कता में वृद्धि के कारण मध्य एशिया की आक्रमणकारियों के रूप में जनसंख्या का स्थानांतरण पश्चिम से पश्चिम एशिया व यूरोप और पूर्व में चीन और दक्षिण में भारत के लिए हुआ।

आल्पस और हिमालय पर्वतों में मौसमी प्रवास के कारण कारण बर्फ पिघलने पर मनुष्य पर्वतों पर उच्च स्थानों की ओर व शीतकाल के आगमन पर वे पुन : घाटियों पर प्रस्थान करते हैं।

इसी प्रकार से अधिक वर्षा के कारण नदियों से उत्पन्न बाढ़ो से जब भूमि और आवास जलमग्न हो जाते हैं लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए विवश होते हैं। उसी प्रकार से वर्षा के अभाव में सूखा पड़ने के कारण लोग अपने निवास स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण लेते हैं।

2. आर्थिक कारक : जनसंख्या स्थानांतरण के कारकों में आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी दशाएं जैसे कृषि योग्य भूमि उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु व सिंचाई के साधन मनुष्य के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी पश्चिमी यूरोप चीन के पूर्वी भाग आदि प्रदेशों में जनसंख्या की अधिकता के लिए आर्थिक कारक महत्वपूर्ण है।

अधिक जनसंख्या वृद्धि होने पर खाद्यान्न और जीवन उपयोगी संसाधनों की कमी होने लगती है जिससे मनुष्य अधिक बेहतर जीवन स्तर के लिए दूसरे संसाधन पूर्ण प्रदेशों की खोज में दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होता है। 18 वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि और गिरते जीवन स्तर के कारण बड़ी संख्या में यूरोप वासी आर्थिक

टिप्पणी

संसाधनों की प्राप्ति के लिए उतरी व दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के लिए प्रस्थान कर गए।

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों से युवा रोजगार की तलाश में बड़े बड़े नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं।

एशिया व दक्षिण अफ्रीकी देशों से हजारों की संख्या में युवा बेहतर जीवन की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में प्रस्थान कर गए हैं।

3. सामाजिक–सांस्कृतिक कारक : सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज, सामाजिक स्तर और धार्मिक संकट आदि कारक प्रवास को प्रभावित करते हैं। कुछ सामाजिक प्रथाओं के परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार के चयनित प्रवास की जाते हैं। ऐसी ही एक प्रथा के अनुसार भारत में विवाह के कारण स्त्रियों के प्रवास की मात्रा अति उच्च है। विकासशील और पिछड़े हुए समाज में सामान्यतः निम्न सामाजिक स्तर के लोगों में गतिशीलता अधिक होती है और प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।उदाहरण स्वरूप भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और बहुत सी पिछड़ी जातियों के पास भूमि व अन्य स्थाई संपत्ति की कमी के कारण भी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रवास करते हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में सर्वाधिक प्रवास की प्रवृत्ति सुशिक्षित, कुशल और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में पाई जाती है। सुशिक्षित और कुशल लोग बेहतर रोजगार और आजीविका के लिए बहुत दूर तक प्रवास कर सकते हैं।

शिक्षा भी प्रवास को प्रोत्साहित करती है और विद्यार्जन के लिए विद्यार्थियों का गांव से नगरों की ओर प्रवास और शिक्षित और प्रशिक्षित युवकों का उच्चतर रोजगार के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रवास इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। रूढ़िवादी और प्राचीन परंपराओं में बंधे हुए समाज में प्रवास कम पाया जाता है।

धार्मिक संकट व धार्मिक स्वतंत्रता प्रवास को प्रोत्साहित करती है। धार्मिक संकटों के कारण लाखों यहूदियों को जर्मनी और ह्यूगनात समुदाय के हजारों लोगों को फ्रांस छोड़ना पड़ा। 1947 में भारत के विभाजन से धर्म के आधार पर करोड़ों लोगों का भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरण हुआ। धर्म के आधार पर ही विभिन्न ऐतिहासिक कालों में धर्म व संस्कृति के प्रचार हेतु विभिन्न व्यक्तियों के समूह देश विदेश में यात्राएं करते रहे। विभिन्न देशों के मुस्लमान हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं। इसी प्रकार से भारत के हिंदू तीर्थयात्री बड़ी संख्या में अमरनाथ, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, वैष्णो देवी और बद्रीनाथ आदि स्थानों पर अस्थाई प्रवास करते हैं।

4. राजनीतिक कारक : राजनीतिक कारकों में युद्ध, राज्य विस्तार की प्रबल इच्छा, उपनिवेश स्थापना, राज्य नीति आदि प्रमुख कारक हैं। जब किसी देश में अधिक जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी होने लगती है तो उस देश के लोग अपने राज्य की सीमा को दूसरे राज्य में विस्तृत करने के लिए पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के लिए सेनाएं समीपवर्ती राज्यों में प्रस्थान करती हैं। महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बाबर, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और उनके हजारों सैनिक भारत

टिप्पणी

में ही बस गए। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, जर्मनों, स्पेनियों, डेचों आदि ने एशिया और अफ्रीकी देशों में उपनिवेशों की स्थापना की। राजनीतिक कारणों से जबरन स्थानांतरण होते हैं। 18 वीं शताब्दी में प्रचलित प्रथा के कारण अमेरिका में अफ्रीका से हजारों नीग्रो लोगों को जबरदस्ती दास के रूप में काम करने के लिए लाया गया। 1947 के भारत विभाजन में करोड़ों लोगों को जबरदस्ती स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रवास में अवरोध

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मनुष्य के रास्ते में बहुत सारे अवरोध आते हैं जिन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है – प्राकृतिक अवरोध और मानव निर्मित (कृत्रिम) अवरोध।

प्राकृतिक अवरोध

ऊंची पर्वत श्रेणियां, विस्तृत महासागर, मरुस्थल, घने व दुर्गम जंगल, हिमाच्छादित पर्वत, दलदल मनुष्य के स्थानांतरण के लिए प्राकृतिक अवरोध हैं।

उच्च पर्वतीय भाग प्रवास में अवरोधक होते थे। हिमालय पर्वत के कारण भारत में आक्रमणकारी घुस नहीं पाए। केवल कुछ दर्रो जैसे खैबर,बोलन आदि से ही भारत में आक्रमण करने के लिए आते थे। प्राचीन काल में विस्तृत महासागर प्रवास के लिए अवरोधक थे। बड़े–बड़े मरुस्थलों को जल के अभाव में पार करना बहुत मुश्किल कार्य होता था। इसलिए मरुस्थल प्रभास के लिए अवरोध होते थे। सघन वनों को पार करना भी मुश्किल कार्य होता था।इसी कारण अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन प्रवासियों से अछूते रहे। संसार के दिन भागों में दलदल पाया जाता है वहां पर भी प्रवास नहीं होता है। हिम आच्छादित भाग भी प्रवास को प्रोत्साहित नहीं करते। उतरी कनाडा,ग्रीनलैंड, अंटार्टिका आदि भूखंड पर मनुष्य ने प्रवास नहीं किया।

कृत्रिम अवरोध

प्राचीन काल में आक्रमणकारियों को दूर रखने के लिए और अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए दीवार बनाने का प्रचलन था।चीन की दीवार इसका उदाहरण है। जर्मनी सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान देश की सीमा पर लोहे की दीवार बनवाई थी और इसी प्रकार बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने लोहे की तारों की बाड़ लगाई है। समाज में प्रचलित रूप यहां सामाजिक प्रथाएं मान्यता है आदि भी उत्प्रवास के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं। वर्तमान समय में राजनीति और सरकारी नियंत्रण प्रवास का सबसे बड़ा अवरोधक है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,न्यूजीलैंड कुछ ऐसे देश हैं जो सीमित अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं।

प्रवास के प्रकार

प्रवास का काल, अवधि, प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रवास की क्षेत्रीय प्रकृति आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है।

टिप्पणी

(अ) कालानुसार प्रवास

ऐतिहासिक काल के अनुसार जनसंख्या प्रवास को मुख्यत : चार वर्गों में रखते हैं :–

1. **प्रागैतिहासिक प्रवास** : जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में प्रवास हुए। अंतर हिम युग के क्रमिक आगमन से जलवायु क्रमशः शीतल और गर्म हो जाती थी। प्रारंभिक मानव जातियों का उद्‌भव मध्य एशिया में माना जाता है। सामान्य जलवायु में जनसंख्या में वृद्धि होती थी और हिम युग के आने से अत्यधिक ठंड के कारण लोग बाहर की ओर पलायन करने लगते थे। हिम युग के उपरांत गर्म जलवायु होने पर बचे हुए मानव की जनसंख्या दोबारा बढ़ जाया करती थी। उसके बाद पुनः हिम युग आने पर मानव एशिया से बाहर की ओर प्रस्थान करता था। जनजातियों का उद्‌भव पहले हुआ वे प्राय : परवर्ती जनजातियों से कमजोर होती थी और अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते थे। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले नीग्रिटो और नीग्रो प्रजातियां कम विकसित हैं और सुदूर जंगलों व में दुर्गम स्थानों पर आश्रय लिए हुए हैं। इनके बाद उत्पन्न होने वाले जनजातियां मध्य एशिया के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है।
2. **ऐतिहासिक प्रवास** : ऐतिहासिक प्रवास को 3 वर्गों में रखा जाता है– 1 प्राचीन कालीन प्रवास 2 मध्यकालीन प्रवास 3 आधुनिक प्रवास।

   रोमन, यूनानी अपना साम्राज्य फैलाने के लिए और भारत का धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका, जावा, मलाया, बर्मा आदि में प्रवास प्राचीन प्रवास का का उदाहरण है। भारत पर मोहम्मद गोरी, तैमूर,बाबर, चंगेज आदि का आक्रमण मध्यकालीन प्रवास के उदाहरण है । आधुनिक काल में यूरोपीय देशों ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए विभिन्न देशों में प्रवास किया। यूरोप के देशों के लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों में प्रवास किया।

(ब) अवधि के आधार पर प्रवास

अवधी के आधार पर प्रवास को चार भागों में बांटा जाता है :–

1. **दीर्घकालीन प्रवास** : इस प्रकार के प्रवास कभी–कभी होते हैं। ये बड़े या लघु पैमाने पर भी हो सकते हैं।17 वीं और 19 वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका,दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की ओर होने वाले प्रवासों को इस प्रकार के प्रवास के अंतर्गत रखा जाता है।
2. **अल्पकालीन प्रवास** : इस श्रेणी में प्रवास आते हैं जिनकी अवधि छोटी होती है। इस प्रकार के प्रवास में तीर्थ यात्रा, सद्‌भावना यात्रा, राजनैतिक यात्रा, व्यापार सम्बंधित यात्रा आदि को रखा जाता है। इस प्रकार के प्रवास में प्रवासी अपने मूल स्थान पर कुछ दिनों या महीनों में ही लौट आता है।
3. **दैनिक प्रवास** : बड़े–बड़े नगरों, औद्योगिक केंद्रों की ओर बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग दैनिक

प्रवास करते हैं। लोग कारखानों, कार्यालयों, स्कूलों , महाविद्यालयों, अस्पतालों या अन्य उद्देश्यों के लिए रोजाना प्रवास करते हैं।

इस प्रकार के प्रवास में लोग सांय कालीन समय अपने घर को लौट जाते हैं।

टिप्पणी

4. **मौसमी प्रवास** : किसी विशेष ऋतु या निश्चित समय में होने वाले प्रवास को मौसमी प्रवास कहते हैं। भारत में बकरवाल गुज्जर, भोटिया जनजाति हिमालय पर्वत में मौसमी प्रवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन ऋतु में बर्फ पिघलने पर यह लोग हिमालय पर्वत के उच्च भागों में अपने पशुओं को लेकर प्रवास करते हैं। शरद ऋतु में बर्फ गिरने पर ये लोग अपने पशुओं के साथ घाटियों में उतर आते हैं। इस प्रकार यह ऋतु बदलने के साथ प्रवास करते हैं।

(स) आकार के अनुसार प्रवास

प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आकार के अनुसार प्रवास के दो वर्गों में बांटा जाता है – बृहद प्रवास या बृहद जनसंख्या प्रवास और लघु प्रवास या अल्पसंख्यक प्रवास।

बृहद प्रवास में स्थानांतरण करने वालों की संख्या अधिक होती है। 1947 का भारत भारत–पाक विभाजन के दौरान लाखों लोगों का प्रवास हुआ।

लघु प्रवास में व्यक्तियों की संख्या कम होती है। विभिन्न प्रकार की खिलाड़ी टीम, प्रतिनिधिमंडल आदि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करती हैं ।

(द) क्षेत्र के अनुसार प्रवास

क्षेत्र के आधार पर प्रवास को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है :–

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास।

एक देश से दूसरे देश में होने वाले मानव स्थानांतरण को अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास स्थाई, अस्थाई, अल्पसंख्यक, बृहद संख्यक, ऐच्छिक या जबरन किसी प्रकार का हो सकता है। बृहद व स्थाई प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका प्रभाव उत्प्रवासी व अप्रवासी देशों तथा स्वयं प्रवासी पर पड़ता है। इस प्रकार के प्रवास के कारण नवीन संस्कृति का जन्म होता है। आंतरिक प्रवास अपने देश के अंदर होता है।

3.3.2 जन्मदर एवं मृत्युदर का मापन

जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में गिरावट।

जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन, और किसी प्रजाति विशेष के व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन का मापन हेतु उन जनसंख्या को ''प्रति इकाई समय'' कहते हैं। जीवविज्ञान में, जनसंख्या वृद्धि शब्द का प्रयोग किसी जीव के लिये किया जाता है, किंतु इस लेखन में अधिकांशत: इसका संबध सांख्यिकी में मानव जाति की जनसंख्या से है।

सांख्यिकी में, जनसंख्या वृद्धि का प्रयोग जानकारी हेतु और अधिक विशिष्ट शब्द जनसंख्या वृद्धि दर के लिए किया जाता है। यह अक्सर विशेष रूप से मानव की विश्व जनसंख्या के लिये प्रयोग किया जाता है।

टिप्पणी

जनसंख्या वृद्धि के सरल मॉडलों में सम्मिलित हैं मैल्थूसियन वृद्धि मॉडल और तार्किक मॉडल। सांख्यिकी और ईकोलोजी में, जनसंख्या वृद्धि दर (पीजीआर) बढती जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या की विभाजन दर होती है। विशेष रूप से, पीजीआर को मूल रूप से समय की अवधि की इकाई में जनसंख्या के परिवर्तन के लिये प्रयोग किया जाता है। उस अवधि के आरंभ में अक्सर जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या के प्रतिशत को वर्णित किया जाता है। इसे एक फार्मूले में लिखा जा सकता है:

$$\text{Growth rate} = \frac{(\text{population at end of period} - \text{population at beginning of period})}{\text{population at beginning of period}}$$

(पर्याप्त रूप से छोटे समय की अवधि की सीमा में)

उपरोक्त फार्मूले को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

वृद्धि दर= अपक्व जन्म दर - अपक्व मृत्यु दर, + प्रवासन दर, या $\Delta P/P = (B/P) - (D/P) + (I/P) - (E/P)$। इसमें P का अर्थ है कुल जनसंख्या, B का अर्थ है जन्म की संख्या, D का अर्थ है मृत्यु की संख्या, I का अर्थ है अप्रवासन, और E का अर्थ है अप्रवासियों की संख्या।

फार्मूला जनसंख्या वृद्धि के स्रोत ज्ञात करने की अनुमति देता है, चाहें वह प्राकृतिक वृद्धि हो या नेट प्रवासन दर की वृद्धि। प्राकृतिक दर से तात्पर्य है देश में उत्पन्न जनसंख्या, चाहें यह उच्च जन्म दर हो, कम मृत्यु दर हो, या दोनों का संयोजन। नेट प्रवासन दर अप्रवासियों की संख्या और प्रवासियों की जनसंख्या का अंतर।

अधिकांशत: जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने का सामान्य तरीका है अनुपात, न कि दर। एक निश्चित समय की अवधि इकाई में जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने का तरीका है समय की उस अवधि के आरंभ में जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिशत को व्यक्त करना।

यह है:

$$\text{Growth ratio} = \text{Growth Rate} \times 100\%$$

सकारात्मक वृद्धि अनुपात (या दर) दर्शाती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि नकारात्मक वृद्धि दर दर्शाती है कि जनसंख्या घट रही है। वृद्धि दर शून्य दर्शाता है कि दोनों समय लोगों की संख्या समान थी -- जन्म और मृत्यु का नेट अंतर, मृत्यु और प्रवासन शून्य है। हालांकि, वृद्धि दर तब भी शून्य हो सकती है जब वहां जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन दर, और आयु वितरण में दोनों समय में विशेष परिवर्तित रहा हो। समान रूप से, जन्म दर = कुल जनसंख्या में से प्रति वर्ष प्रति 100 लोगों की मृत्यु का औसत।

संबंधित मापन है नेट प्रजनन दर। प्रवासन की अनुपस्थिति में, एक से अधिक नेट प्रजनन दर दर्शाती है कि महिलाओं की आबादी बढ़ रही है, जबकि एक से कम (उप-स्थापन प्रजनन) नेट प्रजनन दर दर्शाती है कि महिलाओं की आबादी घट रही है।

टिप्पणी

किसी क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ने की क्षमता अधिक होना या ऐसा वातावरण हो तो इसे अत्यधिक जनसंख्या कहा जाता है। इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है या प्रजनन क्षमता में। मानव जनसंख्या में स्पाइक से समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि प्रदूषण और यातायात की सघनता, इनका समाधान या/और इसे विकृत किया जा सकता है तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन द्वारा। इसके विपरीत, ऐसे क्षेत्रों को ''कम जनसंख्या'' में माना जा सकता है यदि किसी आर्थिक प्रणाली (जनसंख्या पतन को देखें) को लागू करने के लिये पर्याप्त बड़ी नहीं है। इन दोनों अति के बीच आदर्श जनसंख्या गठित होती है।

विश्व में, मानव जनंसख्या की वृद्धि दर में गिरावट हो रही है जबकि यह 1962 और 1963 में 2.20 प्रतिशत पति वर्ष के साथ चरम पर थी। 2009 में, अनुमानित जनसंख्या वृद्धि 1.1 प्रतिशत थी। सीआईए विश्व फैक्टबुक में दी गई विश्व की जन्म दर, मृत्यु दर, और वृद्धि दर (थोड़ी भिन्नता के साथ) क्रमशः 1.986 प्रतिशत, 0.837 प्रतिशत और 1.13 प्रतिशत है। पिछले सौ सालों से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और कृषि उत्पादन में भारी बढोत्तरी के कारण जिसने हरित क्रांति को संभव बनाया है, इससे जनंसख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।

मनुष्यों की संख्या की वास्तविक वार्षिक वृद्धि में गिरावट आई है। जो 1989 में 88.0 मिलियन के साथ अपने चरम पर थी, 2003 में घटकर 79.3 मिलियन हो गई, इसके बाद 2006 में यह बढ़कर पुनः 75.2 मिलियन हो गई। इसके बाद, वार्षिक वृद्धि में गिरावट आई है। 2009 में मानव जनसंख्या बढ़कर 74.6 मिलियन हो गई, और 2050 तक सीधे गिर कर 41 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है, इस समय जनसंख्या बढ़कर लगभग 9.2 बिलियन हो जायेगी। हाल ही के दशकों में विश्व के हर क्षेत्र में वृद्धि दर में भारी गिरावट देखी गई है, यद्यपि मध्यपूर्व और उप-सहारा अफ्रीका, कुछ देशों में यह वृद्धि दर अभी 2 प्रतिशत है, और दक्षिणी एशिया, दक्षिणीपूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका में भी।

कुछ देशों को नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव हुआ है, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में (मुख्य रूप से निम्न प्रजनन दर और प्रवासन के कारण)। दक्षिणी अफ्रीका में, एचआईवी से संबंधित मृत्यु के कारण वृद्धि बहुत ही धीमी है। कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। 2005 से जापान की जनसंख्या का भी घटना आरंभ हो चुका है।

जनसंख्या में गिरावट का अभिप्राय किसी जीव की जनसंख्या में गिरावट से हो सकता है, किंतु इस लेख इसका संबंध मानव जनसंख्या में गिरावट से है। इस शब्द का प्रयोग आम तौर पर मानव जनसंख्या में भारी गिरावट के लिये किया जाता है। इसे दीर्घकालिक सांख्यिकी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। शहरी पतन या ग्रामीण उत्थान के रूप में, किंतु आम तौर पर इसका प्रयोग हिंसा, रोग या अन्य मौसमीय विकृतियों के कारण जनसंख्या में भारी गिरावट के लिये किया जाता है।

कभी कभी इसे जनसंख्या घटाव के रूप में भी जाना जाता है, जनसंख्या में गिरावट किसी क्षेत्र की जनगणना में जनसंख्या की गिरावट को जनसंख्या पतन कहते हैं। इसके

टिप्पणी

कई कारण हो सकते हैं: इनमें से प्रमुख हैं उप स्थापन गर्भाधान (सीमित प्रवासन के साथ), भारी अप्रवासन, भारी उत्प्रवास, रोग, महामारी, और युद्ध। इतिहास बडे पैमान पर जनसंख्या के पतन के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए अनेक युद्ध विशिष्ट जनसंख्या की कमी के कारण हुए हैं। 20वी सदी से पहले, जनसंख्या में गिरावट अधिकांशत: रोग, भुखमरी और/या प्रवासन के कारण देखी जाती थी। यूरोप में ब्लैक डैथ, अमेरिका में औल्ड वर्ल्ड का आगमन, वाटरवर्ग मेस्फि, दक्षिणी अफ्रीका में सिट्सी मक्खी का घुस जाना और आयरलैंड की विशाल महामारी ये सभी जनसंख्या में गिरावट के प्रमुख कारण रहे। आज के जमाने में, एड्स की महामारी भी कुछ अफ्रीकी देशों में जनसंख्या में गिरावट का कारण बन गई है। कम बारंबारता के साथ, जनसंख्या पतनों का करण जातिसंहार या नरसंहार हैं, उदाहरण के लिये, 1970 में कंबोडिया में खैमर अतिवादियों द्वारा बड़े पैमान पर नरसंहार करने के कारण जनसंख्या में उस समय गिरावट आ गई।

महामारी भी बार बार जनसंख्या घटाने में अपनी भूमिका निभाती रही है, चाहे वह युद्ध के परिणाम के रूप में हो, जलवायु स्थितियों के कारण या मनुष्य की नासमझी से हो और इस तरह की कोई भी हो।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डिवीजन की 2002 की रिपोर्ट और यूएस जनगणना ब्यूरों के अनुसार, अब कुछ प्रान्तों में जनसंख्या में गिरावट आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आशा है कि विकसित दुनिया में 2050 तक निम्न स्थापन गर्भाधान 75 प्रतिशत हो जायेगा। यूएस जनगणना ब्यूरो ने नोट किया है कि विश्व की 2002 की जनसंख्या में विश्व में 74 मिलियन लोग जुड़े जो 1989-1990 में जुड़े 87 मिलियन लोगों की संख्या से बहुत कम है। वार्षिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत है, जो 1963-1964 में 2.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है।

कभी कभी कम जनसंख्या शब्द का प्रयोग एक विशेष आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में किया जाता है। इसका संबंध अत्यधिक जनसंख्या के विपरीत क्षमता हेतु नहीं किया जाता है, जिसका संबंध कुल संभावित जनसंख्या से है जिसका पोषण खाद्य, जल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आधारभूतों ढांचे के द्वारा किया जा सकता है। ''कम जनसंख्या''को आम तौर पर ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें देश की वर्तमान आर्थिक प्रणाली के सहयोग के लिये जनसंख्या में भारी गिरावट होती है। इस प्रकार क्षमता लाने के जीवविज्ञानी पहलू से इसका कोई लेना देना नहीं है, किंतु यह एक आर्थिक शब्द है जिससे यह लागू होता है कि कुछ विकसित देशों की स्थानांतरण भुगतान प्रणाली असफल हो सकती है जब वहां पर जनसंख्या में गिरावट एक निश्चित बिंदु तक हो जाती है। एक उदाहरण है कि यदि रिटायर लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत सहयोग दिया गया जिससे बचत में निवेश नहीं होता, और फिर बडे पैमाने पर प्रवासन होता है। ऐसे मामले में, युवा पीढ़ी वृद्ध पीढ़ी का सहयोग नहीं कर सकती।

जनसंख्या परिवर्तन के घटक

- **लिंग संयोजन** : छोटे परिवारों में लड़के को पाने की इच्छा रहती है जिससे आगे चलकर लड़कियों की तुलना में लिंग का औसत बिगड़ जाता है। लिंग औसत में

टिप्पणी

तेजी से गिरावट आई है: 1901 में 972 (प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले) से 1991 में यह संख्या 927 रह गई। हाल ही की जनगणना में कुल मिलाकर थोड़ा सुधार हुआ है जो अब 933 है। दुर्भाग्य से, छह साल की आयु तक के बच्चों में यह अनुपात और भी बिगड़ा हुआ है।

- छह साल की आयु तक के बच्चों में यह अनुपात 1981 में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 962 था, 1991 में 945, 2001 तक यह 927 हो गया। वाल जनसंख्या में इस लिंग भेद अनुपात में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तरांचल, महाराष्ट्र और चडीगढ़ में भारी पतन हुआ है, जहां महिलाओं में गर्भपात का चलन बडे पैमाने में सामने आया है।
- **जनसंख्या घनत्व :** भारत में प्रति किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या का घनत्व 2001 में 325 प्रति वर्ग किलोमीटर था। पश्चिमी बंगाल अभी भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां पर 2001 में यह 903 प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार 880 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर और केरल तीसरे स्थान पर है।
- **आयु संयोजन :** भारतीय जनसंसख्या का वर्तमान आयु वितरण इस प्रकार है। 15 वर्ष की आयु वाले 31.7 से थोडा ज्यादा (पुरुष 173,869,856: महिलाएं 164,003,915), 15 से 64 आयु में यह 63.5 प्रतिशत है (पुरुष 349,785,804 : महिलाएं 326,289,402), और 15 से 64 साल की आयु के बीच यह 4.8 प्रतिशत है (पुरुष 25,885,725, महिलाएं 25,235,905)। भारतीय योजना आयोग के जनसंख्या परियोजनाओं पर बने तकनीक समूह ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) में भविष्यवाणी की है कि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 1.012 बिलियन होगी, मार्च 2001 और 2016 में यह बढ़कर क्रमश: 1.179 और 1.264 हो जायेगी।
- **मृत्यु दर :** 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 में बहत्तर बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। इकहत्तर प्रतिशत (72/1000) नवाजात शिशु जन्म के एक साल के भीतर मर जाते हैं, कम वजन, अपरिपक्व प्रसव, कुपोषण, डायरिया रोग, गले के संक्रमण और कुपोषण के कारण। श्रीलंका की आईएमआर (18/1,000) और चीन (41/1,000) की तुलना में। इसके अतिरिक्त, भारत में, कहीं की भी तुलना में अधिकांश महिलाओं की मृत्यु 0 - 14 साल की आयु में ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाती है। यद्यपि आइएमआर ने इसे कम किया है जो 1951 में प्रति 1000, 146 थी और 1997 में यह प्रति 1000 के मुकाबले 72 है और लिंग भेद का अंतर भी कम हो रहा है, जो देश भर में बहुत अंतर था।

प्रजनन क्षमता

प्रजनन क्षमता जीवन प्रदान करने की प्राकृतिक क्षमता है। मापन के लिये, (प्रजनन क्षमता दर) प्रति दंपत्ति, व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की संख्या होती है। प्रजनन क्षमता गर्भाधान से भिन्न होती है, जिसे प्रजनन (युग्मक उत्पादन द्वारा प्रभावित,

टिप्पणी

उर्वरण और गर्भ धारण के लिये प्रयुक्त के लिये संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है।) बांझपन प्रजनन क्षमता से भिन्न होता है।

मानव प्रजनन क्षमता पोषण, सैक्स व्यवहार, संस्कृति, प्रतिभा, प्रजनन प्रणाली, समय, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली, और भावनाओं के कारकों पर निर्भर होती है।

सांख्यिकीय संदर्भ में, प्रजनन क्षमता का संबंध संतान की वास्तविक उत्पत्ति से है, उत्पादन की शारीरिक क्षमता से अलग जिसे प्रजनन का नाम दिया जाता है। जबकि प्रजनन क्षमता को मापा जा सकता है, क्षमता को नहीं मापा जा सकता। सांखिकीकार प्रजनन दर को विवधता से मापते हैं, जिसे मापने हेतु समय की अवधि को बडे पैमाने पर बांटा जाता है। अवधि के मापकों को एक साल में जनसंख्या के विभाजन हेतु संदर्भित किया जाता है। दूसरी दस्ता डाटा, को एक दशक से लोगों पर लागू किया गया है। अवधि और दस्ता को बडे पैमाने पर प्रयोग किया जाता है।

प्रजनन क्षमता के सामाजिक गुणक

प्रजनन क्षमता की प्रक्रिया की ''तीन चरणों की समीक्षा'' किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक ने 1956 में प्रस्तुत की और इसमें तीन निकटस्थ गुणकों का प्रयोग किया जाता है।

प्रजनन क्षमता के घटकों वाला बोंगार्ट का मॉडल

बोंगार्ट ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें चार गुणकों और पूर्ण गर्भाधान से जनंसख्या की कुल प्रजनन क्षमता (TF) की गणना की जा सकती थी। विवाह (Cm) की सूची, गर्भनिरोध (Cc), कराए गए गर्भपात (Ca) की सूची और बाद के बांझपन (Ci) की सूची। इसकी श्रेणी 0 से 1 होती है। सूची जितनी लंबी होती है, TFR उतना ही अधिक होता है, उदाहरण के लिये, ऐसी आबादी जहां गर्भपात देखने को नहीं मिलते Ca 1 होता है, किंतु ऐसा देश जहां अपरिहार्य गर्भपात का प्रयोग किया जाता है वहां CC 0 होता है।

$$TFR = TF \times Cm \times Ci \times Ca \times Cc$$

इन चारों सूचियों का प्रयोग कुल वैवाहिक प्रजनन क्षमता (TMFR) और कुल प्राकृतिक प्रजनन क्षमता (TN) की गणना में किया जाता है।

$$TFR = TMFR \times Cm$$

$$TMFR = TN \times Cc \times Ca$$

$$TN = TF \times Ci$$

संभोग

पहला चरण है यौन संभोग, और पहले संभोग की आनुपातिक आयु, विवाह के अतिरिक्त, और वैवाहिक सीमा में यौन संभोग की बारंबारता का अनुपात।

गर्भाधान

विशेष शारीरिक स्थितियां किसी महिला को गर्भवती बनाना असंभव बना सकती हैं। इसे ''वेवश गर्भधारण'' कहते हैं। यदि किसी महिला की स्थिति इसे संभव बनाने के अनुकूल है, किंतु गर्भधारण की इच्छा नहीं है, इसे ''उप-गर्भधारण'' का नाम दिया जाता है। यौन

टिप्पणी

रोग (विशेष रूप से गोनारिया, सिफलिस और क्लोमीडिया) के लिए पोषण भी एक कारक है। जिन महिलाओं के शरीर में वसा की मात्रा 20 प्रतिशत से कम होती है उप-गर्भाधान हो सकता है, खिलाड़ियों में यह एक कारण होता है और लोग एनोरेक्सिया के संदेह में रहते हैं। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ रूथ फ्रिक ने इस पर बहस की कि ''एक शरीर में निर्माण में 50,000 कैलोरी लगती है''। उप-प्रजनन क्षमता में बच्चे को जन्म देने के कई सप्ताह भी लगते हैं, और यह अवधि एक साल या इससे अधिक भी हो सकती है स्तनपान के माध्यम से। विकासशील देशों में शिशु फार्मूले की मार्केटिंग हेतु शिशुओं के भोजन की नैतिकता पर 1980 में एक गर्मागर्म राजनैतिक बहस हुई। एक बड़े उद्योग ने महिलाओं और पुरुषों में उप-गर्भाधान को डील करने का विकास कर लिया है। एक समकक्ष बड़े उद्योग भी गर्भनिरोधक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रकट हो गया है जिसे गर्भनिरोध हेतु डिजाइन किया गया है। उनके प्रयोग के प्रभावों में विवधता है। आम तौर पर, 85 प्रतिशत विवाहित दंपत्ति जो गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एक साल में गर्भधारण कर लेते हैं। दर में 20 प्रतिशत की गिरावट आ जाती है जब पलटाव, योनि में स्पंज, या स्खलन का प्रयोग किया जाता है। (इससे कल्पना की जाती है दंपत्ति कभी गर्भनिरोधक का उपयोग करना नहीं भूलते।) इस दर में 2 या 3 प्रतिशत की गिरावट आती है जब गोलियां या आईयूडी को प्रयोग किया जाता है, और लगभग 0 प्रतिशत गिरावट स्थापन में आती है और 0 प्रतिशत नलिका में रुकावट (बन्धयीकरण) से महिला में आ जाती है, या पुरुषों में नसबंदी से।

गर्भावस्था

भ्रूण के स्थापित होने के बाद, बच्चा ठहर सकता है या नहीं भी ठहर सकता। ''अनिच्छा से भ्रूण की मृत्यु दर'' में प्राकृतिक गर्भपात सम्मिलित है और जन्म के समय (मृत भ्रूण का पैदा होना)। मनुष्य के द्वारा भ्रूण गर्भपात करके इरादे से बाधा पहुंचाने को ''चिकित्सीय गर्भपात'' कहा जाता है।

महिलाओं में प्रजनन क्षमता

संयुक्त राज्य में रजोधर्म की औसतन आयु 12.5 साल है। रजोधर्म के बाद बालिकाओं में, लगभग 80 प्रतिशत का मासिक धर्म रजोधर्म के बाद पहले साल एनोअल्टरी थे, 50 प्रतिशत में तीसरे साल और 10 प्रतिशत में यह छठवे साल में थे। 22 से 26 साल की आयु में महिलाओं में प्रजनन क्षमता चरम पर होती है, और अक्सर 30 साल की आयु के बाद गिरावट आ जाती है: एक 30 साल की महिला में 12 प्रतिशत तक गर्भाशय रिजर्व होता है वह जन्म दे देती है, और 40 साल की आयु में यह केवल 3 प्रतिशत रह जाता है। महिलाओं में गर्भाधान को टालने की बढ़ती प्रवृत्ति से बांझपन की समस्या हो सकती है। महिलाओं में गर्भवती होने के प्रयास, दवाई के बिना प्रजनन क्षमता या विट्रो प्रजनन क्षमता निम्नांकित है:

- 30 साल की आयु में, 75 प्रतिशत एक साल में गर्भवती हो जाती हैं, और 91 प्रतिशत चार सालों में।
- 35 साल की आयु में, 66 प्रतिशत एक साल में गर्भवती हो जाती हैं, और 84 प्रतिशत चार सालों में।

टिप्पणी

- 40 साल की आयु में, 44 प्रतिशत एक साल में गर्भवती हो जाती हैं, और 64 प्रतिशत चार सालों में।

उपरोक्त आंकड़े उन गर्भधानों के लिये हैं जिनका बच्चे पैदा होते ही अंत हो जाता है जनता में बढ़ रही गर्भपात की दर को ध्यान में रखते हुये। मार्च आफ डायम के अनुसार, ''लगभग 9 प्रतिशत जाने पहचाने गर्भपात में महिलाओं की आयु 20 से 24 होती है जो गर्भपात में मर जाती है। यह जोखिम 35 से 39 साल की आयु में 20 प्रतिशत बढ जाता है, और 42 साल की आयु में 50 प्रतिशत।

जन्म विकृति, विशेष रूप में उनमें होती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या और व्यवस्था हो, यह माँ की आयु के हिसाब से बढ़ जाती है। मार्क आफ डायम के अनुसार, 25 की आयु में, एक महिला में इसकी संभावना लगभग 1 में से 1 है, डाउन सिंड्रोम में एक बच्चे के लिये इसके 250 अवसर होते हैं, 30 साल की आयु, यह 1,000 में से 1 है, 35 की आयु में, ये अवसर 400 में से 1 है, 40 की आयु में, यह अवसर 100 में 1 है, और 45 की आयु में, इसके 30 में से 1 अवसर होता है।

प्रजनन हेतु दवाईयों का प्रयोग और/या इनविट्रो उर्वरता से बाद की आयु में गर्भवती होने के अवसरों में बढोत्तरी हो जाती है। उर्वरता के उपचार से सफलतापूर्वक गर्भ धाारण करने में सुविधा होती है जिसे वूमैन एज ओल्ड एज 67 में दर्ज किया गया है।

डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि 30 से ज्यादा की वे महिलाएं 6 से अधिक महीनों में गर्भधारण का असफल प्रयास करती आ रही हैं वे कुछ प्रकार की उर्वरता जांचों से गुजरती हैं।

पुरुष प्रजनन क्षमता

आयु बढ़ने के साथ ही उत्थानक्षम दुष्क्रिया बढ़ती है, परंतु जिस तेजी से महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम होती है उस गति से पुरुषों में यह कम नहीं होती। ऐसे भी उदाहरण आए हैं जिनमें कोई पुरुष 94 वर्ष की आयु तक भी प्रजनन के लायक था। तथापि, तथ्य यह बताते हैं की पुरुषों की बढ़ती उम्र के साथ ही वीर्य की मात्रा, शुक्राणुओं की गतिशीलता और शुक्राणुओं की संरचना घट जाती है। 30 साल और 50 साल के पुरुषों पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था की दर में 23 फीसदी और 28 प्रतिशत की गिरावट आई। यह अध्ययन महिलाओं की आयु को नियंत्रित करने के लिए किया गया था।

उम्र के साथ शुक्राणुओं की संख्या भी घट जाती है, 50-80 आयु वर्ग वाले पुरुष 20-50 आयु वर्ग वाले पुरुषों की तुलना में 75 फीसदी तक कम शुक्राणु पैदा करते हैं। हालांकि, इससे भी ज्यादा अंतर इसमें भी आ जाता है कि कितनी बीजोत्पादक नलिकाएं परिपक्व शुक्राणु लिए हुए थी,

- 20-39 साल तक के पुरुषों में 90 फीसदी तक बीजोत्पादक नलिकाएं परिपक्व शुक्राणु लिए होती हैं।
- 40-69 साल तक के पुरुषों में 70 प्रतिशत बीजोत्पादक नलिकाएं परिपक्व शुक्राणु लिए होती हैं।

टिप्पणी

- 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के पुरुषों में 10 प्रतिशत बीजोत्पादक नलिकाएं परिपक्व शुक्राणु लिए होती हैं।

हाल ही में हुए शोध में सामने आया कि जिन बच्चों के बाप बड़ी उम्र के होते हैं, उन बच्चों के बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। इजरायल में हुए एक शोध के अनुसार 40 साल उम्र के लोगों के बच्चों में 30 साल उम्र के पुरुषों के बच्चों की तुलना में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर की चपेट मे आने का खतरा 5.75 गुणा ज्यादा होता है। इसी तरह पैतृक आयु में बढ़ोतरी मनोभाजन से भी जुड़ी है, ऐसा कई शोधों में पाया गया है।

आस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिक वजन मोटापा भी शुक्राणुओं को क्षति पहुंचाता है और स्वस्थ गर्भधावस्था को रोकता है। उनके अनुसार अगर पिता का वजन ज्यादा होता है तो निषेचन की कामयाबी 40 प्रतिशत तक कम हो जाती है।

द अमेरिकी फर्टिलिटी सोसायटी ने शुक्राणुदाताओं के लिए 50 साल या इससे कम की आयु सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की है और युनाइटेड किंगडम के भी बहुत से फर्टिलिटी सेंटर ऐसे व्यक्तियों से शुक्राणु नहीं लेते जिनकी आयु 40 या 45 साल है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब ज्यादा से ज्यातर महिलाएं शिशु दर गणक का प्रयोग निषेचन का अंदाजा लगाने के लिए करने लगी है।

मृत्युदर

मृत्युदर नश्वर या मृत्यु के लिए अतिसंवेदशील होने की दर है, यह अमरता के विपरित है। मृत्युदर किसी जनसंख्या की मौतों की संख्या (सामान्यत या किसी विशेष कारण से) की गणना है। साधारण शब्दों में कहें तो 1000 व्यक्तियों में से प्रति वर्ष मरे लोगों की संख्या। इस तरह एक लाख जनसंख्या की 9.5 मृत्युदर का अर्थ है इस आबादी में से 950 या 0.95 फीसदी लोगों का हर साल मरना।

यह रुग्णता दर से भिन्न है जो एक विशेष समय में कमजोर स्वास्थ्य के व्यक्तियों को दर्शाती है या फिर रोग के समय की प्रति इकाई के अनुपात में आए नए केसों के बारे में बताती है।

मृत्युदर विस्थापन

मृत्युदर विस्थापन से तात्पर्य विशिष्ट जनसंख्या की मृत्यु दर में आए अस्थाई बदलाव से है जो आमतौर पर पर्यावरण की देन होता है जैसे लू या शीतलहर के कारण।

उदाहरण के लिए लू के समय जनसंख्या में मृत्युदर बढ़ जाती है और यह बड़ी उम्र के लोगों या बीमार व्यक्तियों को प्रभावित करती है। लू के बाद के सप्ताह में हालांकि सम्पूर्ण मृत्युदर में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। मृत्युदर के इन अल्पायु बदलावों को कटाई प्रभाव भी कहते हैं। मृत्युदर में इस उतरगामी, प्रतिकरात्मक गिरावट रेट यह बताती है कि लू ने विशेषकर उन लोगों को ज्यादा प्रभावित किया जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब था और वे अल्पकाल में किसी भी समय मर सकते थे।

टिप्पणी

प्रजनन क्षमता और मर्त्यता के निर्धारक तथा परिणाम

उत्पादन एक स्वैच्छिक जैव प्रक्रिया है। उत्पादकता तय करने के क्रम में, मानव जीवन के कई सामाजिक, जैविक, और आर्थिक कारक होते हैं। इन कारकों को निम्न चित्र में दर्शाया गया है।

उत्पादकता निर्धारक कारक

उत्पादकता एक बहुत ही जटिल मामला है। समान्यतः इसपर कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणसंबंधी, शारीरिक, सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य कारकों का आसानी से प्रभाव पड़ता है। आइए उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई शरीरिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को देखते हैं।

- **शारीरिक कारक :** शारीरिक कारक से अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक सीमा से है। यहां, शारीरिक का तात्पर्य सतत रूप से किसी जीव की क्रीयाशीलता है। उत्पादकता के क्षेत्र में, शारीरिक कारक से अभिप्राय स्त्री की प्रजनन क्षमता से है। इसे प्रभावित करने वाले कारक बाँझपन, उच्च रक्तचाप, तनाव, मनोविकार इत्यदि हैं।
- **शरीरिक प्रजनन क्षमता :** जनन क्षमता सबसे पहले शारीरिक प्रजनन क्षमता अर्थात् जनन शक्ति पर निर्भर करती है। उत्पादकता यानि जनन क्षमता के वास्तविक स्तर पर बाँझपन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **अति रक्तचाप :** अतिरक्तचाप, हृदयवहिका रोग तथा तंत्रिकातंत्र रोग की वृद्धि में मुख्य खतरनाक कारक, और अंतिम चरण के किडनी रोग तथा उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है। माहिलाओं में अति रक्चचाप की दर सर्वाधिक होती है। शोध से यह पता चला है कि उच्च रक्तचाप की गोलियां उत्पादकता की दर को कम कर सकती हैं या पुरुष तथा स्त्री दोनों में अनुर्वरता उत्पन्न कर सकती हैं।
- **तनाव :** महिलाओं में तनाव से हार्मोन के स्तर में भारी परिवर्तन होता है, जिससे उनकी उत्पादकता दर में कमी उत्पन्न हो जाती है। तनाव से अण्डोत्सर्ग पर प्रभाव

पड़ता है या यह अण्डाणु-हार्मोन चक्र को बाधित कर देता है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं में यह कॉर्टिजॉल स्तर को बढ़ाकर पूर्ण रूप से रज:स्राव को रोक देता है। इस प्रकार महिलाएं तनाव से बुरी तरह पीड़ित हो जाती हैं एवं अति तनाव और विलंबित रज:स्राव की वजह से ये बांझपन का शिकार हो सकती हैं।

टिप्पणी

शोध से यह भी पता चलता है कि पुरुषों तथा महिलाओं में तनाव के कारण यौनेच्छा में कमी आ जाती है। तनाव से महिलाओं में उत्तेजना की कमी हो जाती है जबकि इससे पुरुषों में तात्कालिक कमजोरी हो सकती है। इससे किसी व्यक्ति के प्रजनक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- **ऑटोइम्यून विकार :** ऑटोइम्यून डिसॉर्डर में सूजन, मधुमेह, थाईरॉइड रोग, संन्धि -वातीय गठिया जैसे रोग आते हैं, जिससे उत्पादकता में कमी उत्पन्न होती है। ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं में गर्भपात तथा अनुर्वरता की संभावना मौजूद रहती है।
- **मनोविकार :** मनोविकार से भी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि मानसिक क्षय वाली स्त्री या तो अनुर्वर होती है या फिर उसे गर्भ धारण करने में दिक्कतें होती हैं। इस रोग के इलाज में भारी मात्रा में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों से महिलाएं या तो अपनी प्रजनन अवधि खो देती हैं या बांझ हो जाती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

- **सांस्कृतिक रिवाज और विश्वास :** समाज में मनुष्य के सांस्कृतिक रिवाज और विश्वास का उनके उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। कई विकासशील देशों में होने वाले किशोर-विवाह के लिए परंपराएं तथा अंधविश्वास उत्तरदायी हैं। विवाह के लिए लड़कियों की औसत आयु 13 या 14 होती हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं की उत्पादक दर बढ़ जाती है। इनकी उत्पादक आयु की अवधि तथा उत्पादन क्रिया की भागीदारी में बढ़ोत्तरी होती है।

  इसके अलावा, विधवा-विवाह प्रतिबंध, बहुपति-प्रथा, बहुपत्नी-प्रथा जैसे कई सारे सांस्कृतिक रिवाजों से भी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। विधवा-विवाह प्रतिबंध तथा बहुपत्नी-प्रथा से उत्पादक दर में कमी आती है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में ठहराव से इनकी उत्पादक अवधि में कमी आती है। बहुपति-प्रथा में किसी स्त्री की उत्पादक अवधि का पूर्ण उपयोग होता है, परिणामस्वरूप उस विशेष परिवार में बच्चों की संख्या में वृद्धि होती जाती है।

  इसके अलावा, धर्म/वर्ग, शिक्षा, जीवन स्तर, जैसे अन्य सामजिक कारकों, के साथ रोजगार भी उत्पादकता पर प्रभाव डालती है।

- **धर्म/वर्ग :** उत्पादकता पर धर्म और वर्ग का गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि जनसंख्या के अन्य हिस्से की तुलना में रोमन कैथोलिक्स में उत्पादकता दर काफी उच्च होती है। इसी प्रकार हिन्दू की तुलना में मुसलमान समाज में उत्पादकता दर काफी उच्च होती है। यह मुख्य रूप से लड़कों की वरीयता देने से होता है। हिन्दू और मुसलमान दोनों के समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़के

टिप्पणी

उनके लिए एक संपत्ति के रूप में होते हैं जिनपर वे पूरी जिन्दगी आश्रित रह सकते हैं। लड़कों के प्रति इस इच्छा की वजह से हिन्दू और मुसलमान समाज में उत्पादकता की दर में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

दूसरी ओर, कैथोलिक समाज में बच्चों की संख्या पर अधिक, और इनकी गुणवत्ता पर कम जोर दिया जाता है। इसलिए कई पौराणिक कथाओं, धर्म-सिद्धांतों और समाज के वर्ग भी किसी देश की उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं।

- **शिक्षा :** शिक्षा का उत्पादकता की दर पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि अधिकांश शिक्षित दंपत्ति, खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त पत्नियां, निम्न स्तरीय शिक्षा प्राप्त महिलाओं की तुलना में, छोटे परिवार को पसंद करती हैं। इस कारण, उच्च शिक्षित व्यक्ति पारिवारिक जीवन से दूर रहना पसंद कर पाते हैं, और परिवार के बाहर किसी अन्य भूमिका में संलिप्त रह सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षित दंपत्तियों को अधिक जानकारियां होती हैं तथा ये अधिक सफल परिवार नियोजक साबित हो सकते हैं।
- **रोजगार :** स्त्री-पुरूष के रोजगार से भी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। पुरुष के रोजगार से उत्पादकता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है परंतु स्त्री और बच्चों के रोजगार से उत्पादकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बच्चों के लिए कोई ऐसा अवसर हो जिससे वह अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सके, तो अधिकांश अभिभावक बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं।

कई समाजशास्त्रियों और आर्थशास्त्रियों ने स्त्रियों के रोजगार और उत्पादकता के बीच संबंध पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। आर्थशास्त्रियों के अनुसार स्त्रियों के रोजगार से घर की आमदनी बढ़ जाती है। इससे उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृति उत्पन्न होती है। इससे बच्चों के अवसर मूल्य में भी वृद्धि होती है, जिससे परिणाम स्वरूप जननक्षमता में ह्रास की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार, कामकाजी महिलाएं अपने घरेलू काम-काज तथा बच्चों के प्रति कम ध्यान दे पाती हैं। इसके फलस्वरूप, इनकी उत्पादकता कम हो जाती है। जब महिलाओं के कार्य और पारिवारिक भूमिकाएं आपस में मेल खाती हों तो ऐसी स्थिति में समाजशास्त्री एक विरुद्ध प्रवृत्ति का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस स्थिति में, उत्पादकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

मृत्यु-दर के निर्धारक एवं परिणाम

मृत्यु या तो महामारी, बीमारी या प्राकृतिक आपदा या दुर्घटनाओं की वजह से होती है। मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। रोगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के नियमों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मृत्यु के अंतर्निहित कारण को ''मृत्यु की ओर सीधे ले जाने वाले बीमारी अथवा चोट के कारण उत्पन्न होने वाला जानलेवा सिलसिला अथवा जानलेवा चोट उत्पन्न करने वाली दुर्घटना या हिंसा'' के रूप में परिभाषित किया गया है। दुनिया भर में मर्त्यता के प्राथमिक कारकों को निम्नांकित ढंग से सूचीबद्ध किया गया है:

टिप्पणी

- हृदय रोग
- कैंसर
- स्ट्रोक
- निम्नवर्ती श्वसन क्षेत्र के संक्रमण
- एड्स
- आकस्मिक चोट या घाव
- अलझाइमर रोग और अन्य डिमेंसिया
- डायरिया जैसे रोग
- टी.बी.
- सेफ्टीसीनिया और नियोनेटल संक्रमण

- **हृदय-रोग :** कार्डियोपैथी या हृदयरोग वे रोग होते हैं जिनसे मानव शरीर के हृदय को प्रभावित करने वाली कई अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कनाडा, इंगलैंड और वेल्स, युनाईट्स स्टेट जैसे कई देशों में होने वाली मृत्यु की मुख्य वजह हृदयरोग होता है। ऐसा पाया गया कि प्रत्येक वर्ष कई लोग कोरोनरी (या स्केमिक) हृदयरोग (दिल का दौरा), कार्डियोमियोपैथी, उच्च रक्तचाप, गठिया-ग्रस्त हृदयरोग और हृदय गति रुकने से मौत के शिकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में होने वाली कुल मृत्यु में लगभग 16.7 मिलियन मृत्यु मिलियन विभिन्न प्रकार के हृदय-रोगों से होती हैं। प्रत्येक वर्ष हृदयरोग से होने वाली 16.7 मिलियन मृत्यु में, स्केमिक हृदयरोग से 7.2 मिलियन, हृदयवाहिका रोग से 5.5 मिलियन, और शेष 3.9 मिलियन उच्चरक्तचाप तथा अन्य हृदय संबंधी हालातों के कारण होती हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 20 लाख लोग दिल के दौरों और आघातों से जीवित बच जाते हैं।
- **कैंसर :** कैंसर वह रोग होता है जिसमें कोशिकाओं के किसी समूह की अपनी वृद्धि सीमा सामान्य से अधिक हो जाती है। लगभग 13 प्रतिशत मानव मृत्यु कैंसर से होती है। दूसरे शब्दों में 2004 में 7.4 मिलियन (पूरे विश्व में होने वाली मौतों का लगभग 13:) का हिसाब लगाया गया। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है परंतु प्रौढ़ उम्र में इसका खतरा अधिकतम रहता है।

  प्रत्येक वर्ष कैंसर से होने वाली कुल मृत्यु में मुख्य प्रकार के कैंसर निम्नांकित हैं:

  - o लीवर (610 000 मृत्यु)
  - o फेफड़ा (1.3 मिलियन मृत्यु/वर्ष)
  - o ब्रेस्ट (519 000 मृत्यु)
  - o आमाशय (803 000 मृत्यु)
  - o कॉलेस्ट्रॉल (639 000 मृत्यु)

  दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले कैंसर अग्रांकित हैं-

टिप्पणी

लिंग	कैंसर का प्रकार
पुरुषों में	फेफड़ा, आमाशय, लिवर, कोलोरेक्टल, ग्रासनली और प्रॉस्टेट
महिलाओं में	स्तन, फेफड़ा, आमाशय, कोलोरेक्टल और गर्भाशय ग्रीवा

कैंसर से होने वाली कुल मौतों का 70 प्रतिशत मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, एक अनुमान के मुताबिक 2030 में यह बढ़कर 12 मिलियन हो जाएगी।

- **स्ट्रोक :** स्ट्रोक को हृद्यवहिका दुर्घटना भी कहते हैं जो मष्तिष्क में जाने वाले रक्त बहाव के अवरुद्ध होने से होता है, आमतौर पर यह रक्त वाहिका के फट जाने या इसमें थक्का जमने से होता है। स्ट्रोक के आम लक्षण हैं- अचानक कमजोरी या हाथ-पांव तथा चेहरे का सुन्न पड़ जाना, जो अधिकांशत: शरीर के एक हिस्से में होता है, बोलने या सुनने में कठिनाई, भ्रम होना, एक या दोनों आंखों से देखने में कठिनाई; संतुलन या सामन्जस्य खोना; चलने-फिरने में कठिनाई, चक्कर आना, बेहोश या अचेत होना। मृत्यु का मुख्य का कारण आघात है। वर्ष 1999 में 5.5 मिलियन लोगों की मृत्यु स्ट्रोक से हुई थी, इस तरह स्ट्रोक मर्त्यता का दूसरा मुख्य कारण है।
- **निम्नवर्ती श्वसन क्षेत्र का संक्रमण :** निम्नवर्ती श्वसन क्षेत्र संक्रमण को प्राय: निमोनिया के पर्यावाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे फेफड़े का फोड़ा और एक्यूट ब्रानकाईटिस हो जाता है। निम्नवर्ती श्वसन क्षेत्र के संक्रमण में कमजोरी, जल्दी-जल्दी सांस लेना, तेज ज्वर, थकान तथा कफ शामिल हैं। निम्नवर्ती श्वसन क्षेत्र के संक्रमण के कारण स्वास्थ्य बजट पर भारी असर पड़ता है और यह आमतौर पर उच्चवर्ती श्वसन क्षेत्र के संक्रमण से अधिक गंभीर होता है।

  निम्नवर्ती श्वसन क्षेत्र का संक्रमण मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में निम्न श्वसन क्षेत्र संक्रमण से 3.9 मिलियन मौतें होती हैं।
- **एड्स :** एक्वायार्ड इम्युनोडेफिसेएन्सी सिन्ड्रोम (एड्स, इम्युनोडेफिसेएन्सी विषाणु (एचआईवी)से उत्पन्न मानव रोग-प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारी है। यूएस सेन्टर फॉर डीजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रीवेन्सन द्वारा 1981 में पहली बार एड्स की पहचान की गई थी। जीन संबंधी शोध से पता चलता है कि एड्स का उद्भव पश्चिमी-मध्य अफ्रीका में, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध या बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था।

  2007 में एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में 2.1 मिलियन लोगों की मौत एड्स से हुई, जिसमें 330,000 बच्चे शामिल थे। इनमें तीन-चौथाई मौतें अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में हुई।

टिप्पणी

- **आकस्मिक क्षति :** आकस्मिक क्षति या दुर्घटनाएं, पूरे विश्व में होने वाली मौतों का मुख्य का कारण हैं। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं, दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बच्चे, पैदल चलने वाले, साईकिल चालक, वृद्ध व्यक्ति सड़कों के अतिसंवेदनशील इस्तेमालकर्ता होते हैं तथा ये ही दुर्घटनाओं के बुरी तरह शिकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरे विश्व में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं से 3000 लोगों की मौत होती है।
- **अल्जाईमर रोग तथा अन्य डिमेंसिया :** डिमेंसिया का सबसे प्रचलित रूप अल्जाईमर होता है। अल्जाईमर रोग के कारण तथा इसकी वृद्धि का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, परंतु शोध से पता चलता है कि यह बीमारी मष्तिष्क में फलक तथा गुत्थी से संबंधित है। एक अनुमान के मुताबिक 2006 में इस बीमारी से 26.6 मिलियन लोग पीड़ित थे। और ऐसा आकलन किया गया है कि 2050 में पूरे विश्व में प्रति 85 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति अल्जाईमर के शिकार होंगे।
- **डायरिया जैसे रोग :** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया का अर्थ है किसी व्यक्ति का एक दिन में 3 या अधिक बार पतला दस्त होना। आमतौर पर ऐसा होना जठरांत्रिक संक्रमण के लक्षण होते हैं जो अनेक प्रकार के जीवाणुओं, विषाणुओं तथा परजीवियों के कारण हो सकते हैं। डायरिया के अनेक कारण हैं। आमतौर पर यह दूषित भोजन, पेयजल अथवा अस्वस्थ लोगों के एक-दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है।

  डायरिया शिशु मृत्यु का सबसे सामान्य कारण है। साथ ही यह अनेक विकासशील देशों में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण है। 2009 में डायरिया के कारण अनुमान है 1.1 मिलियन मौतें 5 साल और उससे ऊपर के लोगों में हुई और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके कारण 1.5 मिलियन मौतें हुई।
- **टी. बी. :** माइकोबैक्टीरियम ट्युबरक्युलोसिस द्वारा उत्पन्नामक जीवाणु जनित रोग को ट्यूबरक्युलोसिस अथवा टी. बी. कहा जाता है। यह रोग सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। संक्रामक रोग होने के कारण यह सक्रियश्वसन रोग से पीड़ित लोगों के गले और फेफड़े से निकलने वाले नन्हें छींटों के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है।

  फेफड़े के सक्रिय टी. बी. के लक्षण हैं खांसी, कभी-कभी खकास में खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन में कमी, बुखार तथा रात को पसीना आना। 2008 में टी. बी. से मरने वाले लोगों की संख्या 1.3 मिलियन आंकी गई है। सबसे अधिक संख्या में मृत्यु दक्षिण-पूर्व एशिया में हुई जबकि प्रति व्यक्ति उच्चतम मर्त्यता अफ्रीका क्षेत्र में पाई गई।
- **नवजात संक्रमण और सैप्टिसीमिया :** संपूर्ण शरीर में प्रदाह की स्थिति और ज्ञात अथवा संदिग्धा संक्रमण नवजात संक्रमण और सैप्टिसीमिया के लक्षण हैं। नवजात संक्रमण बच्चे के जन्म के शुरुआती महीने में होता है। नवजात संक्रमण और सैप्टिसीमिया से जुड़े कुल प्रसवकालीन मृत्य-दर 40% है।

टिप्पणी

3.3.3 प्रवासन : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप

संपूर्ण विश्व में यूरोप और एशिया महाद्वीप उत्प्रवास के प्रधान क्षेत्र रहे हैं जहां पर समय समय पर मानव के प्रवास हुए हैं। अतः उत्प्रवासी के क्षेत्र के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास को दो वर्गों में रखा जा सकता है :– (1) एशियाई प्रवास और (2) यूरोपीय प्रवास।

एशियाई प्रवास : मनुष्य का विकास मध्य एशिया से माना जाता है। यहां पर विकसित होने वाली प्रजातियां प्रवास के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में पहुंच गई। 18 वीं शताब्दी में चीन से लाखों लोगों ने प्रवास किया और एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में जाकर बस गए। हजारों प्रवासी चीनी लोग मंचूरिया,थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम,फिलीपीन बर्मा,कोरिया आदि देशों में जाकर बस गए। एक अनुमान के अनुसार मलेशिया की कुल जनसंख्या के 45ः लोग चीन मूल के हैं और थाईलैंड की कुल जनसंख्या में 17ः लोग चीन मूल के लोग हैं। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग चार लाख चीनी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास कर गए। लगभग दो लाख चीनी लोगों ने अफ्रीका के चाय और कहवा के बागानों व अन्य कार्यों में मजदूरी के लिए अफ्रीका के देशों में प्रवास किया। चीन के हजारों लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका,कनाडा, क्यूबा,दक्षिण अफ्रीका, पीरु,ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप में प्रवास किया।

जापान सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रवास को प्रोत्साहित किया और हजारों जापानी लोग हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हुए। भारत के भी सैकड़ों लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समीपवर्ती देशों जैसे बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया हिंदेशिया आदि देशों में प्रवास किया। ब्रिटिश काल में खेतों में काम करने के लिए लाखों भारतीयों को दक्षिणी अफ्रीका, मॉरीशस, फिजी,गायना और त्रिनिडाड आदि देशों में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने के लिए आसपास के देशों जैसे बर्मा, श्री लंका, हिंदेशिया आदि देशों से लोग आकर भारत में बस गए। आज भारत में 50 लाख प्रवासी लोग विदेशों से आकर बसे हैं।

यूरोपीय प्रवास : 17 वी शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या में बेहद वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों की कमी होने लगी और जीवन स्तर घटने लगा। जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए यूरोप के लोगों ने संसाधनों के लिए पूरे विश्व को तलाशना शुरू किया। नये समुद्री मार्गों की खोज की गई और इन खोजों के परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को खोज लिया गया। इन देशों के संसाधनों के दोहन के लिए सत्रहवीं से लेकर बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में यूरोप के देशों से बड़ी मात्रा में जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। यूरोप के देशों में नई तकनीक का ज्ञान होने से संसाधनों का दोहन तीव्र गति होने लगा। यूरोप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास दो दिशाओं में हुआ–

1. संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि प्रदेश जहां पर यूरोप की जनसंख्या के लिए जलवायु उपयुक्त थी। यह विरल जनसंख्या वाले प्रदेश थे और इन प्रदेशों में यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में मानव प्रवास हुआ।
2. उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में समुद्री मार्गों के द्वारा आसानी से जाया जा सकता था और जनसंख्या भी विरल थी तथा संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यूरोप

के लोगों ने इन देशों में चाय, कहवा,चावल,नील, कपास, गर्म मसालों और गन्ने की कृषि प्रारंभ की।

इन प्रदेशों में खेतों में कार्य करने के लिए यूरोप के लोगों ने सस्ते श्रमिक मुख्यतः अफ्रीका से दास के रूप में लाये।

टिप्पणी

19वीं शताब्दी के आरंभ तक यूरोप में जनसंख्या का दबाव कम होने के कारण लोगों ने प्रवास को महत्व नहीं दिया लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय प्रभास की लहर शुरू हो गई जिसके परिणाम स्वरूप 1820 से लेकर 1940 तक 120 वर्षों की अवधि में लगभग 6 करोड लोगों ने यूरोप से विदेशों में प्रवास किया। यूरोप के लोगों का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशवाद स्थापित करना था तथा लगभग सभी यूरोपीय देश इस प्रयास में जुट गए किंतु उसमें ग्रेट ब्रिटेन शक्तिशाली होने कारण सर्वाधिक सफल रहा व मध्य अक्षांश में स्थित देशों के प्रमुख क्षेत्रों में आपने उपनिवेश स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से बड़ी संख्या में लोगों ने इन देशों की ओर प्रवास किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक ब्रिटिश जनसंख्या ने सबसे ज्यादा प्रवास किया और यह संख्या प्रति वर्ष तीन लाख थी। ब्रिटिश उपनिवेश उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा एशिया के सभी देशों में फैले हुए थे।

जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया के देशों के लोगों ने भी समुद्र पार करके आपने उपनिवेश स्थापित किये। इन सभी देशों का एक ही उद्देश्य था, आर्थिक उन्नति करने के लिए अविकसित क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन करना। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जर्मनी से लगभग 70 लाख लोगों ने विदेशों में प्रवास किया, इटली से लगभग 1 करोड लोगों ने प्रवास किया। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्वी और दक्षिणी यूरोपीय जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी,यूनान देशों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास में भाग लिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश स्वतंत्र हो गए और यूरोपीय प्रवासियों की संख्या बहुत कम हो गई। यूरोप में सर्वाधिक प्रवास उत्तरी अमेरिका और कनाडा के संदर्भ में हुआ जहां पर 4 करोड़ यूरोपीय लोग पहुँचे।

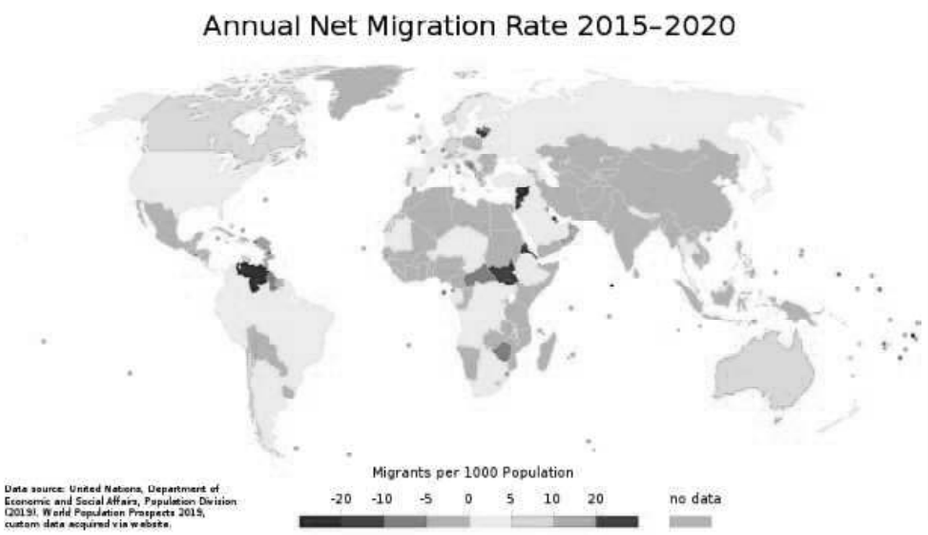

टिप्पणी

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास का महत्व

– प्रवास का प्रभाव ना केवल प्रवासी बल्कि जिस देश से प्रवास हुआ है उस पर और जहां पर प्रवास हुआ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तीनों ही अपने मूल रूप में नहीं रह पाते और इनमें परिवर्तन अवश्यंभावी होता है।

– प्रवासी अपने साथ अपनी परंपराएं, रीति रिवाज,भाषा, संस्कृति, धर्म और तकनीक को साथ लेकर जाता है। और जिस क्षेत्र में प्रवास करता है उसकी परंपराओं,मान्यताओं, रीति–रिवाजों से प्रभावित हो होता है। प्रवास क्षेत्र में परस्पर आदान–प्रदान से नई संस्कृति का विकास होता है। यूरोप के देशों के उपनिवेश विश्व के जिन भागों में भी थे वहां की संस्कृति को प्रभावित किया। यूरोप के देशों की संस्कृति का उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हुआ। मध्य और दक्षिण अमेरिका में बेरोजगारी आदि लैटिन भाषा और यूरोपीय संस्कृति का आज भी वर्चस्व है। शिवराज अमेरिका और कनाडा में अंग्रेजी संस्कृति का वर्चस्व है। चीन,भारत, पाकिस्तान,दक्षिणी अफ्रीका,ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार प्रसार है। इन देशों में पाश्चात्य वेशभूषा,संस्कृति,रहन–सहन,भाषा आदि पर छाप देखी जा सकती हैं। अप्रवासी देशों में विदेशी संस्कृति व भाषा का स्थानीय संस्कृति और भाषा के साथ मिश्रित भी हो गई और नई भाषा का विकास हुआ। चीन और जापान के देशों में अपभ्रंश भाषा का प्रचलन है।

– प्रवासी समुदाय का संबंध अपने मूल स्थान से बना रहता है और दोनों देशों के व्यापारिक, राजनीति और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में सहायक होता है। प्रवासी अपने क्षेत्र की वस्तुओं को आपने मूल स्थान को भेजते हैं और मूल स्थान से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं मंगाते हैं।

– प्रवासी देशों से अधिक संख्या में जनसंख्या के स्थानांतरित हो जाने के कारण वह जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है बेरोजगारी में कमी आती है।

– अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रभाव युवा वर्ग पर भी देखने को मिलता है। युवा लोगों का प्रवास सबसे ज्यादा होता है और उत्प्रवासी प्रदेश में बच्चों, स्त्रियों और वृद्ध जनसंख्या बढ़ जाती है और अप्रवासी क्षेत्र में कार्यशील पुरुषों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है।

– पिछड़े हुए नए क्षेत्रों में नई तकनीक आने से क्षेत्र का विकास होता है संसाधनों के दोहन में तीव्रता आती है। प्रवास के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका,कनाडा, दक्षिण अफ्रीका,ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में आर्थिक विकास हुआ।

– जनसंख्या के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित देशों की संस्कृति,तकनीक,भाषा आदि के आदान प्रदान से दोनों देशों में मित्रता और सहयोग की भावना विकसित होती है। और दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ होते हैं।

अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास

किसी देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले

से दूसरे जिले या एक जनपद से दूसरे जनपद के लिए हो सकता है। इसमें व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य या जनपद की सीमा को पार करता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरे प्रकार के प्रवास को स्थानीय प्रवास कहा जाता है।

टिप्पणी

आंतरिक प्रवास दो प्रकार का होता है–

1. अंतर्राज्यीय / अंतर–प्रांतीय प्रवास (Inter&Provincial or Inter State Migration)
2. स्थानीय प्रवास (Local Migration)

1. अंतर्राज्यीय / अंतर–प्रांतीय प्रवास (Inter&Provincial or Inter State Migration) : इस प्रकार की प्रवास में प्रवासी अपने प्रांत या राज्य की सीमा को लांघ कर अन्य प्रांत या राज्य में प्रवास करते हैं। अंतर राज्य प्रवास पर हर देश में पाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भी इस प्रकार के प्रवास विशेषरूप से देखने को मिलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश,बिहार, हरियाणा,राजस्थान और पंजाब से बड़ी संख्या में लोग आकर बस गए। उत्तर पूर्वी प्रदेश और बिहार की सघन आबादी वाले क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पश्चिमी बंगाल,महाराष्ट्र और गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में बस गए। अंतर्देशीय प्रवास पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं करती और लोग स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते हैं। उत्तरी अमेरिका के भी पूर्वी भागों से लोगों ने पश्चिमी भागों की ओर नये औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास किया। इसी प्रकार रूस के भी पश्चिमी प्रांतों से काफी लोगों ने साइबेरिया में कृषि करने के लिए प्रवास किया। अंतर प्रांतीय प्रवास ग्राम से ग्राम,ग्राम से नगर,नगर से नगर और नगर से ग्राम की ओर हो सकता है।

2. स्थानीय प्रवास (Local Migration) : थोड़ी सी दूरी तक होने वाले प्रवास को स्थानीय प्रवास कहते हैं। एक जनपद से दूसरे जनपद के लिए, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास को इसी श्रेणी में रखा जाता है। प्रवास की दिशा के आधार पर प्रभाव को चार वर्गों में रखते हैं :–

(अ) ग्राम से नगर प्रवास

(ब) नगर से नगर प्रवास

(स) ग्राम से ग्राम प्रवास

(द) नगर से ग्राम प्रवास

(अ) ग्राम से नगर प्रवास : इसे नगरीय प्रवास भी कहा जाता है। बढ़ते हुए औद्योगीकरण के कारण नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में जनसंख्या रोजगार की तलाश में गांव से नगरों की ओर प्रवास करती है। प्रवास के लिए दो शक्तियां कार्य करती हैं – ग्रामीण दबाव शक्ति और नगरीय आकर्षण शक्ति।

ग्रामीण दबाव शक्ति के अंतर्गत निर्धनता,बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा,मनोरंजन आदि सुविधाओं की कमी और न्यून या अनिश्चित मजदूरी आदि युवाओं को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं।

नगरीय आकर्षण शक्ति के अंतर्गत व्यापार, उद्योग, परिवहन,शिक्षा, मनोरंजन,चिकित्सा और अन्य सरकारी सेवाएं इत्यादि युवा वर्ग को आकर्षित करती हैं। अपनी विविध

सेवाओं और रोजगार के अवसर की उपलब्धता के कारण नगरीय केंद्र ग्रामीण युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। विश्व के हर विकासशील देश में इस प्रकार का प्रवास प्रचलन में है।

टिप्पणी

शिक्षा के लिए भी युवा युवा वर्ग रोजाना गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थान जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि और तकनीकी संस्थान शहरों में ही स्थापित होते हैं। बढ़ती हुई आबादी और रोजगार व काम धंधों की कमी के कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है और अन्य समस्याएं जैसे बिजली, पानी,सफाई, मनोरंजन के साधनों की कमी, चिकित्सा आदि की कमी के कारण लोग शहरों में निवास करते हैं। यह प्रवास स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार का हो सकता है।

(ब) नगर से नगर प्रवास : इस प्रकार का प्रवास विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। विकासशील देशों में कुछ बड़े नगरों में भी देखने को मिलता है। इस प्रवास में लोग बेहतर जीविका, रोजगार वाणिज्य,उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छोटे नगरों से बड़े नगरों में प्रवास करते हैं। भारत में कोलकाता,दिल्ली,चेन्नई,मुंबई आदि महानगरों के लिए निकटवर्ती राज्यों व छोटे नगरों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में स्थानांतरण करते हैं। लंदन, मॉस्को, टोक्यो, सिंगापुर , लास एंजिल्स, न्यूयॉर्क, सिडनी इत्यादि स्थानों पर प्रतिवर्ष भारी संख्या में लोग प्रवास करते हैं।

(स) ग्राम से ग्राम प्रवास : इस प्रकार का प्रवास दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। जहां पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है ऐसे क्षेत्रों से ग्रामीण जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों की ओर प्रवास करती है जहां पर पर्याप्त पानी, उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होती है और जहां कृषि के विकास की संभावना मौजूद होती हैं। ग्रामीण जनसंख्या बेहतर रोजगार पाने के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करती है जहां पर कृषि उन्नत अवस्था में होती है रोजगार प्राप्त करने की संभावना होती है। भारत में प्रति वर्ष बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से से लाखों की संख्या में श्रमिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवास करते हैं। यहां क्षेत्रों में 1 साल में तीन फसलें ली जाती हैं। धान, गेहूं गन्ने की फसल में इन श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कई परिस्थितियों में धार्मिक प्राकृतिक और आर्थिक संकट होने पर भी ग्रामीण जनसंख्या द्वारा दूसरे क्षेत्रों में प्रवास किया जाता है।

(द) नगर से ग्राम प्रवास : नगर के ग्राम प्रवास केवल विकसित अर्थव्यवस्था में ही पाया जाता है। विकासशील देशों में बहुत ही कम मात्रा में इस प्रकार का प्रवास होता है। महानगरों के शोर–शराबे और भीड़ भाड़ से दूर स्वच्छ ग्रामीण वातावरण में कुछ लोग अपना आवास बनाकर रहते हैं। और कुछ नहीं ग्रामीण आंचल में फार्म हाउस बना कर कुछ दिनों के लिए भी अस्थाई प्रवास करते हैं।

मौसमी प्रवास : मौसम परिवर्तन या कुछ निश्चित समय अंतराल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले मानव स्थानांतरण को मौसमी या सावधिक प्रवास कहते हैं। सामयिक या सावधिक प्रवास निश्चित समय अवधि के लिए ही होता है और मौसमी

प्रवास प्रतिवर्ष एक निश्चित मौसम में ही होता है। विश्व विभिन्न भागों में मौसमी प्रवास होता है उनके स्वरूप में भिन्नता मिलती है। तीन प्रकार के महत्वपूर्ण मौसमी प्रवास होते हैं :–

टिप्पणी

(1) चलवासी पशुचारकों का मौसमी प्रवास

(2) पर्वतीय मौसमी प्रवास

(3) मजदूरों का मौसमी प्रवास

1. चलवासी प्रवास : विश्व के अर्द्धशुष्क तथा घास के मैदानों में स्थानांतरणशील जनजातियां घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं। चलवासी पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अरब के साइबेरिया की स्ट्रेप्पी घास प्रदेश में खिरगीज, भारत के हिमालय प्रदेश में निवास करने वाले बकरवाल गुज्जर इसके उदाहरण हैं। यूरेशिया के रहने वाले याकूत और लैप जातियां शीत ऋतु में नदियों के किनारों पर तंबू बनाकर रहते हैं और ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर चारागाहों की तलाश में प्रवास करते हैं।

2. पर्वतीय मौसमी प्रवास : विश्व के पर्वतीय भागों में इस प्रकार का प्रवास प्रचलित है क्योंकि पर्वतों के ऊपरी भाग हिम से ढकने के कारण चरागाहें हिमाच्छादित हो जाती हैं। पशु पालकों को अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में पर्वतों के निचले भागों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इस प्रकार का प्रवास निकली घाटी और ऊपरी पर्वतीय भागों के मध्य निश्चित ऋतु में पूर्वनिधारित मार्गों द्वारा प्रतिवर्ष होता है। इसे पर्वतीय मौसमी प्रवास कहते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं के साथ उच्च भागों में निवास करते हैं क्योंकि इस समय पशुओं के लिए पर्याप्त चरागाह उपलब्ध होती है। शरद ऋतु के आगमन पर ऊपरी भागों में तापमान कम होने से यह लोग घाटी के नीचे निचले भागों में अपने पशुओं के साथ स्थानांतरण करते हैं। शरद ऋतु में घाटियों में तापमान उच्च और पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध होता है। ये कुछ निश्चित मार्गों के द्वारा ही प्रतिवर्ष परिवार के साथ प्रवास करते हैं। यह निश्चित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर चलते हैं। दिसंबर तक ये प्रवासी निचली घाटियों में पहुंच जाते हैं। इन घाटियों में रहने के दौरान यह लोग यहां पर अपने उत्पाद जैसे शाल, ऊन,कंबल आदि को बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेते हैं। शीत ऋतु की समाप्ति के उपरांत मार्च–अप्रैल में ये लोग अपने परिवार और पशुओं के साथ पहाड़ों की ओर प्रस्थान करते हैं।

3. मजदूरों का मौसमी प्रवास : इस प्रकार के प्रवास में मजदूर समय विशेष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। कृषि में वर्ष भर कार्य उपलब्ध नहीं होता केवल कुछ समय ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जब कृषि कार्यों में मजदूरों की आवश्यकता होती है तो विभिन्न भागों से कृषि श्रमिक उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रवास करते हैं। कृषि कार्य समाप्त हो जाने पर वे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। 40 –50 वर्ष पूर्व जब संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि यंत्रीकृत नहीं थी तो गेहूं की कटाई और कपास को चुनने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर विदेशों से आते थे। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व इटली और स्पेन से हजारों की संख्या में मजदूरों को

टिप्पणी

अर्जेंटीना में गेहूं की कटाई के लिए लेकर जाया जाता था और कटाई समाप्त होने पर यह मजदूर अपने घरों को लौट जाते थे। भारत में भी हरियाणा और पंजाब में कृषि कार्यों में मजदूरों की आवश्यकता होती है, उस समय आसपास के क्षेत्रों से मजदूर इन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। कार्य समाप्त होने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं। नगरों में कार्य करने वाले श्रमिक फसलों की कटाई के मौसम में अपने गांव लौट जाते हैं और कटाई खत्म होने के उपरांत वापस महानगरों में कार्य करने के लिए लौट आते हैं।

3.3.4 भारत की जनसंख्या गतिकी

शहरी व्यवस्था की अवधारणा को ब्रायन जेएल बेरी (1964) ने अपने उल्लेखनीय अध्ययन ''शहरों की प्रणालियों के भीतर सिस्टम के रूप में शहर'' में पेश किया था। शहरी स्थान अलगाव में मौजूद नहीं हैं।

अलग–अलग कस्बों और शहरों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों की एक पूरी श्रृंखला है और हम शहरी प्रणाली शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि अलग–अलग शहरी केंद्र एक दूसरे कैसे जुड़े हुए हैं। शहरी केंद्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में और जनसंख्या का भौगोलिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के साथ, शहर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के चुम्बक बन गए हैं।

कस्बों और शहरों के बीच अन्योन्याश्रयता किसी देश को एक प्रणाली के रूप में विकसित करती है। शहरी स्थान के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अन्योन्याश्रयता की प्रकृति हो सकती है। नगरों की व्यवस्था में एक में हो रहे जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, रोजगार संरचना इत्यादि परिवर्तन सिस्टम में अन्य शहर के परिणामस्वरूप होंगे। शहरी पदानुक्रम प्रणाली का विचार शहर की अवधारणा के केंद्र में है। शहरी पदानुक्रम अवधारणा मानती है कि शहरी स्थान जनसंख्या के आकार और आर्थिक कार्य में भिन्न होते हैं। शहरी पदानुक्रम का विश्लेषण मुख्य रूप से विभिन्न मानदंडों के आधार पर जैसे जनसंख्या आकार, आर्थिक शक्ति, खुदरा बिक्री और औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के क्रमित क्रम से संबंधित है।

लिंस्की द्वारा संभावित कारकों को प्राइमेट सिटी द्वारा उच्च स्तर की प्रधानता या कठिन वर्चस्व का उत्पादन के संदर्भ में अधिक सटीक शब्दों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि उच्च स्तर की प्रधानता वाले देशों में कुछ विषमताएं प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति होती है:–

1. लघु क्षेत्रीय विस्तार
2. अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व
3. कम प्रति व्यक्ति आय
4. कृषि निर्यात पर उच्च स्तर की निर्भरता
5. जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और
6. कई मामलों में, एक पूर्व औपनिवेशिक स्थिति

प्रधानता का सूचकांक

यह किसी देश या क्षेत्र के सबसे बड़े शहर के सापेक्ष महत्व का माप है।

प्रधानता का सूचकांक = P1/P 2

जहाँ P1 = सबसे बड़े शहर की जनसंख्या और

P2 = दूसरे सबसे बड़े शहर की जनसंख्या

दो मुद्दे हैं जिन पर आम तौर पर प्राइमेट सिटी के संबंध में बहस होती रही है–

1. इसकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता के साथ सरोकार
2. इसकी वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में

टिप्पणी

सार्वभौमिक प्रयोज्यता

यह एक नियम के रूप में सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक नहीं है, बल्कि केवल निश्चित शर्तों के तहत ही सत्य है।

* दोहरी अर्थव्यवस्था में प्रचलित या जहां विकास का निम्न स्तर है।
* शुरुआत में जैसे–जैसे कोई देश आर्थिक रूप से विकसित होता है, प्रधानता बढ़ती जाती है। एक निश्चित समय के बाद प्रधानता कम हो जाती है – लेकिन जेफरसन ने किसी समय कारक के बारे में बात नहीं की है।

भारत में – बॉम्बे/कलकत्ता = 1.1 (1991)

कनाडा – टोरंटो/मॉन्ट्रियल = 1.1

अतः उच्च विकास का अर्थ निम्न प्रधानता नहीं है।

इच्छा

बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रधानता का ऊंचा स्तर मजबूत क्षेत्रीय असमानता और विकास की कमी की अभिव्यक्ति है। यह बार–बार कहा गया है। लेकिन नहीं इस बात की दृढ़ता से पुष्टि की गई है कि प्राइमेट सिटी क्षेत्रीय असंतुलन में योगदान देता है और एक अप्रिय शहरी व्यवस्था है।

दोनों मुद्दों के संबंध में बहस अभी भी संदेह के लिए खुली है। बहरहाल, प्राइमेट सिटी दुनिया के बहुत से देशों और भारत के कई राज्यों में शहरी व्यवस्थाएं होती हैं। भूगोलवेत्ता द्वारा मौलिक प्राइमेट सिटी डेवलपमेंट सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना नहीं की जा सकती है।

भारत का कोई भी शहर पूरे देश पर वर्चस्व नहीं रखता है। वर्तमान में भारत में कोई प्राइमेट सिटी नहीं है। एक प्राइमेट शहर की अनुपस्थिति को आंशिक रूप से देश के बड़े आकार, इसकी औपनिवेशिक विरासत और देश में राष्ट्रवाद की ताकतों में कमजोरियां द्वारा समझाया गया है। एक प्राइमेट सिटी की अनुपस्थिति की जड़ें भारतीय इतिहास में हैं। भारत 1947 तक एक राजनीतिक रूप से एक अकीकृत राष्ट्र नहीं था। प्राथमिक सिटी का विकास अनिवार्य रूप राजनीतिक से निर्देशित प्रक्रिया और

टिप्पणी

स्थिरता की परिस्थितियों में खुद को मुखर करने में समय लगता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर प्राइमेट सिटी विकास मजबूत केंद्र सरकारों के साथ एकात्मक राज्यों की विशेषता है। भारत के संविधान में आंशिक रूप से राज्यों के साथ संघ की साझा शक्ति रूप से राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है । यह राष्ट्रीय के साथ–साथ राज्य स्तर के प्राइमेट शहर के विकास की अनुमति देता है।

भारत में राज्य स्तरीय स्थिति

1. पश्चिम बंगाल – कलकत्ता/आसनसोल = 25.08
2. सिक्किम – गंगटोक/सिंगतम = 9.10
3. कर्नाटक – बंगलौर/हुबली = 5.53
4. महाराष्ट्र – मुंबई/पुणे = 4.88
5. तमिलनाडु – मद्रास/कोयंबटूर = 4.66
6. आंध्र प्रदेश – हैदराबाद/विशाखापत्तनम = 4.25
7. गुजरात – अहमदाबाद/सूरत = 2.75
8. उड़ीसा – कटक/राउरकेला = 1.02
9. मध्य प्रदेश – इंदौर/जबलपुर = 1.09
10. बिहार – पटना/धनबाद = 1.35
11. असम – गुवाहाटी/डिब्रूगढ़ = 1.54
12. उत्तर प्रदेश – कानपुर/लखनऊ = 1.68
13. राजस्थान – जयपुर/जोधपुर = 2.03

तालिका : भारत के सबसे बड़े शहरी स्थानों की जनसंख्या, 1981–2011

शहर	1981	1991	2001	2011
मुंबई	8,243,405	12,596,243	16,368,084	18,414,288
कोलकाता	9,194,018	11,021,918	13,216,546	16,314,838
दिल्ली	8,729,283	8,419,084	12,791,458	11,412,56
चेन्नई	4,289,347	5,421,985	6,424,624	86,96,010

(स्रोतः भारत की जनगणना, 1981–2011)

भारत में क्षेत्र स्तरीय स्थिति

भारत के चार सबसे बड़े शहरी स्थान मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई चार क्षेत्रः पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के महानगरीय शहर का विकास चाहता है। इस स्थिति में भारतीय शहरी व्यवस्था में क्षेत्रीय स्तर पर प्रधानता बनी रहती है। चार मेगा शहर अपने संबंधित क्षेत्रों में सबसे बड़े हैं। पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद शहर बन रहा है। उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली सबसे बड़ा शहर बना रहा और कानपुर शहर दूसरा

टिप्पणी

सबसे बड़ा था। पूर्वी में और दक्षिणी क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहने वाले शहरों ने स्थिति बदल दी है। दक्षिण में क्षेत्र हैदराबाद1951,1961,1971 में दूसरा सबसे बड़ा शहर था।कोलकाता पूर्वी क्षेत्र में शहरी प्रधानता की स्थिति प्रदर्शित कर रहा है। 2001 तक कोलकाता पूर्वी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर से लगभग सात गुना बड़ा था । क्षेत्रीय स्तर पर कोलकाता एक प्रमुख शहर बना रहा और 2011 में प्रधानता स्तर में वृद्धि का अनुभव किया। रामचंद्रन (1989) ने तर्क दिया कि कलकत्ता की प्रधानता का मामला यूनाइटेड किंगडम या दुनिया के अन्य शहरों(प्राइमेट सिटी विशेषताओं के साथ)के भी तुलनीय है। पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर आसनसोल है जो कलकत्ता के संबंध में वास्तव में बहुत छोटा था,1981 में यह कलकत्ता का 1ध्25वां आकार (रामचंद्रन 1989)का था । कोलकाता को उपनिवेशवादियों द्वारा प्रशासनिक,सैन्य और व्यावसायिक गतिविधियाँ के लिए एक रणनीतिक स्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यह कोलकाता की प्रधानता का मुख्य कारण बना। कई वर्षों तक यह भारत का सबसे अधिक औद्योगीकृत महानगर बना रहा और इसलिए इस शहर की ओर जनसंख्या का निरंतर प्रवाह बना रहा।

कोलकाता पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े शहर के रूप में विलीन हो गया इसने आगे चलकर ढेरों का उत्पादन करके पूरे क्षेत्र पर प्रभाव बनाये रखा । इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहरी स्थान होने के कारण, कोलकाता रोजगार, शिक्षा की दृष्टि से प्रवासियों के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इन प्रक्रियाओं ने कोलकाता को एक प्रमुख शहर के रूप में उभरने में योगदान दिया।

कोलकाता की प्रधानता के कारण अन्य बड़े स्तर के शहरों की कमी की का कारण बना,साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वी भारत में शहरीकरण का निम्न स्तर का कारण भी बना।वास्तव में रामचंद्रन (1989) ने देखा कि कलकत्ता के भीतरी इलाकों में ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या कम से कम 20,000 और वह 500,000 आबादी की सेवा करता हो उनकी संख्या बहुत कम हैं। 1981 तक कलकत्ता इस क्षेत्र का एकमात्र मिलियन से अधिक महानगर बना रहा।

1981 में भारत के तीन अन्य क्षेत्रों उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में से प्रत्येक में कम से कम दो मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर थे। कोलकाता को ऐतिहासिक रूप से पूर्वी के किसी भी अन्य शहर से बहुत मामूली प्रतिस्पर्धा मिली। अपने आर्थिक और प्रशासनिक महत्व के कारण कोलकाता पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर बन गया। कोलकाता का मामला भी क्षेत्र में शहरीकरण की प्रधानता और निम्न स्तर के बीच के संबंध की व्याख्या करता है (दास और दत्त 1993)। पश्चिमी क्षेत्र में प्रधानता मौजूद है, हालांकि तुलनात्मक रूप से पूर्वी क्षेत्र की तुलना में कम है। पश्चिमी क्षेत्र में शहरीकरण का स्तर पूर्वी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। 1961 के बाद से पश्चिमी क्षेत्रों में मुंबई की प्रधानता में धीमी गिरावट आई है अपवाद 1991 की अवधि थी जब प्रधानता मूल्य में वृद्धि हुई, लेकिन 2001 में फिर से यह घट गई । यह मुख्य रूप से बढ़ती संख्या और मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के इस क्षेत्र में होने कारण है। पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे दो प्रमुख मिलियन से अधिक शहर हैं जो मुंबई से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

टिप्पणी

दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई कभी भी एक प्राइमेट शहर नहीं था,हालांकि 1981के बाद चेन्नई की सापेक्ष प्रधानता में गिरावट आई है। इस क्षेत्र के अन्य दो प्रमुख शहर चेन्नई को करीब से प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। ये शहर हैं बैंगलोर और हैदराबाद। ये दो शहर उदारीकरण के बाद आईटी हब बन गए।

उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली प्राइमेट सिटी के रूप में लगातार बढ़ रही है। यह एकमात्र शहर उन चार सबसे बड़े शहरों में से हैं जिनकी प्रधानता सूचकांक में 1951 के बाद से कोई गिरावट नहीं आई है। दिल्ली भारत की राजधानी है और केंद्र सरकार शहर के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है,दिल्ली में भी कई शिक्षण संस्थान हैं। ये सभी बढ़ते कदमों से इसको प्रधानता की ओर ले जाते हैं।

रैंक–साइज सेटलमेंट सिस्टम

रैंक–साइज सेटलमेंट सिस्टम की अवधारणा 1949 में G K ZIPF द्वारा सुझाई गई थी।

उन्होंने प्रस्तावित किया कि यदि किसी क्षेत्र की सभी नगरीय बस्तियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए

तो n वें रैंकिंग वाले शहर की जनसंख्या सबसे बड़े शहर की I/n होगी।

इस प्रकार जनसंख्या श्रंखला p.p/2, p/3… होगी। P/n जहां

P = सबसे बड़े शहर (प्राइमेट सिटी) की जनसंख्या।

Pn = P1/n

P1 = प्राइमेट शहर की आबादी

N = रैंक

Pn = nth रैंकिंग वाले शहर की जनसंख्या

रैंक–साइज नियम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करता है :

1. बड़ी बस्तियाँ संख्या में कम क्यों हैं?
2. बड़ी और छोटी बस्तियों के बीच क्या संबंध है?

विविधीकरण के बल

छोटी बस्तियों का स्थान आम तौर पर कच्चे सामग्री के स्रोत से निकटता द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां प्राथमिक आर्थिक सक्रियताएं प्रबल होती हैं, वहां भूमि मूल कच्चा माल या संसाधन बन जाती है। किसानों द्वारा जीवन की आवश्यकताएं हेतु भोजन और अन्य बुनियादी चीजों का उत्पादन करने के लिए जमीन जोत दी जाती है। भूमि पर आधारित एक वर्तमान समाज बड़ी संख्या में एक दूसरे से पैदल दूरी के भीतर बस्तियों वाले गाँवों में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार कृषि के अतिरिक्त अन्य प्राथमिक गतिविधियाँ जैसे खनन, मछली पकड़ने और वानिकी जैसी क्रिया दूरी के नियमित अंतराल पर छोटे आकार की बिखरी हुई बस्तियाँ उत्पन्न करती हैं। जैसे–जैसे समाज आगे बढ़ता है, द्वितीयक उत्पादन कच्चे माल के स्रोत से अधिक दूरी पर बस्तियों

का बसाव संभव करता है। द्वितीयक उत्पादन में विशेषज्ञता वाली बस्तियां दूर स्थित हो सकती हैं, और यह भी हो सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी हों। फिर भी, माध्यमिक आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला कच्चे माल के स्रोत के पास स्थित होना चाहिए ताकि परिवहन की लागत न्यूनीकृत हो सके। माध्यमिक आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक गतिविधियों की तुलना में बड़े आकार और अधिक दूरी की बस्तियाँ उत्पन्न करती हैं।

टिप्पणी

एकीकरण के बल

विविधीकरण की ताकतों के विपरीत, एकीकरण की ताकतों के परिणामस्वरूप कुछ बड़ी बस्तियों का उदय होता है। कच्चे माल के स्रोत के निकटता की बजाय बाजार बस्तियों की अवस्थिति का निर्धारण कारक होता है। बाजार के आकार को बस्ती की आबादी से ही मापा जाता है। इस प्रकार, एक बड़ी बस्ती अपने आप में एक बड़े बाजार का निर्माण करती है। तृतीयक गतिविधियाँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन, सभी उपभोक्ता–उन्मुख हैं और बड़े पैमाने पर शहरों में केंद्रित हैं। हाल के दिनों में, द्वितीय गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला ने बाजार उन्मुखीकरण हासिल कर लिया है। (उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग सामान और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग)।

द्वितीय आर्थिक गतिविधियाँ भी बड़े महानगरों में केंद्रित होती हैं। ये ताकतें कुछ बहुत बड़े शहरों के उद्‌भव की ओर ले जाती हैं। उच्च स्तर की प्रधानता मजबूत अभिकेंद्री बलों की उपस्थिति का सुझाव देती है और इसलिए समूह और एकीकरण की ओर अधिक प्रवृत्ति। $(i > 1)$ प्रधानता का अभाव केन्द्रापसारक बलों का अस्तित्व और विविधीकरण के प्रति उनकी अधिक प्रवृत्ति को बताता है $(i > 0, i < 1)$।

दो बलों के बीच संतुलन यानी एकीकरण और विविधीकरण का संतुलन एक आदर्श शहरी प्रणाली $(i = 0)$ को जन्म दे सकता है जो संभवतः वांछनीय और शहरी योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा लक्षित हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में रैंक–आकार संबंध अनुपस्थित है क्योंकि जनसंख्या के आकार में मुंबई, कोलकाता और दिल्ली एक दूसरे के बेहद करीब हैं। इसके अलावा भारत में राज्यों का एक बड़ा बहुमत भी रैंक–आकार के नियम के अनुरूप नहीं है। वास्तव में प्रधानता भारत के 29 राज्यों में से कम से कम 15 में मौजूद है और अन्य आठ राज्यों (बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड) के प्रमुख शहर दूसरे शहर से केवल कुछ ही बड़े हैं।

केरल, कोचीन, कालीकट और तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) के तीन शहरों में लगभग समान जनसंख्या आकार है और यही हाल मध्य प्रदेश में भोपाल,इंदौर, जबलपुर और पंजाब में लुधियाना, अमृतसर और जालंधर के शहरों का भी है। रैंक–आकार केवल राजस्थान राज्य में अच्छे से दिखाई देते हैं। संक्षेप में, भारत में रैंक–आकार एक नियम के बजाय एक अपवाद है।

रैंक का आकलन

रैंक–साइज नियम और प्राइमेट सिटी अवधारणा, दोनों अनुभवजन्य निर्माण है और उनके उद्देश्य बस्ती का वास्तविक विश्व संरचना की व्याख्या देना हैं। हालांकि

रैंक–आकार नियम एक ही समय में संपूर्ण बस्ती प्रणाली को कवर करता है जबकि प्राइमेट सिटी का कानून केवल प्रमुख शहरों पर केंद्रित है रैंक–आकार के नियम में कम अनुभवजन्य वैधता है।

टिप्पणी

भारतीय संदर्भ में, रैंक–आकार के संबंध अपवाद हैं,जबकि प्राइमेट सिटी अधिकांश भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण विशेषताएँ प्रतीत होती हैं। रैंक–आकार का नियम बस्ती प्रणाली के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की तुलना में कुछ हद तक मौलिक आर्थिक आधार पर वर्णित करता है।दोनों की वांछनीयता बहस का विषय है और दोनों योजनाकारों के लिए अवधारणाएँ रचनात्मक हो सकती हैं।

जिपफ द्वारा दिया गया रैंक–आकार नियम काफी हद तक असंतुलित है और शायद ही कभी अनुभवजन्य रूप से सटीक पाया जाता है। इसके अलावा, यह किसी क्षेत्र या देश के सबसे बड़े आकार की जनसंख्या वाले शहर को बहुत महत्व देता है। हर दूसरी बस्ती का जनसंख्या आकार सबसे बड़े शहर के आकार पर निर्भर करता है। रैंक–आकार के नियम को लागू करना मुश्किल है क्योंकि कोई सार्वभौमिक शहर के आकार की परिभाषा नहीं है।

ऐसे कई शहर हैं जहां निर्मित क्षेत्र शहर की प्रशासनिक सीमाओं के बाहर फैला हुआ है और जहां कई शहर कार्यकर्ता निर्मित क्षेत्रों के किनारे से आगे रहते हैं।

रैंक–साइज नियम के लागू होने की समस्या पर एक नजर डालने के बाद, इसका बेहतर उपयोग तुलनात्मक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।रैंक–आकार का नियम व्याख्यात्मक या भविष्यवाणी के बजाय अधिक वर्णनात्मक है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. वयस्क आयुवर्ग में शामिल किए जाने वाले सदस्यों की उम्र क्या होती है?

   (क) 0–14 (ख) 15–64

   (ग) 65 वर्ष से अधिक (घ) इनमें से कोई नहीं

4. जनसंख्या प्रवास (गतिकी) को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

   (क) प्राकृतिक कारक

   (ख) आर्थिक कारक

   (ग) राजनीतिक कारक

   (घ) प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक–सास्कृतिक एवं राजनीतिक कारक

3.4 जनसंख्या और विकास

आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है। इसे एक समय अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान में वृद्धि के रूप में

टिप्पणी

संदर्भित किया जा सकता है। जीडीपी और जीएनपी में परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है। आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा भी है जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की सामान्य जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षणिक स्तर में सुधार होता है। आर्थिक विकास को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) द्वारा मापा जाता है।

अनेक ऐसे कारक हैं, जिनकी मात्रा में सुधार या वृद्धि से अर्थव्यवस्था उच्च विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। कुछ प्रमुख कारक निम्नांकित हैं–

प्राकृतिक संसाधन : ये एक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक होते है। अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों की खोज, एक अर्थव्यवस्था के साथ उपलब्ध दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का सुधार और विवेकपूर्ण उपयोग इसकी वृद्धि को सुगम बनाता है।

भौतिक पूंजी अथवा आधारिक अवसंरचना : भौतिक पूंजी जैसे सड़कों, स्वचालित मशीनरी, कारखानों, वाहनों में निवेश, मानवीय गतिविधियों के लिए मानव पूंजी की तुलना में अधिक कुशल है। यह समय, ऊर्जा की बचत करता है एवं अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में सुधार करता है।

जनसंख्या अथवा श्रम : श्रम, उत्पादन का एकमात्र सक्रिय कारक होने के नाते, एक अर्थव्यवस्था के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के अन्य समस्त कारकों को एकत्रित कर, जनसंख्या की मात्रा, संरचना, वितरण एवं गति आर्थिक विकास की दर में सहायता या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जितना कुशल और सस्ता श्रम होगा, उत्पादन सस्ता और उच्च गुणवत्ता का होगा।

मानव पूंजी : शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कौशल और क्षमताओं में सुधार के लिए मानव पूंजी में निवेश में वृद्धि से उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार होगा जिससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।जिन देशों में अधिक पूँजी निवेश की जाती है वही देश प्रगति के और अग्रसर हैं।

प्रौद्योगिकी : उन्नत तकनीक श्रम के समान स्तरों के साथ उत्पादकता में सुधार करती है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए लागत कम हो जाती है और समय भी कम लगता है। उच्च तकनीक होने से आप कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन कर सकते हैं।

विधान : स्पष्ट रूप से निर्मित किए गए विधान अर्थव्यवस्था के निर्बाध कार्य संचालन में सहायता करते हैं।

जनसंख्या किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को निर्धारित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या का अत्यधिक होना या अत्यंत कम होना इस पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

ऐसा कहा जाता है कि एक वृद्धिशील जनसंख्या वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार, बड़ा कार्यबल, जनांकिकीय लाभांश के लाभ, अधिक नवाचार, कुल उत्पादन में वृद्धि और बहुत कुछ प्रदान करके आर्थिक विकास में सहायता करती है।

यद्यपि, यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। तीव्र गति से वृद्धि करती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक है।

टिप्पणी

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव

1. **प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव** : अति जनसंख्या देश के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, दोहन तथा अवक्रमण करती है, विशेष रूप से भारत जैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां कृषि बहुसंख्यक आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। भूमि उत्पादन का एक सीमित कारक है। भूमि का विखंडन इसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के अयोग्य बना देता है जिससे उत्पादकता कम हो जाती है।
2. **प्रति व्यक्ति आय में कमी** : जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है
3. **अपर्याप्त पूंजी निर्माण** : व्यक्तियों की आय में कमी के कारण, अधिकांश आय उपभोग के वस्तुओं परव्यय किया जाता है। बचत नगण्य है, इसलिए पूंजीगत वस्तुओं या पूंजी निर्माण में निवेश के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है।
4. **बेरोजगारी और अल्प–रोजगार** : जनसंख्या में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य हो जाती है।
5. **पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव** : अति जनसंख्या का सर्वाधिक गंभीर एक प्रभाव यह है कि वृद्धिशील जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, शहरीकरण, अपशिष्ट उत्पादन, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान, वनोन्मूलन, रेत खनन, घटते जल स्तर ने, पर्यावरण को अवक्रमित किया है,
6. जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक बुरा प्रभाव है।
7. **संघर्ष एवं अपराध** : सीमित संसाधनों के लिए अत्यधिक व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा से विवेक रह जाता है। अपराध, शराब, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग दिनचर्या बन जाता है।
8. **अपर्याप्त जीवन स्तर** : जनसंख्या में वृद्धि के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने से व्यक्तियों का जीवन स्तर निम्न कोटि का हो जाता है।
9. **नित्य वैश्विक महामारी और जानपदिक रोग** : अल्प आय एवं बचत के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश नगण्य है। निर्धनता, अपर्याप्त स्वच्छता और भीड़ भाड़ के कारण महामारी और जानपदिक रोगों का प्रकोप निरंतर होता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में विश्व की सर्वाधिकजनसंख्या वाले देश चीन के वुहान में एक महामारी कोविड –19 का प्रकोप, इसकी विशाल जनसंख्या और मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण कुछ ही समय में एक वैश्विक महामारी बन गया।
10. कुपोषण, अकाल, बाढ़ तथा सूखे की स्थिति बनती है।

3.4.1 भारत के जनसंख्या–संसाधन प्रदेश

जनसंख्या स्वयं एक संसाधन की तरह होती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की खोज, प्रबंधन, उपयोग आदि में महत्वपूर्ण होती है। विश्व के प्रत्येक देश

टिप्पणी

में संसाधनों का वितरण समान नहीं पाया जाता है। प्रत्येक देश में संसाधनों का वितरण और उपयोग भी समान नहीं होता क्योंकि किसी भी देश के संसाधनों के उपयोग के लिए मानव बुद्धि और कौशल की आवश्यकता होती है। किसी देश की जनसंख्या और उसमें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जनसंख्या को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है – अनुकूलतम जनसंख्या, अति जनसंख्या और अल्प जनसंख्या। अन्य देशों की भांति भारत में भी जनसंख्या और संसाधन का वितरण समान नहीं है। सर्वप्रथम पी. सेनगुप्ता, (1970) ने भारत को जनसंख्या– संसाधन प्रदेशों में विभक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास और जनांकिकीय संरचना के आधार पर संपूर्ण भारत को 3 वृहत् श्रेणियों के अंतर्गत जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया। पी. सेनगुप्ता द्वारा निर्धारित भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निम्नलिखित हैं:–

1. गत्यात्मक प्रदेश (Dynamic Region)

– पश्चिमी बंगाल डेल्टा

– लावा प्रदेश

– तमिलनाडु प्रदेश

– पंजाब डेल्टा और गंगा –यमुना डेल्टा

– दक्षिण–पूर्वी कर्नाटक पठार

2. अग्रदर्शी या भावी प्रदेश (Prospective Region)

– उत्तर –पूर्वी पठार

– गोदावरी बेसिन

– अरावली पहाड़ी और मालवा पठार

– दक्षिणी –पश्चिमी कर्नाटक पठार

– ब्रह्मपुत्र घाटी

3. समस्याग्रस्त प्रदेश (Problematic Region)

– मध्य –पूर्व का मैदान

– उड़ीसा तट

– केरल तट

– लक्षद्वीप

– उत्तर –पूर्वी कर्नाटक एवं रायल सीमा

– राजस्थान मरुस्थल

– उत्तरी –पश्चिमी हिमालय

– पूर्वी पहाड़ी –पठारी प्रदेश –अंडमान निकोबार द्वीप समूह

टिप्पणी

1. गत्यात्मक जनसंख्या–संसाधन प्रदेश (Dynamic Population Resource Region) : इस वर्ग में वह प्रदेश शामिल किए जाते हैं जिनमें बड़े बड़े औद्योगिक नगर व नगरीय केंद्र स्थित हैं।नगरों में रोजगार के अधिक अवसर होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को आकर्षित करती है जिससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। इन प्रदेशों में नगरीकरण का स्तर अति उच्च पाया जाता है। गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में पांच प्रदेश आते हैं:– पश्चिमी बंगाल डेल्टा,लावा प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, पंजाब का मैदान और गंगा जमुना मैदान,दक्षिण पूर्वी कर्नाटक का पठार।

पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में हुगली नदी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके दोनों किनारों पर महत्वपूर्ण नगरीय व औद्योगिक केंद्र बसे हुए हैं। हुगली नदी घाटी और दामोदर नदी घाटी का सर्वाधिक विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में आसपास के घने बसे हुए प्रदेशों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं इसलिए नगरीकरण का स्तर ऊंचा पाया जाता है। इसी कारण से यहां पर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि भी अधिक पाई जाती है। लावा प्रदेश में भी नगरीकरण और औद्योगिकरण उच्च पाया जाता है। इस प्रदेश में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, पुणे आदि विशाल औद्योगिक केंद्र हैं। मुंबई और अहमदाबाद के औद्योगिक केंद्रों के लिए आधारभूत संरचनात्मक तत्व जैसे पूंजी, बीमा, परिवहन सुविधाएं, कच्चा माल, श्रम, शक्ति आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे यह अत्यधिक मात्रा में उद्योगों को आकर्षित करती है। और औद्योगिक केंद्रों के अधिक होने से यहां पर आसपास के क्षेत्रों से जनसंख्या प्रचुर मात्रा में स्थानांतरण करती है और नगरीकरण उच्च पाया जाता है।

तमिलनाडु में जनसंख्या घनत्व है परंतु जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। यहां पर उद्योगों का केंद्रीकरण नहीं पाया जाता अपितु औद्योगिक विकास विकेंद्रित नगरीय केंद्रों पर हुआ है। चेन्नई मदुरई कोयंबटूर, तूतीकोरिन आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरीय केंद्र हैं । इन नगरों में पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक और वाणिज्य क्रियाओं का विकास हुआ है।

पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पारम्परिक रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र रहे हैं। दिल्ली इसी क्षेत्र के मध्य में स्थित है और दिल्ली एक महानगर होने के साथ भारत की राजधानी है और इसमें छोटे–बड़े कई औद्योगिक केंद्र भी स्थापित हैं। यहां पर जनसंख्या घनत्व और वृद्धि दर तथा सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर उच्च पाया जाता है।

दक्षिणी कर्नाटक पठार में तुमकुर, कोलार, मैसूर, बेंगलुरु, मांड्या जनपद आते हैं। औद्योगिक दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र स्थापित हैं। बंगलौर को इस क्षेत्र का आईटी हब के रूप में माना जाता है।इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व, वृद्धि दर उच्च और साथ ही नगरीकरण और सामाजिक विकास का स्तर भी अधिक पाया जाता है।

2. अग्रदर्शी जनसंख्या–संसाधन प्रदेश (Prospective Population Resource Region) : इस देश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का

टिप्पणी

पर्याप्त और समुचित विकास नहीं हो पाया है। परंतु भविष्य में प्रौद्योगिकी विकास, सामाजिक जागरूकता,शिक्षा, तकनीकी ज्ञान आदि की वृद्धि से इस प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का औद्योगिक विकास और नगरीय विकास की संभावना बढ़ गई है। इस प्रदेश के अंतर्गत 5 क्षेत्र इस प्रकार से हैं :– उत्तर पूर्वी पठार, गोदावरी बेसिन, अरावली पहाड़ी व मालवा पठार,दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक पठार और ब्रह्मपुत्र घाटी।

उत्तर पूर्वी पठार में झारखंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा पठारी भाग आते हैं और इन पठारी भागों में अकूत खनिज संसाधनों के भंडार स्थित है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क, मैंगनीज,टंगस्टन,अभ्रक,कोयला डोलोमाइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में इन विशाल भंडारों का उत्खनन और उपयोग कम हो पा रहा है लेकिन भविष्य में बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी विकास और तकनीकी ज्ञान से इस क्षेत्र में प्रगति के विशेष अवसर मौजूद हैं और भविष्य में इन इन प्रदेशों में हो औद्योगिक केंद्र स्थापित होने की संभावना है। औद्योगिक केंद्र स्थापित होने पर यहां पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जीवन स्तर में सुधार आएगा।

गोदावरी बेसिन में कोयला, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं । तेलंगाना बेसिन और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों का उचित उपयोग होने से यहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा है।

मालवा पठार और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में तांबा, सीसा, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, जिंक लिग्नाइट, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं।

परंतु इन क्षेत्रों में इन संसाधनों का उचित मात्रा में दोहन नहीं हो पाया है जिसकी वजह से यहां पर औद्योगिक विकास कम हुआ है। लेकिन इस औद्योगिक प्रदेश के विकसित होने की संभावनाएं विद्यमान हैं। अभी यहां पर जनसंख्या घनत्व नहीं बन पाया जाता है और जनसंख्या वृद्धि दर भी कम है। सामाजिक और आर्थिक विकास मध्यम स्तर का पाया जाता है।

दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक पठार पर खनिज संसाधनों की प्रचुर भंडार विद्यमान है और जल विद्युत विकास की भी संभावनाएं मौजूद हैं। यहां पर विद्यमान खनिज संसाधनों के आधार पर सीमेंट उद्योग, धातु के समान से संबंधित उद्योग,लोहा– इस्पात उद्योग के विकास की अनेक संभावनाएं पाई जाती हैं। इन उद्योगों के विकास होने से यहां पर विद्यमान जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

ब्रह्मपुत्र घाटी में कोयला, पेट्रोलियम और वन संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं जिनके आधार पर यहां औद्योगिक विकास की अद्वितीय संभावनाएं हैं। इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है और जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च है परंतु सामाजिक आर्थिक विकास स्तर मध्यम प्रकार का है। यहां पर बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश,बिहार,पश्चिम बंगाल से लोग आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए हैं जो यहां पर स्थित अनेक तेल शोधन शालाओं में,निर्माण कार्यों में और वन विभाग में कार्यरत हैं। यहां पर स्थित संसाधनों के उचित प्रयोग से यहां पर औद्योगिक विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं।

टिप्पणी

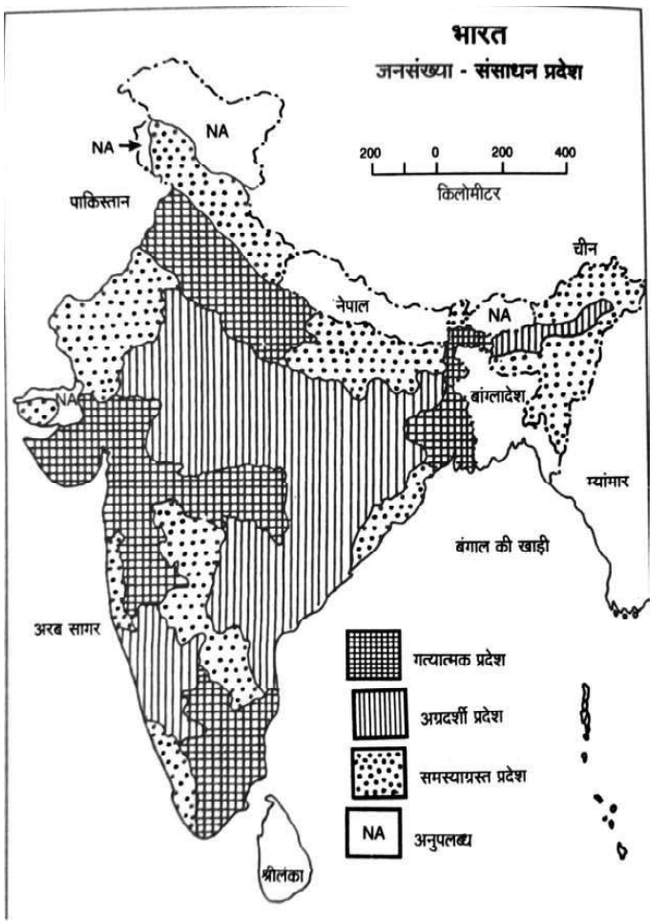

3. समस्याग्रस्त जनसंख्या–संसाधन प्रदेश (Problematic Population Resource Region) : इस प्रदेश के अंतर्गत 9 विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं जो देश के अलग–अलग भागों में उपस्थित हैं। इनका जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि दर भी भिन्न है। कुछ प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है और कुछ प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। इन प्रदेशों का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी निम्न है, केवल केरल इसका अपवाद है। प्रदेश के अंतर्गत 9 प्रदेश हैं – मध्यपूर्व गंगा मैदान, राजस्थान मरुस्थल एवं कच्छ प्रदेश,उड़ीसा तट, केरल तट, उत्तरी– पूर्वी कर्नाटक एवं रायलसीमा, लक्ष्यदीप, उत्तरी –पश्चिमी हिमालय,पूर्वी पहाड़ी– पठारी प्रदेश,अंडमान निकोबार दीप समूह।

इस प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे प्रदेश में जो जनसंख्या विस्फोट और अति जनसंख्या की समस्या से ग्रसित हैं तो कुछ प्रदेशों में जनसंख्या निम्न और संसाधनों का अभाव पाया जाता हैं। इन प्रदेशों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं, उच्च तकनीकी ज्ञान, शिक्षा और कुशल श्रमिकों का आभाव होने से सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न पाया जाता है। इनमें से कुछ प्रदेशों में पर्यावरण जनसंख्या के अनुकूल नहीं होने से प्रदेश पिछड़े हुए हैं।

मध्य पूर्व गंगा के मैदान के अंतर्गत बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान क्षेत्र आते हैं। यहां पर जनसंख्या का दबाव कृषि पर अधिक है।इस क्षेत्र में व्यापक

टिप्पणी

बेरोजगारी,अशिक्षा और निर्धनता होने के कारण आर्थिक सामाजिक विकास निम्न स्तर का पाया जाता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि के लिए कम भूमि की उपलब्धता, अल्प औद्योगिक विकास के कारण यह समस्या ग्रस्त क्षेत्र बन गया है। क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में आसपास के क्षेत्रों में पलायन करते हैं। निरंतर गरीबी का सामना करना पड़ता है।

राजस्थान मरुस्थल में वर्षा की अपर्याप्तता,सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण कृषि को हतोत्साहित करती है। यहां औद्योगिक विकास भी अपर्याप्त है। कच्छ प्रदेश दलदली और लवणयुक्त मिट्टी के कारण कृषिविहीन क्षेत्र है।

उड़ीसा तट मे जनसंख्या वृद्धि तीव्र है लेकिन औद्योगिक विकास कम होने से सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न है। यहां जनसंख्या घनत्व अधिक है और यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में असफल है।

केरल तट या मालाबार तट एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां पर अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। यहां पर जनसंख्या का घनत्व और सामाजिक आर्थिक स्तर दोनों ही उच्च हैं। यहां पर अधिक जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति बन गई है। अत्यधिक जनसंख्या का अकेले कृषि के सहारे भरण–पोषण संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये एक समस्या ग्रस्त प्रदेश बन गया है।

उत्तर पूर्वी कर्नाटक एवं रायलसीमा कृषि उद्योग आदि में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां की कम उपजाऊ मिट्टी, वर्षा की कमी कृषि को प्रोत्साहित नहीं करती। यहां पर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि कम है। सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर भी निम्न प्रकार का है।

लक्षद्वीप देश की मुख्य भूमि से काफी दूर और समुंद्र में स्थित होने के कारण औद्योगिक विकास में पिछड़ा हुआ है। लक्षदीप में संसाधनों की कमी और कृषि के लिए भूमि उपलब्ध ना होने से किसी प्रकार का विकास संभव नहीं है।

उत्तर पश्चिमी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर,उत्तराखंड की पर्वतीय भाग आते हैं।यहां कृषि के लिए भूमि सीमित है और अधिक ऊंचाई कारण परिवहन सुविधाओं की कमी के करण औद्योगिक विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। यहां पर उपलब्ध भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है और जीवन स्तर निम्न है। यहां पर जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है।

पूर्वी पहाड़ी–पठारी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सामाजिक–आर्थिक विकास दोनों ही निम्न पाए जाते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर,नागालैंड,त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम आदि राज्य स्थित है। इन प्रदेशों में रहने वाले लोग आदिवासी हैं और प्राचीन और परंपरागत ढंग से कृषि और आखेट कार्य करते हैं। यहां कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण उत्पादन भी कम पाया जाता है। यहां के लोग अत्यंत पिछड़ा जीवन व्यतीत करते हैं।

अंडमान और निकोबार दीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है,जहां की जलवायु भूमध्य रेखीय तथा भूमि वर्षा वनों से ढकी हुई है। जनसंख्या घनत्व और वृद्धि दोनों ही निम्न हैं। यहां पर औद्योगिक विकास ना के बराबर है।

टिप्पणी

3.4.2 सामाजिक–आर्थिक विकास तथा जनसंख्या स्तर

मानव विकास सूचकांक (HDI) एक संयोजित सूचकांक (आँकड़ा) है, जो देशों को वहाँ के 'मानव विकास' के आधार पर स्थान देता है (रैंक या क्रम प्रदान करता है) तथा विकसित (अत्यधिक विकसित), विकासशील (मध्य विकसित), तथा अविकसित (कम विकसित) देशों को पृथक करता है। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय-GNI (जीवन स्तर के एक प्रतीक के रूप में) से संबंधित आँकड़ों से बनाया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र की सहायता से निर्धारित किया जाता है। स्थानीय संस्थाओं और कंपनियों द्वारा प्रदेशों, शहरों और गाँवों आदि के भी मानव विकास सूचकांक बनाये जाते हैं।

एचडीआई के मूल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मानव विकास रिपोर्ट (HDRs) में मिलते हैं। यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक़ द्वारा प्रकल्पित कर ज़ारी किया गया था। इसका स्पष्ट उद्देश्य था, ''विकास अर्थशास्त्र के फोकस का स्थानांतरण राष्ट्रीय आय लेखांकन से जन केंद्रित नीतियों की तरफ़ करना''। मानव विकास रिपोर्टों को बनाने के लिए, महबूब उल हक़ सुपरिचित विकास अर्थशास्त्रियों, पॉल स्ट्रीटेन, फ्रांसेस स्टीवॉर्ट, गुस्टव रानीस, केथ ग्रिफ्फिन, सुधीर आनंद और मेघनाद देसाई के साथ आये। लेकिन इसकी क्षमताओं और कार्यपद्धतियों पर अमर्त्य सेन का कार्य था जिसने अंतर्निहित सैद्धांतिक ढाँचा प्रदान किया। हक़ आश्वस्त थे कि जनता, अकादमियों और नीतिनिर्माताओं को विश्वास दिलाने के लिए मानव विकास के एक सामान्य संयोजित माप की आवश्यकता है ताकि वे विकास को आर्थिक वृद्धि से मूल्यांकित न करें बल्कि इसे मानव कल्याण में सुधार भी मानें। प्रारम्भ में अमर्त्य सेन ने इस विचार का विरोध किया, लेकिन उन्होंने मानव विकास सूचकांक (HDI) को विकसित करने में हक़ की मदद करना ज़ारी रखा। सेन की चिंता थी कि मानवीय क्षमताओं की पूर्ण जटिलता को एक अकेले सूचकांक में समाहित करना मुश्किल है। हक़ ने उन्हें आश्वस्त किया कि केवल एक सामान्य संख्या नीति-निर्माताओं का ध्यान आर्थिक संकेंद्रण से मानव कल्याण की ओर स्थानांतरित करेगी।

HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा वर्ष 1990 से इसके वार्षिक मानव विकास रिपोर्टों के लिए इस्तेमाल किया गया है।

अन्य संस्थाएँ और कम्पनियाँ भी देशों के लिए भिन्न-भिन्न तरह के सूत्रों का प्रयोग करते हुए विभिन्न संख्याओं वाला HDI बनाती हैं।

एचडीआई में तीन आयाम

2010 की रिपोर्ट से एचडीआई तीन आयामों को संयोजित करता है :

एक लम्बा और स्वस्थ जीवन– जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा।

ज्ञान तक पहुँच– स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष।

समुचित जीवन-स्तर– प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय (पी.पी.पी. अमेरिकी डॉलर में)।

इससे पहले सन् 2009 की रिपोर्ट तक एचडीआई निम्नलिखित तीन आयामों को संयोजित करता था :

टिप्पणी

- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो जनसंख्या, स्वास्थय और दीर्घजीवन का सूचकांक है।
- ज्ञान और शिक्षा, जो प्रौढ़ साक्षरता दर (दो तिहाई भार के साथ) और प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कुल नामांकन अनुपात (एक तिहाई भार के साथ) द्वारा मापा जाता है।
- जीवन-स्तर, जिसमें क्रय-शक्ति क्षमता (पी.पी.पी) पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के प्राकृतिक लघुगणक द्वारा प्रदर्शित की जाती है।

घटक

मानव विकास, स्वास्थ्य और कल्याण के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। यह भौतिक, जैविक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटकों को समाविष्ट करता है। एक संयोजित पैमाना अथवा मानव विकास सूचकांक में इनमें से कुछ ही व्यक्त होते हैं, जिसके तीन आयाम होते हैं: जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापित आय।

सभी एक-आयामी मापकों की भाँति जो विविध जटिल चरों को मापने का प्रयास करते हैं। यह भी निहित त्रुटियों से दूषित होता है, लेकिन यह फिर भी तुलनात्मक रूप से एक जनसंख्या के जन कल्याण की एक उपयोगी माप है।

जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास

आर्थिक विकास एक साधारण, निम्न-आय अर्थव्यवस्था से आधुनिक, उच्च-आय अर्थव्यवस्था की ओर सतत संवृद्धि के साथ एक राष्ट्र की जनसंख्या के जीवन-स्तर में वृद्धि है। यदि जीवन का स्थानीय स्तर बेहतर हो सकता है, तो आर्थिक विकास भी उन्नत होगा। इसकी परिधि उस प्रक्रिया और उन नीतियों को समाविष्ट करती है जिनके द्वारा एक राष्ट्र अपने लोगों के आर्थिक, राजनैतिक, और सामाजिक कल्याण को सुधारता है। न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च के गूनसालो एल फॉनसेसका आर्थिक विकास को 'राष्ट्रों के आर्थिक विकास के विश्लेषण' के तौर पर परिभाषित करते हैं।

'यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा' ज सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉयनेन्स एंड डेवलपमेंट, का कहना है:

''आर्थिक विकास एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और दूसरों लोगों ने 20वीं शताब्दी में बहुधा इस्तेमाल किया है। यद्यपि, पश्चिमी देशों में यह संकल्पना शताब्दियों से अस्तित्व में थी। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और विशेषरूप से औद्योगिकीकरण कुछ और ऐसे शब्द हैं, लोग जिनका प्रयोग आर्थिक विकास पर चर्चा करते हुए करते हैं। कोई भी यह निश्चित नहीं है कि यह संकल्पना कब जन्मी, फिर भी अधिकतर लोग इससे सहमत होते हैं कि विकास, पूँजीवाद के उद्‌भव और सामंतवा द के खात्मे से निकटता से बँधा हुआ है।''

सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आर्थिक विकास का अध्ययन औद्योगिक-आर्थिक आधुनिकीकरण के कारणों की परिकल्पना, आर्थिक विकासकों द्वारा ऐतिहासिक रूप से

टिप्पणी

प्रयुक्त आर्थिक विकास के चरण या संकेत तथा आधुनिक समाज में संगठनात्मक और उद्यम (एनटरप्राइज) विकास से संबंधित पहलुओं को सम्मिलित करता है। इसमें एक ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से व्यापार संगठन तथा उद्यम विकास पर समाजशास्त्रीय अनुसंधान; बाज़ार तथा प्रबंधन-कर्मचारी के क्रमिक विकास (वृद्धि, आधुनिकीकरण) की विशिष्ट प्रकियाएँ ; और समसामयिक पश्चिमी समाज में औद्योगिक संगठन के स्वरूपों में संस्कृति संबंधी परा-राष्ट्रीय समानताएँ और असमानताएँ अंतर्निहित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक-आर्थिक संवृद्धि तथा उपलब्धि के स्तरों में मौजूद पर्याप्त बदलावों की प्रकृति और कारणों के मद्देनज़र, यह इस तरह के सवालों के जवाब ढूँढ़ता है कि क्यों श्रमिक उत्पादकता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर दूसरे देशों की तुलना में कुछ देशों में काफी अधिक हैं?

मैनप्रेल और वेन का कहना है कि विकास को आर्थिक संवृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी और औद्योगीकृत देशों के बराबर के जीवन-स्तर की प्राप्ति को शामिल करने में द्वितीय विश्व युद्ध के समय से समझा गया है।

आर्थिक विकास को एक स्थिर सिद्धांत के रूप में भी समझा जा सकता है जो एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। शमपीटर के अनुसार, इस साम्य स्थिति में बदलावों का आर्थिक संकल्पना में प्रमाणन केवल बाहरी मध्यवर्ती कारकों द्वारा प्रेरित होता है।

क्या संवृद्धि से विकास होता है?

आश्रितता सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि ग़रीब देशों ने कभी-कभी निम्न या शून्य विकास के साथ आर्थिक संवृद्धि का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, उन स्थितियों में जहाँ उन्होंने अमीर औद्योगीकृत देशों के लिए मुख्यत: संसाधन-प्रदाताओं की तरह काम किया है। हालाँकि एक विपक्ष तर्क भी है कि आय में वृद्धि के कुछ हिस्से को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानव विकास पर खर्चे जाने से इस संवृद्धि से विकास भी होता है।

रानिस एट एल (2000) के अनुसार, हम आर्थिक संवृद्धि को मानव विकास से दो-तरफा संबंध के तौर पर देखते हैं। इसके सिवाय, रानिस ने पहली कड़ी का सुझाव दिया जो जीएनपी के साथ मानव विकास को लाभांवित करने वाली आर्थिक वृद्धि है। अर्थात् परिवारों, सरकार और एनजीओ जैसे संगठनों द्वारा किये जाने वाले व्यय द्वारा जीएनपी, मानव विकास में वृद्धि करता है। आर्थिक संवृद्धि के बढ़ने से, आय में बढ़ोत्तरी के कारण, परिवार और व्यक्ति इन व्ययों को संभावित रूप से बढ़ाते है, जिससे मानव विकास में बढ़ोत्तरी होती है। इससे आगे, व्यय में बढ़ोत्तरी की वजह से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा का बेहतर होना ज़ारी रहता है और बाद में इससे आर्थिक संवृद्धि होगी।

निजी आय में वृद्धि के अतिरिक्त, आर्थिक संवृद्धि अतिरिक्त संसाधन भी उत्पन्न करती है जो समाज सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल इत्यादि) को बेहतर बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं। समाज सेवाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन पैदा करने से, असमान आय वितरण को इस तरह से सीमित किया जायेगा कि समाज सेवाओं को हर समुदाय में समान रूप से वितरित किया जाय; इससे हर व्यक्ति को लाभ पहुँचे। इस प्रकार, जनता के जीवन-स्तर में भी सुधार होगा।

टिप्पणी

सारांश में, जैसा कि आनन्द के आलेख (1993) में उल्लेखित है, हम मानव विकास और आर्थिक संवृद्धि के संबंध को तीन विभिन्न व्याख्याओं में देख सकते हैं। पहला, औसत आय में वृद्धि जिससे स्वास्थ्य और आहार में सुधार आता है ('आर्थिक संवृद्धि के माध्यम से क्षमता विस्तार' के नाम से जाना जाता है)। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि सामाजिक परिणाम केवल आय ग़रीबी को कम करके ही बेहतर किये जा सकते हैं ('गरीबी न्यूनीकरण के माध्यम से क्षमता विस्तार' के नाम से जाना जाता है)। और तीसरा, जो 'समाज सेवाओं द्वारा क्षमता विस्तार' के नाम से जाना जाता है, सामाजिक सेवाओं में सुधार को बहुत सी आवश्यक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और साफ पेयजल इत्यादि के साथ परिभाषित करता है।

जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास

किसी देश की आर्थिक संवृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि के अपने प्रभाव होते हैं जो सकारात्मक (धनात्मक) या नकारात्मक (ऋणात्मक) हो सकते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों की ओर देखेंगे:

(1) जनसंख्या वृद्धि से, खपत बढ़ती है जिससे जीएनपी/जीडीपी कम होगा। इससे आयात में बढ़ोत्तरी होगी और निर्यात में कमी आयेगी। परिणामस्वरूप बजट दोष या घाटा होगा और दाम आसमान छूयेंगे।

(2) प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग या अति उपयोग। जनसंख्या वृद्धि की वजह से आदमी से भूमि का अनुपात कम होता है। चूँकि भूमि बेलोच होती है, कोई भूमि की आपूर्ति या मात्रा को नहीं बढ़ा सकता है।

(3) कच्चा-माल या प्राथमिक सामान या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त या परिष्कृत होते हैं जिनसे निर्मित सामानों का उत्पादन होता है और इनके उपज अवशेषों में से कुछ का पुनर्चक्रण किया जाता है और कुछ को प्रकृति में सीधे फेंक दिया जाता है जो प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

(4) प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव, यदि जनसंख्या वृद्धि श्रमशक्ति के साथ मेल नहीं खाती है तो इसका प्रति व्यक्ति आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(5) जनसंख्या वृद्धि और जीवन-स्तर, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि से खपत में बढ़ोत्तरी होती है या भोजन ग्रहण करने वाले मुँहों की संख्या बढ़ती है। इनसे जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

(6) जनसंख्या और कृषि, भूमि पर दबाव बढ़ाता है और इससे प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी बढ़ती है।

(7) जनसंख्या और रोजगार, जनसंख्या के बढ़ने से बेरोज़गारी बढ़ती है।

(8) जनसंख्या और सामाजिक ढाँचा, चूँकि एक डॉक्टर अधिक से अधिक मरीज़ों को देखता है, अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का दबाव बढ़ता है।

(9) जनसंख्या वृद्धि पूँजी निर्माण को घटाता है।

(10) जनसंख्या वृद्धि का परिणाम प्रतिभा पलायन है।

(11) चूँकि जनसंख्या वृद्धि से शहरी मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती है, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

5. इनमें से क्या जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है?

   (क) प्रतिव्यक्ति आय में कमी (ख) संघर्ष एवं अपराध

   (ग) बेरोजगारी–अल्प रोजगार (घ) पर्याप्त जीवन स्तर

6. लावा प्रदेश–तामिलनाडु, पंजाब डेल्टा एवं दक्षिण–पूर्वी कर्नाटक पठार किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में आते हैं?

   (क) अग्रदर्शी (ख) गत्यात्मक

   (ग) समस्याग्रस्त (घ) इनमें से कोई नहीं

3.5 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (ग)
3. (ख)
4. (घ)
5. (घ)
6. (ख)

3.6 सारांश

किसी जनसंख्या की लगातार परिवर्तनशील आयु, वर्ष, माह या समय सबसे छोटी इकाई के संदर्भ में विभिन्नता प्रदान कर सकती है। इस निरंतरता के कारण इसके आयु–संरचना अध्ययन के लिए कुछ सुविधाजनक वर्गों में आयु को व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न अनियंत्रित समूहीकरण हो सकते हैं। एक वर्ष के आयु वर्ग, पाँच वर्ष के आयु वर्ग और दस वर्ष के आयु वर्ग को अपनाया गया है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष वर्गों को भी अपनाया जाता है।

नगर तथा गांव मानव व सामाजिक जीवन के दो पहलू माने जाते हैं। शहर समाज से निर्मित एक वातावरण है जिसमें सामुदायिक जीवन के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का सम्पूर्ण संशोधन किया जाता है। परन्तु इसके विपरीत गांवों का प्रकृति से निकट का सम्बन्ध होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि जहां पर मानव एवं प्रकृति के बीच अन्तःक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है वह गांव है और इसके विपरीत जहां पर मानव एवं प्रकृति के बीच सम्बन्ध अप्रत्यक्ष एवं क्षीण है वह नगर होते हैं।

टिप्पणी

समाज की विभिन्न प्रथाओं को, जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करती हैं, महिला–पुरुष भेदभाव की संज्ञा दी जा सकती है। किसी पितृसत्तात्मक समाज में, जो प्रायः विश्व के सभी भागों में प्रचलित है, महिला–पुरुष भेदभाव एक आम बात है। वह जाति हो या वर्ग, वंश अथवा नृजाति, महिलाएं हर जगह सर्वाधिक उत्पीड़ित प्राणी हैं। महिला–पुरुष भेदभाव मुख्यतः शासक और शासित का संघटन है। प्रचलित विचार है कि कुछ लोग बृहत्तर बुद्धि जैसी कुछ विशेषताओं के साथ जन्म लेते हैं, और उन्हें जन्म से ही श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि महिलाएं अधीनस्थ प्राणी हैं।

मनुष्य एक गतिशील प्राणी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मनुष्य इतिहास से के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रतिरूप के निर्धारण में प्रवास का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व के हर क्षेत्र में प्रवास होता रहा है और ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में जलवायु परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाले विभिन्न मानव प्रजातियां वहां से स्थानांतरित होकर विश्व विभिन्न भागों में पहुंच गई और इसके फलस्वरूप समस्त संसार में मानव बसाव हो गया। मनुष्य जिस स्थान को को छोड़ता है वहां की संस्कृति, रीति–रिवाज, तकनीकी कौशल, ज्ञान आदि को आपने साथ जाता है नूतन स्थानों पर इसका प्रसार करता है। ठीक उसी प्रकार नये स्थान की संस्कृति से प्रभावित होता है वहां की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

मजदूर समय विशेष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। कृषि में वर्ष भर कार्य उपलब्ध नहीं होता केवल कुछ समय ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जब कृषि कार्यों में मजदूरों की आवश्यकता होती है तो विभिन्न भागों से कृषि श्रमिक उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रवास करते हैं। कृषि कार्य समाप्त हो जाने पर वे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं।

मानव विकास सूचकांक (HDI) एक संयोजित सूचकांक (आँकड़ा) है, जो देशों को वहाँ के 'मानव विकास' के आधार पर स्थान देता है (रैंक या क्रम प्रदान करता है) तथा विकसित (अत्यधिक विकसित), विकासशील (मध्य विकसित), तथा अविकसित (कम विकसित) देशों को पृथक करता है। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय-GNI (जीवन स्तर के एक प्रतीक के रूप में) से संबंधित आँकड़ों से बनाया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र की सहायता से निर्धारित किया जाता है।

3.7 मुख्य शब्दावली

- **संघटक** : संरचना करने वाले कारक।
- **प्रवासन** : अन्य स्थान पर जाकर बसना।
- **अपरिवर्तनशील** : जिसमें कोई बदलाव नहीं आए।
- **आबादी** : जनसंख्या।
- **कृत्रिमता** : बनावटीपन।

- **व्यक्तिवादिता** : मात्र स्वयं के हित तक सीमित।
- **लैंगिक** : लिंग (स्त्री–पुरुष) से संबंधित।

टिप्पणी

3.8 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. जनसांख्यिकीय भिन्नता के निर्धारक क्या हैं?
2. उत्पादक आयु समूह से क्या आशय है?
3. नगरीकरण किसे कहते हैं?
4. जनसंख्या प्रवास का क्या तात्पर्य है?
5. मृत्युदर विस्थापन से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या संरचना के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए।
2. भारतीय जनसंख्या की संरचना में 'जनसंख्या प्रवास, जन्मदर एवं मृत्युदर का मापन' का विश्लेषण कीजिए।
3. जनसंख्या गतिकी से क्या आशय है? भारत की जनसंख्या गतिकी पर प्रकाश डालिए।
4. भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का रेखांकन कीजिए।
5. 'सामाजिक–आर्थिक विकास तथा जनसंख्या स्तर' पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए।

3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

Census of India. 1991 : A state Profile.

Clarke, John L 1973 : Population Geography, Pergamon Press, Oxford.

Mamona, C.B. 1981 : India's populations Problem, Kitab mahal N-Delhi.

United nations 1974 : Methods for projections and Urban and Rural Populations No. VIII, New York.

King, Leslie. 1986 : Central place Theory, Saga Punlications New Delhi.

Nangia, Sudesh. 1976: Delhi Metropolitan Region. K.B. Publications New Delhi.

Ramchandran. R. 1992 : Urbanisation and Urban Systems in India, Oxford University Press, N. Delhi.

Singh. R.L. and Kashi nath singh (editor) 1975 : Readings in Rural settlement Geography, National Geographic society of India.

इकाई 4 मानवीय अधिवास : उद्भव, आकार तथा अभिवृद्धि

टिप्पणी

संरचना

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 अधिवास बस्तियों के उद्भव–विकास की सैद्धांतिकता
  4.2.1 मानव अधिवास बस्तियों के आकार
  4.2.2 अधिवास निरूपक निर्धारक
4.3 आकार और वृद्धि में स्थानिक और सामाजिक प्रवृत्तियां
  4.3.1 अधिवासों के विविध स्वरूप
  4.3.2 सैद्धांतिक मॉडल और अनुभवजन्य निष्कर्ष
  4.3.3 विश्व जनसंख्या वृद्धि : रुझान एवं प्रवृत्तियां
4.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
4.5 सारांश
4.6 मुख्य शब्दावली
4.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.8 सहायक पाठ्य सामग्री

4.0 परिचय

मानव निवास की मूल इकाई घर है। यह एकसाधारण झोंपड़ी, आधुनिक फ्लैट या एक भव्य महल हो सकता है। बस्तियों के संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहे जाते हैं। मनुष्य अपने रहने के लिए कुछ भूमि के टुकड़े पर अपना स्वामित्व स्थापित करता है और मकान अथवा भवन निर्माण करता है। बस्ती की प्रक्रिया में दो प्रमुख बातें होती हैं– 1 लोगों का समूह, 2 संसाधनों के आधार पर भूमि का आवंटन।

बस्तियों के अनेक स्वरूप पाए जाते हैं। आकार के आधार पर एक बस्ती परिसर, पल्ली से लेकर गांव, खेड़ा, कस्बा, नगर, महानगर कुछ भी हो सकती है। बस्ती मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है– ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ये दोनों बस्तियां जनसंख्या, आकार, व्यवसाय की दृष्टि से एक–दूसरे से अलग होती है।

इस इकाई में हम अधिवासीय बस्तियों के उदभव–विकास की सैद्धांतिकता, आकार एवं वृद्धि में स्थानिक–सामाजिक प्रवित्तियों तथा अधिवासों के विविध स्वरूपों का अध्ययन करेंगे।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- अधिवास वस्तियों के उद्भव–विकास की सैद्धांतिकता को समझ पाएंगे;
- अधिवासों के विविध स्वरूपों से अवगत हो पाएंगे;
- विश्व जनसंख्या वृद्धि संबंधी रुझान एवं प्रवृत्तियों का विवेचन कर पाएंगे।

4.2 अधिवास बस्तियों के उद्‌भव–विकास की सैद्धांतिकता

टिप्पणी

एक बस्ती से एक महानगर के विकास को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया मॉडल बस्तियों के विकास का पता लगाता है। एक गांव को घरों के एक छोटे समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्रायः सजातीय लोग रहते हैं जिनका एकमात्र व्यवसाय प्राथमिक संसाधन से संबंधित उपयोग जैसे कृषि, मछली पकड़ना, खनन, आखेट आदि होता है। एक महानगर मानव अधिवास का अंतिम अग्रिम रूप है जहाँ मनुष्य नवीनतम तकनीकी का लाभ उठाकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इन दो विकास की चरम सीमाओं के बीच, हम वृद्धि के कई चरण पा सकते हैं। इस प्रकार क्रमिक विकास की अवधारणा डेविस के 'परिदृश्य विकास ' सिद्धांत से मिलती है।

यह संभव है कि डेविस के मॉडल की तरह, अधिवास विकास में भी गिरावट और अन्त में पुर्नयौवन हो सकता है। पुरातत्वविदों का दावा है कि ट्रॉय शहर की खुदाई में पता चला की इस शहर का विकास 9 बार हुआ है। डॉर्पफील्ड ने नौ सिद्धांत स्तरों के अनुक्रम की पहचान की, जो नौ अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके दौरान घरों का निर्माण किया गया, कब्जा किया गया और अंततः नष्ट कर दिया गया। हिंदू पौराणिक कथाओं में 'आडवा' की राजधानी द्वारका के उत्थान और पतन का वर्णन है। विकासवादी प्रक्रिया कई पहलुओं में परिवर्तन लाती है, ये हैं आकारिकी और जनसंख्या व समाज। आकारिकी का परिणाम है– क्षेत्र विस्तार में भूमि उपयोग का पुनर्गठन और वास्तु परिवर्तन। बढ़ती जनसंख्या के साथ सजातीय समूह खुद को एक बहु–सांस्कृतिक समूह में बदल देता है जिसकी प्राथमिक पहचान सिर्फ शहर से होती है। यह मूल सामाजिक संरचना को बदल देता है। जनसंख्या में वृद्धि वहाँ पाए जाने वाले व्यवसाय की संभावनाओं का परिणाम है।

इसके लिए प्रौद्योगिकी और सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण है। विकास के हर चरण के साथ अधिवास अधिक लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। साथ ही अधिक लोग और अधिक नौकरियों के कारण उपलब्ध सेवाओं की संख्या और मानक भी बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार अधिवास जिसमें कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, के साथ बढ़ने लगता है तो औषधालय और सामान्य अस्पताल भी उभरते हैं, और अंत में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र तक विकसित हो सकते हैं।

यदि किसी क्षेत्र की बस्तियों को कुल प्रणाली का घटक माना जाता है तो यह स्पष्ट है कि एक बिंदु पर विकास बिना किसी वृद्धि के जुड़ा होगा या दूसरे में गिरावट से यह संभावना है कि बस्तियों के समूह में से केवल एक ही सबसे जटिल अवस्था में विकसित होगा, जबकि अन्य सभी कुछ हद तक विकास के पहले स्तरों पर बने रहते हैं। हालाँकि, यह सब शायद अति–सरलीकृत है। जरूरी नहीं की बदलाव अनिवार्य रूप से यूनिडायरेक्शनल हो, कभी–कभी जनसँख्या वृद्धि के स्थान पर जनसंख्या घट भी सकती है।

टिप्पणी

अधिवासीय बस्तियों के विकास का एक अन्य सिद्धांत

'ग्रामीण से शहरी परिवर्तन का मॉडल' की वैधता पर संदेह किया जाता है। यदि शहरीकरण की व्याख्या सांस्कृतिक के रूप में की जाती है,तो शहरों की उत्पत्ति को केवल क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। शहर हमेशा मौजूदा गांवों से विकसित नहीं होते हैं। केवल सीमित क्षेत्रों में बसे ग्रामीण कृषि से नगरों का उदय हुआ; यह एकमात्र सत्य नहीं है। कई नगर कहीं और पहले से ही शहरीकृत समाजों के प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव के उत्पाद थे। शहरीकृत क्षेत्र से निकलने वाले किसी प्रकार के प्रभाव वाले समाजों में पहले से ही पूर्वनिर्धारित परिस्थितियों वाले समाज में उपजे परिवर्तन से शहरों का विकास हुआ (कार्टर, 1983)।

नदी के किनारे तीन गांवों के स्थल पर कोलकाता का विकास, विकास की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुआ। यह क्षेत्र विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक अंग्रेजी व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया।

इस प्रोत्साहन के बिना इस शहर के आज की तरह महानगर बनने की संभावना बहुत कम थी। किसी भी बस्ती के विकास का अध्ययन शहरी चरण में ग्रामीण चरण की बजाय आसान है। दूसरी ओर ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति और विकास को ट्रेस करना अधिक मुश्किल है। राजस्व रिकॉर्ड से अधिनिवासन और भू–उपयोग बदलने के क्रम को प्रकट किया जा सकता है। लेकिन सामाजिक, ऐतिहासिक और रूपात्मक परिवर्तनों को स्थानीय किंवदंतियाँ, लोककथाएँ और स्थान के नामों के अध्ययन से अधिक समझा जा सकता है। एस. सेन और जे. सेन, 1989 प्रकाशित और अप्रकाशित राजस्व अभिलेखों, मौखिक इतिहास और स्थान के नामों का अर्थ आदि स्रोत का उपयोग कर बारह गांवों का विस्तृत अध्ययन किया। एक बस्ती के विकास का अध्ययन अलगाव (Isolation) नहीं किया जा सकता है। अधिवास अपने पर्यावरण और इसके आसपास की बस्तियों के साथ अंतक्रिया के माध्यम से बढ़ता या घटता है। बंगाल के अन्य शहरों की भांति कलकत्ता के विकास का इतिहास भी जनसंख्या और क्षय का इतिहास है। इस महानगर में सेवाओं की सघनता अन्य केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों के ठहराव या मंदता के परिणामस्वरूप है। ऊपर से पिछली दो शताब्दियों में यहां बसावट का परिदृश्य संतुलित, पदानुक्रमित संरचना से एक प्राइमेट सिटी मॉडल के लिए बदल गया है। इसलिए अधिवास और अधिवास प्रणाली का उदय तब होता है जब अलग–अलग ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं। एक पूरे क्षेत्र के विश्लेषण के उचित अध्ययन के लिए विस्तृत व सटीक जानकारी के संग्रह की आवश्यकता होती है।

4.2.1 मानव अधिवास बस्तियों के आकार

ग्रामीण और शहरीय दो तरह के मानव अधिवास होते हैं। दोनों तरह की बस्तियों के आकार में अंतर होता है।

1. ग्रामीण बस्तियां विरल रूप से अवस्थित होती हैं।
2. ग्रामीण बस्तियों में कृषि या अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों की अधिकता होती है।

टिप्पणी

3. ग्रामीण जनसंख्या कम गतिशील होती हैं इसीलिए सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं।

4. नागरिक अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करते हैं।

नगरीय बस्ती

1. नगरीय बस्तियों की संख्या कम और आकार में बड़ी होती हैं।
2. नगरीय बस्तियों की जनसंख्या द्वितीय व तृतीय क्रियाकलापों में विशिष्टता रखती है।
3. नगरीय क्षेत्रों में जीवन जटिल व तीव्र होता और सामाजिक संबंध भी औपचारिक व व्यक्तिगत होते हैं।
4. नगरीय बस्तियाँ विनिर्माण प्रक्रियाओं और विभिन्न प्रकार की सीमाओं पर निर्भर करती हैं।

अधिवास आकार

बसावट के आकार को उसके क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। एक बड़े क्षेत्र के आकार की बस्ती क्षेत्र में जरूरी नहीं कि एक बड़ी आबादी हो। बस्ती के आकार को जनसंख्या के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, न कि केवल इसके क्षेत्र की सीमा के संदर्भ में। बस्ती की वृद्धि से तात्पर्य क्षेत्रीय विस्तार से नहीं अपितु जनसंख्या के अधिक घनत्व से है।

एक गाँव का जनसंख्या घनत्व भूमि की वहन क्षमता से संबंधित होता है। आम तौर पर जहां भूमि समतल और कृषि दृष्टि से उपजाऊ होती है वहां गाँव बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए चीन की नदी घाटियों और भारत की नदी घाटियों में बसी बस्ती की तुलना में उबड़–खाबड़ इलाकों में पाई जाने वाली बस्तियों की संख्या ज्यादा होती है। भारत में, गांव के आकार में क्षेत्रीय भिन्नता अधिक पाई जाती है।

हिमाचल क्षेत्र में एक गांव की जनसंख्या 208 है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है।

बस्ती की श्रेणियां निम्नांकित हैं:–

(i) छोटे गाँव की जनसंख्या (500 से कम)

(ii) मध्यम गांव की जनसंख्या (500–999)

(iii) बड़े गांव की जनसंख्या (1000–1999)

(iv) अधिक बड़े गांव (2000–4999)

(v) बहुत बड़े गाँव (5000 और उससे अधिक)

कुछ अपवादों को छोड़कर, सभी जिलों में आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है विशेष रूप से मध्यम और बड़ी श्रेणियों के आकार में। इंदौर और पश्चिम और पूर्वी

निमाड़ में बहुत बड़े गांव स्थापित हो गए है। यह ग्रामीण संरचना में बदलाव को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास और परिवहन सुविधाओं का विकास है।

शहरी बस्तियों का आकार अधिक जटिल कारणों से उत्पन्न होता है। किसी बस्ती को शहरी कहने के लिए आवश्यक न्यूनतम आकार, एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500 व्यक्ति है, जबकि यह डेनमार्क और स्वीडन में 250 व्यक्ति है। भारत में आवश्यक जनसंख्या 5000 है, पर कुछ खास शर्तों के अन्तर्गत। शहरी केंद्रों की जनसंख्या वृद्धि अन्य बातों के अलावा शहर के कार्य पर निर्भर करती है। आज सबसे बड़े मेगा शहर जिनकी जनसंख्या पाँच मिलियन से अधिक है वे विश्व के प्रमुख व्यवसाय और वित्तीय केंद्र हैं।

4.2.2 अधिवास निरूपक निर्धारक

आकृति विज्ञान में गांव की सघन बस्ती के विकास के लिए न्यूक्लिएशन को जिम्मेदार माना गया है। अब,सामाजिक–स्थानिक संरचना के सूक्ष्म–स्तरीय विवरण को समझने के लिए हैमलेटाइजेशन का विश्लेषण किया जाता है।

जनसंख्या का दबाव जंगलों और चरागाहों का सीमांत क्षेत्रों में होने से पशुपालक जाति को सघन अधिवास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक नया हैमलेट केंद्र विकसित हुआ। ऐसा समूहन, विशुद्ध रूप से जाति (अहीरों) पर ही आधारित होकर उत्तर पश्चिम में हुआ। पूर्व समूह, मुख्य कबीले के एक सदस्य के आसपास बसा रहा तो इस वंशज को पुरवा के रूप में नामित किया गया जिसका अर्थ एक गांव की दूसरी बस्ती है।

बाद की आबादी को एक छोटे से किनारे पर बसाया गया। इस चरण के दौरान लगातार सूखे की स्थिति के कारण फसल बर्बाद हो गई। राजपूत (खेत मजदूरों पर निर्भर) राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे, और बनारस राज्य के अधिकारियों को कुछ बकाया भुगतान पर उच्च कुल पदानुक्रम के एक राजपूत द्वारा फिर से भूखंडों पर कब्जा कर लिया गया था। इस प्रकार, एक अलग छोटी इकाई, लगभग तीसरी केंद्रीय इकाई के समीप, समय के साथ तीन आवासों के साथ बढ़ी।

ब्रिटिश शासन के दौरान, परिवहन सुविधाओं में सुधार हुआ और जनसंख्या के दबाव ने आबादी में बसने वालों को शहरों में रोजगार तलाशने के लिए मजबूर किया। कुछ दूधवालों ने, दूसरे लोगों के साथ, कलकत्ता में रोजगार प्राप्त किया और कुछ पैसे कमाने के बाद राजपूतों से कुछ भूखंड खरीदे (जिन्होंने अपनी बचत से अधिक खर्च किया)। अजमेर नामक एक व्यक्ति द्वारा नवनिर्मित एक कुएं के चारों ओर पांचवें स्थान पर कब्जा कर लिया गया। इस बस्ती को अजमेर का इनारा कहा गया।

दूधवाले, जो बाहर पैसा कमा सकते थे, उन्होंने खुद को अपने सामूहिक परिवार से अलग कर लिया और यहां अपने भूखंडों पर बस गए। सातवें चरण (1950 के बाद) के दौरान, आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव सामाजिक, स्थानिक बिखराव पर स्पष्ट दिखाई दिए। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ने कई भूमिहीन लोगों को ग्राम समाज की भूमि (सामान्य भूमि) प्रदान की। चरण 3 की केंद्रीय इकाई के दक्षिण में सड़क के

टिप्पणी

किनारे (ज्यादातर नोनिया और चमार) बस गए। बिजनेस क्लास के तहत किसी ने स्थानीय बाजार में फ्राइड राइस (लाई) की बिक्री शुरू की, और कुछ धोबी भीड़ के कारण पुरानी साइट को छोड़कर मुख्य स्थल के पश्चिम में सड़क के किनारे बस गए। कुछ अन्य जाति के लोग भी सड़क किनारे जमीन खरीद कर विभिन्न प्रकार की दुकाने खोलकर बाजार के रूप में विकसित किये कुछ मामलों में दुकान–सह–निवास भी स्थापित हुए। चमार (हरिजन) अनुसूचित जाति ने भी अम्बेडकरनगर के नाम पर उत्तर–पूर्वी जंगल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

जाति और अलगाव

हम आकृति विज्ञान में जाति और उप–जाति के अनुसार क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं, तो पाते हैं कि निकट से संबंधित रिश्तेदारों के घर पास–पास होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक रूप से विविध प्रकार के घनत्व की समूहवार सीमाएं भी होती हैं।

आधार या छत या बस्तियों के विभिन्न तत्वों जैसे पानी के स्रोत, आदि खेती पर आधारित होते हैं। विभिन्न कारक एक समूह को एक खंड के रूप में विकसित करने में सहायक होते हैं। ये हैं उम्र, सेक्स, पैदाइशी बनाम वैवाहिक, अभी पैदा हुआ बनाम शादीशुदा और अंदरूनी बनाम बाहरी। कुछ सामुदायिक संरचनाएं पुरुषों और महिलाओं को अलग–अलग आवंटित की जाती हैं। अलग–अलग पैमाने, विनिर्देश, उपचार और तत्व जैसे खिड़कियां, आदि।

एक ही संरचना में अलग–अलग तत्व, स्थान, फर्नीचर आदि मुख्य रूप से प्रत्येक लिंग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। शवदाहस्थल, शयनगृह, नृत्य मैदान शो आदि एक अन्य प्रकार का लिंग अलगाव दर्शाते हैं। विभिन्न जातियाँ के बीच आवासों का पृथक्करण, विभिन्न भागों में उनकी गतिशीलता विशेष रूप से जल स्रोतों के लिए, समारोहों के दौरान सामुदायिक भवन और स्थान (चौपाल)– दावतें और त्यौहार या यहां तक कि उपवास भी जाति–धर्म के अनुसार सामाजिक अलगाव को दर्शाते हैं। सामाजिक स्थिति, पदानुक्रम ऐसे आवासों की स्थिति में परिलक्षित होता है।

सांस्कृतिक रूप से मानव और मवेशियों के रहने की संरचना का विविध स्वरूप विभिन्न रूपों में प्रकट होता है।

कृषक आवास और खेत

किसान के आवास का स्थान कार्यात्मक रूप से कृषि योग्य खेतों, चरागाहों, जल स्थलों और जंगलों से संबंधित माना जाता है। कुछ अपवादों को छोड़ कर यह माना जाता है कि किसान एक कॉम्पैक्ट आवास में एक जगह पर कब्जा कर लेता है। उसके खेत बीच में परस्पर जुड़ी वस्तुओं की संख्या से अलग हो जाते हैं। किसानों के अन्य आवास हो सकते हैं– गाँव के रास्ते, जल निकाय, बंजर भूमि, खेतों के बगीचे। किसान का आवास केवल विश्राम स्थल ही नहीं वरन् अनेक विविधताओं का केंद्र होता है।अनेक गतिविधियां बहुत सामान्य रूप से यहाँ घटित होती हैं।

टिप्पणी

किसान खुली हवा में सांस लेता है, सोता है, चलता है, गपशप करता है, झगड़ा करता है और अपने आवास में प्रार्थना करता है। जीवन के प्रत्येक कदम पर, वह ज्यादातर सुई और कुदाल सरीखे सभी उपकरणों को एक पारस्परिक सहयोगी के रूप में पाता है।

किसान का सामाजिक स्थान इस रूप में है :

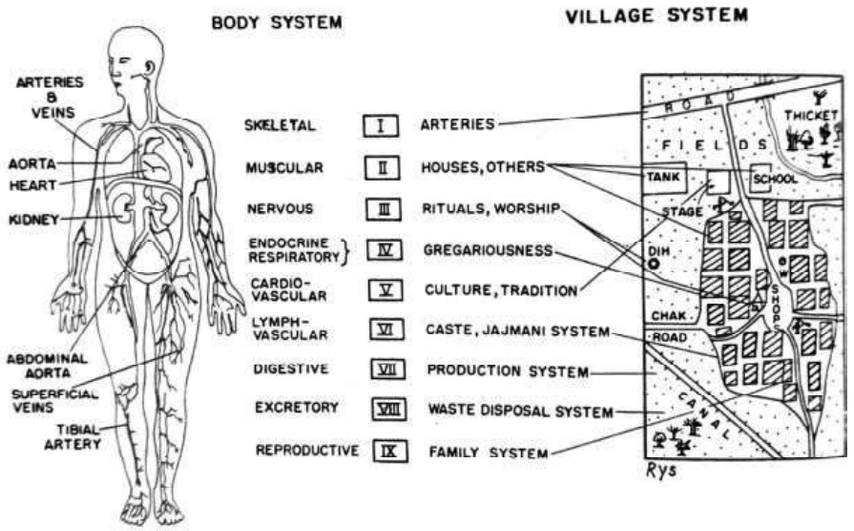

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बस्ती में विस्तार विभिन्न जातियों के सदस्यों, मुख्य रूप से खेती करने वाली जातियों, पशुपालकों द्वारा प्रमुखता से होता है। इसके बाद सेवावर्ग द्वारा। बाद के चरण में, वन को साफ करने से लेकर फसलों, चरागाहों और लकड़ियों के लिए भूमि का स्वामित्व प्राप्त करके बस्ती की सघन रूपात्मक संरचना चौड़ीकरण की प्रक्रिया से सम्बंधित है।

मिट्टी की उर्वरता में थोड़ी भिन्नता के कारण संबंधित भूमि के साथ एक निश्चित आकार की सममित रूप से दूरी वाली रिहायशी बस्तियां समानांतर चल रही होती हैं।

यह मानते हुए कि किसान नमूना गांव बसाने में एक केंद्रीय स्थान रखता है, स्थापना में दूरी को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:–

मालवा क्षेत्र में गांव के बीच दूरी

S.No.	Village Name	Distance in Metres
1	धारार	1,272
2	डाटाना	2,516
3	भूगोर	2,135
4	उदयगीर	1,376
5	साँची	2,387
6	धामनोद	1,108
7	गुलझारा	1,209

टिप्पणी

8	खुर्दा	1723
9	पिपलोड	2730
10	मटकूली	1378
11	अजनाड	2127
12	बामनखेफी	2714
13	भीलखेड़ी	2109
14	मानपुर	2737

इंट्रा–विलेज स्पेसिंग

यहां हम मालवा क्षेत्र और उत्तरी मैदान से उदाहरण ले सकते हैं। रिक्ति की गणना चार मान्यताओं और एक सरल सूत्र के साथ की गई है।

यह मान लिया है किः (ए) किसी भी क्षेत्रीय इकाई में हेक्सागोनल आकार गांव की जमीन में, समान आकार के होते हैं, (बी) गांव की पूरी आबादी क्षेत्र के केंद्र में स्थित सघन बस्ती में रहती है, (सी) गांव के हर भूखंड पर पहुंचा जा सकता है, (डी) निवासी अपने गांव की सीमा के बाहर किसी भी भूखंड पर खेती नहीं करते हैं।

इंट्रा विलेज डिस्टेंस का फार्मूला–

$$Vfd = 05373\sqrt{A/N}$$

जहाँ Vfd = सीमा–दूरी के खेत से निवास करने वाला गाँव

A = इकाई का क्षेत्रफल

N = बस्तियों की संख्या।

कृषि–निवास दूरी 1,108 से 2,737 मीटर तक भिन्न होती है। यह भिन्नता जंगलों में पड़े गांवों के आकार के अनुसार सागर, गुना जिलों और माही बेसिन के ऊबड़–खाबड़ इलाकों में पाई जाती है।

भदोही जिले (उत्तर प्रदेश) में औसत अंतर अर्थात गांव दूरी का स्तर 538 मीटर (0.538 किमी) है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी 1120 मीटर (1.12 किमी)। तत्संदर्भित डेटा को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(1) बहुत कम दूरी (<500 मीटर) : यह 32 न्यायपंचायत के 501 गांवों में पाया जाता है और कम से कम 32.96% क्षेत्र को कवर करता है। विविध पर्वतमाला,छतमी में 372 मीटर से, वारी में 498 मीटर तक यह क्षेत्र एक संकरी पट्टी के रूप मध्य उत्तरी और दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। उपजाऊ मिट्टी व अच्छी तरह से संपन्न विकसित बाजार केंद्र इसमें स्थित हैं।

(2) निम्न (500–600 मीटर) : ऐसी न्यायपंचायतें 36.15% क्षेत्र में फैली हुई हैं। मध्य भाग में उपजाऊ मिट्टी और परिवहन सुविधा का मुख्य आकर्षण है। दूरी तिलंगा में 509 मीटर, औराई में 550 मीटर, बीसापुर में 595 मीटर तक पाई जाती है।

टिप्पणी

(3) मध्यम (600–700 मीटर) : हालांकि इस समूह के न्यायपंचायत क्षेत्र पूरे तहसील में बिखरे हुए हैं, फिर भी उत्तर पश्चिमी भाग मुख्य वितरण प्रदर्शित करता है। यह कुल के 12.05% के क्षेत्र के साथ 92 गांवों को कवर करता है। दूरी कुरौना में 600 मीटर, रामनगर में 621 मीटर, दरवासी में 662 मीटर और 690 मीटर दारुनाहा तक मिलती है। ये औसत उपजाऊ मिट्टी के साथ ताहिल के उसर और ताल क्षेत्र हैं।

(4) उच्च (700–800 मीटर) : इस श्रेणी के 57 गांव बाढ़ के प्रभाव में फैले खादर और ताल क्षेत्र हैं। यह 10.30% क्षेत्र को कवर करता है। दूरी जाठी 704 मीटर से पट्टी बेजान में 784 मी तक पाई जाती है।

(5) बहुत ऊँचा (800 मीटर और उससे अधिक) : इस श्रेणी में 36 गाँव शामिल हैं। यह 8.09% क्षेत्रफल में वारीपुर, डीग, इब्राहिमपुर और अजयपुर न्यायपंचायत में फैला हुआ है। बाढ़ की स्थिति और उसर भूमि सीमांत आदि कारक अधिक दूरी सीमा तय करते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

1. एक हजार से कम किंतु 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव क्या कहलाते हैं?
   (क) छोटे गांव (ख) मध्यम गांव
   (ग) बड़े गांव (घ) बहुत बड़े गांव
2. इंट्रा विलेज डिस्टेंस के फार्मूले ($Vfd = 05373\sqrt{A/N}$) में N का अर्थ क्या है?
   (क) सीमा–दूरी के खेत से निवास करने वाला गांव
   (ख) इकाई का क्षेत्रफल
   (ग) बस्तियों की संख्या
   (घ) कृषि योग्य भूमि

4.3 आकार और वृद्धि में स्थानिक और सामाजिक प्रवृत्तियां

कोई भी बस्ती चाहे वह बहु–केंद्रक या एक–केंद्रक हो, सभी के अपने सामाजिक–स्थानिक और कार्य–आयाम होते हैं। इस प्रकार के नाभिक, द्वि–नाभिक या बहु–नाभिक मॉडल की बस्तियों की कल्पना की जाती है। चूंकि मानव बसावट एक सांस्कृतिक घटना है, इसलिए विभिन्न स्थलों पर किसी भी बस्ती के आकारिक विकास में सांस्कृतिक विशेषताएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई क्षेत्रों के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त अनुभव, क्षेत्र में बस्तियों के साथ–साथ ग्रंथों से पता चलता है कि प्राथमिक मूल संस्थापक सभी प्रकार की बस्तियों में केन्द्रक बन जाते हैं। संस्थापक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किसी क्षेत्र या भूमि पर कब्जा करने के लिए आ सकता है :–

टिप्पणी

(अ) एकल प्रमुख कबीले और रिश्तेदारी सदस्य समूह के रूप में अपने सहयोगियों के साथ।

(ब) सहयोगियों के साथ कबीले और बहु–रिश्तेदार सदस्य।

(स) अपने सहयोगियों के साथ बहु–जाति और कबीले–रिश्तेदार सदस्य।

(द) अद्वितीय जनजातियां नस्लीय विशेषताओं वाले एकल–कबीले।

बस्तियों के ऐतिहासिक कब्जे के लिए ये चार वैकल्पिक रणनीतियाँ, विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन में पाई जाती हैं। बस्तियों में रूपात्मक संरचना के विकास के विभिन्न चरण या उदभव के चरण होते हैं। बस्ती की सघनता, पुरवाकरण और बहु केंद्रक होना समय की देन है, जो किसी संस्कृति क्षेत्र और जातीय समूह के लिए सबसे उपयुक्त होती है।

(अ) पहले उदाहरण में, एक बस्ती जिसमें संस्थापक के रूप में एक प्रमुख कबीला होता है, स्थल के मुख्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और उसके परिवार के सदस्य आसपास बगल में रहते हैं। सहयोगी जैसे पुजारी, सेवा वर्ग, मजदूरों को समय और क्षेत्र–विशेष की आवश्यकता अनुसार जैसे रक्षा, दिशा और धार्मिक–अनुष्ठान मानदंड के अनुसार जगह आवंटित होती हैं। यह वही बस्ती, यदि आगे बस्तीकरण का अनुभव करती है। मध्यकालीन अवधि के दौरान समग्र उत्तर भारत में यह सामान्य विशेषता थी। इसने राजपूत वंश की क्षेत्रीय संगठन विशेषता को जन्म दिया है। अन्य जातियों के वर्चस्व वाले गांवों के भूमिहार, कुर्मी, सचान, कटियार, कुशवाहा, त्यागी, पटेल, ब्राह्मण, मुस्लिम, जाट और गुज्जर के क्षेत्रीय वितरण में भी यही विशेषता पाई जाती है।

(ब) एकल कबीले और बहु–रिश्तेदार सदस्य भी उनकी सुविधा के अनुसार ग्राम भूमि क्षेत्र का बंटवारा करके कई समूहों में बंट जाते हैं। कई ब्राह्मण और राजपूत गाँव नदियों के उपजाऊ मैदानों में संयुक्त रूप से एक साथ फले–फूले, चाहे वह मैदानी इलाकों में हो या पठारों पर।

आवंटित स्थान पर इकट्ठे हुए उनके सहयोगी स्पष्ट सामाजिक–स्थानिक सरंचना में सहायक बनते हैं। जैसे की धारार और दत्ताना, भुगोर (मालवा क्षेत्र), भोगी, भरैची और नटवा (वाराणसी) इनके कब्जे के कारण संरचना के विकास को प्रकट करते हैं। ये लोग अपने सहयोगियों के साथ एक सघन बस्ती या एक केंद्रक में बस गए। इस तरह की बस्तियां, बाद में सहयोगियों द्वारा, मूल बसावकर्ता द्वारा या क्षेत्रीय जागीरदार के माध्यम से प्राप्त अनुदान से जमीन खरीद कर फैल जाती हैं।

(स) बहु–जाति और कबीले–रिश्तेदारी समूह ने पूर्वी भारत (बिहार)के नदी मैदानों में,मालवा पठार और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के भागों में बड़ी बस्तियां बसाई। यह उन जगहों पर हुआ, जहां विभिन्न जाति के लोगों ने रिश्तेदारी समूहों में; एक गाँव के क्षेत्र पर अपने करीबियों और सहयोगियों के साथ कब्जा कर लिया था। बिहार में नैनी

टिप्पणी

इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ राजपूतों (गौतम, काकण, अमेठी और बैस), और ब्राह्मणों (मिश्रा और तिवारी) उप–जाति समूहों से संबंधित लोगों ने आकृतिय विकास किया। अन्य जाति के लोगों ने क्षेत्रीय विकास के लिए जजमानी प्रणाली का समर्थन किया। समान वृद्धि सारण के मैदान में हुई। मझनपुरा में वृद्धि प्रदर्शित करने वाला एक चित्र दर्शनीय है–

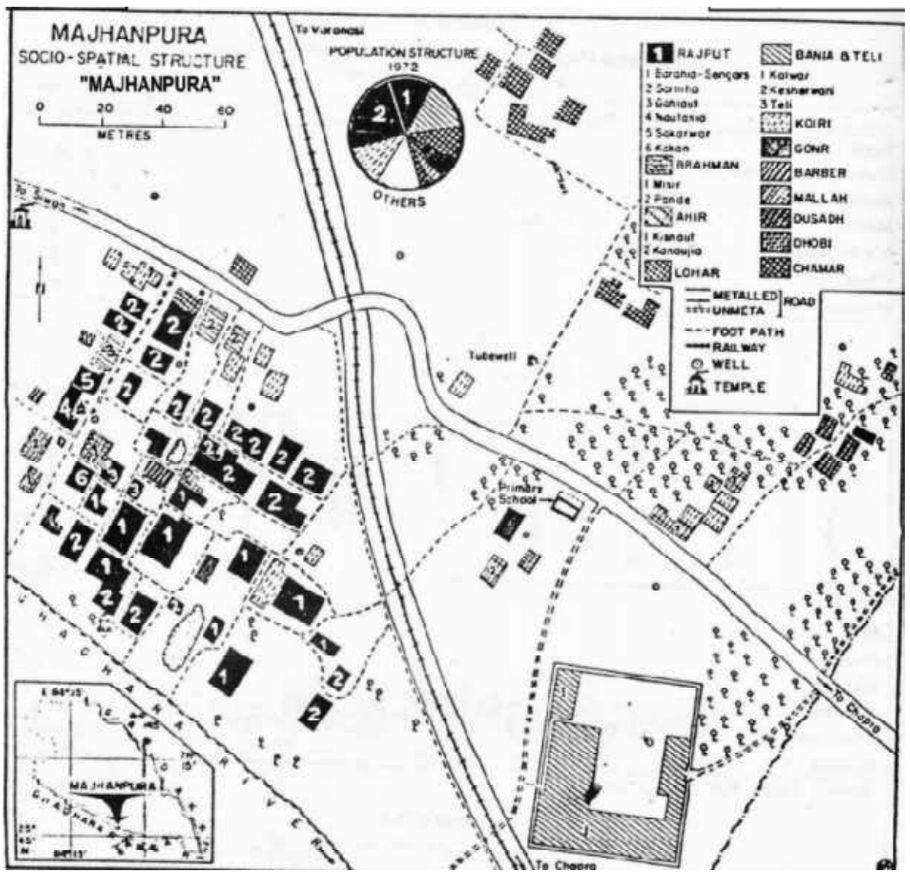

यह संयोजन भूमिहार और राजपूत, कुर्मी और अहीर, राजपूत और ब्राह्मण, जाट और गुर्जर या अन्य प्रसार और फैलाव से हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में यह बहु–नाभिक केंद्र व्यवस्था दिखा सकता है।

(द) एकल–कबीले आदिवासी समूह आकारिकी संबंधित जनजातियों की नस्लीय विशेषताओं के अनुसार विकसित होते हैं। अलग–अलग जगहों पर झोंपड़ियों में रहने वाले रिश्तेदारी समूह अलग–अलग संरचनात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। ऊसर और वन सीमा पर बसी नई बस्तियों के अध्ययन से पता चलता है कि आकारिकी संरचना अभी भी मॉडल में बताये गई शर्तों के आधार पर आ रही है। यह स्पष्ट है, कि बाद में आने वाली बस्तियों के विकास में उद्यमी जो किसी भी जाति से सम्बंधित हों, आकारिकी की संरचना बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम जनकपुर बस्ती को ले सकते हैं जो वन सीमा पर आडव परिवार द्वारा 1951 से शुरू की गई थी और अब, यह एक अच्छी तरह से विकासित लगभग 20 घरों का गांव है।

टिप्पणी

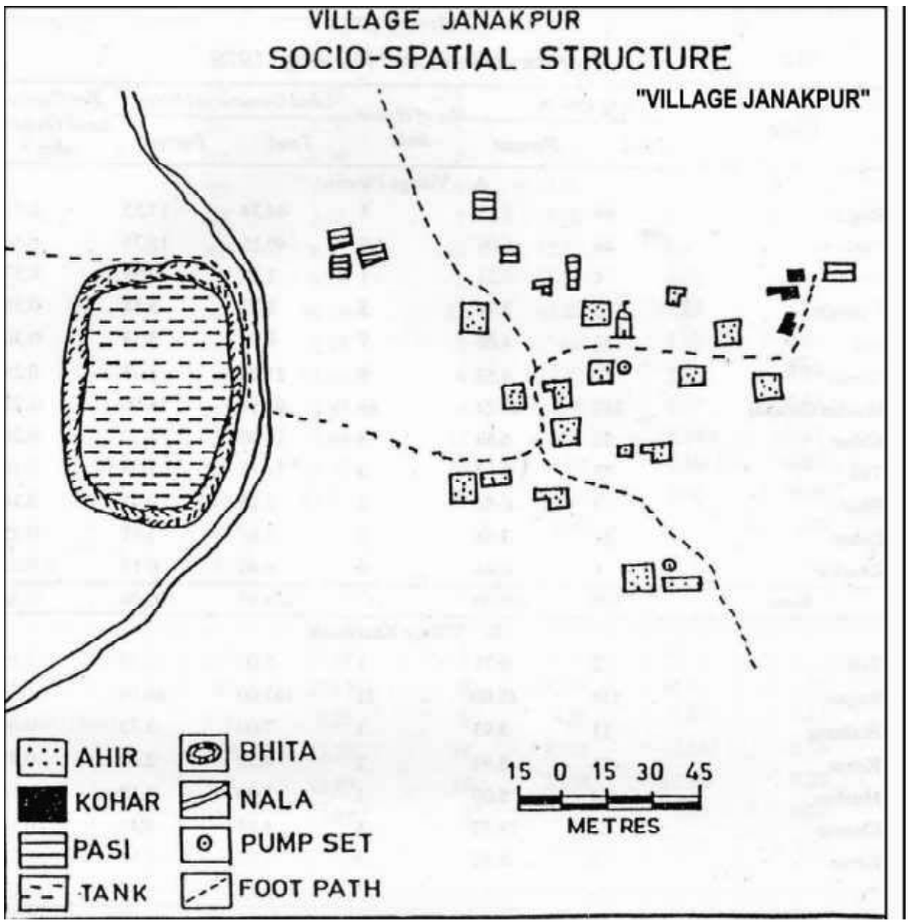

4.3.1 अधिवासों के विविध स्वरूप

1. **प्रकीर्ण या बिखरे ग्रामीण अधिवास** : इन बस्तियों में अलग–अलग बसे हुए घर या कृषि गृह, आवास गृह होते हैं। मकान चाहे पक्के बने हुए हों या झोपड़ी या भव्य इमारतें अगर एक दूसरे से पृथक,बीच में दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि छोड़कर बसे हैं तो प्रकीर्ण अधिवास कहलाते हैं।इस प्रकार के अधिवास एंग्लो अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलते हैं।भारत में भी कुछ स्थानों पर देखने को मिलते हैं।

2. **सघन या पुंजित ग्राम** : इस प्रकार के आवास में घर एक दूसरे से परस्पर सटे हुए बनाए जाते हैं। गांव में कृषक समुदाय के घर होते हैं जिससे चारों और उनके खेत होते हैं। भारत, चीन, जापान के सघन बसे भागों में लोग पुंजित गांव में ही रहते हैं। यूरोप व लेटिन अमेरिका के गांवों में अधिवास का यह सबसे सामान्य रूप है। अफ्रीका व मध्य पूर्व के प्रारंभिक कृषक समुदाय इस प्रकार के गांव में रहते हैं। सघन गाँवों में गलियों का कोई प्लान नहीं होता। फिंच व ट्रिवार्था ने इनको न्यष्टित बस्तियां या सघन बस्तियों के नाम दिए हैं।

टिप्पणी

सघन बस्तियों के आकार के आधार पर कई प्रकार होते हैं। नंगला (Hamleted) सबसे छोटे आकार की बस्ती होती है। कस्बे (ज्वूद) में ग्रामीण सेवा केंद्र भी होते हैं।

3. **अपखंडित अधिवास** : इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास में गांव की सीमा के अंतर्गत ही बसाव बिखरा हुआ मिलता है। अर्थात जहां कोई भी केंद्रीय ग्राम नहीं होता, उसे अपखंडित बसाव कहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां बंगाल के डेल्टा प्रदेश, गंगा, घागरा और ताप्ती नदी के पश्चिम में सरयूपार मैदान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा यमुना मैदान, अंबाला आदि जिले में पाई जाती हैं।

जल की प्राप्ति, भूमि का स्वरूप, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, सुरक्षा, मिट्टी की उत्पादकता, आर्थिक, धार्मिक,सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व अधिवास को प्रभावित करते हैं।

अधिवास प्रतिरूप (Spatial pattern of Settlement)

अधिवास प्रतिरूप से तात्पर्य अधिवासों की आकृति, घनत्व, अंतराल और प्रकीर्ण आदि से है। किसी ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप उसकी आकृति को बताता है। यह उसकी अवस्थिति पर निर्भर करता है।यह अधिवास की आकारिकी (morphology) को बताने वाला प्रमुख अंग है। किसी स्थान की धरातलीय बनावट, जल राशियां, भूमि का ढाल, भूजल तल,दलदलों की उपस्थिति, टीले आदि प्रति–कारक अधिवास की आकृति पर प्रभाव डालते हैं।

1. **रेखीय प्रतिरूप** : इस प्रकार के प्रतिरूप में अधिवास किसी नदी या सड़क के किनारे लंबाकार रूप से बस जाते हैं। ऐसे अधिवासों में मकान के द्वार सड़क या नदी की तरफ खुलते हैं। दोनों किनारों पर बसे हुए मकानों के द्वार आमने–सामने खुलते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप को लंबाकार या रिबन प्रतिरूप भी कहते हैं।
2. **चेकर बोर्ड प्रतिरूप** : मैदानी भागों में कहीं दो मार्गों के संगम स्थल पर जो गांव बस जाते हैं उनकी गलियां और रास्ते मिलकर आयताकार या वर्गाकार पर प्रतिरूप बनाते हैं। गांव का विकास भी छोटी–छोटी गलियों के कारण होता है। फ्रांस, इसराइल, जर्मनी, मलेशिया में नियोजित ग्राम अधिवास इसी प्रतिरूप पर बसाए जाते हैं।
3. **वृत्ताकार प्रतिरूप** : इस प्रकार के अधिवास किसी तालाब, झील या किसी धार्मिक स्थल के चारों ओर बसे होते हैं।इस प्रतिरूप के गांवों में सड़कों का विन्यास भी वृताकार हो जाता है। इस ग्रुप में दो प्रकार के अधिवास आते हैं –
   - **नाभिकीय**– इसका केंद्र खाली होता है। उसके चारों ओर गांव बसा होता है। गांव तालाब, झील, मंदिर आदि के चारों ओर बसा होता है।
   - **नाभिक**– इसमें केंद्र बसा होता है और उसे चारों ओर गांव बसा होता है। केंद्र में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निवास स्थान होता है, जैसे गांव के मुखिया, पुरोहित आदि का।

टिप्पणी

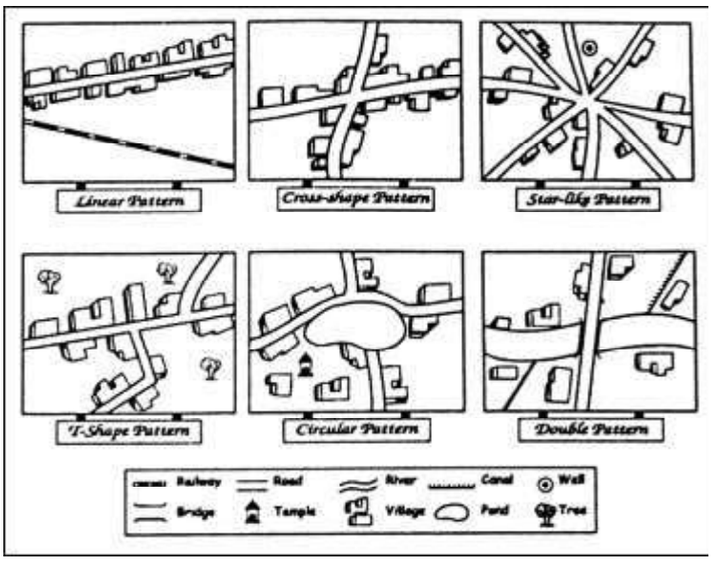

4. **अरीय प्रतिरूप** : अरीय प्रतिरूप में ग्रामीण आदिवासियों में से अनेक दिशाओं से रास्ते गांव के केंद्र में आकर मिलते हैं। इस प्रकार के अधिवास में गांव के मध्य में या तो मुख्य घर होता या कोई सार्वजनिक स्थल होता है। इस प्रकार के अधिवास में रास्तों का सकेंद्रीय विकास होता है। इसे कोववेव पैटर्न भी कहते हैं।

5. **मधुछत्ता प्रतिरूप** : इस प्रकार के प्रतिरूप गुंबदनुमा झोंपड़ी के रूप में झुंड के रूप में पाए जाते हैं। मध्य अफ्रीका के पिग्मी लोग, वैकिंगा झोंपड़िया व खोई सान झोंपड़ियां, प्रशांत महासागर में समोआ द्वीप के गोल घरों समूह वाले ग्रामीण अधिवास, दक्षिण अफ्रीका के जुलू लोग, दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर होड़ा जनजाति के लोग और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों में मछुआ समुदाय के लोग इस प्रकार के अधिवासों में रहते हैं।

6. **तारा प्रतिरूप** : जब कई स्थानों से और कई दिशाओं से कच्ची और पक्की सड़कें आकर मिलती हैं तो वहां के अधिवास का प्रतिरूप तारा की आकृति में होता है। तारा प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास में गलियां व मुख्य मार्ग नाभिक में आकर मिलते हैं।गलियों व मार्गो के सहारे स्थित गृह गांव नाभि स्थल की ओर से सटे हुए मिलते हैं। चीन के यंगतीसीक्यांग, बिहार के मुजफ्फरपुर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तारा प्रतिरूप की बस्तियाँ मिलती हैं।

7. **तीरनुमा प्रतिरूप** : इस प्रकार के अधिवास किसी बड़ी नदी या अंतरिप के तीव्र मोड़ पर बसे होते हैं। सिरे पर मकानों की संख्या अधिक व मार्गो के सहारे मकानों की संख्या कम होती है। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, उड़ीसा में चिल्का झील प्रदेश, केरल में युनत्म नूरा, खंभात की खाड़ी पर कुंडा गोपनाथ, बिहार में बूढ़ी गंडक के मोड़ पर इसी प्रकार के प्रतिरूप के अधिवास मिलते हैं।

8. **पंखा प्रतिरूप** : इस प्रकार के अधिवासों का विकास डेल्टाई प्रदेशों में नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ तटीय भागों में होता है। भारत में ऐसे गांव गोदावरी,कृष्णा, कावेरी, गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं।

टिप्पणी

9. **सीढ़ी प्रतिरूप** : ऐसे प्रतिरूपों का विकास पर्वतों की ढालों पर होता है। पर्वतों पर मकानों का विकास कई स्तरों पर होता है। भारत में ऐसे गांव हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में तथा अमेरिका के रॉकीज और एंडीज पर्वत तथा यूरोप में अल्पस पर्वतों के समीप पाए जाते हैं।

10. **अनाकार प्रतिरूप** : ऐसे अधिवास उबड़ –खाबड़ धरातल, दलदली क्षेत्र या बहुतायत वनीय क्षेत्रों में जहाँ असुरक्षा की भावना होती है, वहां पाए जाते हैं। चीन के दक्षिणी भाग में, भारत और पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों में अनियमित व आनाकार प्रतिरूप की बस्तियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं।

11. **हरित प्रतिरूप** : इस प्रकार के प्रतिरूप के अधिवास इंग्लैंड में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास हरे भरे वृक्षों से घिरे होते हैं।

ग्रामीण अधिवासों की आकारिकी

ग्रामीण अधिवासों की आकारिकी के संबंध में विभिन्न भूगोलवेताओं ने विभिन्न मत दिए हैं। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह के अनुसार ''ग्रामीण बस्तियों की आकारिकी का अर्थ अधिवासों के भू–तलीय नियोजन व उनके मकानों के अध्ययन से है।"

आर. बी. मण्डल के अनुसार ''ग्रामीण बस्तियों की आकारिकी से तात्पर्य है उसकी शारीरिकी से है जो भौतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। यह स्वयं अधिवास के भौतिक स्वरूप व संरचना से स्पष्ट होती है।"

ग्रीक विद्वान सी. ए. डाक्सीयडिस ने ग्रामीण अधिवास की शारीरिकी के चार अंग बताए हैं:–

समांगी भाग – खेत

केंद्रीय भाग – निर्मित क्षेत्र

परिसंचरण भाग – गलियां व सड़कें

विशिष्ट भाग – विद्यालय, मंदिर पंचायत आदि

किसी भी अधिवास के लिए चारों भाग अति महत्वपूर्ण होते हैं। इस अकारिकी में आवासीय, गैर आवासीय, आने–जाने के रास्ते, खेत खलियान आदि आते हैं। गांव का केंद्र भाग सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला भाग होता है। यह सघन रूप से बसा हुआ होता हैं और इस पर भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है।

प्रोफेसर ए.बी. मुखर्जी के अनुसार आकारिकी जनसंख्या, आर्थिक क्रिया व सांस्कृतिक भू दृश्य से संबंधित होती है, जिसमें निवास्य या निवासी की शास्त्रीय–भौगोलिक विशेषता होती है।

ग्रामीण बस्तियों की आकारिकी के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं– मनुष्य व उनके द्वारा बनाए गए संगठन।

ग्राम आकारिकी के विकास की प्रक्रिया

ग्राम आकारिकी, गांव की वृद्धि के साथ–साथ निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में विकसित होती है–

टिप्पणी

1. **शैशवावस्था** : यह प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें सबसे पहले भूमि अधिग्रहण करने वाले अपना आवास बनाते हैं। इस अवस्था में पहले एक वंश के लोग ही बसते हैं।

2. **प्रारूपोत्पति अवस्था** : इस अवस्था में गांव का विस्तार होता है। गांव में नई सड़कें व गलियां अस्तित्व में आ जाती हैं। उनके किनारे भवन बनने लगते हैं और इनके सहारे सेवा प्रदान करने वाली दूसरी जातियों के लोग भी बसने लगते हैं। सड़कों की चौड़ाई ज्यादा नहीं होती है।

3. **आकारजनक अवस्था** : इस अवस्था में गांव की आकारिकी एक निश्चित रूप ग्रहण कर लेती है। इसके अंतर्गत केंद्र से बाहर की ओर घर बनने लगते हैं। इसमें बस्तियों के प्रभावकारी रसूख रखने वाले लोगों को सेवाएं देने वाले लोग बसते हैं। बस्ती के केंद्र में गांव को बसाने वाले लोगों के आवास होते हैं। इन आवासों के चारों ओर सेवा प्रदान करने वाली जातियां जैसे कुम्हार, लोहार, नाई, धोबी, बढ़ई आदि के मकान होते हैं। जैसे जैसे बस्ती का आकार बढ़ता है वैसे ही निम्न वर्ग के लोग बस्ती के उपरांत भाग में बसने लगते हैं। अतः विकास के साथ ग्राम आकारिकी में बदलाव आ जाता है।

4.3.2 सैद्धांतिक मॉडल और अनुभवजन्य निष्कर्ष

आधुनिक शहरों की विशिष्ट विशेषताओं में से एक उनका उच्च स्तर की आंतरिक विशिष्टता है। विभिन्न शहरी कार्यों के लिए निश्चित क्षेत्र होते हैं। शहर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए परिदृश्य और सामाजिक–आर्थिक वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन की दिशा और आसन्न क्षेत्र एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं जो एक बार स्थापित होने के बाद हर शहर में स्थापित हो जाता है। एक शहरी बस्ती का लेआउट शुरू में इसके भौतिक वातावरण से संबंधित हो सकता है। हालाँकि, एक चरण आता है जब रूप और संरचना उत्पादन के तरीके और सामाजिक संरचना जैसे अन्य कारकों द्वारा बड़े पैमाने पर यह निर्धारित किया जाता है। स्थल और उच्चावच आम तौर पर शहर के समग्र आकार को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, कोलकाता, हुगली नदी और दलदल के बीच स्थित है, जबकि लंदन एक संरचनात्मक बेसिन पर केंद्र से रेडियल रूप से विकसित हुआ है।

• परम्परागत सिद्धांत

नगरों की वृद्धि और अकारिकी के संबंध में 1920 के दशक में एरनेस्ट डब्ल्यू वर्गिस ने अपना सकेंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये एक समाजशास्त्री थे और इनका अध्ययन शिकागो पर आधारित था। उनका सिद्धांत सबसे पहले 1923 में 'प्रोसीडिंग्स इन अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ''के 58 वें संस्करण प्रकाशित किया गया। 1925 में The City में एक लेख प्रकाशित हुआ। वर्गिस ने बताया कि किसी शहर का बाहरी विकास उसके केंद्र से बाहर सभी ओर बहुत सी सकेंद्रीय पेटी के रूप में होता है। यह पेटियां नगर की वृद्धि के साथ बाहर की ओर सरकती रहती हैं। नगर अपने केंद्र स्थल के चारों ओर एक क्रमबद्ध सकेंद्रीय वृत्ताकार क्षेत्र में विकसित होता है। उसके अनुसार

टिप्पणी

विकास क्रम में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में अतिक्रमण होता है। केंद्रीय व्यापार केंद्र से बाहर की ओर जाने से सामाजिक बुराइयों का क्रमशः ह्रास होता है। नगर के 5 सकेंद्रीय पेटीयां केंद्र से बाहर की ओर इस प्रकार मिलती हैं:–

1. आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक पेटी (Central business district) : इस पेटी को आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक इसलिए कहा गया है कि यह क्षेत्र नगर के व्यापारिक यातायात, सामाजिक व नगरीय जीवन का केंद्र होता है। शिकागो में केंद्र व्यापार क्षेत्र को लूप और पिट्सबर्ग में गोल्डन टेंपल कहते हैं। फुटकर व्यापार क्षेत्र और फुटकर व्यापार क्षेत्र से बाहर की ओर नगर का वृत्ताकर थोक व्यापार आता है। यहां पर दुकानें, दफ्तर व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। यह CBD क्षेत्र गैर रिहायशी क्षेत्र होता है।

2. संक्रमण पेटी (transition zone) : यह क्षेत्र केंद्रीय व्यापारिक पेटी के चारों ओर फैला होता है। इसमें केंद्रीय व्यापारिक पेटी से आए हुए लोग बस जाते हैं। यह औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है। यहां पर कुछ मलिन बसिया पाई जाती हैं। अमेरिका के नगरों में यह क्षेत्र अप्रवासियों द्वारा बसाया हुआ मिलता है।

3. श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र (Zone of Working Men's Houses) : यह संक्रमण पेटी के के चारों ओर फैला होता है। यहाँ रहने वाले निकट के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं ताकि वे अपने काम पर आसानी से पहुंच सकें। यहाँ मध्यम श्रेणी के लोगों के मकान कम ही मिलते हैं।

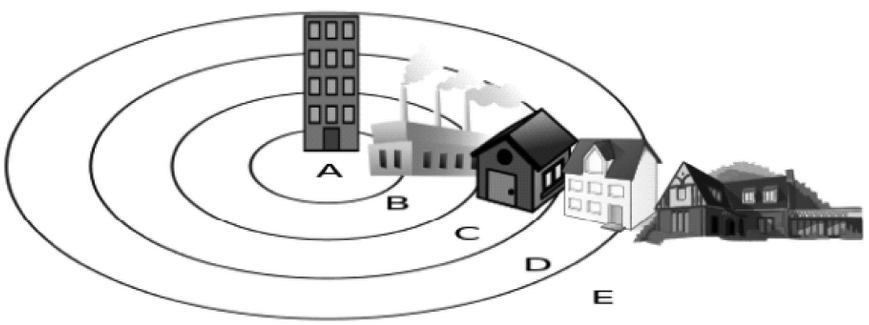

4. श्रेष्ठ रिहायशी मकानों का क्षेत्र (Zone Better Residences) : इस पेटी में छोटे व्यापारी, पूंजीपति, उद्योगपति और प्रबंधक आदि लोगों के मकान होते हैं। यहां अच्छे होटल भी देखने को मिलते हैं। इस पेटी में लोगों की भव्य भवन आदि मिलते हैं और मकानों के आगे काफी खुला भाग पाया जाता है।

5. नगर की ओर अधिगमन करने वालों का क्षेत्र (The Commuter's Zone) : यह नगर की सबसे बाहरी पेटी होती है, जिसमें केंद्रीय व्यापारिक पेटी और उपनगरीय क्षेत्रों का अभिगमन होता रहता है। इस पेटी में रहने वाले अधिकांश लोग केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में हो रहे कार्यों से संबंधित होते हैं। कुछ लोगों ने इस पेटी को शयनगार का नाम दिया है। नगर की इस पेटी में परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होती है।

टिप्पणी

• होमर हॉयट का खंडीय सिद्धांत (Homer Hoyt's sector Theory)

नगरों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत अमेरिका के समाजशास्त्री होमर हाइट ने 1939 में प्रकाशित किया। हाइट ने बताया कि विभिन्न प्रकार के रिहायशी क्षेत्र अलग–अलग त्रिज्या के सहारे बाहर की ओर फैलते हैं। प्रत्येक खंड के भारी चाप में होने वाली नई वृद्धि उस खंड के पूर्ववर्ती लक्षणों को समेटे हुए रहती है। हाइट के अनुसार नगर में निम्नांकित प्रकार के खंड देखने को मिलते हैं:–

1. केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र
2. थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग खंड
3. निम्न स्तर का आवासीय खंड
4. मध्यम श्रेणी आवासीय खंड
5. उच्च स्तर का आवासीय खंड

हाइट का नगर विकास का खंडिय सिद्धांत नगरी भवनों के किराए पर आधारित है। खंडीय सिद्धांत में भिन्न–भिन्न किराए के क्षेत्र स्थिर न होकर परिवर्तनशील होते हैं। किसी एक सेक्टर में उच्च किस्म के आवासीय क्षेत्र उसी सेक्टर में बाहरी सीमाओं की ओर जाने का प्रयास करते हैं। इससे पुराने मकानों का क्षेत्र पीछे रह कर मध्यम श्रेणी का बन जाता है।

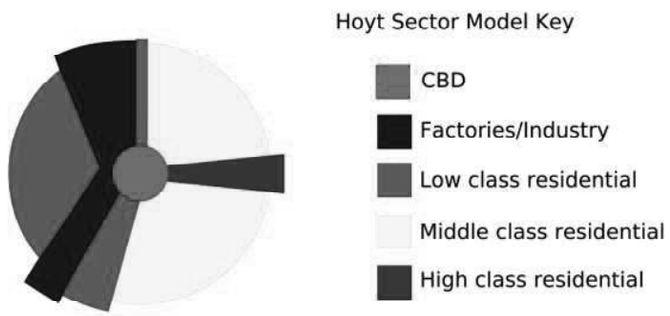

– नगर का लंबवत विकास होता है। एक परिवार वाले मकान एक से अधिक परिवार वालों में परिवर्तित हो जाते हैं।

– जनसंख्या बढ़ने पर मकान नगर की सीमा से बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। इसे अपकेंद्रीय विस्तार कहते हैं। इस के तीन रूप होते हैं: (क) ध्रवीय विकास (ख) एकाकी बस्तियां (ग) एकांकी बस्तियों का संलयन।

– खाली पड़े भूखंडों पर मकान बनने लगते हैं।

• बहु–नाभिक सिद्धांत (Multi Nuclei Theory)

भूगोलवेत्ता हैरिस तथा उलमान द्वारा 1945 में यह सिद्धांत दिया गया। इनके अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक ही केंद्र की नहीं वरन कई भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है। इन विकास केंद्रों की संख्या उस क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास और अवस्थिति की शक्तियों पर निर्भर करता है। यह कारक कुछ कार्यों का समूहीकरण कर देता है और कुछ कार्यों का प्रकीर्ण कर देता हैं।

उलमान के अनुसार नगरों की वृद्धि का प्रारूप अलग–अलग केंद्र के चारों ओर मिलता है ना कि केवल एक ही उत्पति केंद्र के चारों ओर। सिद्धांत के अनुसार नाभि केंद्र से कोई फुटकर व्यापार केंद्र, बंदरगाह, कोई विशिष्ट उद्योग, कोई खदान या कोई समुद्री पुलिन पृथक्करण का कारण हो सकता है। नगर में बहु–नाभिकों के उदय के लिए ये परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं :–

- कुछ कार्यों के संपन्न होने के लिए अनेक सुविधाएं एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं।
- कुछ कार्यों को विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। नगर का बिक्री क्षेत्र नगर के भीतरी भागों से यातायात से जुड़ा होता है।
- कुछ कार्य सर्वोत्तम लोगों के ऊंचे किराए को देने में असफल होते हैं जैसे थोक व्यापार व भंडारण के कार्य। ऐसी क्रियाएँ कम किराये वाले स्थानों पर चलती हैं।
- कुछ क्रिया एक दूसरे के विपरीत पनपती हैं जैसे किसी नगर में फैक्ट्री का विकास और उच्च श्रेणियों के आवास क्षेत्र एक दूसरे के पास नहीं पनपते हैं। इसी प्रकार फुटकर व्यापार क्षेत्र व थोक व्यापार क्षेत्र भी अलग होते हैं।

हैरिस व उलमान ने अपने सिद्धांत में 9 बहु–नाभिकों की चर्चा की :–

1. **केंद्रीय व्यापार क्षेत्र (C.B.D)** : यह नगर का प्रमुख केंद्र होता है और विभिन्न यातायात साधनों से पूरे शहर से जुड़ा होता है। यहाँ जमीन महंगी होती है। पैदल चलने वालों वालों की संख्या अधिक होती है। कुछ महानगरों में नियमित विकास न होने के कारण केंद्रीय व्यापारी क्षेत्र नगर कि केंद्र में विकसित न होकर प्रायः एक छोर पर विकसित हो जाता है। शिकागो, सेंट लुइस व साल्ट लेक सिटी इसके उदाहरण हैं।
2. **थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण क्षेत्र** : यह क्षेत्र केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के निकट ही पाया जाता है। यहाँ बाजार की समीपता व श्रम की निरंतरता बनी रहती है। यह नगर के अन्य भागों से यातायात से जुड़ा होता है। यह पड़ोसी क्षेत्रों की सेवा करता है।

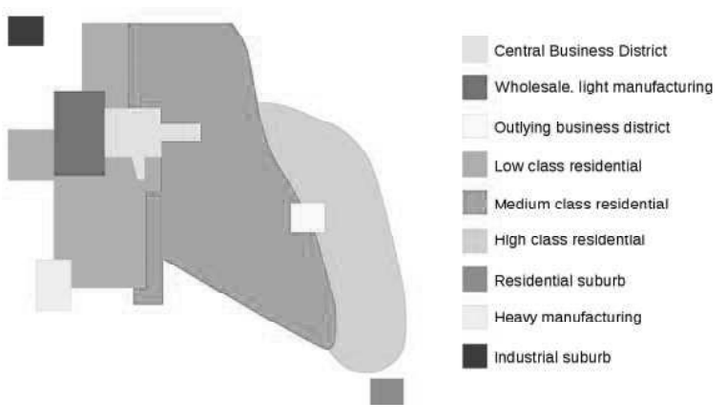

3. **निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्र** : निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्रों का विस्तार केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या भारी उद्योग के निकटवर्ती भागों में होता है। यहां पर श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं।

टिप्पणी

4. **मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र** : इस प्रकार के आवासीय क्षेत्रों का विकास उस भूमि पर होता है जो दूसरे भागों से अपेक्षाकृत सस्ती होती है। इन क्षेत्रों का विकास वहां होता है जहाँ मध्यम प्रकार की सुविधाएं पाई जाती है। यह क्षेत्र रेलवे या सड़क मार्गों के निकट विकसित होते हैं।
5. **उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र** : यह शहर के प्रदूषण, दुर्गंध, शोर, और धुएँ आदि से दूर विकसित होते हैं।
6. **भारी उद्योग क्षेत्र** : भारी उद्योग क्षेत्र का विकास नगर के बाहरी भागों में होता है। ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि कम कीमत पर उपलब्ध होती है।
7. **छोटे–छोटे नाभि चित्र** : विश्वविद्यालय, विद्यालय, कोई सांस्कृतिक केंद्र, बाहरी व्यापार क्षेत्र, छोटे औद्योगिक केंद्र स्वतंत्र नाभि की तरह कार्य करते हैं। मनोरंजन स्थल या पार्क ऊंची श्रेणी की आवासीय विकास को आकर्षित करते हैं। वाशिंगटन का रोकक्रिक पार्क, लंदन का हाइड पार्क इसका उत्तम उदाहरण है।
8. **आवासीय उपनगर** : यह प्रमुख नगर से दूर उपनगर में स्थित आवासीय क्षेत्र होता है। यहां पर रहने वाले लोग मुख्य नगर में रोज जीविका कमाने के लिए यात्रा करते हैं।
9. **औद्योगिक उपनगर** : बड़े औद्योगिक नगर के समीप ही छोटे औद्योगिक नगर स्थापित हो जाते हैं।

आर्थिक मॉडल :

पारिस्थितिकी के सिद्धांतों पर आधारित शहरी भूमि उपयोग मॉडल में केवल मानव व्यवहार के सामाजिक पहलू पर बल दिया गया है। रॉबर्ट एम. हैग (1986) ने अपने लेख और बाद में उन आर.वी. रैटक्लिफ (1949) और विलियम अलोंसो (1964) ने लगान के सिद्धांतों के अनुसार शहरी भूमि का उपयोग के प्रारूप का विश्लेषण किया। एक अमेरिकी क्षेत्रीय वैज्ञानिक विलियम अलोंसो ने 1964 में अंतर–शहरी स्थानिक विभिन्नता के लिए भूमि मूल्यों में भिन्नता और भूमि उपयोग की तीव्रता पर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा।

जमीन और लगान के बीच संबंध

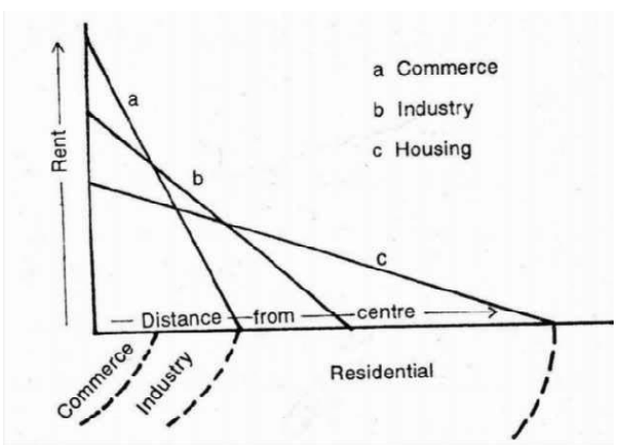

टिप्पणी

यह वोन थुनेन के लगान मॉडल और कृषि भूमि उपयोग पैटर्न जैसा था।

शहर का मुख्य भाग आम तौर पर एक व्यावसायिक क्षेत्र होता है जिसमें प्रमुख कार्यस्थल शामिल होते हैं। इसलिए, भूमि की मांग शहर के केंद्र से दूरी की तीव्रता के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिणामस्वरूप, भूमि का मूल्य दूरी के अनुपात में बदल जाता है। भूमि पर कब्जा अब उपयोगकर्ता की भुगतान क्षमता पर निर्भर करेगा। केंद्र से दूरी का मतलब अधिक परिवहन लागत भी है। यह संभव है कि बढ़ती दूरी के साथ भूमि पर लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला एक 'बोली–किराया' वक्र बनाया जाये। हालांकि बाहरी क्षेत्रों में अधिक भूमि उपलब्ध है पर परिवहन लागत अधिक है, जबकि भीतरी शहर में अधिक लोगों के लिए जमीन कम है पर कम यात्रा व्यय लागत है।

एक शहर की बदलती आकृति (Changing Morphology of Cities)

दुनिया के सभी शहरों के हिस्सों में भौतिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन आए हैं। पिछले सौ वर्षों में शहर की सीमा क्षेत्र में वृद्धि के साथ–साथ शहर के ऊर्ध्वाधर विकास में तेजी रुके साथ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए है। यह वृद्धि अधिक से अधिक लोगों को शहरों में रहने की अनुमति देती है जिससे तेजी से शहरी आकृति विज्ञान में परिवर्तन होता है। ये बदलाव मुख्यतः दो कारणों से संभव हुए हैं–

तकनीकी कारक : सबसे पहले रेलवे और मोटर कारों के आने से परिवहन तेज और आसान हो गया है। जिन लोगों को रोजाना सिटी सेंटर आना पड़ता है, अच्छी सड़कों और परिवहन से यात्रा के समय में कटौती होने के बाद से अब दूर रहने का जोखिम उठा सकते है। ऐसा क्षेत्र जिसे कभी उपनगरीय माना जाता था, सिटी आवागमन क्षेत्र में आ गया। इस क्षेत्र को फास्ट ट्रेन द्वारा जुड़ने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध हो गई। मुंबई का विकास इस घटना का एक आदर्श उदाहरण है।

बिजली : परिवर्तन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक बिजली रहा है। बिजली संचालित लिफ्टों ने भवन को लंबवत रूप से बढ़ने दिया है। जमीन के एक ही हिस्से का कई परतों में उपयोग किसी शहर की वृद्धि और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हो गया है। देश में ऊंची इमारतें नगर आकारिकी का एक अभिन्न अंग बन गयी हैं।

4.3.3 विश्व जनसंख्या वृद्धि : रुझान एवं प्रवृत्तियां

तेज दर से बढ़ती जनसंख्या के अतिरिक्त मानव को विभिन्न आंकड़ों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है जो जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के मूल में हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या की आबादी में वृद्धि को विभिन्न भौगोलिक और अन्य कारक प्रभावित करते हैं।

जनसंख्या वृद्धि पृथ्वी के उन भागों पर निर्भर करती है जहां के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण दशायें मानव के वास और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती हैं। विश्व की जनसंख्या वृद्धि की एक सामान्य प्रवृति निम्नानुसार वर्गीकृत की जा सकती हैं:

टिप्पणी

- उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र
- निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र
- सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र

किसी भी वस्तु की अधिकता अच्छी नहीं होती। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। चाहे वह आपका जीवन हो, आपका वातावरण हो या समूल पर्यावरण हो। जीवन के लिए किसी भी वस्तु का न होना चीज़ों को गलत बना देता है। इसके विपरीत, किसी वस्तु की अधिकता बुरी बला है। अच्छा तभी हो सकता है जब सभी घटक संतुलित रहें। किसी भी वस्तु की अधिकता व अनियंत्रण से विनाश संभव है। जनसंख्या की अधिकता भी उनमें से एक है। अधिक जनसंख्या किसी नियत क्षेत्र में रहने वाली आबादी को दर्शाती है। अन्य शब्दों में, जनसंख्या की अधिकता उच्च धनत्व को दर्शाती है। यदि किसी नियत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक है तो यह जनसंख्या की अधिकता है।

जनसंख्या की अधिकता को समझने के लिए मुख्य घटक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुपात से है। इसका अर्थ है कि उस नियत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या मानव कार्यकलापों को वहन करने की क्षमता व अपेक्षाकृत पर्यावरण की क्षमता से अधिक है। प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की जनसंख्या कब अधिक होती है? जब किसी नियत क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, पर्यावरण का पतन शुरू हो जाता है। भोजन का अभाव और अन्य वस्तुओं और सेवाओं में अधिक जनसंख्या के कारण कमी आ जाती है।

घनी आबादी के लिए उत्तरदायित्व कारक

घनी आबादी प्रकृति की देन नहीं है। इस दशा के लिए विभिन्न घटक जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक मिलकर किसी क्षेत्र की घनी आबादी के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक कारक में उपजाऊ भूमि और मानव आवास के हित में प्राकृतिक दशाएं हैं और मानव निर्मित घटकों में औद्योगीकरण, दूरसंचार सुविधा, व्यापार और वाणिज्य, धर्म, प्रवास और जन्म दर में कमी आदि शामिल हैं। अनुमान यह लगाया गया है कि उपजाऊ भूमि पर रहने वाले लोगों की आबादी घनी है जहां पर खेतीबाड़ी का काम पर्याप्त मात्रा में किया जाता है।

खेतिहर मजदूर की मदद के लिए, कृषि कार्यों के लिए बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। जनसंख्या के बसाव में जलवायु दशाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि किसी स्थान की जलवायु उस स्थान पर रहने वाले लोगों के अनुकूल होती है जैसे हल्की गर्म, हल्की ठंडी और औसतन वर्षा आदि तो उस स्थान की जनसंख्या असीमित होती जाती है जबकि खराब जलवायु वाले क्षेत्रों अत्याधिक ठंडे, अत्याधिक गर्म स्थानों की जनसंख्या विरल पायी जाती है। आर्कटिक और अंटार्टिक क्षेत्रों में अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत विरल संख्या पायी जाती है।

टिप्पणी

राष्ट्र का औद्योगीकरण भी किसी क्षेत्र की सघन जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगीकरण, व्याापार और वाणिज्य उस क्षेत्र में बसाव के लिए लोगों को आकर्षित करता है। इसके कारण घनी आबादी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।

सांस्कृतिक अवरोध जैसे धर्म आदि भी उत्तरदायी बनते हैं। पुरुष अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं और उसमें भी लड़के क्योंकि यही धर्म की मान्यता है।

अधिकांश विकासशील देशों में शिक्षा का अभाव जनसंख्या नियंत्रण उपायों का अवरोधक है। जन्म नियंत्रण उपायों को नहीं अपनाए जाने की स्थिति में जन्म दर में वृद्धि होती है। आज दवाएं मानव की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सक्षम हैं। इस प्रकार से विज्ञान भी जन्म दर वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

घनी आबादी का अन्य महत्वपूर्ण घटक अप्रवास है। राष्ट्र के बहुत से भागों में अप्रवास बहुत बड़ी समस्या है। विकेंद्रीकरण, शहरीकरण, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और उसी स्थान पर बस जाना बहुत सामान्य हो गया है। राष्ट्र के कुछ भागों में अप्रवासियों की भीड़ के कारण असंतुलन की समस्या पैदा हो गयी है और जो घनी आबादी की स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

चीन और भारत सबसे घनी आबादी वाले देश माने जाते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा राष्ट्र बन गया। इसका मुख्य कारण ज्ञान का अभाव और संसाधनों की अधिकता है। दोनों ही देश कृषि पर आधारित हैं। की मिट्‌टी, वन और जलवायु सभी मानव के आवास के लिए हितैषी हैं। अन्य घनी आबादी वाले देश अफ्रीका, यूरोप, जापान और सोवियत संघ आदि हैं। भविष्य में यहां संसाधन अभाव के कारण वैश्विक पर्यावरण तंत्र नष्ट होगा और या विनाश होने की समस्या बढ़ जाएगी।

घनी आबादी की समस्याएं

घनी आबादी से बहुत-सी समस्याएं जुड़ी हैं। इससे आर्थिक समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अप्रवास संबंधी समस्याएं, अकाल, शहरीकरण, गरीबी, प्रदूषण और विवाद और युद्ध, नवीनीकरण नहीं होने वाले संसाधन, भोजन आदि की कमी पैदा हो जाएगी।

वैश्विक पर्यावरण पर घनी आबादी के कारण पड़ने वाले मुख्य प्रभाव विश्व में देखे जा सकेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन भोजन, पानी, शरण स्थल और ऊर्जा संसाधनों के अभाव की समस्या पैदा हो जाएगी। संसाधनों के अभाव के कारण जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। एक तरफ जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ उपलब्ध संसाधन कम होते जायेंगे और दूसरी तरफ उनके लिए अधिक नगरों और कस्बों की आवश्यकता होगी। सड़कों पर वाहनों की अधिकता से पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो जायेंगी। भोजन उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती जायेगी जबकि दूसरी तरफ संसाधन समाप्त होते जायेंगे।

देशों के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो जायेगी जैसे वस्तु निर्माण कार्य (जीएमपी) और जीवन का स्तर, बेरोज़गारी, मुद्रा-स्फीति में कमी आयेगी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण में वृद्धि, सभी देशवासियों के कार्यान्वयन की समस्या और राज्य विकास कार्यक्रम व राष्ट्रों के विकास पर सरकारी व्यय बढ़ता जायेगा।

टिप्पणी

घनी जनसंख्या से विवाद और युद्ध की समस्या भी पैदा हो जायेगी। सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव की परिस्थितियों में आमतौर पर वृद्धि होगी और विवाद सुलझ ही नहीं पायेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की भयावह समस्या पैदा हो जायेगी।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण संपूर्ण विश्व में शहरीकरण बढ़ जायेगा लेकिन जीवन की गुणवत्ता में कमी आयेगी। गरीबी, प्रदूषण, भोजन वितरण में असमानता और भ्रष्टाचार जैसे कारक जनसंख्या में वृद्धि के ही परिणाम हैं। यह बहुत ही संवेदनशील और जटिल समस्या है जिसकी तरफ उन सभी लोगों ध्यान देने की आवश्यकता है जो इस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, विशेष तौर से उन लोगों को जो जिनके पास बदलाव की सामर्थ्यता है।

निम्न जनसंख्या की अवधारणा

निम्न जनसंख्या घनी आबादी के विपरीत की स्थिति है। निम्न जनसंख्या वह स्थिति है जिसमें किसी नियत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध संसाधानों की तुलना में काफी कम है। दूसरे शब्दों में, ऐसे क्षेत्र के लोग जो बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, कम आबादी वाले क्षेत्र कहलाते हैं। कम आबादी वाले देश संसाध नों की दृष्टि से धनी देश हैं जैसे भोजन, ऊर्जा और खनिज पदार्थ। उनका आर्थिक ढांचा पूरी तरह से विकसित है। यह अपेक्षाकृत अधिक कौशल वाली जनसंख्या होती है। इनके रहन-सहन का स्तर उच्च और आय भी अधिक होती है।

कम जनसंख्या के कारण

कम जनसंख्या के लिए पर्यावरण सबसे मुख्य कारक है। पर्यावरणीय घटक जैसे मिट्‌टी का ऊपजाऊपन, जलवायु आदि जनसंख्या वितरण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कम जनसंख्या की स्थिति उन स्थानों पर होती है जिन स्थानों पर जलवायु अत्यधिक गर्म, अत्यधिक आर्द, अत्यधिक ठंडी या अत्यधिक शुष्क होती है। इस प्रकार की दशाएं आमतौर पर जीवन के लिए हितकारी नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार के स्थानों पर बसाव हेतु कम ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए कनाडा, साइबेरिया, अमेज़न बेसिन, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल आदि। इनमें से बहुत से क्षेत्र में संसाधानों का अत्यधिक अभाव है लेकिन ये स्थान मानव के रहने लायक नहीं हैं। इन देशों में संसाधनों की बाहुल्यता है लेकिन आर्थिक रूप से गरीब क्षेत्र हैं।

जनसंख्या की कमी का एक मुख्य कारण माता-पिता की कम संतान की इच्छा भी है। महिलाएं बच्चों के बीच अंतर चाहती हैं। पहले परिवार में 2-3 बच्चे जरूरी थे लेकिन अब बच्चों की मांग घटकर 1-2 तक ही रह गयी है। 20 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करने की बजाय महिलाएं 30 या उसके बाद बच्चा पैदा करना पसंद करती हैं। कुछ मामलों में महिलाओं की जीवन शैली संतानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट होने के प्रति जिम्मेदार है। काम के अत्यधिक दबाव के कारण देरी से विवाह के कारण बच्चे पैदा करने की क्षमता नष्ट होना स्वाभाविक है। गर्भपात की मान्यता भी न्यूनजनसंख्या की वजह बनती है।

कम जनसंख्या के परिणाम

विश्व में कम जनसंख्या के प्रभाव के कारण आर्थिक विकास, संसाधन विकास, जीवन का स्तर आदि से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोग

टिप्पणी

संसाधनों का दोहन बहुत कम मात्रा में करते हैं। काम करने वाले लोगों की कमी के कारण क्षेत्र में आर्थिक दशा बहुत खराब हो जाती है। रहन-सहन के स्तर में गिरावट आती है। लोगों की कमी के कारण काम करने के लिए भी लोग नहीं मिल पाते हैं। मरने या सेवा निवृत्त होने वाले लोगों के स्थान पर नए लोगों की भरती का अभाव हो जाता है। जनसंख्या की कमी से जन्म की दर में भी कमी आती है।

इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा

इष्टतम बेहतरीन स्थिति है। शब्द 'इष्टतम' सबसे अनुकूल परिस्थिति को दर्शाता है।

ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कम या अधिक होना आम बात है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक हो सकता है। कुछ स्थानों पर जनाधिक्य से संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ रही है जबकि अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम होने के कारण संसाधनों का दोहन अत्यधिक किया जाता है। न तो संसाधनों का अभाव हो और न ही उनका दोहन अधिक किया जाए, इसके लिए संतुलन अतिआवश्यक है। इसीलिए बहुत से विचारकों ने इष्टतम जनसंख्या के विचार को महत्व दिया।

इष्टतम स्थिति उन स्थितियों में होती है जब देश के लोग उस देश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में संतुलित होते हैं। इसलिए जनसंख्या के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए, मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है। सरकार को इसके लिए उपाय करने चाहिए। इसमें सभी पर्यावरणीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र और अप्रवास, संतानोत्पत्ति की क्षमता, मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण और अप्रवास के सटीक आंकड़े, आयु का वितरण और जीवन के स्तर में बदलाव आदि शामिल हैं। इष्टतम जनसंख्या के अन्तर्गत दीर्घकालीन समाज के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा में आबादी का संतुलन कायम रखना, नए संसाधानों के दोहन के बीच सही स्तर बनाना एवं बढ़ती जनसंख्या के साथ अन्य प्रकार के रोजगार विकसित करना महत्वपूर्ण है।

माना यह जाता है कि इष्टतम जनसंख्या का कोई विशेष मानक नहीं है। यह देश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधानों पर बदलती निर्भरता को कायम रखता है। तकनीकी ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। यदि नए संसाधन विकसित हैं तो देश बड़े स्तर पर जनसंख्या की सहायता कर सकता है। दूसरी तरफ, यदि किसी देश के संसाधान समाप्त हो जाते हैं तो वर्तमान जनसंख्या भी अधिक जनसंख्या हो सकती है। तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन और इसका विकासात्मक उपयोग भी इष्टतम आकार को साकार कर सकेगा।

जनसंख्या वितरण संबंधी रुझान

विश्व में शहरी जनसंख्या पिछले तीस वर्षों में दोगुनी हो गयी है। हरेक 10 व्यक्तियों में से चार व्यक्ति नगर क्षेत्रों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकीय वेत्ताओं ने नगरों की तरफ प्रवास को मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवास के रूप में दर्शाया है।

नगरों में जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, महामारी, जल जनित बीमारियां और अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इन खतरों से निबटने के लिए कौशल और

पर्याप्त निवेश आवश्यक हैं। ये सभी घातक प्रभाव आधुनिक नगरों के आकार और उनके कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं और बार-बार उनकी दीर्घकालीन जीवन क्षमता के बारे में प्रश्न उठता है।

टिप्पणी

पिछले 30 वर्षों से जनसंख्या समूह बड़े से और बड़ा होता जा रहा है। विकासशील राष्ट्रों में गरीब नगर हैं जिनमें वे सभ्य जीवन व्ययतीत करने के लिए सबसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

बड़े नगर आधुनिक जीवन के प्रभावशाली पहलू बन गए हैं। कारण नगर में अथाह तेज़ी के साथ जनसंख्या वृद्धि है। लंदन के अतिरिक्त बीसवीं शताब्दी की शुरुआत तक पाँच 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर मौजूद ही नहीं थे। मध्य शताब्दी तक, 6 नगरों की जनसंख्या 50 लाख हो गयी। नगरों की जनसंख्या में तेज़ी के साथ वृद्धि होने के कारण वे भी विश्व की जनसंख्या को बढ़ाने में समान रूप से भागीदार साबित हुए हैं। कभी जनसंख्या के केवल 14 प्रतिशत लोग नगर क्षेत्रों में रहते थे लेकिन अब 43 प्रतिशत से अधिक लोग नगर क्षेत्रों में रहते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

3. बीच में दूरियां, कृषि भूमि छोड़कर परस्पर पृथक रूप से बसे अधिवास क्या कहलाते हैं?

   (क) प्रकीर्ण अधिवास (ख) पुंजित ग्राम

   (ग) अपखंडित अधिवास (घ) इनमें से कोई नहीं

4. नगरीय विकास विषयक 'बहु-नाभिक सिद्धांत' किसने दिया?

   (क) एरनेस्ट डब्ल्यू वर्गिस (ख) होमर हाइट

   (ग) हैरिस तथा उलमान (घ) रॉबर्ट एम. हैग

4.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (ग)
3. (क)
4. (ग)

4.5 सारांश

एक बस्ती से एक महानगर के विकास को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया गया मॉडल बस्तियों के विकास का पता लगाता है। एक गांव को घरों के एक छोटे समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्रायः एक सजातीय लोग रहते हैं जिनका एकमात्र व्यवसाय प्राथमिक संसाधन से संबंधित उपयोग जैसे कृषि, मछली पकड़ना,

टिप्पणी

खनन, आखेट आदि होता है। एक महानगर मानव अधिवास का अंतिम अग्रिम रूप है जहाँ मनुष्य नवीनतम तकनीकी का लाभ उठाकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इन दो विकास की चरम सीमाओं के बीच, हम वृद्धि के कई चरण पा सकते हैं।

अधिवास अपने पर्यावरण और इसके आसपास की बस्तियों के साथ अंतक्रिया के माध्यम से बढ़ता या घटता है। बंगाल के अन्य शहरों की भांति कलकत्ता के विकास का इतिहास भी जनसंख्या और क्षय का इतिहास है। इस महानगर में सेवाओं की सघनता अन्य केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों के ठहराव या मंदता के परिणामस्वरूप है। ऊपर से पिछली दो शताब्दियों में यहां बसावट का परिदृश्य संतुलित, पदानुक्रमित संरचना से एक प्राइमेट सिटी मॉडल के लिए बदल गया है। इसलिए अधिवास और अधिवास प्रणाली का उदय तब होता है जब अलग–अलग ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं।

आधार या छत या बस्तियों के विभिन्न तत्वों जैसे पानी के स्रोत, आदि खेती पर आधारित होते हैं। विभिन्न कारक एक समूह को एक खंड के रूप में विकसित करने में सहायक होते हैं। ये हैं उम्र, सेक्स, पैदाइशी बनाम वैवाहिक, अभी पैदा हुआ बनाम शादीशुदा और अंदरूनी बनाम बाहरी। कुछ सामुदायिक संरचनाएं पुरुषों और महिलाओं को अलग–अलग आवंटित की जाती हैं। अलग–अलग पैमाने, विनिर्देश, उपचार और तत्व जैसे खिड़कियां, आदि।

विभिन्न शहरी कार्यों के लिए निश्चित क्षेत्र होते हैं। शहर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए परिदृश्य और सामाजिक–आर्थिक वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन की दिशा और आसन्न क्षेत्र एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं जो एक बार स्थापित होने के बाद हर शहर में स्थापित हो जाता है। एक शहरी बस्ती का लेआउट शुरू में इसके भौतिक वातावरण से संबंधित हो सकता है। हालाँकि, एक चरण आता है जब रूप और संरचना उत्पादन के तरीके और सामाजिक संरचना जैसे अन्य कारकों द्वारा बड़े पैमाने पर यह निर्धारित किया जाता है।

जनसंख्या की अधिकता को समझने के लिए मुख्य घटक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुपात से है। इसका अर्थ है कि उस नियत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या मानव कार्यकलापों को वहन करने की क्षमता व अपेक्षाकृत पर्यावरण की क्षमता से अधिक है। प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की जनसंख्या कब अधिक होती है? जब किसी नियत क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, पर्यावरण का पतन शुरू हो जाता है।

जनसंख्या की कमी का एक मुख्य कारण माता-पिता की कम संतान की इच्छा भी है। महिलाएं बच्चों के बीच अंतर चाहती हैं। पहले परिवार में 2-3 बच्चे जरूरी थे लेकिन अब बच्चों की मांग घटकर 1-2 तक ही रह गयी है। 20 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करने की बजाय महिलाएं 30 या उसके बाद बच्चा पैदा करना पसंद करती हैं। कुछ मामलों में महिलाओं की जीवन शैली संतानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट होने के प्रति जिम्मेदार है।

टिप्पणी

4.6 मुख्य शब्दावली

- **आवंटन** : वितरण।
- **आखेट** : शिकार।
- **मॉडल** : प्रारूप।
- **संरचना** : बनावट।
- **स्थानिक** : स्थानीय/क्षेत्रीय।
- **ऊसर** : अनुपजाऊ भूमि।
- **वृत्ताकार** : जिसका आकार वृत्त जैसा हो।
- **पुरोहित** : पूजापाठ करने वाला ब्राह्मण।

4.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. ग्रामीण एवं शहरी अधिवास की बस्तियों में क्या अंतर होता है?
2. अधिवास में जाति एवं अलगाव संबंधी भूमिका क्या होती है?
3. सघन या पुंजित ग्राम किसे कहते हैं?
4. होमर हॉयर का खंडीय सिद्धांत क्या है?
5. इष्टतम जनसंख्या से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. अधिवास–बस्तियों के उद्‌भव विकास विषयक प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए।
2. मानव अधिवास बस्तियों के निरूपक निर्धारण क्या हैं? समझाकर लिखिए।
3. अधिवासों के विविध स्वरूपों की विवेचना कीजिए।
4. सैद्धांतिक मॉडल और अनुभवजन्य निष्कर्ष से क्या तात्पर्य है? विश्लेषण कीजिए।
5. विश्व जनसंख्या वृद्धि संदर्भित रुझान एवं प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए।

4.8 सहायक पाठ्य सामग्री

Census of India. 1991 :A state Profile.

Clarke, John L 1973 : Population Geography, Pergamon Press, Oxford.

Mamona, C.B. 1981 : India's populations Problem, Kitab mahal N-Delhi.

United nations 1974 : Methods for projections and Urban and Rural Populations No. VIII, New York.

King, Leslie. 1986 : Central place Theory, Saga Punlications New Delhi.

Nangia, Sudesh. 1976: Delhi Metropolitan Region. K.B. Publications New Delhi.

Ramchandran. R. 1992 : Urbanisation and Urban Systems in India, Oxford University Press, N. Delhi.

Singh. R.L. and Kashi nath singh (editor) 1975 : Readings in Rural settlement Geography, National Geographic society of India.

टिप्पणी

इकाई 5 अधिवास पदानुक्रम

टिप्पणी

संरचना

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 अधिवास पदानुक्रम का आधार (क्रिस्टॉलर तथा लॉस की संकल्पना)
  5.2.1 पदानुक्रम में सहायक कारक
  5.2.2 केंद्रीय स्थान सिद्धांत : केंद्रीयता और पदानुक्रम का मापन
5.3 भारत में अधिवासीय पदानुक्रम की प्रायोगिक अवस्थिति
  5.3.1 भारत में अधिवासों का पदानुक्रमिक प्रतिरूप
  5.3.2 भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना
5.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
5.5 सारांश
5.6 मुख्य शब्दावली
5.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.8 सहायक पाठ्य सामग्री

5.0 परिचय

अधिवास बस्तियों को उनके आकार या अन्य सुविधाओं या कार्यों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों से विभाजित करना होता है। पदानुक्रम के अनुसार केंद्रीय स्थानों के अनेक वर्ग–समूह पाए जाते हैं, जिनमें कार्यों का जाल परस्पर संबंधित रूप से फैला होता है। भूगोल में पदानुक्रम विचारधारा का विशेष महत्व है क्योंकि कोई भी शहर एकांत में नहीं बस सकता है, वह विभिन्न प्रकार के दूसरे शहरों से विभिन्न कार्यों के द्वारा जुड़ा होता है और शहर किसी भी स्थान के आर्थिक और सामाजिक बदलाव में विशेष भूमिका अदा करते हैं। शहरी व्यवस्था की अवधारणा को सबसे पहले ब्रायन जे.एल. बेरी (1964) ने अपने उल्लेखनीय कार्य ''शहरों की प्रणालियों के भीतर प्रणाली के रूप में शहर'' में प्रस्तुत किया।

विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के साथ कस्बे और शहर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के चुम्बक बन गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शहर परस्पर संबंधित शहरी स्थानों की एक जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं और ये क्षेत्रों और राष्ट्रों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन में आधारभूत तत्व होते हैं। कस्बों और शहरों के बीच अन्योन्याश्रयता किसी देश की स्वतंत्र बस्तियों को एक शृंखला के बजाय एक शहरी स्थान प्रणाली के रूप में दिखाती है।

किसी भी शहरी व्यवस्था को शहरी स्थानों के अन्योन्याश्रित नेटवर्क रूप में परिभाषित किया गया है। शहरी स्थान के बीच अन्योन्याश्रयता की प्रकृति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हो सकती है। नगरों की व्यवस्था में किसी एक शहर में हो रहे परिवर्तन जैसे जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, रोजगार संरचना के परिणाम सिस्टम में अन्य शहर पर भी नजर आते हैं। शहरी पदानुक्रम का विचार शहरी प्रणाली

टिप्पणी

की अवधारणा के केंद्र से है। शहरी पदानुक्रम अवधारणा मानती है कि शहरी स्थान जनसंख्या के आकार और आर्थिक कार्य में भिन्न होते हैं। शहरी पदानुक्रम का विश्लेषण मुख्य रूप से विभिन्न मानदंडों जैसे जनसंख्या आकार, आर्थिक शक्ति, खुदरा बिक्री और औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के आधार पर शहर के क्रमित–क्रम से संबंधित है।

इस इकाई में हम अधिवास पदानुक्रम संदर्भित क्रिस्टॉलर तथा लॉस की अवधारणा को समझते हुए; पदानुक्रम में सहायक कारक केंद्रीयता व पदानुक्रम मापन तथा भारत में अधिवास पदानुक्रम का अवलोकन करेंगे।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- अधिवासीय पदानुक्रम संबंधी क्रिस्टॉलर तथा लॉस के विचार जान पाएंगे;
- पदानुक्रम में सहायक कारक केंद्रीयता व पदानुक्रम मापन समझ पाएंगे;
- भारत में अधिवासों का पदानुक्रम विवेचित कर पाएंगे।

5.2 अधिवास पदानुक्रम का आधार (क्रिस्टॉलर तथा लॉस की संकल्पना)

नगरों के आकार, बनावट तथा कार्य को पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार माना गया है। विद्वानों ने पदानुक्रम निर्धारित करने के आधार में कार्यों को विशेष महत्व दिया है। पदानुक्रम बस्तियों की केंद्रीयता पर आधारित होता है। केंद्रीयता का अर्थ उस बस्ती में पाए जाने वाले केंद्रीय कार्यों की संख्या व विशेषता से है। इन केंद्रीय कार्यों की विशेषता व गुण पर दो बातों का प्रभाव पड़ता है: बस्ती में पाए जाने वाले कार्यों की संख्या व प्रकार तथा इन कार्यों का स्तर। एक केंद्रीय कार्य के अंतर्गत अनेक उपविभाग पाए जाते हैं: शिक्षा कार्य प्राइमरी स्तर, सेकेंडरी स्तर, कॉलेज स्तर और विश्वविद्यालय स्तर का होता है।

नगरीय बस्तियों द्वारा दो प्रकार से कार्य किए जाते हैं –

प्रादेशिक महत्व के कार्य : ये वे कार्य हैं जो नगर को उसके बाहरी क्षेत्रों से जोड़ते हैं और उनके स्थायित्व पर प्रभाव डालते हैं। इन कार्यों में औद्योगिक प्रकार के कार्य होते हैं।

स्थानिक के महत्व के कार्य : ये वे कार्य होते हैं जो नगर में काम करने वालों और उनके आश्रितों की सेवा करते हैं। इन कार्यों को निम्न तथ्य प्रभावित करते हैं–

(अ) विशेष प्रकार के संस्थान जैसे तकनीकी संख्या या विभागीय स्टोर, (ब) विभिन्न सेवाओं की मांग की गहनता में भिन्नता का पाया जाना जैसे विशेष

चिकित्सक, उच्च किस्म के माल विक्रेता, (स) परिवहन की बढ़ती हुई गतिशीलता व सुलभता पदानुक्रम निर्धारण की विधियां।

नगरों के पदानुक्रम निर्धारण करने के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं। इन विधियों को निम्न समूहों में रखा जा सकता है–

टिप्पणी

• नगरों की संख्या और विविधता आधारित पदानुक्रम

इस आधार पर नगरों का पदानुक्रम निर्धारित करने में उन्हें मिलने वाली समस्त सुविधाओं और सेवाओं की गणना की जाती है। बस्ती में पाए जाने वाले कार्यों की संख्या और उनकी विशेषता को देखा जाता है। इस प्रकार सबसे अधिक कार्य में सबसे ऊंची विशेषता रखने वाली बस्ती को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इस दृष्टि में सबसे प्रमुख कार्य विस्कोसिन तथा न्यूयार्क विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। सन् 1930 के बाद से अधिवासीय पदानुक्रम संबंधी बहुत कार्य हुआ। सन् 1931 में होफर,1932 में डी. सेन्डर्सन, 1933 में ब्रूनर और कॉल्ब, 1934 में आर. ई. डिकिंसन और 1944 में ए.ई.समेल्स ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1958 बैरी तथा गेरिसन जैसे विद्वानों ने 52 आर्थिक कार्यों को चुना और स्नोमिश प्रदेश की बस्तियों का अध्ययन किया। 1966 में डब्ल्यू कारूर्थस ने इंग्लैंड और वेल्स की प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का पदानुक्रम निर्धारित करने में खुदरा व्यापार कार्य के आंकड़ों का प्रयोग किया।

भारत में भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सर्व प्रथम प्रयास डॉ आर.एल. सिंह ने बनारस के प्रभाव क्षेत्र की बस्तियों को उनके कार्यों और आकार के आधार पर चार भागों में बांटा – नगर, उपनगर, बड़े कस्बे, छोटे कस्बे।

1964 में बी.एल.एस. प्रकाश राव ने कर्नाटक राज्य के नगरों का पदानुक्रम निर्धारित किया। 1966 में आर.सी. मैफिब्ड ने लुधियाना व जालंधर जिलों के 61 केंद्रों का अध्ययन किया व सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए 129 कार्यों के आधार पर इन केंद्रों का पदानुक्रम किया।

• कार्यों की केंद्रीयता पर आधारित पदानुक्रम

कार्यों की केंद्रीयता के आधार पर 1933 में क्रिस्टॉलर, 1953 में हैगर स्ट्रैंड, 1954 में स्वेन व गोल्ड गोडलुण्ड महत्वपूर्ण कार्य किए। क्रिस्टॉलर ने टेलीफोन संख्या के आधार पर बस्तियों की केंद्रीयता को ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया और पदानुक्रम में सहायक कारकों पर विचार किया।

5.2.1 पदानुक्रम में सहायक कारक

क्रिस्टॉलर ने नगरों की केंद्रीयता मापने के लिए टेलीफोन की संख्या को आधार माना जो उस समय पश्चिमी देशों के नगरों का पदानुक्रम करने में महत्वपूर्ण रहा।

डब्लू. के. ड़ी. डेविस ने वेल्स केंद्रीय स्थानों का पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रतिपादित किया –

$C = 1 \times 100/T$

C = कार्य का स्थिति गुणांक = कार्य का निर्गम

टिप्पणी

T = संपूर्ण व्यवस्था में कुल निर्गमों की संख्या

यदि किसी क्षेत्र में 500 मेडिकल स्टोर हैं तो स्थिति गुणांक $C = 1 \times 100/500 = 0.2$ होगा

1964 में पालोमाकी ने फिनलैंड के दक्षिणी बोथनिया क्षेत्र में अध्ययन करके केंद्रीयता मापने की दो विधियां बताई–

मात्रात्मक और गुणात्मक

मात्रात्मक विधि नगरों में पाए जाने वाले कार्यों के प्रकारों की संख्या पर आधारित है। गुणात्मक विधि के अंतर्गत के कार्यों को अपने संकेतक समूह में कितना स्थान है: ऐसा कार्य के गुणांक की गणना करके ज्ञात किया जा सकता है। कार्यों की प्राप्ति के बीच सह संबंध का स्तर केवल कार्यों के जोड़ों की परस्पर अंतर निर्भरता को बताने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह केंद्रीय स्थानों को सामान्य केंद्रीयता पर विभिन्न संस्थानों की निर्भरता को भी स्पष्ट करता है।

1974 में प्रकाश राव व रामचंद्रन ने मुजफ्फरनगर जिले को कृषि प्रदेश का प्रतिनिधि मानते हुए उसमें केंद्रीय स्थानों के केंद्रीय कार्यों की गणना करके पदानुक्रम निर्धारित किया। इन कार्यों में उनके द्वारा खुदरा व्यापार कार्यों को महत्व दिया गया।

रेंज और देहलीज (threshold) के संकल्पना से हमें पता चलता है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करते हुए कैसे एक पदानुक्रम विकसित होता है। उपनिवेशवाद के दौरान केंद्रीय स्थानों ने त्रिकोणीय जाली चौखनों की रचना करते हुए अन्त में षटकोणीय रूप ले लिया। चित्र दर्शनीय है–

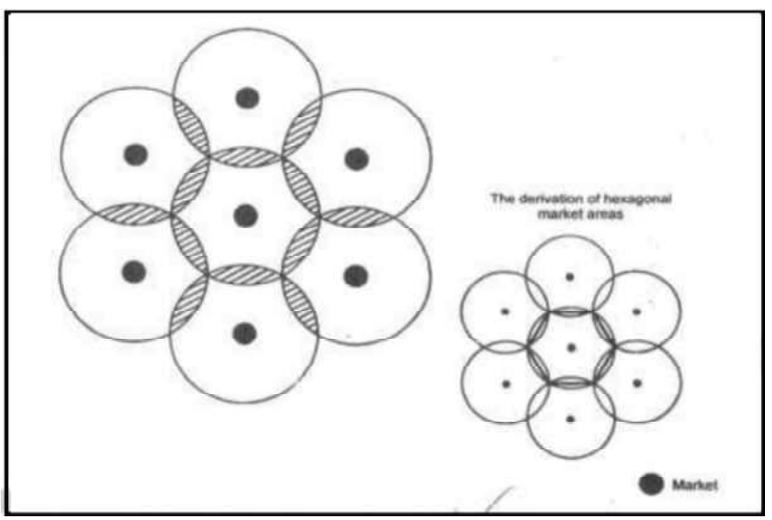

इसके लिए 5 अवधारणाएं मानी गईं –

1. एक क्षेत्र की समान क्रय–शक्ति का समान वितरण वाला मैदान होना चाहिए,
2. केंद्रीय सामान निकटतम केंद्रीय स्थान से खरीदा जाना चाहिए,
3. केंद्रीय स्थान का पूरक क्षेत्र मैदानी सीमा के साथ मेल खाना चाहिए,

टिप्पणी

4. उपभोक्ता की यात्रा को कम से कम किया जाना चाहिए,
5. किसी भी केंद्रीय स्थान द्वारा ज्यादा लाभ अर्जित नहीं की जा सकता है।

यदि यह पैटर्न निचले स्तर पर देखा जाता है, तो क्रमिक रूप से निचला क्रम, केंद्रीय स्थान और केंद्रीय बाजार क्षेत्रों का एक पूर्ण पदानुक्रम मिल जाता है। ऐसे पदानुक्रम की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से निम्नानुसार उभरती हैं :

1. प्रत्येक निचला क्रम, केंद्रीय स्थान, तीन उच्च–क्रम केंद्रीय स्थानों के बीच में स्थित होगा।
2. प्रत्येक उच्च श्रेणी का केंद्रीय स्थल अपने चारों ओर छह अगले निचले श्रेणी के स्थानों से घिरे होंगे।
3. प्रत्येक निचला क्रम केंद्रीय स्थान तीन अगले उच्च क्रम वाले द्वारा साझा किया जाएगा।
4. प्रत्येक उच्च श्रेणी केंद्र स्थान पर, 3 अगले निचले श्रेणी एवं बाजार क्षेत्र अभिसरण करेंगे।

यह क्रिस्टॉलर की शब्दावली भी है कि प्रत्येक केंद्रीय स्थान द्वारा स्वयं केंद्र सहित कुल बस्तियों की संख्या को सेवा प्रदान करने को इसका k मान कहा जाता है। k मान केंद्रीय स्थान या उच्च क्रम स्थान द्वारा सेवा की गई निम्न क्रम की बस्तियों की संख्या से निर्धारित होता है।

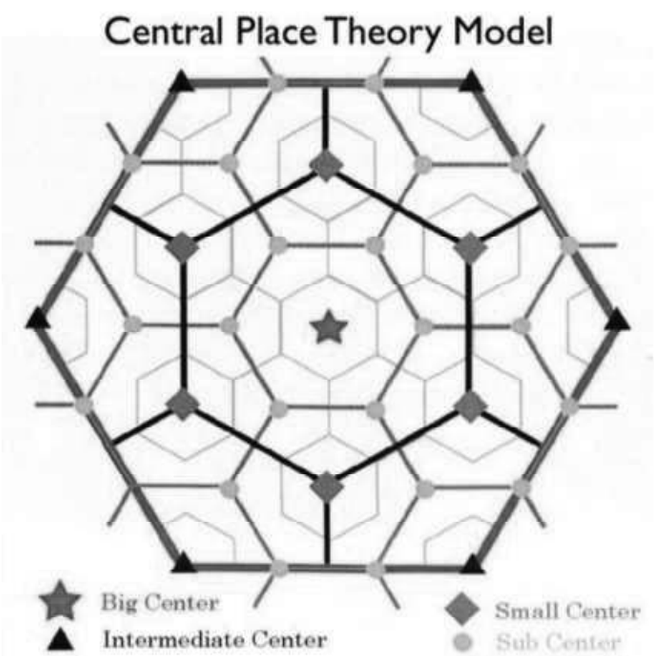

चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रथम क्रम केंद्रीय स्थल आपने साथ–साथ अपने से निचले क्रम की 6 बस्तियों की एक तिहाई जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है और इस प्रकार ये तीन बस्तियों के बराबर सेवा प्रदान करता है जो कि $K = 3$ मूल्य होता है। इस प्रकार यह निचले क्रम की बस्तियों के ग्राहक को आसपास

टिप्पणी

के तीन केंद्रीय स्थानों में से सेवा चुनने का मौका देता है। इस तरह बाजार अनुकूलन नियम या क्रिस्टॉलर का बाजार नियम लागू होता है। K = 4 नेटवर्क यातायात प्रवाह का सबसे बचत वाला प्रबंध है। निम्न कोटि के केंद्र उच्च कोटि के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखाओं पर पाए जाते हैं। एक केंद्रीय स्थान अपने अलावा छह केंद्रों की आधी जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार $(6 \times 1/2 = 4)$ यह कुल 4 स्थानों को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार K = 4 पदानुक्रम विकसित होता है। प्रशासकीय अनुकूलन अवस्था में यह अपने केंद्र सहित आसपास की 6 छोटी बस्तियों की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार $(6 + 1 = 7)$ k = 7 पदानुक्रम विकसित होता है।

प्रत्येक क्रम में अपेक्षित केंद्रीय स्थानों की संख्या की गणना करने के लिए, क्रमिक घटाव और भाग विधि काम करती है। यदि K = 3 और बस्तियाँ संख्या में 81 हैं, तो प्रत्येक क्रम के केंद्रीय स्थान की अनुमानित संख्या होगी–

प्रथम क्रम = 81-81/3=54

द्वितीय क्रम = 81/3-81/9 = 18

तृतीय क्रम = 81/9-81/27 = 6

चतुर्थ क्रम = 81/27-81/81 = 2

पंचम क्रम = 81/81-81/243 = 1

प्रत्येक क्रम के केंद्र के बीच औसत अंतर, बस्ती के बढ़ते क्रम के साथ बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए K = 3 नेटवर्क में उच्च क्रम के केंद्र स्थान में अंतराल, छोटे क्रम की बस्तियों से 1.7 ज्यादा होगा। अगर प्रथम क्रम में अंतराल 5 km है तो द्वितीय क्रम में अंतराल = $5 \times \sqrt{3} = 8.7$ km, तीसरे क्रम में यह अंतराल = $8.7 \times \sqrt{3}$ 15-1 km और चौथे क्रम में यह अंतराल = $15.1 \times \sqrt{3} = 26.2$ km और पांचवे क्रम में यह = $26.2 \times \sqrt{3} = 45.4$km होगा।

लॉस ने सभी k नेटवर्क का इकट्ठा इस्तेमाल किया और उनके आकार में बदलाव किया। K = 3 व्यवस्था को उन उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जिनको कम दूरी की आवश्यकता थी और K = 4 में उन उत्पादों को जो थोड़ी ज्यादा दूरी और K = 7 में उन उत्पादों को जो सबसे ज्यादा सीमा की आवश्यकता थी।

इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते है कि निश्चित K = 3 नेटवर्क मानचित्र पर खींचा गया है और K = 4 नेटवर्क पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर के ऊपर बना कर उसे K = 3 मानचित्र के ऊपर सामान्य केंद्रीय स्थल के ऊपर उसे अंगूठे की सहायता से पिन किया गया।

ओवरले को घुमाने से K = 3 और k = 4 दोनों कागज पर कई प्रमुख स्थान मेल खाते हैं।

उदाहरण के लिए यदि हमारे पास K = 3 स्कूल प्रणाली और K = 4 अस्पताल प्रणाली है, तो हम ओवरले को घुमाने का प्रयास करते हैं ताकि हाई स्कूल और अस्पताल दोनों ही अलग स्थानों की अपेक्षा एक ही स्थान पर स्थापित हों।

लॉस ने K = 7 और इससे भी उच्चतर K नेटवर्क को मानचित्र में जोड़ने की कोशिश की ताकि एक ही स्थान पर अधिक से अधिक सेवाएं एक ही दिशा में स्थापित हो पाएं।

टिप्पणी

लॉस का नेटवर्क

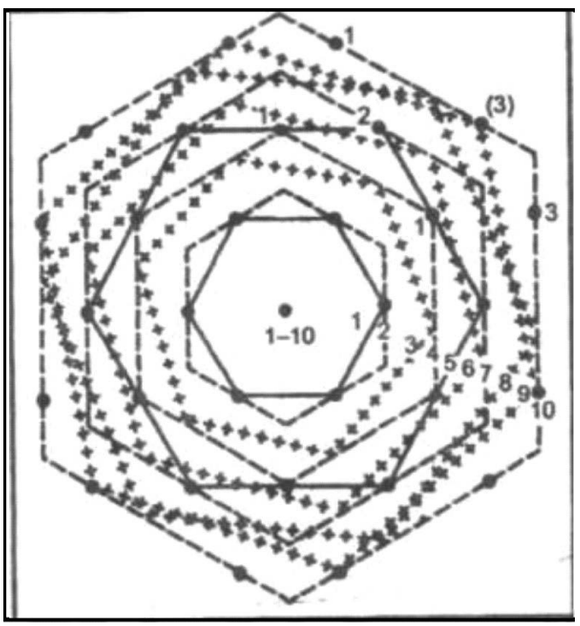

लॉस ने मानचित्र घुमा कर, 12 क्षेत्र उत्पादित किये जिनमें से 6 कई सेवाएं प्रदान करते हैं और शेष छह कुछ सेवाएं ही प्रदान करते हैं। इसे उन्होंने क्रमशः 'सम्पन्न शहर सेक्टर 'और 'गरीब शहर सेक्टर' कहा है।

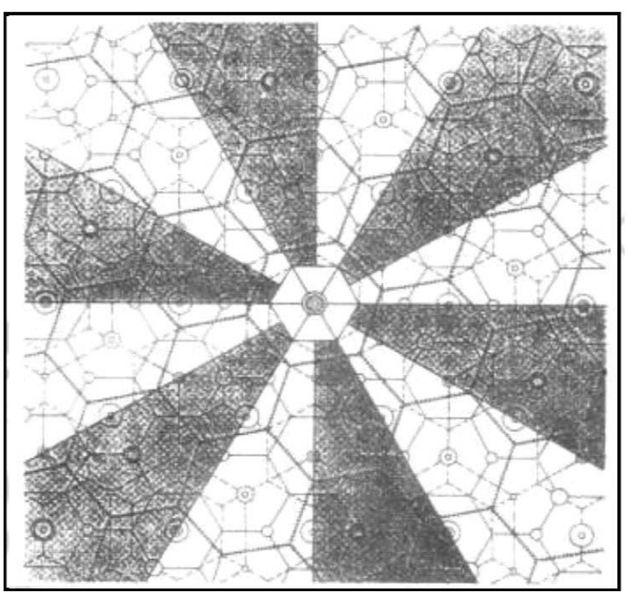

क्रिस्टॉलर के पदानुक्रम में कई निश्चित स्तर होते हैं जिसमें एक विशेष स्तर के सभी स्थानों का आकार और कार्य समान होता है और सभी उच्च क्रम वाले स्थान छोटे केंद्रीय स्थानों के सभी कार्य करते हैं।

टिप्पणी

इसके विपरीत लोस्चियन पदानुक्रम लचीला है। इसमें अलग–अलग स्तरों के बजाय केंद्रों का लगभग निरंतर अनुक्रम होता है। इसलिए एक ही आकार के नगर को एक ही प्रकार के कार्य नहीं करने पड़ते, और बड़े केंद्र को छोटे केंद्र वाले कार्य भी नहीं करने पड़ते।

इनके अलावा भी बहुत से तरीकों की सहायता से किसी केंद्रीय स्थान के पदानुक्रम और उसकी केंद्रीयता को नापा जा सकता है। ये हैं:– स्कैलोग्राम एनालिसिस, जनसंख्या सीमा और स्थान केंद्र और कार्य की रैंकिंग विधि, किसी बस्ती का उनके कार्य के आधार पर पदानुक्रम आदि।

सन 1949 में जी.के.जिफ ने कोटि आकार नियम की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने किसी प्रदेश के नगरों के जनसंख्या आकारों उनकी कोटियों के बीच मिलने वाले अनुभवात्मक नियमितताओं को एक सरल नियम के रूप में समान्यीकृत किया जिसे कोटि का नियम कहते हैं। इसका निम्नलिखित सूत्र है:–

$P_r = P_1/N$

$P_r =$ किसी क्षेत्र में नगरों कोटि का क्रम

$P_1 =$ प्रथम या प्रधान नगर की जनसंख्या

$r =$ ज्ञात किए जाने वाले नगर की कोटि

इस सूत्र के अनुसार यदि प्राइमेट नगर की जनसंख्या 10 लाख है तो दसवें स्थान के नगर की संख्या एक लाख होगी।

भारत में रैंक–आकार संबंध

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या आकार के रूप में रैंक–आकार संबंध अनुपस्थित है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली इस संदर्भ में एक–दूसरे के बहुत करीब हैं। इसके अलावा एक बड़े बहुमत से राज्य भी रैंक–आकार के नियम के अनुरूप नहीं हैं। वास्तव में, प्रधानता भारत के कम से कम 15 राज्यों में मौजूद है और आठ राज्यों (बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड) के प्रमुख शहर दूसरे शहर से केवल कुछ ही बड़े है। केरल में तीन शहर कोचीन, कालीकट और तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) लगभग समान जनसंख्या आकार के हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर और भोपाल, पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और जालंधर आदि शहरों का है। रैंक–आकार राजस्थान राज्य में अच्छे से दिखाई देता हैं। संक्षेप में, भारत में रैंक–आकार का नियम एक नियम के बजाय एक अपवाद है।

गुरुत्व अथवा अंत्यक्रिया नियम

इस नियम का प्रतिपादन एच.सी.केरी ने 1859 में किया था।यह नियम दो क्षेत्रों के बीच के संबंधों को तर्कसंगत तरीके से जांचने का प्रयत्न करता है।इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है :–

$I = P_1P_2/d$

$I = P_1$ और P_2 स्थानों के मध्य सापेक्षिक सबंध

टिप्पणी

P_1 = बड़े नगर की जनसंख्या

P_2 = छोटे नगर की जनसंख्या

d = महानगरों के बीच की रेखीय

दूरी

तीन नगरों के प्रभाव क्षेत्र की सीमा इस नियम के अनुसार निम्न प्रकार रहेगी –

IP_1 नगर का प्रभाव क्षेत्र

= (40000)(20000)/20 = 40

1P_2 नगर का प्रभाव क्षेत्र

= (40000)(5000)/15 = 13.3

1$P_1$1P_3 का प्रभाव क्षेत्र

= (20000)(5000)/10 = 10

नगरों के बीच की दूरी और जनसंख्या आकार पर प्रभाव डालती है।नगर आकार बड़ा होने पर अपना प्रभाव क्षेत्र बड़ा रखेगा।

नेस्टेड पदानुक्रम सिद्धांत

अमेरिकी भूगोलवेत्ता ए के फिलबर्क ने अपने नेस्टेड पदानुक्रम सिद्धांत को निम्नलिखित पर आधारित किया :

1. विभिन्न व्यवसायों जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, विनिर्माण, उद्योग और व्यापार के बीच अंतर–सम्बन्ध पाए जाते हैं जो समान क्षेत्रों पर होते हैं और जो अधिभोग की दृष्टि से समरूप हैं।
2. **नोडल क्षेत्रों की उत्पत्ति** : एक नोडल क्षेत्र में विभिन्न तरह के समान क्षेत्र पाए जाते हैं जो केंद्रबिंदु से जुड़े होते हैं। एक नोडल क्षेत्र का उदाहरण एक शहर हो सकता है, जो विभिन्न मोहल्लों से बना होता है।
3. **नोडल संगठन का नेस्टेड पदानुक्रम** : यह नेस्टेड पदानुक्रम सिद्धांत की तीसरी अभिधारणा है, जो अधिभोग इकाइयों की व्यवस्था से संबंधित है। यह पदानुक्रम एक समान संबंध से नोडल संगठन में बदल जाता है।

फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम

अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैली ने 1931 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार किसी स्थान के द्वारा किसी नगर से प्राप्त फुटकर व्यापार की मात्रा,उस नगर की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उस स्थान एवं नगर के बीच की दूरी में वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। इस नियम को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया गया है:–

$$\frac{s_1}{s_2} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$$

टिप्पणी

S_1 व S_2 का तात्पर्य है दो नगरों P_1 और P_1 द्वारा अपने मध्य में स्थित किसी कस्बे या गांव को जो माल फुटकर में बेचते हैं उनकी दोनों नगरों द्वारा बेची जाने वाली अलग अलग मात्रा। P_1 और D_1 दोनों नगरों की अपनी–अपनी जनसंख्या जो उस कस्बे या गांव के लिए प्रतिस्पर्धा धारण किए हुए हैं। D_1 का अर्थ है– उस मध्यवर्ती गांव या कस्बे से दोनों नगरों की वास्तविक दूरियां।

5.2.2 केंद्रीय स्थान सिद्धांत : केंद्रीयता और पदानुक्रम का मापन

एक प्रणाली के भीतर बस्तियों की दूरी का सैद्धांतिक अध्ययन वाल्टर क्रिस्टेलर द्वारा किया गया था। उनकी पुस्तक ''दक्षिणी जर्मनी में केंद्रीय स्थान'' 1933 में लिखी गई जिसका अनुवाद सी.डब्ल्यू. बास्किन द्वारा 1955 में किया गया (1996 में प्रकाशित)।

यह सिद्धांत अभी भी बस्ती प्रणालियों के विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। क्रिस्टॉलर के सिद्धांत का सार यह है कि एक भूमि की निश्चित उत्पादकता एक बस्ती का समर्थन करती है। यह बदले में इस भूमि को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती है। इसे पूरक क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे कभी कभी सहायक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बस्ती अपने आप में एक केंद्रीय स्थान है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल मार्क जेफरसन ने 1931 में अपनी क्लासिकल बस्ती,' नामक कृति में किया।

सहायक क्षेत्र की सीमा केंद्रीय स्थान के आकार के साथ बदलती रहती है। आकार इस मामले में वास्तव में किए गए कार्यों से संबंधित है, न कि केवल जनसंख्या से। हालांकि अंततः दहलीज जनसंख्या का विचार दर्शाता है कि ये दोनों संबंधित हैं।

जैसा कि हमने देखा है, एक बस्ती प्रणाली अलग–अलग आकार की बस्तियों से बनी होती है जो पदानुक्रमित क्रम में आती हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना सहायक क्षेत्र होगा जिसका आकार उसके द्वारा केंद्रीय स्थान पर किए गए कार्यों की जटिलता से निर्धारित होगा। एक बड़े सहायक क्षेत्र में कई छोटे क्षेत्र शामिल होंगे और ये छोटे क्षेत्र उच्च क्रम के कार्यों के लिए बड़े केंद्रीय स्थानों पर निर्भर होंगे। इसकी इच्छा से सेवा क्षेत्रों का एक नेस्टेड पदानुक्रम बनाते हैं।

आदर्श रूप से प्रत्येक केंद्रीय स्थान इसके चारों ओर एक गोलाकार सहायक क्षेत्र से घिरा होना चाहिए, क्योंकि यह एक पूर्ण केंद्रीय पद सुनिश्चित करता है। हालाँकि, इस प्रकार की ज्यामिति या तो अतिव्यापी भागों का निर्माण करेगी या खाली या बिना सेवा वाले क्षेत्र रह जायेंगे। इस समस्या को षट्भुज बनाने के लिए परिधि समतल करके हल किया जा सकता है जो एक दूसरे के खिलाफ ओवरलैप या रिक्त स्थान के बिना फिट होते हैं।

जैसे–जैसे बस्तियों के उच्च और उच्च क्रम सामने आते हैं, घोंसले की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक एक प्रणाली का सबसे बड़ा क्षेत्र क्षेत्रीय राजधानी नहीं बन कर उभरता। यह सारा क्षेत्र इसके सहायक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक सहायक क्षेत्र का आकार समान रहता है और उन्हें एक साथ रखा जाता है। एक ही स्तर के संबंधित केंद्रीय स्थान एक–दूसरे से समान दूरी पर पाए जाते

टिप्पणी

हैं। क्रिस्टॉलर ने दक्षिण जर्मनी में केंद्रीय स्थानों के सात स्तरों की पहचान की और एक दूसरे से उनकी दूरी के साथ–साथ जनसंख्या और उनके पूरक क्षेत्र के आकार का अनुमान लगाया। वर्णनात्मक नामों से उन्हें वर्गीकृत किया है। तथ्य यह है कि कोई ग्रामीण–शहरी द्वंद्ववाद नहीं है और बस्तियों को एक निरंतरता का हिस्सा माना जाता है। इसे बस्तियों के अध्ययन में अब तक का सबसे संपूर्ण सिद्धांत माना गया है।

सबसे छोटा केंद्रीय स्थान एक षट्भुज के पूरक क्षेत्र की आबादी के साथ–साथ अपनी बस्ती की आबादी को को भी सेवाएं प्रदान करता है। हेक्सागोनल सीमा एक पूरक क्षेत्र को बी, सी आदि से सीमांकित करती है।

इस प्रकार केंद्रीय स्थान ए को ऐसी बस्ती की कुल जनसंख्या का एक तिहाई की सेवा करने वाला माना जाता है। निचले क्रम के किसी भी केंद्रीय स्थान द्वारा वास्तव में कुल 6 बस्तियों की संख्या को सेवाएं दी जाती हैं। इसे प्रत्येक उच्च क्रम द्वारा सेवा प्रदान की गई बस्तियां की संख्या में वृद्धि के अनुपात को निरूपित करने के लिए एक स्थिरांक के रूप में लिया गया था। प्रथम क्रम तीन बस्तियों को सेवाएं देता है। दूसरे क्रम का केंद्र स्थान नौ की सेवा करता है। तीसरे क्रम का स्थान सत्ताइस की सेवा करता है और इसी तरह बढ़ता रहता है।

यह क्रिस्टॉलर का $k = 3$ सिद्धांत है, जहां k एक स्थिरांक है। सिद्धांत अनुकूलन पर आधारित है जहां प्रत्येक स्तर पर ग्राहक केंद्रीय स्थान के जितना संभव हो उतना करीब रहता है। इस का मतलब है कि समान स्तर से केंद्रीय स्थान समान दूरी जबकि प्रत्येक स्तर की वृद्धि के बाद केंद्रीय स्थानों के बीच की दूरी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। सिद्धांत बताता है कि किसी बस्ती प्रणाली में केंद्रीय स्थानों का स्थान इस प्रकार होना चाहिए कि सेवा के लिए किसी ग्राहक द्वारा तय की गई दूरी को न्यूनतम किया जा सके।

वाल्टर क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत

क्रिस्टॉलर और एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1935 में किया। उसके बाद वर्ष 1938 में अंतरराष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने एक शोधपत्र द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नगरीय केंद्र को उत्पादक भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल पोषित करता है। किसी केंद्र की सत्ता इसलिए बनी रहती है कि वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करता है। क्रिस्टॉलर का यह सिद्धांत वॉन थूनेन से मिलता जुलता था। जर्मन विद्वान होने के कारण इनका अध्ययन दक्षिणी जर्मनी के ग्रामीण व अधिवासों पर आधारित था। क्रिस्टॉलर के सिद्धांत का सार यह थाः–

1. एक केंद्रीय स्थान न्यूनतम कुल यात्रा दूरी के केंद्र में स्थित होता है, जो इसके पूरक क्षेत्र के ग्राहकों को न्यूनतम लागत और विक्रेता को अधिकतम लाभ के लिए कार्य और सेवाएं प्रदान करता है।
2. केंद्रीय स्थानों का पदानुक्रम मौजूद होता है, जहां उच्च क्रम वाले स्थान निम्न क्रम के स्थानों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उच्च क्रम स्थान,निम्न क्रम के स्थानों को उनके पास मौजूद कार्य के अलावा कार्य प्रदान करता है।

टिप्पणी

3. उच्च क्रम के अद्वितीय कार्य का प्रभाव व्यापक होता है, जो सामान्य से अधिक होता है।
4. उच्च क्रम वाले स्थान निचले क्रम के स्थानों की तुलना में बड़े क्षेत्र को सेवा देते हैं। उच्च क्रम के क्षेत्रों के केंद्र उच्च डिग्री की केंद्रीयता रखते है।
5. उच्च क्रम के स्थान संख्या में कम और व्यापक रूप से दूरी पर स्थित होते हैं।
6. बड़े क्षेत्र में बहुत से संस्थान होते हैं जो निम्न क्रम के सर्वव्यापक कार्य के अलावा अद्वितीय कार्य भी प्रदान करते हैं क्योंकि कस्टमर हर सेवा चाहे व उच्च स्तर की हो या निम्न स्तर की, प्राप्त करने के लिए कम से कम दूरी तय करना चाहता है।
7. केंद्रीय स्थानों का पदानुक्रम केंद्र के निचले क्रम के केंद्र के साथ विकसित होता है। एक हेक्सागोनल मानार्थ क्षेत्र के भीतर निचले क्रम के केंद्रों का घोंसला तीन प्रमुख नियम विपणन, यातायात और प्रशासनिक स्वरूप द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सिद्धांत की तीन बुनियादी अवधारणाओं को संचलन, नेटवर्क, नोड्स, पदानुक्रम एवं सतहों के क्रमिक चरणों के रूप में अध्ययन के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। केंद्रीय स्थल सिद्धांत का मूल निम्नांकित 6 प्रमुख अवधारणाओं द्वारा निर्मित है :–

1. एक क्रमिक सिद्धांत के रूप में केंद्रीकरण क्रिस्टलर ने प्रतिपादित किया कि सेवाएं केंद्र–बिंदुओं के आसपास केंद्रित होती हैं जो अन्य बिंदुओं के बजाय अधिक महत्वपूर्ण हैं।
2. **केंद्रीय स्थान** : यह सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह अपने से बड़े क्षेत्र में सामान और सेवाएं प्रदान करता है। किसी क्षेत्र में, केंद्रीय स्थान इसकी केंद्रीयता से निर्धारित होता है। कुछ बाध्य और बिंदु बाध्य स्थान या बसावट इसके चारों और पाए जाते हैं। एक निश्चित पैमाने के अनुसार एक स्थान को उच्च क्रम और निम्न क्रम में रखने के लिए उस स्थान के केंद्रीय कार्यों जैसे उसने कितनी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान की,आदि को ध्यान में रखना पड़ता है।
3. **महत्व और केंद्रीयता** : किसी बस्ती का महत्व, इसके निवासियों का कुल योग नहीं है, बल्कि उनके संयुक्त आर्थिक प्रयासों का परिणाम है। यह हो सकता है कि जनसंख्या के आकार और केंद्रीयता की डिग्री के बीच सहसंबंध मौजूद हो।
4. **केंद्रीय कार्य** : ये वो कार्य हैं जो खास स्थानों पर केंद्रित होते हैं लेकिन बहुत सारे स्थानों के लिए होते हैं। ये सर्वव्यापक कार्य नहीं होते हैं। किसी कार्य की डिग्री इसके घटित होने की आवृत्ति के विपरीत होती है। उच्च क्रम केंद्रीय कार्य उच्च क्रम केंद्रीय स्थान से संबंधित हैं और निचले क्रम के कार्य निचले क्रम केंद्रीय स्थान या सहायक केंद्रीय स्थान के हैं। ये कार्य हैं व्यापार, बैंकिंग, प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य और परिवहन आदि।

टिप्पणी

5. **पूरक क्षेत्र** : केंद्रीय स्थान वह है जहां अधिशेष मौजूद है। एक पूरक क्षेत्र वह है, जहां की कमी मौजूद है। पहला कार्यों और सेवाओं के माध्यम से उत्तरार्द्ध को संतुलित करता है।

6. **आर्थिक दूरी और वस्तुओं में विविधता** : मांग और आपूर्ति माल, भण्डारण लागत, भार और समय में कमी तथा यात्रियों का संचार यात्रा में लगने वाला समय, असुविधा और पैसे द्वारा निर्धारित होता है। किसी भी वस्तु या सेवा की मांग और बाजार के क्षेत्र की एक उच्च सीमा होती है जिसके बाहर वह नहीं जा सकता। प्राथमिक विद्यालय या स्थानीय किराना स्टोर की सीमा कम है जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय या डिपार्टमेंटल स्टोर में उच्च सीमा पर्याप्त है। यह दर्शाता है कि किसी भी वस्तु या सेवा की अपनी विशेषताएं होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाती हैं। ऊपरी सीमा एक स्थानिक सूचकांक है जो केंद्रीय स्थान से सबसे दूर की दूरी से निर्धारित होता है। निचली सीमा एक मात्रा सूचकांक है जो केंद्रीय स्थान पर उस कार्य का समर्थन करने के लिए आवश्यक लोगों की न्यूनतम संख्या द्वारा निर्धारित होता है।

अपने इस सिद्धांत को विकसित करने के लिए, क्रिस्टॉलर ने निम्नलिखित सरलीकृत धारणाएँ बनाईं–

1. सभी क्षेत्रों एक असीमित आइसोट्रोपिक (सभी फ्लैट), सजातीय, असीमित सतह।
2. समान रूप से वितरित जनसंख्या।
3. सभी बस्तियां समान दूरी पर हैं और त्रिकोणीय जाली पैटर्न में मौजूद होती हैं।
4. समान रूप से वितरित संसाधन।
5. दूरी क्षय तंत्र।
6. पूर्ण प्रतिस्पर्धा और सभी विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करने वाले आर्थिक लोग हैं।
7. उपभोक्ता समान आय स्तर और समान खरीदारी व्यवहार के हैं।
8. सभी उपभोक्ताओं की समान क्रय शक्ति और वस्तुओं की मांग होती है।
9. उपभोक्ता निकटतम केंद्रीय स्थानों पर जाते हैं, जो वह कार्य प्रदान करते हैं जिसकी उनको जरुरत होती है। वे तय की जाने वाली दूरी को कम करते हैं।
10. माल या सेवाओं का कोई भी प्रदाता अतिरिक्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है (प्रत्येक आपूर्तिकर्ता का भीतरी इलाकों पर एकाधिकार है।)

    इसलिए, इन केंद्रीय स्थानों के व्यापार क्षेत्र जो एक विशेष अच्छी या सेवा प्रदान करते हैं, इन सभी के आकार समान होने चाहिए।
11. परिवहन का केवल एक ही प्रकार है और यह सभी दिशाओं में समान रूप से सुगम्य होगा।

    परिवहन लागत तय की गई दूरी के सीधे आनुपातिक है।

    सिद्धांत तब दो अवधारणाओं पर निर्भर करता था : दहलीज और सीमा।

टिप्पणी

– दहलीज न्यूनतम बाजार (जनसंख्या या आय) है जो किसी विशेष वस्तु या सेवा को बेचने के लिए आवश्यक है।

– सीमा वह अधिकतम दूरी है जो उपभोक्ता सामान या सेवा प्राप्त करने के लिए यात्रा करने के लिए तैयार होता है।

[इन उपभोक्ता वरीयताओं के परिणामस्वरुप विभिन्न आकारों के केंद्रों की एक प्रणाली सामने आएगी। प्रत्येक केंद्र पदानुक्रम के स्तर बनाने वाले विशेष प्रकार के सामानों की आपूर्ति करेगा। कार्यात्मक पदानुक्रम के अंतर्गत बस्तियों के अंतर, आकार और कार्य के संबंध में सामान्यीकरण किए जा सकते हैं।

– बस्तियाँ जितनी बड़ी होंगी, उनकी संख्या उतनी ही कम होगी जैसे कि कई छोटे गाँव होंगे, लेकिन कुछ बड़े शहर होंगे।

– बस्तियाँ जितनी बड़ी होती हैं, उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक होती है, अर्थात गाँव आमतौर पर एक साथ पाए जाते हैं, जबकि शहर बहुत अधिक दूर होते हैं।

– जैसे–जैसे एक बस्ती आकार में बढ़ती है, उसके कार्यों की सीमा और संख्या में वृद्धि होगी।

– जैसे–जैसे बस्ती का आकार बढ़ता है, उच्च–क्रम वाली सेवाओं की संख्या भी बढ़ेगी, यानी सेवाओं में विशेषीकरण बढ़ जाता है।

पदानुक्रम पिरामिड के आधार पर शॉपिंग सेंटर, समाचार एजेंट आदि हैं जो निम्न क्रम के सामान बेचते हैं। ये छोटे केंद्र होते हैं। पिरामिड के शीर्ष पर उच्च क्रम के सामान बेचने वाले केंद्र हैं। ये केंद्र बड़े हैं। निम्न क्रम की वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैं: अखबार के स्टॉल, किराने का सामान, बेकरी और डाकघर। उच्च क्रम की वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरणों में गहने, बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर आदि शामिल हैं। उन्हें बहुत बड़ी आबादी और मांग को सेवाएं देनी होती है।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बस्तियां त्रिकोणीय जाली में बनेंगी, क्योंकि यह बिना किसी ओवरलैप के क्षेत्रों की सेवा करने के लिए सबसे कुशल पैटर्न है। क्रिस्टॉलर द्वारा कहा गया कि विभिन्न लेआउट में K–मान होते हैं जो दिखाते हैं कि केंद्रीय स्थानों के प्रभाव क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ता है – केंद्रीय स्थान स्वयं एक के रूप में गिना जाता है। प्रत्येक भाग को इसके हिस्से के रूप में गिना जाता है।

k = 3 बाजार का सिद्धांत

विपणन सिद्धांत K = 3 के अनुसार, एक उच्च–क्रम स्थान (नोड) का बाजार क्षेत्र अपने पड़ोस में स्थित निचले आकार के स्थानों (नोड) के बाजार क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से को सेवा देता है। निचले आकार के नोड्स (संख्याओं में 6)बड़े आकार षट्भुज के किनारों पर स्थित होते हैं।प्रत्येक उच्च–क्रम बस्ती को प्रत्येक उपग्रह बस्ती का एक तिहाई मिलता है (जो कुल 6 हैं), इस प्रकार $K = 1 + 6 \times 1/3 = 3$ होगा।

इस प्रकार अधिवासों का पदानुक्रम 3,9, 27,81, 243 क्रम में होगा।

टिप्पणी

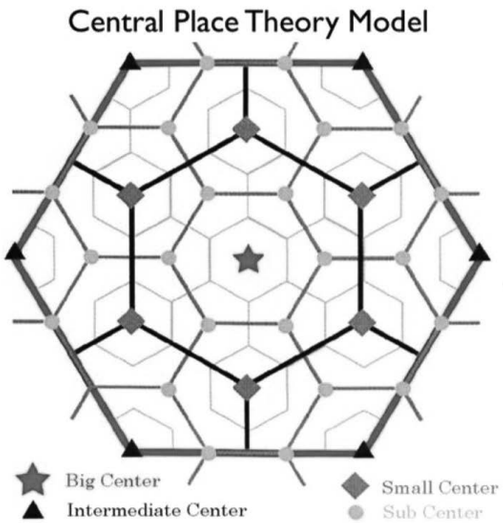

हालाँकि, इस K = 3 मार्केटिंग नेटवर्क में तय की गई दूरी कम से कम हो जाती है।

K = 4 परिवहन अथवा यातायात सिद्धांत

K = 4 परिवहन सिद्धांत के अनुसार, उच्च–क्रम वाले स्थान के बाजार क्षेत्र में छह पड़ोसी निचले–क्रम स्थानों में से प्रत्येक के बाजार क्षेत्र का आधा हिस्सा शामिल होता है, क्योंकि वे उच्च–क्रम वाली बस्तियों के आसपास षट्भुज के किनारों पर स्थित होते हैं। यह केंद्रीय स्थानों का एक पदानुक्रम उत्पन्न करता है जिसके परिणामस्वरूप सबसे कुशल परिवहन नेटवर्क विकसित होता है। उच्च क्रम के केंद्र को जोड़ने वाले मुख्य परिवहन मार्गों पर अधिकतम केंद्रीय स्थान स्थित होते हैं। परिवहन सिद्धांत में सभी पदानुक्रम स्तरों पर केंद्रीय स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों की लंबाई को कम करना शामिल है।इस प्रणाली में, निचले क्रम के केंद्र सभी उच्च क्रम केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों के किनारे स्थित होते हैं। सड़क के साथ स्थानों के इस संरेक्षण से सड़क की लंबाई कम हो जाती है। हालांकि, प्रत्येक उच्च क्रम केंद्र के लिए, विपणन सिद्धांत के तहत 6 केंद्रों के आधे क्षेत्रफल तथा खुद के क्षेत्रफल को सेवाएं देनी होती हैं $(1 \times 1\backslash 2 \times 6 = 4)$। इस नियम के अंतर्गत केंद्र उनके प्रदेशों की संख्या 4,16, 64, 252 का क्रम होगा।

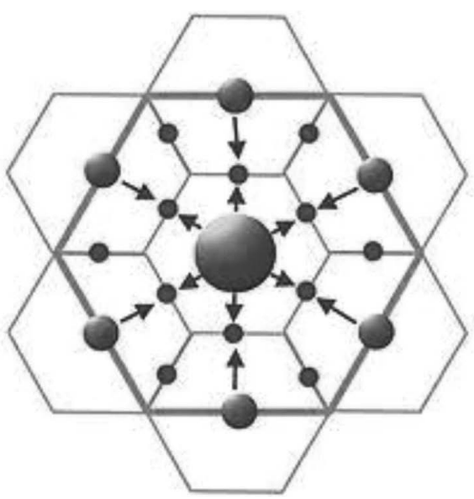

टिप्पणी

K = 7 प्रशासनिक सिद्धांत

K = 7 प्रशासनिक सिद्धांत (या राजनीतिक–सामाजिक सिद्धांत) के अनुसार, बस्तियों को सात के अनुसार घोंसला बनाया जाता है। छोटी बस्तियों के बाजार क्षेत्र बड़ी बस्ती के बाजार क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से संलग्न हैं। चूंकि सहायक क्षेत्रों को प्रशासनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें विशेष रूप से एक ही उच्च–क्रम वाले स्थान पर आवंटित किया जाना चाहिए। कुशल प्रशासन इस पदानुक्रम में नियंत्रण सिद्धांत है। इसमें 7 पुरवा को एक सेवा केंद्र सेवा पहुंचाएगा। नगर 2401 पुरवों की और 49 सेवा केंद्रों की तथा 343 कस्बों की सेवा करेंगे।

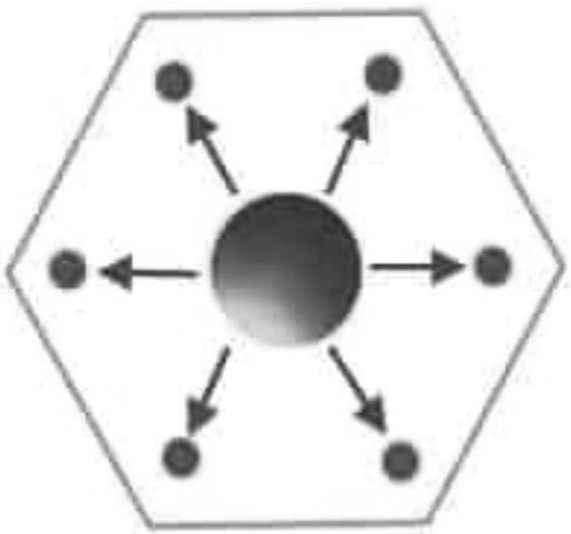

क्रिस्टॉलर ने अपने अध्ययन में पाया कि टेलीफोन की संख्या एक शहर में उपलब्ध केंद्रीय सामान की श्रेणी के लिए एक उपयोगी संकेतक प्रदान करती है। टेलीफोन डेटा के साथ वह एक शहर की केंद्रीयता को परिभाषित करता है। शहर में टेलीफोन की संख्या से शहर की आबादी घटाकर, शहर के पूरक क्षेत्र की टेलीफोन प्रति जनसंख्या की औसत संख्या से गुणा किया जाता है।

उदाहरण के लिए एक शहर की जनसंख्या 25,000 और टेलीफोन की संख्या 5000 है। प्रत्येक 50 लोगों के लिए एक फोन पर 5000–25000(1/50) 4500 का सूचकांक होगा। यह सूचकांक मूल रूप से अपेक्षित सेवाओं के स्तर और केंद्र के अंदर वास्तविक सेवा के स्तर के अंतर को मापता है।

क्रिस्टॉलर के सिद्धांत की आलोचना

1. सिद्धांत का केवल कल्पनात्मक अध्ययन संभव है, जबकि वास्तविक अध्ययन संभव नहीं है।
2. संपूर्ण प्रदेश में सभी तत्व एक अवस्था या परिस्थिति में नहीं मिल सकते।
3. प्रत्येक जगह की अर्थव्यवस्था प्राथमिक या द्वितीय उत्पादन पर निर्भर करती है, काल्पनिक है।
4. कई बार राजनीतिक निर्णय भी पदानुक्रम में बाधा पैदा करते हैं।

5. वर्तमान में तीव्र व आधुनिक परिवहन और संचार के साधन व्यक्ति को मुख्य सेवा केंद्र तक बिना किसी असुविधा के शीघ्र पहुंचा देते हैं। इसलिए सिद्धांत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खरा नहीं उतरता।

टिप्पणी

ऑगस्ट लॉस का सिद्धांत

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ऑगस्ट लॉस ने ''इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन'' नामक पुस्तक को 1940 में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने स्थान का एक सामान्य सिद्धांत स्थापित किया। लॉस ने बिक्री राजस्व से संबंधित अधिकतम लाभ और विपणन कारक के विचार की ओर घ्यान केंद्रित किया। उन्होंने दावा किया कि एक अकेला आर्थिक खिंचाव नहीं है जो अधिकांश बस्तियों को प्रभावित करता है बल्कि यह बाजार, संचार या प्रशासन का जटिल संयोजन है। उन्होंने बाजार क्षेत्र के आकार और आकृति को समझाने का प्रयास किया, जिसके भीतर एक स्थान सबसे बड़ा राजस्व कमाएगा। आपके सिद्धांत की मुख्य बातें हैं–

1. एक समदैशिक सतह
2. वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर आपूर्ति
3. जनसंख्या समान रूप से वितरित है
4. कीमत में वृद्धि के साथ मांग घट जाती है। यदि परिवहन लागत में वृद्धि से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उत्पादन केंद्र से दूरी के साथ मांग घट जाएगी। मांग वक्र शंकु के आकार का होगा और बाजार क्षेत्र वृत्ताकार।
5. उद्यमी एक आर्थिक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है।

उन्होंने दुनिया को कुछ ज्यादा ही आसान मानकर एक समतल मैदान में बदल दिया जिसमें आपूर्ति स्थिर रखी और मान लिया कि कीमत में वृद्धि के साथ किसी उत्पाद की मांग कम हो जाती है। यदि परिवहन लागत में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ जाती है, उत्पादन केंद्र से दूरी के साथ मांग घट जाएगी।

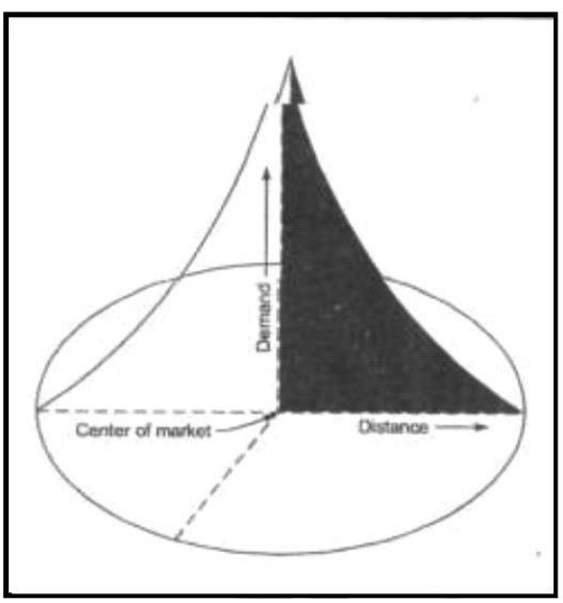

टिप्पणी

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई निर्माता स्थित हैं पर प्रत्येक निर्माता क्षेत्र में एक दूसरे से इस तरह से समान दूरी पर हैं कि उनके बाजार क्षेत्र वृत्ताकार हैं।

बाजार क्षेत्र का आकार उद्यमियों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे ही उत्पादक या उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होती हैं, उनके बाजार क्षेत्र छोटे और छोटे हो जाते हैं और लाभ में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इसके अलावा, निर्माता आगे बढ़ते हैं वृत्ताकार क्षेत्र में कुछ वृत्तों के बीच स्थान बिना सेवा के छूट जाते हैं और अंततः ये एक षट्भुज का आकार ले लेते हैं।

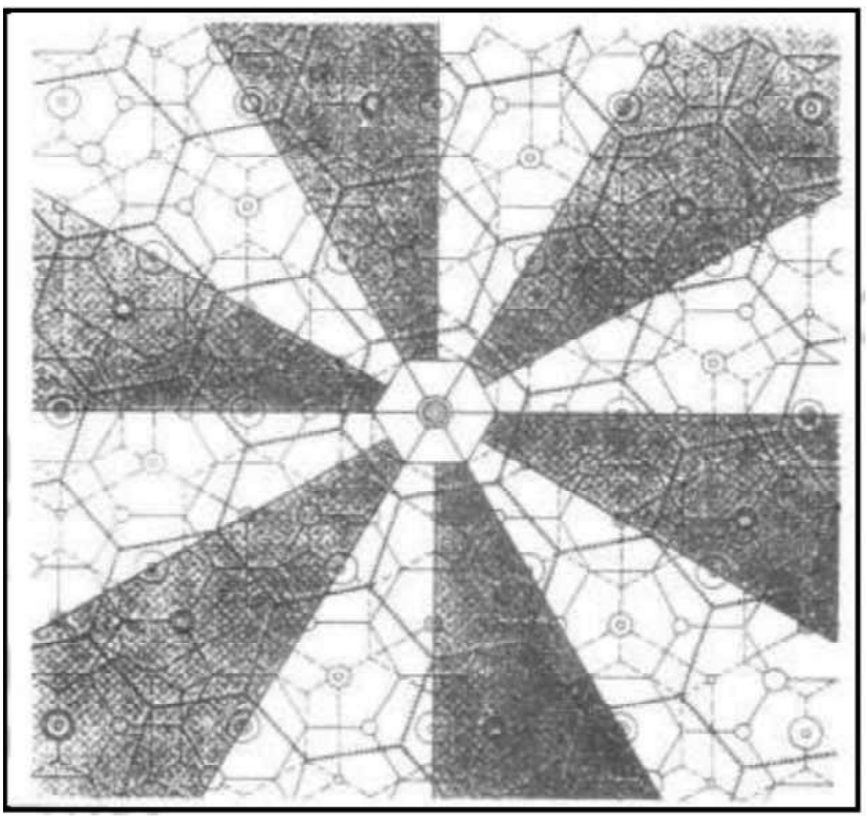

प्रत्येक उत्पाद एक अलग आकार के बाजार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और इसलिए हेक्सागोन्स का आकार भी अलग–अलग होगा।

लॉस ने एक स्थानिक संरचना खोजने का प्रयास किया जो दोनों उत्पादकों और उपभोक्ता के लिए सक्षम हो। इसकी पहचान के लिए उन्होंने मैदान पर स्थापित उत्पादन बिंदु के पूरे सेट में से एक प्रोडक्शन सेंटर को चुना। फिर षट्भुजों को इस प्रकार व्यवस्थित किया ताकि सभी के लिए सामान्य हो। फिर उन्होंने षट्भुजों को केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घुमाया और बाकी हिस्सों को लिया जहां अधिकतम संख्या में हेक्सागोन्स मेल खाकर अधिकतम मांग के बिंदु के रूप में स्थापित हों और जो आदर्श रूप से उद्योग के केंद्रण के रूप विकसित होने चाहिए। बारह में से, छह क्षेत्र उभरे जिनमें कई बस्तियां मौजूद थीं और कई सेवाओं की पेशकश की गई थी। अन्य छह क्षेत्र ऐसे थे, जहां बस्तियां और सेवाएं कम थीं।

हेक्सागोनल संरचना को स्थापित करने के लिए एक आवश्यक वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाइयों की संख्या महत्वपूर्ण है। यह संख्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक काफी उतार–चढ़ाव करेगी। क्रिस्टॉलर के विपरीत लॉस, इस तथ्य को अनुमति देते हैं और इसे अपनी संरचना में ढालते हैं।

टिप्पणी

उनका मानना है कि खेतों या इकाइयों और उनके हेक्सागोनल के निकटतम वितरण को देखते हुए बाजार क्षेत्रों में खेतों की सबसे छोटी संख्या तीन होगी।

यह न्यूनतम सीमा है और उसके बाद चार और सात और लगातार क्रम जारी रहेगा। यह क्रिस्टॉलर द्वारा विकसित तर्क के साथ सहमति है, लेकिन लॉस सफल व्यवस्थाओं की पूरी शृंखला के लिए विचार देते हैं। क्रिस्टॉलर की केवल 3, 4, 7 और लॉस की पूरी शृंखला 3, 4, 7, 9 12, 13, 16 आदि है।

वह दस सबसे छोटे क्षेत्रों पर विचार करते हुए उनके बीच संबंध को सारणीबद्ध करते हैं। इस प्रकार, अधिकतम मांग के बिंदु उद्योग की एकाग्रता के रूप में उभरते हैं। बेची गई प्रत्येक अच्छी और दी जाने वाली प्रत्येक सेवा की एक अलग निचली और ऊपरी सीमा होगी। विभिन्न बिन्दुओं पर प्रदान की गई सेवा की अलग सीमा होगी।

इस प्रकार, एक सोचे गए समान धरातल पर डिजाइन किए गए विभिन्न जालों की स्थिति बन जायेगी। एक बिंदु पर सभी जालों को मनमाने ढंग से केंद्रित करके कुछ क्रम पेश किए जा सकते हैं, जो महानगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे विभिन्न जालों (षट्भुजों) को इस बिंदु पर लगभग घुमाकर शहर के समृद्ध और शहर गरीब क्षेत्रों को अधिकतम डिग्री के संयोग साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। शहर के अमीर और शहर के गरीब क्षेत्रों के बीच मुख्य परिवहन मार्ग स्थित होगा।

आलोचना

लॉस के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर हुई है:–

1. लॉस का सिद्धांत अमूर्त प्रकृति का है।
2. इसने मांग पर अधिक जोर दिया।
3. यह किसी स्थान की स्थानीय अन्योन्याश्रयता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखने में विफल रहा है।
4. बाजार की मांग के बारे में लॉस की धारणा बहुत सरल थी। वास्तव में एक उद्यमी को मांग को आधार के रूप में अनुमान लगा कर किसी इकाई की स्थापना से पहले कई स्थानीय मुद्दों से निपटना पड़ता है।
5. बाजार अलगाव में नहीं होते बल्कि अतिव्यापन करते हैं। इसलिए, जैसा कि लॉस ने बताया है, स्थान संतुलन शायद ही कभी किसी इकाई/उद्यमी और उसके बाजार के बीच होता है।
6. अनुभवजन्य अध्ययन में ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई दिया जैसा कि सिद्धांत में परिकल्पित है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. भारत में जनसंख्या आकार के रूप में 'रैंक–आकार' किस राज्य में अच्छे से दिखाई देता है।

   (क) महाराष्ट्र (ख) प. बंगाल

   (ग) राजस्थान (घ) उड़ीसा

2. केन्द्रीय स्थल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?

   (क) क्रिस्टॉलर (ख) रैली

   (ग) फिलबर्क (घ) लॉस

5.3 भारत में अधिवासीय पदानुक्रम की प्रायोगिक अवस्थिति

भारत में अधिवास–पदानुक्रम गांवों/कस्बों से शहरों की तरफ है। जब एक कस्बा अस्तित्व में आता है, तो वह एक या कई कारकों पर आधारित कार्यों को अर्जित कर लेता है। इन कार्यों का पदानुक्रम निम्न प्रकार से होता है–

1. **प्रसंस्करण** : यह एक कस्बे का सर्वाधिक मूलभूत कार्य होता है, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है, उदाहरण के लिए–गेहूं का आटे में तथा तिलहन का तेल में सर्वाधिक सुगम पहुंच वाला गांव सामान्यतः प्रसंस्करण केंद्र बन जाता है। संभवतः यह प्राचीनतम कस्बों के उदय का प्रमुख कारण रहा होगा।

2. **व्यापार** : प्रसंस्करण के उपरांत, कस्बों का अगला स्तर बाजार से जुड़ा होता है, जो प्रसंस्करित माल या विनिर्मित उत्पादों के विनिमय केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये बाजार साप्ताहिक या दैनिक आधार पर संचालित होते हैं। संपूर्ण भारत में साप्ताहिक बाजारों का आयोजन एक सामान्य विशेषता है। ये केंद्र एक या अधिक वस्तुओं के सम्बंध में विशेषीकृत हो सकते हैं, जैसे– खाद्यान्न, फल व सब्जी, पालतू पशु इत्यादि।

3. **कृषि–उत्पादों का थोक व्यापार** : ऐसे शहर नगरों के कार्यात्मक प्रतिरूप में अगले उच्च स्तर का निर्माण करते हैं। परिवहन सुविधा इन शहरों में एक निर्णायक कारक होती है। इन शहरों में प्रसंस्करण कार्यों के अतिरिक्त विनिर्माण गतिविधि एवं अन्य सेवाओं का विकास भी होता है। ये छोटे आकार के शहर सामान्यतः परिक्षिप्त होते हैं। इनमें एक या अधिक वस्तुओं का विशेष स्थान हो सकता है। उदाहरणार्थ, हापुड़ खाद्यान्नों के थोक व्यापार का केंद्र है, जबकि अहमदाबाद सूती वस्त्र, सांगली हल्दी, बंगलौर रेशम तथा गुंटूर तंबाकू के लिए प्रसिद्ध हैं।

4. **सेवाएं** : इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, संचार इत्यादि सम्मिलित हैं। ये सेवाएं सामान्यतः गांवों में उपलब्ध नहीं हो सकतीं। इन सभी कार्यों में प्रशासन

सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। एक नगर पंचायत संघ, राज्य सहकारी समिति या एक जिले का मुख्यालय हो सकता है। प्रशासनिक नगरों में कानूनी अदालतें, पुलिस स्टेशन एवं अन्य सरकारी विभाग भी होते हैं। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर का एक अच्छा उदाहरण है।

टिप्पणी

5. **विनिर्माण एवं खनन** : इस प्रकार की गतिविधियां बड़े नगरों के उदय में योगदान देती हैं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर रोजगार अवसरों का जन्म होता है तथा व्यापार, सेवा, यातायात, सहायक उद्योग जैसी अन्य उपयोगी आर्थिक गतिविधियों का विकास होता है। ये गतिविधियां संलग्न क्षेत्रों से वृहत स्तर पर प्रवासन को आकर्षित करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के चारों ओर जमशेदपुर का विकास हुआ जबकि कोलार एवं रानीगंज खनन गतिविधियों के फलस्वरूप विकसित हुए।

6. **परिवहन** : सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों तथा नगर के विकास एवं अग्र विस्तार हेतु परिवहन एक मूलभूत आवश्यकता है। इसीलिए अनेक नगर रेलवे स्टेशनों या बंदरगाहों के आस–पास विकसित हुए हैं। दक्षिण भारत में जोलार पेट्टी नामक शहर एक रेलवे जंक्शन के चारों ओर विकसित हुआ है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कांडला, पारादीप इत्यादि नगरों का विकास बंदरगाहों के आस–पास हुआ है।

7. **तीर्थ भ्रमण/पर्यटन** : तीर्थ भ्रमण यात्रा एवं अस्थायी निवास से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। तीर्थस्थलों पर परिवहन एवं यात्री निवास की सुविधाओं का विकास होता है। तिरुपति, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी एवं रामेश्वरम तीर्थ स्थानों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। दार्जिलिंग, शिमला, ऊटकमंड पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुए कुछ नगरों में से हैं।

8. **आवासीय सुविधाएं** : आवासीय कार्यों व सुविधाओं वाले शहर प्रायः बड़े नगरों के चारों ओर विकसित होते हैं, जहाँ निम्न कीमत वाली भूमि, सस्ती मूलभूत सुविधाएं तथा मुख्य नगर के साथ त्वरित सम्पर्क कायम करने वाली परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होती है। सोनीपत, फरीदाबाद, नोएडा जैसे नगर दिल्ली के चारों ओर विकसित हुए हैं, जिनमें विनिर्माण गतिविधियों का विकास भी हुआ है।

किसी नगर के कार्य उसकी अवस्थिति, आधारभूत संरचना, सुविधाओं तथा ऐतिहासिक व आर्थिक कारणों पर आधारित होते हैं। अधिप्रभावी कार्य की उस गतिविधि विशेष में संलग्न व्यक्तियों को संख्या के आधार पर पहचाना जा सकता है।

5.3.1 भारत में अधिवासों का पदानुक्रमिक प्रतिरूप

विभिन्न स्तरों पर नगरों का वितरण इस प्रकार से होता है कि छोटे नगर संख्या में अधिक तथा सघन रूप से स्थापित होते हैं। इनमें से प्रत्येक के कार्यों अथवा संरचना के आधार पर पदानुक्रम को स्पष्ट किया जा सकता है।

टिप्पणी

संरचनात्मक पदानुक्रम

संपूर्ण विश्व के शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू नगर प्रणाली के भीतर बड़े एवं छोटे शहरों के विकास का असमान प्रतिरूप मौजूद होना है। प्रत्येक नगर प्रणाली के अंतर्गत कुछ बड़े नगर तथा अनेक छोटे कस्बे विद्यमान होते हैं। बड़े नगरों में कुल शहरी जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़ा भाग रहता है, जबकि संख्या में अधिक होने के बावजूद छोटे नगरों द्वारा कुल शहरी जनसंख्या में अपेक्षाकृत अल्प भागीदारी निभायी जाती है।

दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर भारतीय नगरीय प्रणाली के शीर्ष पर स्थित हैं। इन शहरों में कुल शहरी जनसंख्या का एक–तिहाई से भी अधिक भाग रहता है। इनके बाद एक लाख तक की जनसंख्या वाले प्रथम श्रेणी के नगर तथा मध्यम नगर (द्वितीयक एवं तृतीयक नगर) आते हैं। इन नगरों में एक–चौथाई से अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के नगर,जिनकी संख्या कुल शहरों की संख्या का 48 प्रतिशत है, संपूर्ण शहरी जनसंख्या के मात्र 105 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित प्रमुख नगरों एवं कस्बों के वितरण प्रतिरूप में उल्लेखनीय असमानता देखी जा सकती है।

कार्यात्मक पदानुक्रम

प्रत्येक प्रमुख कार्य का अपना पृथक् पदानुक्रम होता है। उदाहरणार्थ– प्रशासन की दृष्टि से सबसे निचले स्तर पर राजस्व ग्राम होता है। इसके बाद पंचायत संघ–विकास खंड–तहसील–जिला का स्थान आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई इत्यादि सरकारी विभाग जिला मुख्यालय पर स्थित होते हैं। जिला मुख्यालय से ऊपर राज्य की राजधानी होती है, जहां राज्यपाल, राज्य विधायिका, उच्च न्यायालय, सचिवालय इत्यादि होते हैं। शीर्ष स्तर पर देश की राजधानी नई दिल्ली है, जहां संसद, राष्ट्रपति भवन, संघीय सचिवालय तथा उच्चतम न्यायालय स्थित हैं।

इसी प्रकार व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण जैसी अन्य गतिविधियों का अपना विशिष्ट पदानुक्रम होता है, जिसके अंतर्गत निम्नस्तरीय कार्य छोटे कस्बों में तथा उच्चस्तरीय कार्य बड़े शहरों में संचालित किये जाते हैं। प्रत्येक स्तर पर उस विशिष्ट कार्य को समर्थन प्रदान करने के लिए एक सुनिश्चित सीमा के भीतर जनसंख्या का होना जरूरी होता है।

नगर क्षेत्र

एक नगर क्षेत्र, वह क्षेत्र होता है जो एक नगर से कार्यात्मक सम्पर्क रखता है। ये सम्पर्क रोजगार, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों से सम्बद्ध हो सकते हैं। इन संपर्कों की मजबूती मुख्यतः परिवहन की लागत एवं यात्रा में लगने वाले समय पर निर्भर होती है। ये सम्पर्क अन्य शहरों के साथ होने वाली प्रतिस्पर्द्धा पर भी निर्भर करते हैं। एक नगर क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कई प्रकार से किया जा सकता है–

1. मुख्य नगर की ओर होने वाले अभिगमक यातायात को मापकर। इस तरीके से नगर क्षेत्र की सीमाएं मुख्य परिवहन मार्गों के आस–पास बन जाएंगी, तथा परिवहन सुविधाओं की कमी वाले भागों में सिमट जाएंगी।

टिप्पणी

2. रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के आवासीय ठिकानों,कार्यालयों एवं अन्य मुख्य इमारतों व स्थलों की पहचान कर उसका मानचित्रण करके।
3. विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं बाहरी मरीजों के आवासीय पते एकत्रित करके उनके मानचित्रण द्वारा।
4. शहर को माल की आपूर्ति करने वाले तथा शहर से आने वाले माल को स्वीकार करने वाले स्थानों को चिन्हित करके। आपूर्तिकर्ताओं एवं प्रतिकर्ताओं की उभयनिष्ठता के कारण दो नगर क्षेत्रों की सीमाएं अधिव्याप्त हो सकती हैं।

एक नगर क्षेत्र की सीमा समय के साथ परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए, रेलवे लाइन की स्थापना या तीव्रतर बस मार्ग का निर्माण नगर क्षेत्र की सीमाओं को विस्तार दे सकता है, क्योंकि उस स्थिति में अधिक संख्या में लोग उस क्षेत्र की ओर प्रवासन करेंगे। एक नगर तथा उस आधारित क्षेत्र की जरूरतों के नियोजन में नगर क्षेत्र की सीमाओं की पहचान सहायक सिद्ध होती है।

ग्रामीण–शहरी विच्छेद सीमा

यह एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसमें दूरी बढ़ने के साथ–साथ शहरी प्रभाव क्रमिक रूप से घटता जाता है। शहरी प्रभाव को मूलतः जनसंख्या की रोजगार संरचना से मापा जाता है। यदि जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग गैर–कृषि गतिविधियों में संलग्न है, तब उस क्षेत्र को शहरी माना जा सकता है अन्यथा यह एक ग्रामीण क्षेत्र होता है।

ग्रामीण–शहरी विच्छेद सीमा क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी विशेषताएं आपस में गुंथ जाती हैं। उदाहरण के लिए, फलों व सब्जियों की खेती इस क्षेत्र को ग्रामीण चरित्र प्रदान करती है, जबकि एक कारखाने की अवस्थिति इसे शहरी रूप दे देती है। इस प्रकार यह क्षेत्र एक शहरी–ग्रामीण स्थिरांक को प्रदर्शित करता है।

यदि इस क्षेत्र में शहरी विकास की गति मद्धिम होगी तो इसका भौतिक विस्तार भी धीमा होगा। इस क्षेत्र के विस्तार में परिवहन की निर्णायक भूमिका होती है।

मुख्य शहर के लोग इस विच्छेद सीमा क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं क्योंकि यहां शहरी एवं ग्रामीण–दोनों प्रकार के जीवन का आनंद उठाया जा सकता है। धीरे–धीरे इस क्षेत्र की अपनी खुद की आधार संरचना एवं सेवाएं विकसित हो जाती हैं। सस्ते एवं तीव्रतर परिवहन के अतिरिक्त अन्य रियायतें उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र की ओर होने वाले प्रवासन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो मुख्य शहर की भीड़भाड़ को कम करने में सहायक होगा।

5.3.2 भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना

स्वतंत्र्योत्तर काल में भारत के बड़े आकार वाले नगरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. मुख्य रेल एवं सड़क मार्गों के साथ–साथ आवासीय कॉलोनियों का विकास।
2. नगरों द्वारा उपनगरीय क्षेत्र का अभिग्रहण।
3. मध्यवर्ती स्थानों में उद्योगों का विकास।

टिप्पणी

4. औपनिवेशिक काल के दौरान बनाये गये पुराने बंगलों का सरकारी आवासों एवं कार्यालयों में रूपांतरण।
5. नयी आवासीय कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं उपनगरीय कस्बों का नियोजित विकास।
6. शहरों के भीतरी भागों में मलिन बस्तियों का विस्तार।

इस प्रकार भारतीय नगर विभिन्न इमारतों के सम्मिश्रण हैं, जहाँ भूमि उपयोग की कई श्रेणियां पायी जाती हैं।

इसका सम्बंध प्राचीन किले, महल या धार्मिक स्थल से है, जिसके चारों ओर एक नगर का विकास होता है। भारत में इन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं–

1. यहां सड़कों व गलियों का एक जटिल चक्रव्यूह होता है, जो प्रायः एक अंतिम बिंदु पर समाप्त होता है। यातायात सामान्यतः एक–तरफा होता है।
2. इमारतें अधिकांशतः पुरानी होती हैं, जो वास्तुशिल्प की विशिष्ट शैलियों को दर्शाती हैं। इन इमारतों में सामान्यतः छोटे उद्यान, छज्जे, अटारी इत्यादि होते हैं। बहुमंजिली इमारतों के निर्माण हेतु ऐसी अनेक इमारतों को तोड़ा जा चुका है।
3. प्राचीन नगर जाति/समुदाय के आधार पर बिखरे होते हैं।
4. इनमें विशेषीकरण का अभाव होता है तथा यहां भूमि का मिश्रित उपयोग (नीचे दुकान तथा ऊपर मकान) होता है।
5. कुछ नगरों में थोक गतिविधियां सम्पन्न होती हैं। यहां भीड़भाड़ एवं यातायात गतिरोध की समस्या बनी रहती है। इसी कारण अनेक परिवार बाहरी इलाकों में बसने चले जाते हैं।
6. इन भागों में आगंतुक व्यापारियों के ठहरने व खाने–पीने के लिए होटलों व रेस्तरांओं का विकास भी किया जाता है।

• छावनी एवं रेलवे कॉलोनियां

ये लक्षण भी औपनिवेशिक काल के दौरान उभरकर आये। इन भागों में नियोजित आयताकार सड़क प्रतिरूप तथा रेसकोर्स एवं परेड ग्राउंड के रूप में विशाल खुला स्थान पाया जाता है। इन क्षेत्रों में स्कूल, डाकखाना, अस्पताल जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अधिकांश छावनी क्षेत्र अपनी पृथक् पहचान रखते हैं, क्योंकि वे एक पृथक् छावनी बोर्ड के अधीन आते हैं।

• रेलतंत्र के परिणाम

भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण रेलमार्गों की शुरुआत के साथ आरंभ हुआ। रेलवे स्टेशन से शहर के मुख्य केंद्र तक जाने वाले सड़क मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस मार्ग पर दुकानों एवं होटलों की संख्या बढ़ती चली गयी। उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के आस–पास आवासगृहों के समूह स्थापित हो गये, जिनके स्वामी अधिकांशतः बाहर से आने वाले प्रवासी थे। मध्यवर्ती स्थानों में मलिन बस्तियां, उद्योग एवं आवासीय भवन स्थापित हो गये।

टिप्पणी

• **नवीनतम विकास**

रेलमार्गों की तुलना में उपनगरीय सड़क परिवहन का तेजी से विकास हुआ है। ये उपनगरीय क्षेत्र मुख्य शहर के आस–पास के 50 किमी. क्षेत्र में फैले होते हैं। उन्नीस सौ तिहत्तर में तेल कीमतों के बढ़ने के परिणामस्वरूप नगरों के क्षैतिज विस्तार में बाधा पहुंची और परिवहन की लागत अत्यधिक बढ़ गयी। लोग अपने–अपने कार्यस्थलों के निकट बसने को वरीयता देने लगे। उस समय ऊर्ध्वाधर वृद्धिपर एक बढ़ता हुआ दबाव मौजूद था। शहर में खुले स्थानों पर भी इमारतों का निर्माण शुरू हो गया। यह प्रवृति महानगरों एवं औद्योगिक केंद्रों में अधिक देखी गयी।

• **अनियोजित नगर विकास**

एक अनियोजित नगर विकास तब उत्पन्न होता है जब सार्वजनिक परिवहन में सुधार के साथ शहर देश में विस्तार करता है। इसमें नगर का विस्तार क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के संदर्भ में होता है। अनियोजित नगर विकास का कारण गांव से शहरों की ओर और साथ ही छोटे कस्बों से बड़े नगरों की ओर प्रवासन तथा जनसंख्या में वृद्धि है। अनियोजित नगर विकास की अवधारणा महत्व की रही है, विशेष रूप से, जैसेकि यह बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी समस्या है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, अनियोजित नगर विकास बड़े रूप में अनियंत्रित रहा है।

ग्रीन बेल्ट का निर्माण करके अनियोजित नगर विकास को रोका जा सकता है।

जब अनियोजित विकास होता है, तब कृषि योग्य भूमि में स्वाभाविक रूप से कमी होने लगती है; गरीबी, अपराध और शहरीकरण से जुड़े अन्य मामलों में वृद्धि होने लगती है; विशेष रूप से झुग्गी–बस्तियों का विस्तार और पर्यावरणीय ह्रास होता है।

भारत में, अनियोजित नगर विकास मेट्रोपोलिटन नगरों के साथ जुड़ा है जो पूरे देश के गांवों और कस्बों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनियोजित नगर विकास दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु, कानपुर, इलाहाबाद और अन्य बड़े नगरों के आस–पास देखा जाता है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. भारतीय नगरीय प्रणाली के शीर्ष पर स्थित हैं–
   (क) 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
   (ख) 7 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
   (ग) 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
   (घ) 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
4. अनियोजित ग्रामीण विकास का परिणाम इनमें से क्या नहीं होता?
   (क) कृषि योग्य भूमि की कमी
   (ख) गरीबी एवं अपराध
   (ग) शहरीकरण संबंधी मामलों में वृद्धि
   (घ) पर्यावरणीय विकस

टिप्पणी

5.4 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ग)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)

5.5 सारांश

सन् 1930 के बाद से अधिवासीय पदानुक्रम संबंधी बहुत कार्य हुआ। सन् 1931 में होफर,1932 में डी. सेन्डर्सन, 1933 में ब्रूनर और कॉल्ब, 1934 में आर. ई. डिकिंसन और 1944 में ए.ई.समेल्स ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1958 बैरी तथा गेरिसन जैसे विद्वानों ने 52 आर्थिक कार्यों को चुना और स्नोमिश प्रदेश की बस्तियों का अध्ययन किया। 1966 में डब्ल्यू कारूर्थस ने इंग्लैंड और वेल्स की प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का पदानुक्रम निर्धारित करने में खुदरा व्यापार कार्य के आंकड़ों का प्रयोग किया।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या आकार के रूप में रैंक–आकार संबंध अनुपस्थित है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली इस संदर्भ में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसके अलावा एक बड़े बहुमत से राज्य भी रैंक–आकार के नियम के अनुरूप नहीं हैं। वास्तव में, प्रधानता भारत के कम से कम 15 राज्यों में मौजूद है और आठ राज्यों (बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड) के प्रमुख शहर दूसरे शहर से केवल कुछ ही बड़े है।केरल में तीन शहर कोचीन, कालीकट और तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) लगभग समान जनसंख्या आकार के हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर और भोपाल, पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और जालंधर आदि शहरों का है।

पदानुक्रम पिरामिड के आधार पर शॉपिंग सेंटर, समाचार एजेंट आदि हैं जो निम्न क्रम के सामान बेचते हैं। ये छोटे केंद्र होते हैं। पिरामिड के शीर्ष पर उच्च क्रम के सामान बेचने वाले केंद्र हैं। ये केंद्र बड़े हैं। निम्न क्रम की वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैंः अखबार के स्टॉल, किराने का सामान, बेकरी और डाकघर। उच्च क्रम की वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरणों में गहने, बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर आदि शामिल हैं।

दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर भारतीय नगरीय प्रणाली के शीर्ष पर स्थित हैं। इन शहरों में कुल शहरी जनसंख्या का एक–तिहाई से भी अधिक भाग रहता है। इनके बाद एक लाख तक की जनसंख्या वाले प्रथम श्रेणी के नगर तथा मध्यम नगर (द्वितीयक एवं तृतीयक नगर) आते हैं। इन नगरों में एक–चौथाई से अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के नगर,जिनकी संख्या कुल शहरों की संख्या का 48 प्रतिशत है, संपूर्ण शहरी जनसंख्या के मात्र 105 प्रतिशत

भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित प्रमुख नगरों एवं कस्बे के वितरण प्रतिरूप में उल्लेखनीय असमानता देखी जा सकती है।

एक अनियोजित नगर विकास तब उत्पन्न होता है जब सार्वजनिक परिवहन में सुधार के साथ शहर देश में विस्तार करता है। इसमें नगर का विस्तार क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के संदर्भ में होता है। अनियोजित नगर विकास का कारण गांव से शहरों की ओर और साथ ही छोटे कस्बों से बड़े नगरों की ओर प्रवासन तथा जनसंख्या में वृद्धि है। अनियोजित नगर विकास की अवधारणा महत्व की रही है, विशेष रूप से, जैसाकि यह बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी समस्या है।

टिप्पणी

5.6 मुख्य शब्दावली

- **प्रणालियां** : पद्धतियां।
- **सांख्यिकीय** : संख्या से संबंधित।
- **षटभुज** : छह भुजाओं से युक्त।
- **अद्वितीय** : जिसके समान दूसरा नहीं हो।
- **परिप्रेक्ष्य** : संदर्भ।
- **परिकल्पित** : जिसकी कल्पना की गई हो।

5.7 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. अधिवास पदानुक्रम में स्थानिक महत्व के कार्य क्या हैं?
2. पदानुक्रम निर्धारण संबंधी डेविस का सूत्र क्या है?
3. लॉस का K नेटवर्क क्या है?
4. क्रिस्टॉलर सिद्धांत की आलोचना किन बिन्दुओं पर की गई?
5. अनियोजित विकास से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. अधिवास पदानुक्रम विषयक क्रिस्टॉलर तथा लॉस की संकल्पना पर प्रकाश डालिए।
2. पदानुक्रम में सहायक कारकों का विश्लेषण कीजिए।
3. केंद्रीयता और पदानुक्रम का मापन समझाइए।
4. भारत में अधिवासीय पदानुक्रम प्रतिरूप की विवेचना कीजिए।
5. भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालिए।

5.8 सहायक पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

Census of India. 1991 : A state Profile.

Clarke, John L 1973 : Population Geography, Pergamon Press, Oxford.

Mamona, C.B. 1981 : India's populations Problem, Kitab mahal N-Delhi.

United nations 1974 : Methods for projections and Urban and Rural Populations No. VIII, New York.

King, Leslie. 1986 : Central place Theory, Saga Punlications New Delhi.

Nangia, Sudesh. 1976: Delhi Metropolitan Region. K.B. Publications New Delhi.

Ramchandran. R. 1992 : Urbanisation and Urban Systems in India, Oxford University Press, N. Delhi.

Singh. R.L. and Kashi nath singh (editor) 1975 : Readings in Rural settlement Geography, National Geographic society of India.